



वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2017-18

निर्यात और रोजगार बढ़ाने के लिए परियोजना निर्यातों का संवर्धन

किसी देश से परियोजनाओं और सेवाओं का निर्यात उस देश के तकनीकी उन्नयन और निर्यात निष्पादन की मूल्य श्रृंखला में वृद्धि का परिचायक होता है। परियोजना निर्यातों के कॉन्ट्रैक्ट आम तौर पर ऊंची कीमतों वाले होते हैं। कड़ी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए निर्यातकों को विदेशी खरीदारों को प्रतिस्पर्धी ऋण शर्तें प्रस्तुत करनी होती हैं। इस तरह, परियोजना निर्यातों के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में लंबी अवधि के आस्थगित ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व में औद्योगिक मांग में गिरावट के चलते दुनिया भर की सरकारें अब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण (ईपीसी) परियोजनाओं के रूप में ऊंची कीमतों वाली मशीनरी, श्रम, विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा और बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को लक्षित कर रही हैं।

परियोजना आयातक देशों में भू-वाणिज्यिक विस्तार के लिए परियोजना निर्यात प्रभावी माध्यम हैं। ये निर्यात हेतु घरेलू विनिर्माण उद्योग को रफ्तार देते हैं और विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ-साथ घरेलू कंपनियों के लिए मांग को बढ़ाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार और आर्थिक विकास पर द्विगुणित प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, परियोजना निर्यात बैकवर्ड लिंकेज के जरिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देते हुए भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल में भी योगदान देते हैं। साथ ही, इससे संबंधित उद्योगों में रोजगारों के अवसर भी पैदा होते हैं।

भारत से परियोजना निर्यातों की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। तब से ही हर बीतते साल के साथ परियोजना निर्यातों का विकास होता रहा है। भारतीय कंपनियां आज विभिन्न विदेशी बाजारों में अलग-अलग तरह की परियोजनाओं पर काम कर रही हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी क्षमता तथा विशेषज्ञता का परिचय दे रही हैं। भारत के निर्यातों में वृद्धि से एक्जिम बैंक करीब से जुड़ा रहा है। भारत तथा उधारकर्ता देशों में बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा निधिक परियोजनाएं भारतीय आपूर्तिकर्ताओं, कॉन्ट्रैक्टरों और परामर्शदाताओं को व्यवसाय के आकर्षक अवसर प्रदान करती हैं। ये अवसर बिजली, जल आपूर्ति, परिवहन, टेलीकम्यूनिकेशन, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान हैं। इन क्षेत्रों में अपने उपयुक्त अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता रखने के चलते बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा निधिक परियोजनाओं में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में भारतीय कंपनियों की स्थिति काफी अच्छी है। सफल परियोजना निर्यात सुविचारित दूरदृष्टि का परिणाम हैं।

विषय वस्तु

निदेशक मंडल	02
प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	03
आर्थिक परिवेश	09
निदेशकों की रिपोर्ट	19
व्यवसाय परिचालन	23
वित्तीय विवरण	49
निर्यात विकास कोष	93

निदेशक मंडल

(18 मई, 2018 तक की स्थिति)

भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक



सुश्री रीता तेवतिया
सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय



श्री रमेश अभिषेक
सचिव
औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय



श्री टी.एस. तिरुमूर्ति
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय



डॉ. अरविंद सुब्रमण्यन
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय



श्री पंकज जैन
संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय वित्त)
वित्तीय सेवाएं विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक, संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों से निदेशक



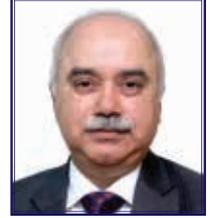
डॉ. एम. डी. पात्रा
कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक



श्री रजनीश कुमार
अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक



श्रीमती गीता मुरलीधर
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
ईसीजीसी लिमिटेड



श्री राजीव ऋषि
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया



श्री एम. के. जैन
प्रबंध निदेशक व सीईओ
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड



श्री दीनबंधु महापात्र
प्रबंध निदेशक व सीईओ
बैंक ऑफ इंडिया

पूर्णकालिक निदेशक



श्री डेविड रस्कीना
प्रबंध निदेशक



श्री देबाशिस मल्लिक
उप प्रबंध निदेशक

प्रबंध निदेशक का वक्तव्य



बीते साल को सामान्य तौर पर, भारतीय बैंकिंग जगत के लिए और खास तौर पर, एक संस्थान के रूप में, एक्जिम बैंक के लिए, बहुत अच्छे वर्षों में नहीं गिना जा सकता। पिछले कुछ महीनों के दौरान, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने देश के वित्तीय ढांचे में सुधार की दिशा में कुछ उपाय किए। यद्यपि, लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये सुधारात्मक उपाय वित्तीय क्षेत्र के लिए अच्छे हैं। तथापि, इनके चलते भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है और एक्जिम बैंक इससे अछूता नहीं रहा है।

वित्तीय वर्ष 2014 तक दोहरे अंक में बढ़ने वाला बैंकों का सकल ऋण, वित्तीय वर्ष 2015 में अचानक एक अंक में सिमट गया। वित्तीय वर्ष 2016 और वित्तीय वर्ष 2017 में इसमें और गिरावट आई। वित्तीय वर्ष 2018 में इस सकल ऋण वृद्धि में 0.80% का मामूली सुधार आया और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 8.20% वृद्धि हुई। यह धीमी वृद्धि दर मोटे तौर पर

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा कर्ज की धीमी चुकौती के कारण रही, जिससे दोहरे तुलन पत्र (ट्विन बैलेंस शीट) की समस्या खड़ी हो गई।

वस्तु निर्यातों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2014 में 314 बिलियन यूएस डॉलर के आंकड़े को छूने के दो साल बाद 300 बिलियन यूएस डॉलर का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने और गैर-तेल आयात बढ़ने से व्यापार घाटा और बढ़ने की आशंका है।

वहीं दूसरी ओर, बाहरी परिवेश में सुधार के कुछ संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं वृद्धि की ओर अग्रसर हैं। पिछले कुछ समय में वैश्विक व्यापार में आई गिरावट में 2017 में कुछ सुधारात्मक संकेत मिले। तथापि, दुनियाभर में बढ़ते संरक्षणात्मक रुख और व्यापार युद्ध के संकेतों को देखते हुए सतत व्यापार परिवेश के लिए चिंता बनी हुई है।

व्यवसाय परिणाम

नए विनियामक उपायों का असर वित्तीय क्षेत्र की स्थिति पर दिखाई देता है, जिसने एक्जिम बैंक के प्रदर्शन को भी प्रभावित किया है।

बैंक के निवल ऋण पोर्टफोलियो में थोड़ी बढ़ोतरी हुई और यह 4.76% की निवल आस्ति वृद्धि के साथ, यथा 31 मार्च, 2017 के ₹ 1026 बिलियन की तुलना में, यथा 31 मार्च, 2018 को ₹ 1075 बिलियन रहा। कुल ऋण पोर्टफोलियो में पॉलिसी व्यवसाय यानी भारत सरकार की ओर से अथवा भारत सरकार के निर्देश पर किए गए व्यवसाय का हिस्सा 38% रहा। जबकि वाणिज्यिक व्यवसाय का हिस्सा यथा 31 मार्च 2018 को बैंक के कुल ऋण पोर्टफोलियो का 62% रहा। नियामकीय बदलावों और व्यापार परिवेश के मंदा रहने से वित्तीय वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही में आस्तियों में गिरावट आई, और वे अनर्जक आस्तियों में तब्दील हो गईं। बैंक ने अनर्जक आस्तियों की समस्या से निपटते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रावधान किए। तथापि, यथा 31 मार्च, 2018 को जोखिम भारित आस्ति अनुपात

(सीआरएआर) के प्रतिशत के रूप में बैंक की पूँजी 10.35% रही, जो कुल पूँजी के लिए आरबीआई के न्यूनतम 9.00% के मानक से ऊपर है।

वर्ष के दौरान, बैंक को भारत सरकार से ₹ 5 बिलियन की पूँजी प्राप्त हुई। यथा 31 मार्च, 2018 को बैंक की चुकता पूँजी ₹ 73.59 बिलियन और आरक्षित निधि ₹ 22.41 बिलियन रही। बैंक की अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग संप्रभु के समान रही, जो मूडीज द्वारा बीएए2, स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा बीबीबी- , फिच रेटिंग्स द्वारा बीबीबी- और जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा बीबीबी+ रही।

पिछले कुछ वर्षों से, भारत सरकार द्वारा बैंक को नियमित रूप से पूँजी प्रदान करते हुए सहयोग दिया जा रहा है और विशेष रूप से रणनीतिक परियोजना निर्यातों में बैंक की भूमिका तथा बैंक से उम्मीदें बढ़ने के साथ ही यह सहयोग भी नियमित रूप से मिलते रहने की उम्मीद है।

पॉलिसी व्यवसाय

वर्तमान में बैंक कई रियायती वित्तपोषण कार्यक्रमों में शामिल है, जो सामान्यतः मध्यम से लंबी अवधि के होते हैं।

ऋण-व्यवस्था ऐसा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और तब से ही विदेश मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से बैंक द्वारा ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जाती रही हैं। आज की तारीख में, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और सीआईएस क्षेत्रों के 62 विकासशील और अल्प विकसित देशों को एक्जिम बैंक द्वारा ऋण-व्यवस्थाएं दी गई हैं। ये ऋण-व्यवस्थाएं बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई हैं।

बैंक 2011 से भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में 'राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण' (बीसी-एनईआईए) नाम के अभिनव कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय परियोजना निर्यातों को ईसीजीसी लिमिटेड के साथ मिलकर संयुक्त रूप से सहयोग प्रदान कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के परियोजना निर्यातों को परंपरागत बाजारों के साथ-साथ ऐसे विकासशील देशों के नए बाजारों में बढ़ावा देना है, जिन्हें मध्यम अथवा दीर्घावधि के लिए आस्थगित ऋणों की जरूरत होती है। बीसी-एनईआईए कार्यक्रम को इसकी शुरुआत से ही उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली है।

एक्जिम बैंक देश की प्रमुख निर्यात वित्त संस्था है और भारत सरकार को इस क्षेत्र में नीतिगत सुझाव देने के साथ-साथ भारत सरकार की भू-आर्थिक रणनीतिक पहलों को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाती है। इस संबंध में, भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, निर्यात विकास कोष (ईडीएफ- एक्जिम बैंक द्वारा संचालित कोष) द्वारा ईरान को (ईडीएफ और सात ईरानी बैंकों के बीच फ्रेमवर्क करार) ₹ 30 बिलियन की क्रेता ऋण सुविधा प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा मंजूर अनुसार, इस संपूर्ण राशि का इस्तेमाल भारत से स्टील रेलों के निर्यात और चाबहार बंदरगाह विकास परियोजना के लिए किया जाएगा।

वर्ष 2015 से बैंक भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में हासिल की गई रणनीतिक महत्व की परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करते हुए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से रियायती वित्तपोषण योजना का परिचालन भी कर रहा है। इस स्कीम के तहत एक्जिम बैंक ने बांग्लादेश के रामपाल, जिला-बागरहाट में 1320 मेगावाट (2x660 मेगावाट) की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना के वित्तपोषण के लिए 1.60 बिलियन यूएस डॉलर का मीयादी ऋण प्रदान किया है। यह ऋण बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, बांग्लादेश और एनटीपीसी लिमिटेड, इंडिया की बराबर हिस्सेदारी वाले संयुक्त उद्यम 'बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड' (बीआईएफपीसीएल) को प्रदान किया गया है। एक बार कमीशन होने के बाद, उम्मीद है कि यह ताप विद्युत संयंत्र बांग्लादेश का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र होगा, जो हजारों बांग्लादेशी नागरिकों के जीवन में प्रकाश लाने का काम करेगा।

इसके साथ ही एक्जिम बैंक, 'परियोजना विकास कोष' के कार्यान्वयन में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ भी एक अधिकार प्राप्त (एंपावर्ड) संस्था के रूप में काम करता है। इस कोष की स्थापना कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम (सीएलएमवी) में भारतीय निवेशों को बढ़ाने के लिए ₹ 5 बिलियन की प्रारंभिक राशि के साथ की गई है। इस पहल के अंतर्गत, बैंक ने सीएलएमवी क्षेत्र में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए संभावनाओं वाले क्षेत्रों को चिह्नित किया है। इन रिपोर्टों के आधार पर ही इस क्षेत्र में चिह्नित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विशेष निधियां (स्पेशल पर्पज व्हीकल) स्थापित की जाएंगी। पीडीएफ पहल भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट नीति' के अनुरूप है।

वाणिज्यिक व्यवसाय

वैश्विक एकीकरण के इस दौर में किसी संस्था की वैश्विक मौजूदगी उसकी सफलता की मापक है। किसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह बात और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। एक्जिम बैंक इस महत्व को समझते हुए भारतीय कंपनियों को उनके वैश्वीकरण प्रयासों में मदद और प्रोत्साहन के लिए 'विदेशी निवेश वित्त' कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशों में भारतीय निवेश को शुरू से ही सहयोग प्रदान करता रहा है। इसके अतिरिक्त, बैंक घरेलू अर्थव्यवस्था में निर्यात क्षमता विकसित करने के लिए नई निर्यात उन्मुख इकाइयों की स्थापना, उनके विस्तार, आधुनिकीकरण, उपकरणों की खरीद, शोध एवं विकास के लिए भी वित्तीय समाधान प्रदान करता है। हाल ही में ऐसा ही सहयोग एक फार्मास्यूटिकल और वैक्सीन निर्माता फर्म को दिया गया, जो अपने क्षेत्र की दुनिया की पांच शीर्ष कंपनियों में शामिल है और उभरते हुए बाजारों में शीर्ष तीन में शामिल है। निर्यात क्षमता सृजन के लिए हमारे ऋण कार्यक्रमों और विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम के खाते में सफलता की कई कहानियां रही हैं। एक्जिम बैंक भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र की कुछ ऐसी कंपनियों के साथ जुड़कर गौरवान्वित है, जो बैंक की सहभागिता से आज नई ऊंचाइयों पर हैं।

इसके साथ ही एक्जिम बैंक ग्रासरूट स्तर के उद्यमों में अंतर्निहित व्यवसाय की संभावनाओं को देखते हुए उनके व्यवसाय को सुगम बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए भी सजग है। बैंक देश के ग्रामीण इलाकों में स्थित उद्यमों के वैश्वीकरण में सहयोग करता है। बैंक द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनके उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग सहयोग प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान, बैंक ने टाटा ट्रस्ट की अभिनव पहल सेंटर फॉर माइक्रोफायनेंस एंड लाइवलीहुड (सीएमएल) के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैंक ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने के साथ-साथ इन उद्यमों के विदेशों में विस्तार के लिए इनके उत्पादों को ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर भी प्लेस कराया है।

सूक्ष्म और ग्रासरूट उद्यमों के साथ काम करते हुए बैंक ने उनके उत्पादों के विकास और डिजाइन से जुड़ी कुछ प्रमुख समस्याओं को भी दूर किया है। बैंक कौशल विकास और प्रशिक्षण संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन करा हस्तशिल्प

उत्पादों के ग्रामीण दस्तकारों और शिल्पकारों की पहुंच देश-विदेश में बढ़ाने के लिए उन्हें सहयोग प्रदान करता रहा है। इसके अतिरिक्त, ऐसे उद्यमों के साथ मिलकर काम करने के लिए अलग से एक टीम है, जो इनके अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग प्रयासों में सहयोग करती है। भारतीय विनिर्माताओं और ग्रामीण उद्यमियों को निर्यात ऑर्डर हासिल कराने में मिल रही सफलता बैंक के लिए संतोष का विषय है।

संसाधन

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न भू-भागों से अलग-अलग निवेशक आधारों और विभिन्न इंस्ट्रूमेंट के जरिए 3.26 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाए।

बैंक ने अगस्त 2017 में 400 मिलियन यूएस डॉलर का 5 वर्षीय रेग-एस फ्लोटिंग रेट फोरमोसा बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किया। बैंक यह निर्गम तिमाही लाइबोर+100 बेसिस पॉइंट की दर पर जारी करने में कामयाब रहा और इस तरह यह भारत से बाहर सबसे बड़ा फोरमोसा बॉन्ड बना। साथ ही किसी भारतीय वित्तीय संस्था द्वारा पहला फोरमोसा ट्रांजैक्शन रहा।

जनवरी 2018 में बैंक ने 1 बिलियन यूएस डॉलर का 10 वर्षीय बॉन्ड निर्गम (इश्यू) सफलतापूर्वक जारी किया। यह 144/ए रेग एस फॉर्मेट में बैंक का दूसरा बॉन्ड रहा। निर्गम को 100 से ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक निवेशकों से 1.8 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का अभिदान मिला, जो निर्गम के आकार से 1.8 गुना ज्यादा रहा। शुरुआत में निर्गम को यूएस ट्रेजरी दर से 150 बेसिस पॉइंट ऊपर बेचा जाना तय हुआ था, किन्तु बाद में बैंक इस निर्गम को यूएस ट्रेजरी दर से 125 बेसिस पॉइंट ऊपर लाने में कामयाब रहा। फलस्वरूप बैंक ने 3.897% प्रतिफल की तुलना में 3.875% की कूपन दर पर बॉन्ड जारी किए। यह किसी भारतीय संस्था के लिए 10 साल के निर्गम के लिए यूएस ट्रेजरी दर पर अब तक का सबसे बेहतर स्प्रेड रहा।

शोध एवं विश्लेषण

कारोबारी संभावनाओं वाले उद्योगों, क्षेत्रों और देशों से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए एक्जिम बैंक में शोधकर्ताओं की एक अलग टीम है, जो बैंक और देश के लिए हितकारी विषयों का विश्लेषण करती रहती है। वर्ष के दौरान प्रकाशित कुछ प्रमुख शोध अध्ययनों में शामिल हैं: पर्यावरण अनुकूल

वस्तुओं में व्यापार: परिदृश्य; जावक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए भारतीय कंपनियों का अंतरराष्ट्रीयकरण: प्रकृति, निर्धारक कारक और विकासात्मक प्रभाव; तेल की कीमतों और पेट्रोलियम कूड व उत्पादों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार: भारतीय परिदृश्य; वित्तीयकरण और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की विनिमय दरों के निर्धारण पर इसका प्रभाव; आसियान-भारत सहयोग का सुदृढ़ीकरण: रुझान और भावी संभावनाएं; भारत-श्रीलंका व्यापार एवं निवेश संबंध: मौजूदा रुझान एवं संभावनाएं; लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में भारतीय निवेश: रुझान एवं संभावनाएं; प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार: भारतीय परिदृश्य।

अफ्रीकी विकास बैंक की हाई-फाइव रणनीति को ध्यान में रखते हुए एक्जिम बैंक ने 5 कार्यकारी आलेखों का एक संग्रह प्रकाशित किया है। पोषित अफ्रीका; अफ्रीका में जल स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा; एकीकृत अफ्रीका; अफ्रीका में विनिर्माण; और अफ्रीका में बिजली क्षेत्र पर केंद्रित इस संग्रह में भारत के लिए इन क्षेत्रों में अफ्रीका के साथ मिलकर काम करने के अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

बैंक ने अपने नॉलेज-बेस और भारत के विभिन्न राज्यों में व्याप्त निर्यात अवसरों की समझ का सदुपयोग करते हुए यूएनडीपी के साथ मिलकर पूर्वोत्तर आद्योगिक क्लस्टरो में के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की निर्यात क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम पर काम शुरू किया है। बैंक ने वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश से निर्यात: रुझान, अवसर तथा नीतिगत परिप्रेक्ष्य शीर्षक से भी एक शोध अध्ययन प्रकाशित किया है।

एक पॉलिसी बैंक की भूमिका में, बैंक जानकारियों का प्रसार करता रहा है और भारत सरकार द्वारा व्यापार तथा निवेश के संबंध में कोई भी जानकारी मांगे जाने पर उपलब्ध कराता रहा है। इसके साथ-साथ, बैंक के अधिकारी निर्यात ऋण पर गठित अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी समूह की बैठकों में भारत की वार्ता टीम का हिस्सा रहे हैं।

संस्थागत सहयोग

बैंक दूसरे विकासशील देशों में संस्था निर्माण को प्रोत्साहित करता रहा है। बैंक को विकासशील देशों में शुल्क आधारित परामर्श प्रदान करने संबंधी कार्य दायित्व मिलते रहे हैं। एक विकासशील देश के संदर्भ में नए उत्पाद और सेवाएं शुरू करने का बैंक का तीन दशकों से अधिक का अनुकरणिय

अनुभव, अन्य विकासशील देशों के लिए अपने एक्जिम बैंक और विकास वित्त संस्थाएं स्थापित करने और वित्तीय उत्पाद विकसित करने में महत्वपूर्ण रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में घाना निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम घाना) ने अपने विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग के लिए बैंक को नियुक्त किया।

बैंक ने दुनियाभर में अपनी सहभागी संस्थाओं के साथ परंपरागत संबंधों को और मजबूत किया है। बहुपक्षीय संस्थाओं और भारतीय कंपनियों को साझा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से, बैंक ने विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं में व्यवसाय अवसरों पर श्रृंखलाबद्ध सेमिनारों का आयोजन किया। इन सेमिनारों में भारत से आपूर्तिकर्ताओं, कॉन्ट्रैक्टरों और परामर्शदाताओं ने हिस्सा लिया और उनके लिए इन बहुपक्षीय संस्थाओं के अधिकारियों से सीधे चर्चा कर पाना संभव हो सका।

9वां ब्रिक्स सम्मेलन 2017 में चीन में हुआ। इस सम्मेलन के दौरान एक्जिम बैंक ने ब्रिक्स अंतर बैंक सहयोग तंत्र के अंतर्गत ब्रिक्स देशों के अन्य सदस्य विकास बैंकों के साथ दो बहुपक्षीय करार किए। ये करार थे- अंतर बैंक स्थानीय मुद्रा ऋण-व्यवस्था करार और क्रेडिट रेटिंग से संबंधित सहयोग ज्ञापन। अंतर बैंक स्थानीय मुद्रा ऋण-व्यवस्था करार ब्रिक्स सदस्य बैंकों के बीच राष्ट्रीय कानूनों, हस्ताक्षरकर्ता संस्थाओं के विनियमों और नीतियों के अनुसार द्विपक्षीय करारों को सुगम बनाएगा। वहीं, क्रेडिट रेटिंग से संबंधित सहयोग ज्ञापन के माध्यम से ब्रिक्स सदस्य विकास बैंकों के बीच आंतरिक रेटिंग साझा की जा सकेगी और यह ब्रिक्स देशों में सीमा पार ऋण प्रदान करते समय सुविचारित निर्णय लेने में एक उपयुक्त तंत्र की भूमिका निभाएगा।

बैंक ने जुलाई 2017 में जेनेवा में आयोजित निर्यात-आयात बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्सिड) की वार्षिक आम बैठक में भी हिस्सा लिया। इसके बाद नवंबर 2017 में ब्राजील में बीएनडीईएस (ब्राजीलियाई विकास बैंक) द्वारा एक एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बैंक ने नवंबर 2017 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एशियाई एक्जिम बैंक फोरम (ईबीएफ) की 23वीं वार्षिक बैठक में भी हिस्सा लिया, जिसकी मेजबानी ईएफआईसी द्वारा की गई। बैंक ने 1996 में ईबीएफ की स्थापना में

भी निर्णायक भूमिका निभाई थी। समय के साथ यह संस्था आर्थिक सहयोग और निर्यात ऋण एजेंसी के परिचालन के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्ट पद्धतियों को साझा करने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में विकसित हुई है।

बैंक एशिया प्रशांत में विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एडफिएप) का भी सदस्य है और बैंक ने फरवरी 2018 में नई दिल्ली में आयोजित बैठक की संयुक्त रूप से मेजबानी भी की थी। इस बैठक की थीम 'समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा - विकास वित्त संस्थाओं की भूमिका थी। इस अवसर पर बैंक के दो शोध अध्ययनों- व्यापार वित्त को बढ़ावा: विकास बैंकों और निर्यात ऋण एजेंसियों की अग्रणी भूमिका तथा लचीला व्यापार वित्त ढांचा: आलेखों का संकलन का विमोचन किया गया।

बैंक के निदेशक मंडल में सम्मानित और प्रतिष्ठित निदेशक हैं, जिन्होंने बैंक को अपने लक्ष्य हासिल करने में मार्गदर्शन किया है। बैंक के निदेशक मंडल में सुश्री रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री रमेश अभिषेक, सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री टी.एस. तिरुमूर्ति, सचिव, आर्थिक संबंध, विदेश मंत्रालय; डॉ. अरविन्द सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार; श्री पंकज जैन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय; डॉ. एम.डी. पात्रा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक; श्रीमती गीता मुरलीधर, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड; श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; श्री एम.के. जैन, प्रबंध निदेशक व सीईओ, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड; श्री राजीव ऋषि, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया; और श्री दीनबंधु महापात्र, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं।

बैंक के निदेशक मंडल में परिवर्तन भी हुए हैं। श्री एम.के. जैन, प्रबंध निदेशक व सीईओ, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड; श्री दीनबंधु महापात्र, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया; श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; श्री विजय केशव गोखले, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय; और श्री टी.एस. तिरुमूर्ति, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय को भी बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया था।

श्री अमर सिन्हा, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय; श्रीमती अरुन्धती भट्टाचार्य, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; श्री विजय केशव गोखले, सचिव, (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय; श्री किशोर खरात, प्रबंध निदेशक व सीईओ, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड; और श्रीमती उषा अनंतसुब्रह्मण्यन, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, पंजाब नेशनल बैंक ने अपना कार्यकाल पूरा कर लेने अथवा पदभार परिवर्तन के कारण अपने-अपने निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया है। निदेशकों के रूप में दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए बैंक उनका आभार मानता है।

चुनौतीपूर्ण कारोबारी परिवेश के बावजूद, बैंक ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने और भारतीय कंपनियों को उनके वैश्वीकरण के प्रयासों में सहयोग करने के अपने मिशन को पूरा करने की दिशा में पूरे उत्साह से कार्य करता रहा। बैंक, ऋण लेने वाले देशों में सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने के उद्देश्य के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित करते हुए सरकार के पॉलिसी बिजनेस के अनुपालन में सक्रिय रहा। मुझे पूरा भरोसा है कि बैंक, विदेशों में भारत के सद्भावना दूत की भूमिका निभाने के अतिरिक्त, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देते हुए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता रहेगा।



डेविड रस्कीना

प्रबंधन

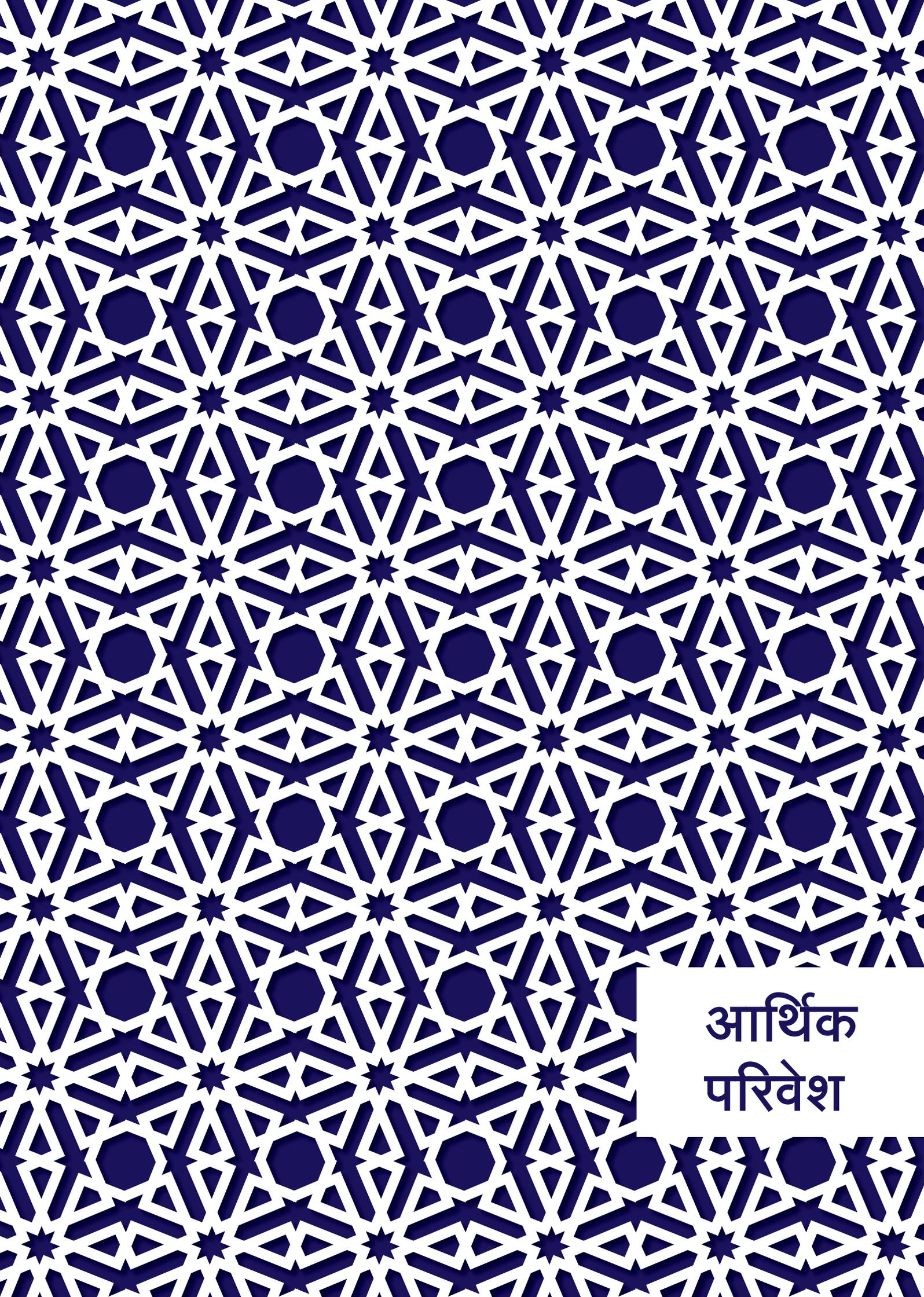


बैठे हुए, बाएं से दाएं -

सुदत्त मंडल, सैम्युअल जोसेफ, प्रहलादन अय्यर, हर्षा बंगारी, संगीता शर्मा, डेविड रस्कीना, देबाशिस मल्लिक,
रीमा मार्फतिया, सुनीता सिंदवानी, नदीम पंजेतन, डेविड सिनाटे, सी. पी. रवीन्द्रनाथ मेनन

खड़े हुए, बाएं से दाएं -

गौख भंडारी, विक्रमादित्य उगरा, धर्मेन्द्र सचान, श्रीराम सुब्रमनियम, मंजिरी भालेराव, दीपाली अग्रवाल, मीना वर्मा,
तरुण शर्मा, सुजीत भाले, टी.डी. सिवाकुमार, उत्पल गोखले, पी. जे. मंजुनाथ



आर्थिक
परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के मुताबिक, वर्ष 2017 में वैश्विक वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत रही, जो वर्ष 2016 में 3.2 प्रतिशत थी। यह 2011 के बाद सबसे अच्छी दर है। यह बढ़त विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निवेश में सुधार, उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में जारी मजबूत वृद्धि और यूरोप की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के चलते वैश्विक व्यापार में आए उछाल के कारण दर्ज की गई। वर्ष 2017 के दौरान कनाडा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, जर्मनी और अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि उल्लेखनीय रूप से उच्चतर रही। चीन, बांग्लादेश, भारत और आसियान-4 (मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम) सहित उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी उत्पादन वृद्धि में बढ़त दर्ज की गई। वहीं, ब्राजील, अर्जेंटीना, रूस और नाइजीरिया जैसी अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दरें भी 2017 में सकारात्मक रही।

विश्व व्यापार

मात्रा के संदर्भ में, वर्ष 2017 में वैश्विक व्यापार में वृद्धि (माल और सेवाओं में वृद्धि) पिछले साल की तुलना में दोगुनी से अधिक रही और यह 4.9 प्रतिशत आकलित की गई, जो 2016 में 2.3 प्रतिशत थी। यह वृद्धि लगातार दो साल की गिरावट के बाद दर्ज की गई है। यह बढ़त विशेष रूप से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निवेशों के रफ्तार पकड़ने और एशिया में विनिर्माण उत्पादन बढ़ने के कारण देखी गई। गैर-ईंधन वस्तुओं की विश्व व्यापार कीमतें पिछले साल के मुकाबले 2017 में पांच गुना बढ़ीं और इनमें 6.8 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोत्तरी दर्ज की गई, जो 2016 में 1.5 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि थी। चीन से धातुओं की मांग बढ़ना, खाद्य पदार्थों के लिए सख्त आपूर्ति शर्तें और वैश्विक मांग में आया सामान्य उछाल इस बढ़ोत्तरी के प्रमुख कारण रहे। वहीं दूसरी तरफ, तेल उत्पादन को सीमित करने के लिए ओपेक+ करार में हुए विस्तार से तेल की वैश्विक कीमतें भी कई गुना बढ़ीं। 2017 में तेल की कीमतों में 23.3 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जो 2016 में 15.7 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि थी।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूँजी प्रवाह

2017 में उभरते बाजारों को निवल निजी निवेश आवक में पिछले साल के मुकाबले 50 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी

देखी गई। यह 2016 के 795 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2017 में 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गया। यह बढ़त अनुकूल वैश्विक वित्तीय स्थितियों और वैश्विक वृद्धि के साथ-साथ पोर्टफोलियो ऋण प्रवाह में आई तेजी के चलते रही।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं का चालू खाता शेष

2017 के लिए चालू खाता अधिशेष (सरप्लस) पिछले साल की तुलना में इस साल तुर्की और भारत में चालू खाता घाटा बढ़ने के चलते घटकर 172 बिलियन यूएस डॉलर रह गया, जो पिछले साल 197 बिलियन यूएस डॉलर था। अधिशेष में यह गिरावट लगातार दूसरे साल दर्ज की गई।

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के बाह्य ऋण

इन अर्थव्यवस्थाओं का बाह्य ऋण, 2016 के 55.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 2017 में 13.8 प्रतिशत बढ़कर 63.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गया। यह बढ़त मुख्य रूप से इन अर्थव्यवस्थाओं में सरकार और घरेलू ऋण बढ़ने के चलते दर्ज की गई।

भारतीय अर्थव्यवस्था

कॉर्पोरेट क्षेत्र में लगातार दबाव और भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ मंदा रहने के चलते वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निवेश में वृद्धि भी कुछ धीमी रही। तदनुसार, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक, भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 6.7 प्रतिशत रही, जो पिछले साल 7.1 प्रतिशत थी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह वृद्धि निर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसार सेवाओं जैसा उप-क्षेत्रों के रफ्तार पकड़ने तथा वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सेवाओं तथा लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में वृद्धि के कारण सतत रही।

कृषि

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कृषि क्षेत्र का वास्तविक सकल मूल्य योजन (जीवीए) पिछले वर्ष के 6.3 प्रतिशत की तुलना में 3.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। उच्च आधार प्रभाव के चलते खाद्यान्न उत्पादन में पिछले कृषि वर्ष के दौरान 9.4 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 1.6 प्रतिशत की धीमी वृद्धि हुई। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में जीडीपी में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का हिस्सा पिछले साल के 17.9 प्रतिशत से गिरकर 17.1 प्रतिशत रह गया।

उद्योग

औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5.5 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष 6.8 प्रतिशत थी। वृद्धि दर में यह कमी खनन और उत्खनन गतिविधियों में आई गिरावट तथा विनिर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में मंदी को दर्शाती है। हालांकि निर्माण क्षेत्र ने रफ्तार पकड़ी, जिसमें पिछले साल की 1.3 प्रतिशत के मुकाबले 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। औद्योगिक क्षेत्र के समग्र योगदान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह 29.1 प्रतिशत रहा, जबकि पिछले साल यह 29.3 प्रतिशत था। इसी प्रकार खनन और विद्युत क्षेत्र में मंदी के चलते औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में भी गिरावट आई और वित्तीय वर्ष 2016-17 की 4.6 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में 23 उद्योग समूहों में से 11 में पिछले वर्ष के मुकाबले ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। तंबाकू उत्पादों और इलेक्ट्रिकल उपकरणों के उत्पादन में इस अवधि के दौरान सबसे बड़ी गिरावट आई।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के उपयोक्ता आधारित वर्गीकरण के अनुसार, प्राथमिक वस्तुओं, सहायक सामग्री और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में वृद्धि दर क्रमशः 3.7 प्रतिशत, 2.2 प्रतिशत और 0.6 प्रतिशत के साथ थोड़ी धीमी रही। वहीं दूसरी तरफ, पूँजीगत वस्तुओं और इंफ्रास्ट्रक्चर/ निर्माण वस्तुओं में क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान क्रमशः 3.2 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत थी।

सेवाएं

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सेवा क्षेत्र ने कुछ रफ्तार पकड़ी। इस क्षेत्र में पिछले साल की 7.5 प्रतिशत की तुलना में इस साल 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह सुधार मुख्यतः होटल, परिवहन, संचार और प्रसार सेवाओं में वृद्धि के कारण रहा, जिनमें पिछले साल की 7.2 प्रतिशत के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 8.0 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सेवाओं में इसी अवधि के दौरान 6.0 प्रतिशत की तुलना में 6.6 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं में हालांकि पिछले साल के मुकाबले कुछ गिरावट

आई, लेकिन उच्च वृद्धि दर बरकरार रही। इन क्षेत्रों में वृद्धि दर 10.0 प्रतिशत रही, जो पिछले साल 10.7 प्रतिशत थी। जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में बढ़कर 53.8 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष 52.8 प्रतिशत था।

बुनियादी ढांचा (इन्फ्रास्ट्रक्चर)

कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत बुनियादी ढांचा उद्योग के प्रमुख आठ उद्योग हैं। आईआईपी में इन आठ उद्योगों का लगभग 40.3 प्रतिशत भार है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इन आठ उद्योगों में वृद्धि पिछले वर्ष की 4.8 प्रतिशत से गिरकर 4.3 प्रतिशत रह गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्टील उद्योग में वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले काफी धीमी रही। यह वित्तीय वर्ष 2016-17 के 10.7 प्रतिशत से गिरकर 5.6 प्रतिशत रह गई। इसके बाद रिफाइनरी उत्पादों में भी वृद्धि दर 4.9 प्रतिशत से गिरकर 4.6 प्रतिशत रह गई। वहीं, विद्युत क्षेत्र में वृद्धि पिछले साल की 5.8 प्रतिशत से गिरकर 5.3 प्रतिशत रही। प्राकृतिक गैस और सीमेंट में पिछले वर्ष की क्रमशः 1.0 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्रमशः 2.9 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। कच्चे तेल के क्षेत्र में इस अवधि के दौरान 0.9 प्रतिशत की गिरावट आई, वहीं उर्वरक क्षेत्र अपरिवर्तनशील बना रहा।

मुद्रास्फीति

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की 4.5 प्रतिशत के मुकाबले गिरकर वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 3.6 प्रतिशत रही। यह गिरावट, वर्ष के दौरान मानसून अच्छा रहने से खाद्य कीमतों में गिरावट होने के कारण रही। वहीं कोर सीपीआई मुद्रास्फीति यथावत बनी रही, जिसमें खाद्य और ईंधन समूह शामिल नहीं है। धोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2016-17 की 1.7 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में बढ़कर 2.9 प्रतिशत हो गई। यह बढ़ोत्तरी वस्तुओं और ऊर्जा की वैश्विक कीमतों में हुई वृद्धि के कारण हुई।

पूँजी बाजार

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत का निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पिछले साल के 35.6 बिलियन यूएस डॉलर के मुकाबले 31.1 बिलियन यूएस डॉलर रहा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत के निवल पोर्टफोलियो निवेश में पिछले साल के 7.6 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में अच्छी बढ़ोत्तरी हुई और यह 22.1 बिलियन यूएस डॉलर रहा।

विदेश व्यापार और भुगतान संतुलन

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत का वस्तु निर्यात 303.3 बिलियन यूएस डॉलर का रहा और इसमें पिछले साल के मुकाबले 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मुख्य रूप से गैर-तेल निर्यातों में, लगातार दूसरे साल वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के आयात में भी पिछले साल के मुकाबले 20.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 464.7 बिलियन यूएस डॉलर का रहा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 18.5 प्रतिशत बढ़कर 37.4 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। उधर, गैर-तेल निर्यातों में इसी अवधि के दौरान 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कृषि और संबंधित क्षेत्रों के उत्पादों, समुद्री उत्पाद, रसायन और संबंधित उत्पाद, बेस मेटल, मशीनरी और पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादों के निर्यातों में भी वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पेट्रोलियम और इसके उत्पादों (मुख्य रूप से कच्चे तेल) का आयात 108.6 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 24.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान गैर-तेल आयात 356.1 बिलियन यूएस डॉलर का

रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 19.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रत्न एवं आभूषणों, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, रसायनों और संबंधित उत्पादों, मशीनरी तथा अयस्क और खनिज प्रमुख मर्चे रहे, जिनके आयातों में गैर-तेल श्रेणी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

कुल मिलाकर, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत का व्यापार घाटा पिछले वर्ष के 108 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में बढ़कर 161.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत से सेवाओं का निर्यात 195.1 बिलियन यूएस डॉलर रहा जिसमें पिछले वर्ष के 163.1 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में 19.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वित्तीय वर्ष 2017-18 में सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात पिछले वर्ष के 73.7 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में बढ़कर 77.3 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। इसी अवधि के दौरान पूँजी और वित्तीय लेखा के अंतर्गत निवल आवक 14.8 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 47.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गई।

मार्च 2018 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले वर्ष के 370 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 424.4 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुँच गया। वहीं, बाह्य ऋण भी बढ़ा जो मार्च 2017 के 471.3 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर मार्च 2018 के अंत में 529.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमुख नीतिगत परिवर्तन

मौद्रिक नीति

- रेपो रेट यथा मार्च 2017 के 6.25 प्रतिशत से घटाकर यथा मार्च 2018 को 6.00 प्रतिशत कर दी गई। वहीं, रिवर्स रेपो रेट यथा मार्च 2018 को 5.75 प्रतिशत रही। सीमांत स्थायी सुविधा दर (मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट) और बैंक दर दोनों को घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया गया।
- सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) को भी चरणबद्ध तरीके से घटाते हुए 20.50 प्रतिशत से कम कर यथा 31 मार्च 2018 को 19.50 प्रतिशत कर दिया गया।

व्यापार नीति

- संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अंतर्गत, दिसंबर 2017 की मध्यावधि समीक्षा के बाद टेक्सटाइल के दो सब-सेक्टरों- रेडीमेड गारमेंट और मेड-अप्स के लिए भारत से वस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) इन्सेंटिव 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया। एमएसएमई/श्रम गहन उद्योगों द्वारा निर्यातों के लिए मौजूदा एमईआईएस इन्सेंटिव भी 2% बढ़ा दिया गया। इन उद्योगों में अन्य के साथ-साथ चमड़ा, कृषि, हैंड टूल, समुद्री उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम पुर्जे जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- सेवाओं के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवसाय, विधि, अकाउंटिंग, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, शिक्षा, अस्पताल, होटल और रेस्टोरेंट जैसी अधिसूचित सेवाओं के लिए भारत से सेवा निर्यात (एसईआईएस) इन्सेंटिव 2% बढ़ाया गया।
- ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की वैधता अवधि 18 माह से बढ़ाकर 24 माह कर दी गई, ताकि जीएसटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत उनकी उपयोगिता को बढ़ाया जा सके। स्क्रिप के हस्तांतरण/बिक्री के लिए जीएसटी दर 12% से घटाकर शून्य कर दी गई है।
- निर्यातों के लिए आवश्यक सामग्री की शुल्क मुक्त (ड्यूटी फ्री) खरीद के लिए स्व-मूल्यांकन आधारित एक नई

स्कीम शुरू की गई। इस तरह के मामलों में स्टैंडर्ड इनपुट-आउटपुट मानदंडों की जरूरत नहीं होगी और इससे सामग्री की खरीद में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा। यह विश्वास पर आधारित है। निर्यातक शुल्क मुक्त कच्चे माल / सामग्री की जरूरत को स्वयं प्रमाणित करेंगे। यह योजना शुरुआत में प्राधिकृत आर्थिक संचालकों (ईओ) के लिए उपलब्ध होगी। ईओ कार्यक्रम के जरिए अधिक संख्या में निर्यातक जुड़ने से इस योजना का विस्तार होगा। इस योजना से व्यापार सुगमता में सुधार आएगा।

- निर्यातकों और आयातकों की विदेश व्यापार से जुड़ी समस्त दिक्कतों और उन्हें सुझाव देने के लिए सिंगल विंडो कॉन्टैक्ट पॉइंट के रूप में डीजीएफटी की वेबसाइट (www.dgft.gov.in) पर contact@DGFT सेवा लॉन्च की गई। निर्यातकों/आयातकों के प्रश्नों के लिए एक संदर्भ संख्या प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी क्रेरी का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इस पर फीडबैक व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है।
- नीतिगत बदलावों, मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार, निर्यात में आने वाली दिक्कतों और खामियों को चिह्नित करते हुए इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास और समन्वय के लिए वाणिज्य विभाग में नया लॉजिस्टिक्स प्रभाग बनाया गया। इन उपायों से लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग सुधरेगी और निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा
- निर्यातकों और आयातकों के लिए सीमा पार व्यापार सुगमता में सुधार लाने के लिए एक प्रोफेशनल टीम बनाई गई। यह टीम निर्यातकों को उनकी निर्यात संबंधी समस्याओं के समाधान, हैंडहोल्डिंग तथा निर्यात बाजारों तक पहुंच बनाने तथा नियामकीय अपेक्षाएं पूरी करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई।
- पूँजीगत वस्तुओं की एक नकारात्मक सूची अधिसूचित की गई है। इसमें वे वस्तुएं शामिल की गई हैं, जिन्हें ईपीसीजी (पूँजीगत माल के लिए निर्यात संवर्धन) की अनुमति नहीं है।

- निर्यात उन्मुख इकाइयों से रियायती और पूर्ण शुल्क पर देशी टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) बिक्री की अवधारणा को खत्म कर दिया गया है। इसलिए डीटीए बिक्री पर मान्य सीमा को भी खत्म कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, मोटर कारों, एल्कोहलिक मदिरा, किताबों और चाय की डीटीए बिक्री पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया गया है।
- मरम्मत / नवीकरण / रद्दोबदल अथवा रि-इंजीनियरिंग के उद्देश्य से आयात किए जाने वाले सेकेंड हैंड माल के आयात से प्रतिबंध हटा दिया गया है, फलस्वरूप रिपेयर सेक्टर में रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।
- सामग्री पर जीएसटी के अपफ्रंट भुगतान के चलते निर्यातकों की कार्यशील पूँजी अटकने की समस्या का भी समाधान कर दिया गया है। पूँजीगत निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना के अंतर्गत अग्रिम प्राधिकार के जरिए पूर्ण रूप से निर्यात उन्मुख इकाइयों, निर्यातकों को विदेश अथवा घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से जीएसटी के अपफ्रंट भुगतान के बिना सामग्री/पूँजीगत वस्तुएं मंगवाने की छूट दी गई है।
- चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई। पैकेज में वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक तीन वर्षों के दौरान ₹ 26 बिलियन के अनुमोदित व्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना 'भारतीय फुटवियर, चमड़ा एवं सहायक सामग्री विकास कार्यक्रम' का कार्यान्वयन शामिल है। इस योजना से चमड़ा क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, चमड़ा क्षेत्र से संबंधित पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान, अतिरिक्त निवेश की सुविधा, रोजगार सृजन और उत्पादन में वृद्धि होगी। इस विशेष पैकेज से 3 साल में 0.324 मिलियन नए रोजगार पैदा होने की संभावना है और फुटवियर, चमड़ा एवं सहायक सामग्री क्षेत्र में 0.20 मिलियन रोजगारों के सृजन में भी मदद मिलेगी।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पुर्जे, फुटवियर और फर्नीचर जैसे कुछ ऐसे क्षेत्रों के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, जिनमें देशी वेल्यू एडिशन की संभावना है। इससे देशी

वेल्यू एडिशन (मेक इन इंडिया) को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार वेल्यू एडेड निर्यातों को भी बढ़ावा मिलेगा।

निवेश नीति

- अगस्त 2017 की एफडीआई नीति के अनुसार, कुल एफडीआई आवक का 90% से अधिक अब ऑटोमैटिक रूट के जरिए है।
- विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) द्वारा एफडीआई आवेदनों की ई-फाइलिंग और ऑनलाइन निपटान की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। एफडीआई व्यवस्था में सबसे उल्लेखनीय संशोधन आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 5 जून, 2017 की अधिसूचना के जरिए किया गया संस्थागत परिवर्तन है। इस अधिसूचना के माध्यम से एफआईपीबी को समाप्त करने की पुष्टि की गई (इस पूर्ववर्ती सरकारी निकाय द्वारा ऐसे एफडीआई प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाता था, जिनके लिए सरकारी अनुमोदन अपेक्षित था)। साथ ही इस अधिसूचना के जरिए विदेशी निवेश सुविधा सेवा पोर्टल (एफआईएफपी) शुरू किया गया, जो एफडीआई आवेदनों को सुगम बनाने के लिए प्रशासनिक निकाय है।
- ई-कॉमर्स: बी2बी ई-कॉमर्स, बी2सी ई-कॉमर्स के लिए अनुमत एकल ब्रांड खुदरा व्यापार संस्था और ई-कॉमर्स खाद्य खुदरा व्यापार में 100 प्रतिशत एफडीआई।
- खुदरा: ऑटोमैटिक रूट के जरिए 100 प्रतिशत और 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। नवीनतम और आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए सरकार के अनुमोदन से खरीद नियमों में ढील दी जा सकती है। ई-कॉमर्स के जरिए किए जाने वाले व्यापार और भारत में निर्मित अथवा उत्पादित खाद्य उत्पादों सहित खुदरा व्यापार के लिए सरकारी अनुमोदन रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में एफडीआई के लिए लागू खरीद नियमों में ढील दी गई है और ये व्यापार शुरू करने के शुरुआती तीन साल तक लागू नहीं होंगे।
- नागरिक उड्डयन: ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं के लिए ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

वैश्विक उत्पादन, व्यापार एवं विश्व व्यापार मूल्य

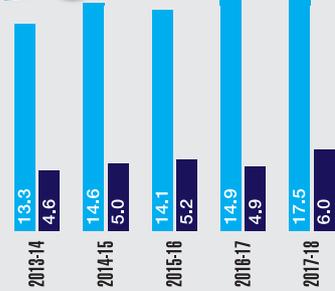
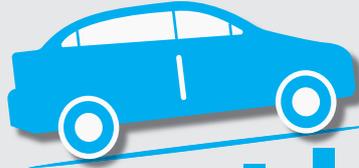
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (अ)	2019 (अ)
I. वैश्विक विकास दर (वास्तविक जी डी पी, % परिवर्तन)	4.3	3.5	3.5	3.6	3.5	3.2	3.8	3.9	3.9
(क) विकसित अर्थव्यवस्थाएं	1.7	1.2	1.3	2.1	2.3	1.7	2.3	2.5	2.2
अमेरिका	1.6	2.2	1.7	2.6	2.9	1.5	2.3	2.9	2.7
कनाडा	3.1	1.7	2.5	2.6	0.9	1.4	3.0	2.1	2.0
यूरो क्षेत्र	1.6	-0.9	-0.2	1.3	2.0	1.8	2.3	2.4	2.0
यूके	1.5	1.3	1.9	3.1	2.2	1.9	1.8	1.6	1.5
जापान	-0.1	1.5	2.0	0.3	1.1	0.9	1.7	1.2	0.9
(ख) उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	6.4	5.4	5.1	4.7	4.3	4.4	4.8	4.9	5.1
उभरता एवं विकासशील एशिया	7.9	7.0	6.9	6.8	6.8	6.5	6.5	6.5	6.6
चीन	9.5	7.9	7.8	7.3	6.9	6.7	6.9	6.6	6.4
भारत	6.6	5.5	6.4	7.4	8.2	7.1	6.7	7.4	7.8
लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्र	4.7	3.0	2.9	1.2	0.1	-0.6	1.3	2.0	2.8
मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका	4.6	5.3	2.5	2.6	2.6	4.9	2.6	3.4	3.7
उपसहारीय अफ्रीका	5.0	4.3	5.3	5.1	3.4	1.4	2.8	3.4	3.7
सीआईएस देश	5.3	3.6	2.5	1.1	-2.2	0.4	2.1	2.2	2.1
रूस	5.1	3.7	1.8	0.7	-2.8	-0.2	1.5	1.7	1.5
उभरता और विकासशील यूरोप	6.5	2.4	4.9	3.9	4.7	3.2	5.8	4.3	3.7
II. वस्तुओं का विश्व व्यापार (मात्रात्मक वृद्धि %)	7.0	2.3	3.3	3.1	2.2	2.2	5.4	5.3	4.8
वस्तुओं का वैश्विक निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर में)	17,931	18,135	18,549	18,635	16,223	15,757	17,422	19,474	20,515
III. विश्व व्यापार मूल्य (यूएस डॉलर, % परिवर्तन)									
विनिर्माण	4.2	2.8	-3.0	-0.4	-2.3	-5.2	1.4	1.9	1.3
तेल	31.6	1.0	-0.9	-7.5	-47.2	-15.7	23.3	18.0	-6.5
गैर ईंधन प्राथमिक पण्य	18.0	-10.1	-1.4	-3.9	-17.5	-1.5	6.8	5.6	0.5

नोट: अ=अनुमान

स्रोत: आई एम एफ, विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यू ई ओ) अप्रैल 2018

चुनिंदा क्षेत्रों का प्रदर्शन

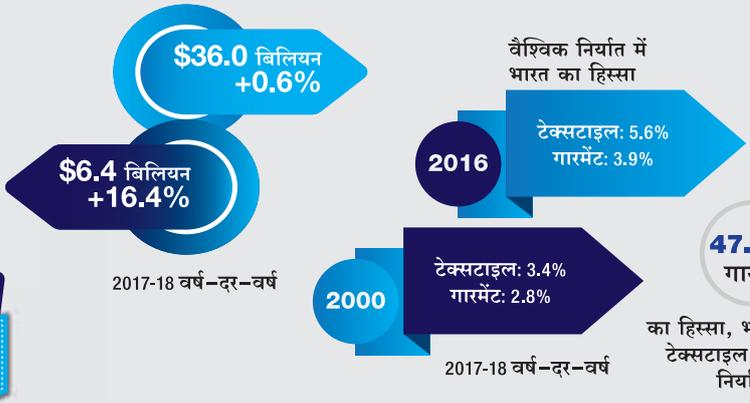
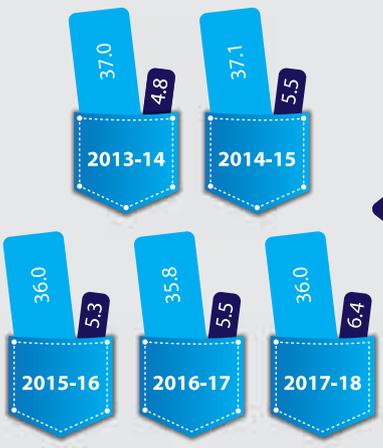
ऑटोमोटिव उत्पाद



2017-18 वर्ष-दर-वर्ष

भारत के जीडीपी का **7.1%**

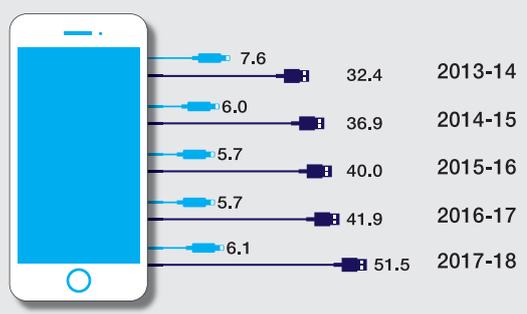
टेक्सटाइल और गारमेंट



- भारत सबसे बड़ा कपास और जूट उत्पादक
- दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल और गारमेंट निर्यातक
- दूसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल विनिर्माण क्षमता

47.7% गारमेंट का हिस्सा, भारत के कुल टेक्सटाइल और गारमेंट निर्यात में

इलेक्ट्रॉनिक्स



2020 तक भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार \$400 बिलियन का होने की उम्मीद

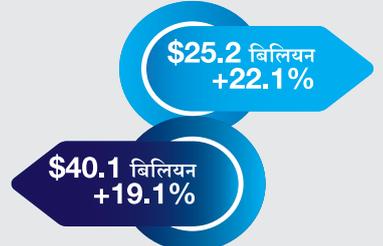
भारत का 60.2% इलेक्ट्रॉनिक माल चीन से आयात

पूँजीगत माल



4.4%

की बढ़त 2017-18 के दौरान, पूँजीगत माल के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में



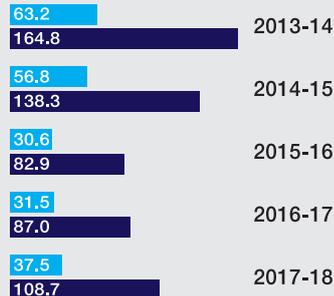
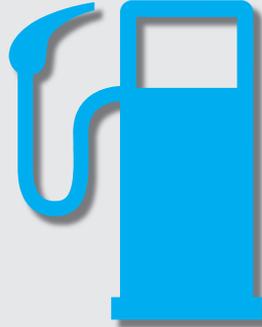
चुनिंदा क्षेत्रों का प्रदर्शन

पेट्रोलियम (कच्चा तेल और उत्पाद)

\$37.5 बिलियन
+18.7%

\$108.7 बिलियन
+24.9%

2017-18 वर्ष-दर-वर्ष



635
मिलियन मीट्रिक टन का तेल भंडार

54
ट्रिलियन क्यूबिक फीट का प्राकृतिक गैस भंडार

96
ट्रिलियन क्यूबिक फीट का अनुमानित शेल गैस भंडार



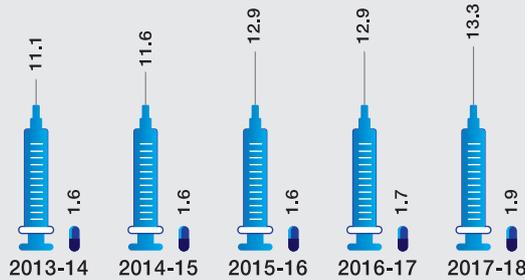
तेल एवं गैस क्षेत्र में आयात (लगभग)

15% - रिफाइनरी
67% - अपस्ट्रीम खंड

फार्मास्यूटिकल उत्पाद



12 वैश्विक निर्यात में 1.8% हिस्से के साथ, 2017 में भारत 12वां सबसे बड़ा निर्यातक रहा



\$13.3 बिलियन
+2.5%

\$1.9 बिलियन
+10.5%

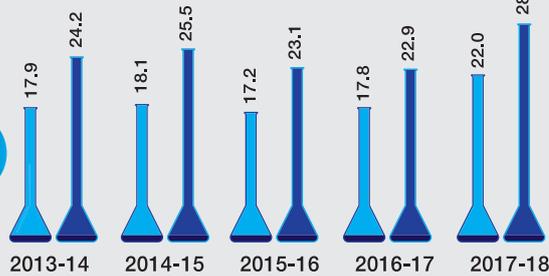
2017-18 वर्ष-दर-वर्ष

रसायन और संबंधित उत्पाद

\$22.0 बिलियन
+24.0%

\$28.6 बिलियन
+24.9%

2017-18 वर्ष-दर-वर्ष



3

रसायनों का एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक

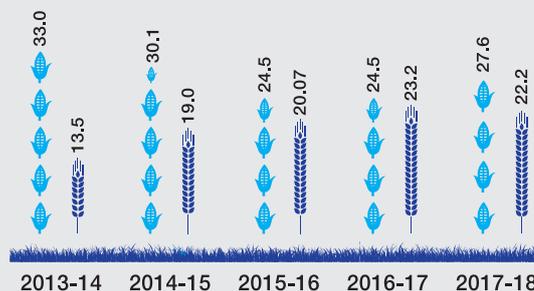
विश्व में सातवां सबसे बड़ा उत्पादक

7



रसायनों और संबंधित उत्पादों के भारत के कुल निर्यात का **67.3%** कार्बनिक रसायन

कृषि और संबंधित उत्पाद



\$27.6 बिलियन
+12.4%

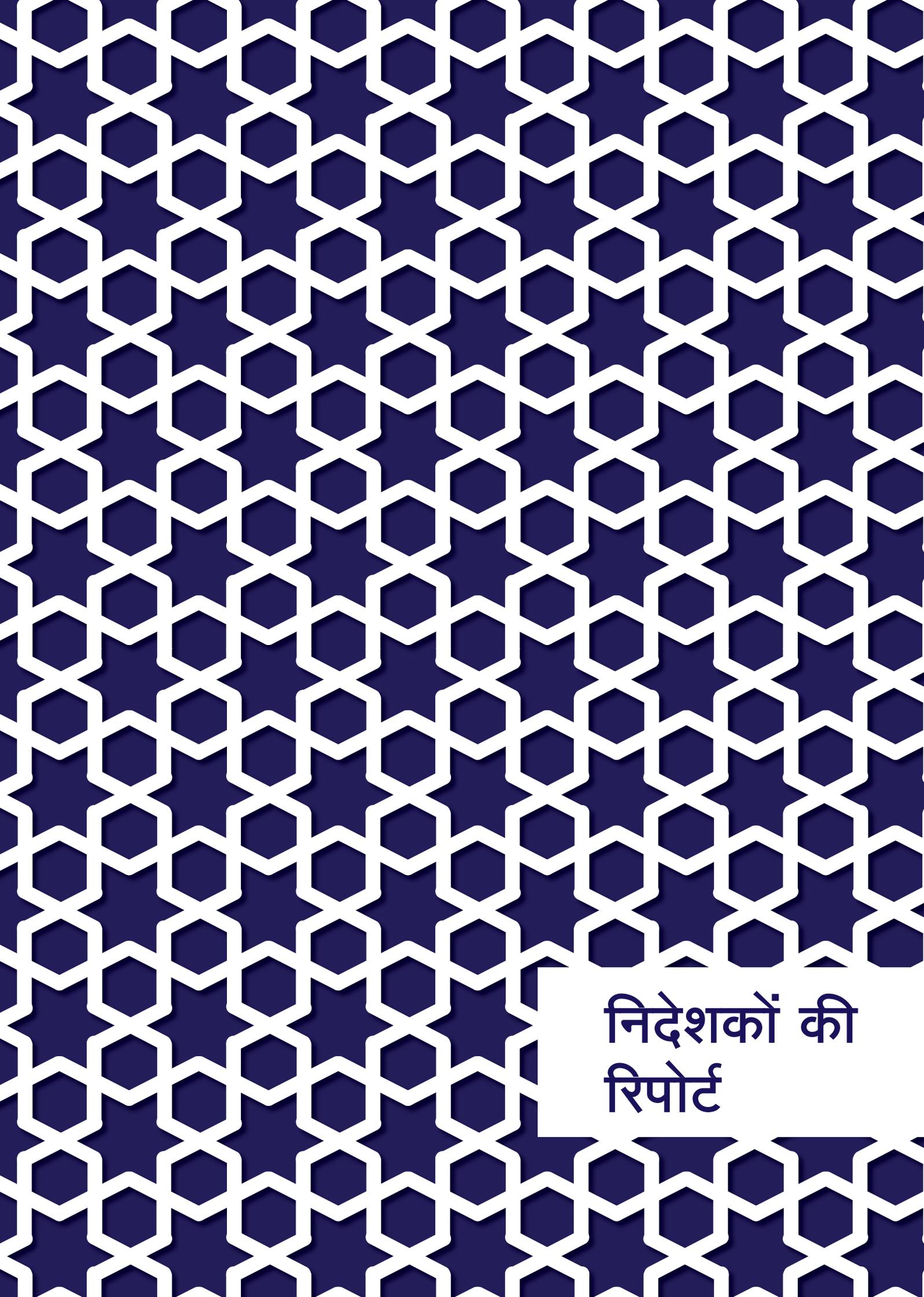
\$22.2 बिलियन
-4.3%

2017-18 वर्ष-दर-वर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था के संक्षिप्त आंकड़े

संकेतक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
जीडीपी (वर्तमान मूल्य पर, बिलियन यूएस डॉलर)	1708.5	1874.3	1863.6	1919.4	2043.3	2147.2	2271.0 ^o	2585.0 ^l
जीडीपी प्रति व्यक्ति (यूएस डॉलर)	1411.7	1502.7	1475.5	1501.2	1579.2	1640.3	1714.2	1929.0 ^l
वास्तविक जीडीपी वृद्धि (%)	8.9	6.7	5.5**	6.4**	7.5**	8.0**	7.1 ^{re**}	6.7 ^{re}
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	8.6	5.0	1.5**	5.6**	-0.2**	0.7**	4.9 ^{re**}	3.4 ^{re}
उद्योग	7.6	7.8	3.3**	3.8**	7.5**	8.8**	5.6 ^{re**}	5.5 ^{re}
सेवाएं	9.7	6.6	8.3**	7.7**	9.7**	9.7**	7.7 ^{re**}	7.9 ^{re}
जीडीपी में क्षेत्रीय हिस्सा (%)								
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	14.6	18.5**	18.3**	18.6**	18.0**	17.5**	17.4 ^{re**}	17.1 ^{re}
उद्योग	27.9	32.5**	31.7**	30.8**	30.2**	29.6**	28.8 ^{re**}	29.1 ^{re}
सेवाएं	57.5	49.0**	50.0**	50.6**	51.8**	52.9**	53.8 ^{re**}	53.8 ^{re}
जनसंख्या (मिलियन)	1210.2	1247.24	1263.1	1278.6	1293.9	1309.1	1324.8	1340.1 ^l
मुद्रास्फूर्ति दर (सीपीआई, वार्षिक औसत %)	10.4	8.3	10.1**	9.3**	5.8**	4.9**	4.5**	3.6**
मुद्रास्फूर्ति दर (डब्ल्यूपीआई, वार्षिक औसत %)	9.6	8.9	6.9**	5.2**	1.3**	-3.7**	1.7**	2.9**
सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	4.8	5.9	4.9	4.5	4.1	3.9	3.5 ^e	3.5 ^e
विनिमय दर (₹/यूएस डॉलर औसत)	45.6	47.9	54.4	60.5	61.1	65.5	67.1	64.4
विनिमय दर (₹/यूरो औसत)	60.2	65.9	70.1	81.2	77.5	72.3	73.6	72.1
निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	249.8	306.0	300.4	314.4	310.3	262.3	276.3	303.3
% परिवर्तन	39.8	22.5	-1.8	4.7	-1.3	-15.5	5.3	9.9 ^e
तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	36.4	56.7	60.9	63.2	56.7	30.6	31.7	37.4
% परिवर्तन	29.0	55.9	7.3	3.8	-10.2	-46.1	3.7	18.5 ^e
गैर-तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	213.4	249.2	239.5	251.2	253.6	231.7	244.6	265.4
% परिवर्तन	41.8	16.8	-3.9	4.9	0.9	-8.6	5.5	8.5 ^e
आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	369.8	489.3	490.7	450.2	448.0	381.0	384.3	464.7
% परिवर्तन	28.2	32.3	0.3	-8.3	-0.5	-15.0	0.9	20.9 ^e
तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	106.0	155.0	164.0	164.8	138.3	82.9	86.9	108.6
% परिवर्तन	21.6	46.2	5.9	0.4	-16.0	-40.0	4.8	24.9 ^e
गैर-तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	263.8	334.3	326.7	285.4	309.7	298.1	297.4	356.1
% परिवर्तन	31.1	26.7	-2.3	-12.6	8.5	-3.8	-0.2	19.7 ^e
व्यापार शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	-120.0	-183.3	-190.3	-135.8	-137.7	-118.7	-108.0	-161.4
सेवाओं का निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	124.6	140.9	145.7	151.8	158.1	154.3	163.1	195.1
सॉफ्टवेयर निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	53.1	62.2	65.9	69.4	73.1	74.2	73.7	77.3
सेवाओं का आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	80.6	76.9	80.8	78.7	81.6	84.6	95.7	117.5
सेवा शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	44.0	64.0	64.9	73.1	76.5	69.7	67.4	77.6
चालू खाता शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	-47.9	-78.2	-87.8	-32.4	-26.8	-22.1	-15.2	-48.7
चालू खाता शेष-जीडीपी का प्रतिशत (%)	-2.8	-4.2	-4.8	-1.7	-1.3	-1.1	-0.7	-1.9
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन यूएस डॉलर)	304.8	294.4	292.0	304.2	341.6	360.2	370.0	424.4
बाह्य ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	317.9	360.8	409.4	446.2	474.7	485.0	471.9	529.7
बाह्य ऋण-जीडीपी अनुपात (%) में	18.2	20.5	22.3	23.9	23.2	23.5	20.2	20.5
अल्पावधि ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	65.0	78.2	96.7	91.7	85.5	83.4	88.0	102.2
अल्पावधि ऋण/कुल ऋण (%)	20.4	21.7	23.6	20.5	18.0	17.2	18.6	19.3
कुल चुकोती अनुपात (%)	4.4	6.0	5.9	5.9	7.6	8.8	8.3	7.5
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (बिलियन यूएस डॉलर)	36.0	46.6	34.3	36.0	45.1	55.6	60.2	61.0
जीडीआर/एडीआर (बिलियन यूएस डॉलर)	2.0	0.6	0.2	0.02	1.3	0.4	-	-
एफआईआई (निवल) (बिलियन यूएस डॉलर)	29.4	16.8	27.6	5.0	40.9	-4.0	7.8	22.1
एफडीआई जावक (बिलियन यूएस डॉलर)	17.2	10.9	7.1	9.2	4.0	8.9	6.6	9.3
मेमो मर्दें:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ^l	2018 ^l
वैश्विक जीडीपी (% परिवर्तन)	4.3	3.5	3.5	3.6	3.4	3.2	3.7	3.9
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	1.7	1.2	1.3	2.1	2.2	1.7	2.3	2.5
उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	6.4	5.4	5.1	4.7	4.3	4.4	4.7	4.9
विश्व पण्य व्यापार (मात्रा % परिवर्तन)	7.0	2.3	3.3	3.1	2.3	2.3	4.3	5.3
विश्व पण्य निर्यात (ट्रिलियन यूएस डॉलर)	17.9	18.1	18.5	18.6	16.2	15.8	17.1	19.5
विश्व पण्य निर्यात के मूल्य में वृद्धि (%)	20.2	1.0	2.1	0.5	-12.9	-2.3	8.2	14.0

नोट: ^o-भारत सरकार के अनुमान, ^l-ईएससी, भारत सरकार के संशोधित अनुमान, ¹-आईआईएफ अनुमान - उपलब्ध नहीं, ^e-% परिवर्तन पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में है, ^{**}-आंकड़े संशोधित आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार।
 स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न अंक; केन्द्रीय बजट, भारतीय रिजर्व बैंक मासिक बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्ट एवं साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुसूचक; वित्त मंत्रालय; सी एस ओ; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईएमएफ) तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)।



निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा लेखों के साथ, बैंक द्वारा निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत की जाती है।

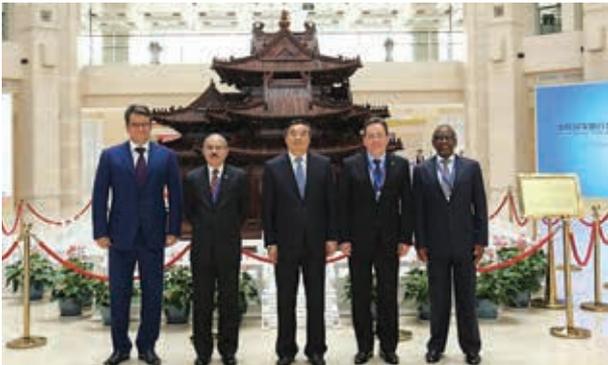
परिचालनों तथा वित्तीय निष्पादन की समीक्षा

ऋण आस्तियाँ

बैंक ने अपने विभिन्न ऋण कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की ₹ 647.78 बिलियन ऋण राशि के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 978.26 बिलियन की ऋण राशि मंजूर की। वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹ 446.94 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने ₹ 685.35 बिलियन के ऋण का संवितरण किया। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ऋण भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹ 371.14 बिलियन की तुलना में ₹ 598.35 बिलियन रहे। यथा 31 मार्च, 2018 को निवल ऋण-आस्तियाँ ₹ 1,075.32 बिलियन की रही, जिसमें गत वर्ष की तुलना में 4.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यथा 31 मार्च, 2018 को बैंक द्वारा दिए गए निवल ऋणों व अग्रिम में 28 प्रतिशत रुपया ऋण एवं शेष 72 प्रतिशत विदेशी मुद्रा ऋण था। यथा 31 मार्च, 2018 को अल्पावधि ऋण निवल ऋणों तथा अग्रिमों का 25 प्रतिशत था।

गैर-निधिक सुविधाएं

बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की ₹ 61.15 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 107.81 बिलियन की गैर-निधिक ऋण सुविधाएं मंजूर की गईं। इनमें परियोजना गारंटियां, वित्तीय गारंटियां तथा साख-पत्र शामिल थे। बैंक का कुल गैर-निधिक पोर्टफोलियो यथा 31 मार्च, 2017 के ₹ 122.31 बिलियन से 8.25 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2018 को ₹ 132.40 बिलियन रहा। इसमें गारंटियां, साख पत्र एवं आपाती साख-पत्र शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 की ₹ 45.13 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 53.80 बिलियन की गारंटियां जारी की गईं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹ 7.49 बिलियन की तुलना



बीजिंग, चीन में आयोजित ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग तंत्र की बैठक में सदस्य विकास बैंकों के प्रमुख।

में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 2.07 बिलियन के साख-पत्र जारी किए गए। बैंक की बहियों में कुल गारंटियां 31 मार्च, 2017 के ₹ 112.36 बिलियन की तुलना में यथा 31 मार्च, 2018 को ₹ 128.36 बिलियन रहीं तथा साख-पत्र यथा 31 मार्च, 2017 के ₹ 9.95 बिलियन की तुलना में यथा 31 मार्च, 2018 को ₹ 4.04 बिलियन रहे।

आय/व्यय

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सामान्य निधि लेखे में ₹ 42.30 बिलियन की कर पूर्व हानि दर्ज की है, जबकि वर्ष 2016-17 में ₹ 3.13 बिलियन का लाभ दर्ज किया गया था। आयकर के लिए ₹ 13.06 बिलियन का प्रावधान करने के बाद वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कर पश्चात हानि ₹ 29.24 बिलियन की रही जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में कर पश्चात लाभ ₹ 0.41 बिलियन था।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निर्यात विकास निधि का कर पूर्व लाभ ₹ 114.55 मिलियन रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह ₹ 101.67 मिलियन था। ₹ 39.64 मिलियन कर प्रावधान के बाद, वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹ 66.49 मिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में कर पश्चात लाभ ₹ 74.90 मिलियन रहा। ₹ 74.90 मिलियन की लाभ राशि अगले वर्ष के लिए अंतरित की गई है।

ऋणों पर ब्याज, विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और शुल्क आदि को मिलाकर कारोबारी आय वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹ 59.14 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 56.56 बिलियन रही। निवेशों पर आय तथा बैंक जमा राशियों आदि पर ब्याज वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹ 33.21 बिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 31.23 बिलियन रही। वित्तीय वर्ष 2017-18 में ब्याज व्यय ₹ 66.40 बिलियन रहा, जिसमें उधारियों के बढ़ने के कारण गत वर्ष की तुलना में ₹ 0.75 बिलियन की वृद्धि हुई। प्रशासनिक खर्च (आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान को छोड़कर) वित्तीय



कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा सेनेगल के विभिन्न क्षेत्रों में निष्पादित की जा रही 225 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए बैंक के क्रेता ऋण से वित्तपोषित परियोजना।



बांग्लादेश में 1320 मेगावाट के मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 1.60 बिलियन यूएस डॉलर के ऋण करार का आदान-प्रदान।

वर्ष 2016-17 के 2.56 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कुल व्यय का 2.75 प्रतिशत रहा।

उधारियां

यथा 31 मार्च, 2018 को कुल उधार राशियां ₹ 1,041.65 बिलियन की रहीं, जो यथा 31 मार्च, 2017 के ₹ 960.73 बिलियन की तुलना में 8.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं।

संसाधन

वर्ष के दौरान बैंक को भारत सरकार से ₹ 5 बिलियन की पूंजी प्राप्त हुई। यथा 31 मार्च, 2018 को ₹ 73.59 बिलियन की चुकता पूंजी तथा ₹ 22.41 बिलियन की आरक्षित निधियों सहित बैंक के कुल संसाधन ₹ 1,137.65 बिलियन रहे। एक्जिम बैंक के संसाधन आधार में रुपया बॉन्ड, जमा प्रमाण-पत्र, वाणिज्यिक पत्र, सावधि जमा राशियां, विदेशी मुद्रा बॉन्ड, विदेशी मुद्रा ऋण तथा दीर्घावधि स्वैप आदि शामिल हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न परिपक्वता अवधि (वर्ष के दौरान जुटाए गए तथा चुकता किए गए को छोड़कर) के कुल ₹ 399.15 बिलियन की उधारियां जुटाईं। इनमें ₹ 186.70 बिलियन के रुपया संसाधन तथा 3.26 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन थे। बॉन्ड, द्विपक्षीय/क्लब/सामूहिक ऋणों के जरिए 2.83 बिलियन यूएस डॉलर तथा खरीद-बिक्री स्वैपों के जरिए (वर्ष के दौरान जुटाए गए तथा चुकता किए गए को छोड़कर) 0.43 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य राशि के विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाए गए। यथा 31 मार्च, 2018 को बैंक के पास कुल 12.84 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन तथा बकाया रुपया संसाधन ₹ 482 बिलियन रहे। यथा 31 मार्च, 2018 को कुल बाजार उधारियां, कुल उधारियों की 100 प्रतिशत तथा बैंक के कुल संसाधनों की 92 प्रतिशत रहीं।

विदेशी मुद्रा संसाधन

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने 3.26 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य राशि के विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाए। बैंक



कोत दि'वार में चार सैन्य अस्पतालों के उन्नयन के लिए 71.40 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर।

ने अगस्त 2017 में 5 साल के लिए 400 मिलियन यूएस डॉलर का रेग एस फ्लोटिंग रेट फोरमोसा बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किया। यह भारत से बाहर अब तक का सबसे बड़ा फोरमोसा बॉन्ड और किसी भारतीय वित्तीय संस्था द्वारा पहला फोरमोसा ट्रंजैक्शन था। बैंक ने जनवरी 2018 में 1 बिलियन यू एस डॉलर का 10 वर्षीय बॉन्ड निर्गम सफलतापूर्वक जारी किया, जो 144 ए/ रेग एस बॉन्ड फॉर्मेट में बैंक का दूसरा बॉन्ड था। निर्गम को 100 से ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक निवेशकों से कुल 1.8 बिलियन यू एस डॉलर से अधिक का अभिदान मिला। बॉन्ड निर्गम को किसी भारतीय संस्था के लिए 10 साल के निर्गम के लिए यू एस ट्रेजरी दर पर अब तक का सबसे बेहतर स्प्रेड मिला। इस निर्गम ने अन्य भारतीय बॉन्ड जारीकर्ताओं के लिए 144 ए/ रेग एस बाजारों तक पहुंचने के लिए एक बेंचमार्क भी स्थापित किया है। बैंक ने अब तक विभिन्न विदेशी मुद्राओं जैसे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानी येन, मैक्सिकन पिसो, ऑफशोर रेनमिन्बी, सिंगापुर डॉलर, दक्षिण अफ्रीकी रैंड, स्विस फ्रैंक, टर्किश लीरा तथा यू एस डॉलर आदि में संसाधन जुटाए हैं।

अंतरराष्ट्रीय तथा देशी रेटिंग

बैंक को मूडीज ने बीएए2 (स्थिर) रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा बीबीबी- (स्थिर) तथा फिच द्वारा बीबीबी- (स्थिर) रेटिंग तथा जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जेसीआरए) द्वारा बीबीबी+ (स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई है। वर्ष के दौरान भारत सरकार की जारीकर्ता रेटिंग के उन्नयन के फलस्वरूप मूडीज ने रेटिंग बीएए3 से अपग्रेड कर बीएए2 कर दी है। उपरोक्त सभी रेटिंग निवेश ग्रेड या उससे ऊपर की रेटिंग हैं, जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य हैं। बैंक के देशी ऋण लिखतों को दीर्घावधि लिखतों (इंस्ट्रुमेंट्स) के लिए क्रिसिल, इक्रा तथा केयर जैसी रेटिंग एजेंसियों से उच्चतम रेटिंग अर्थात् 'एएए' तथा अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए क्रिसिल, इक्रा एवं केयर रेटिंग एजेंसियों से ए1+ रेटिंग प्रदान की गई है।

आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार उस ऋण/कर्ज को अनर्जक आस्ति (एन पी ए) के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके संबंध में देय ब्याज और/या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है। 31 मार्च, 2018 को बैंक की सकल अनर्जक आस्तियां ₹ 119.76 बिलियन रही हैं, जो बैंक के कुल ऋणों तथा अग्रिमों का 10.37 प्रतिशत है। यथा 31 मार्च, 2018 को बैंक की निवल अनर्जक आस्तियां ₹ 40.28 बिलियन (प्रावधान घटाकर) रहीं जो निवल ऋणों तथा अग्रिमों (प्रावधान घटाकर) का 3.75 प्रतिशत हैं। यथा 31 मार्च, 2018 को प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 71.26 प्रतिशत था।

आस्ति वर्गीकरण

'अनर्जक आस्तियां' वे आस्तियां होती हैं जिनके ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्तें 90 दिनों से अधिक अतिदेय होती हैं। जब ऐसी अवमानक आस्तियां 12 माह से अधिक अवधि तक अनर्जक आस्ति के रूप में बनी रहती हैं, तो उन्हें 'संदिग्ध आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 'हानि आस्तियां' वे होती हैं जो वसूली के योग्य नहीं समझी जातीं। यथा 31 मार्च, 2018 को सकल अनर्जक आस्तियों में से 24.96 प्रतिशत अवमानक आस्तियां तथा 75.04 प्रतिशत संदिग्ध आस्तियां रहीं। यथा 31 मार्च, 2018 को निवल अनर्जक आस्तियों में से अवमानक आस्तियां 56.59 प्रतिशत तथा संदिग्ध आस्तियां 43.41 प्रतिशत रहीं। यथा 31 मार्च, 2018 को बैंक की कोई हानि आस्तियां नहीं थीं।

पूँजी पर्याप्तता

जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत की तुलना में यथा 31 मार्च, 2018 को 10.35 प्रतिशत रहा। यथा 31 मार्च, 2017 को यह 15.81 प्रतिशत था। ऋण-इक्रिटी अनुपात यथा 31 मार्च, 2018 को 10.85 रहा, जबकि यथा 31 मार्च, 2017 को यह 7.99 था।



रवांडा में 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 81 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर।

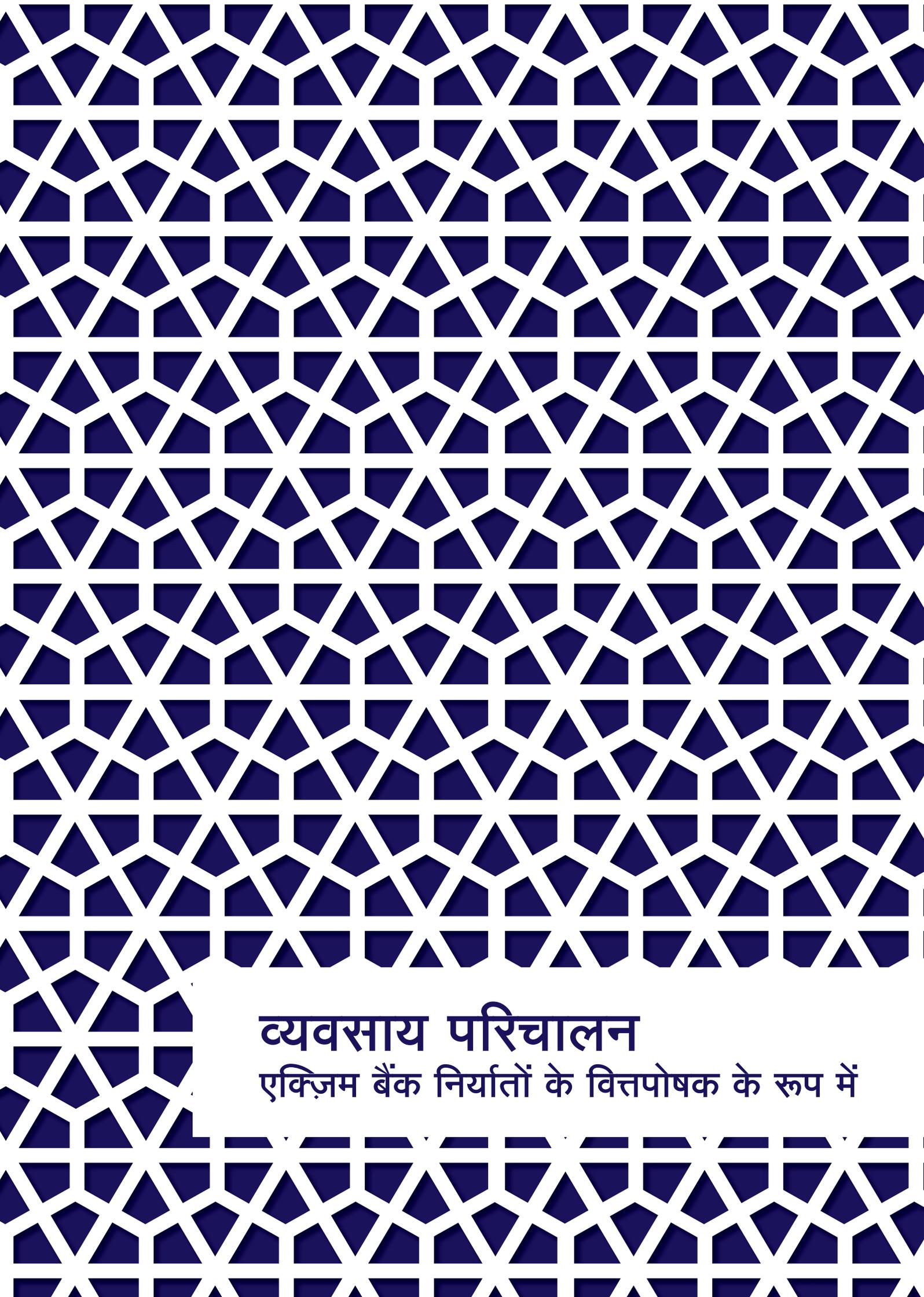
अधिकतम ऋण सीमा (एक्सपोजर) मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के लिए 31 मार्च, 2002 से एकल उधारकर्ता के लिए अधिकतम ऋण सीमा वित्तीय संस्था की पूँजी निधियों की 15 प्रतिशत और समूह उधारकर्ताओं के लिए 40 प्रतिशत की निर्धारित की है। बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विशेष मामलों में यह सीमा पाँच प्रतिशत तक और बढ़ाई जा सकती है अर्थात् एकल उधारकर्ता के लिए यह सीमा वित्तीय संस्था की कुल पूँजी निधियों की 20 प्रतिशत तक और उधारकर्ता समूहों के लिए 45 प्रतिशत तक हो सकती है। एकल उधारकर्ताओं और उधारकर्ता समूहों के लिए इस अधिकतम ऋण सीमा (क्रमशः 20 प्रतिशत और 45 प्रतिशत) को क्रमशः अतिरिक्त पांच प्रतिशत बिंदुओं (अर्थात् कुल पूँजी निधियों का 5 प्रतिशत) और दस प्रतिशत बिंदुओं (अर्थात् कुल पूँजी निधियों का 10 प्रतिशत) तक और बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि बढ़ाई गई सीमा भारत में बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए हो। यथा 31 मार्च, 2018 को एकल तथा समूह उधारकर्ताओं को बैंक की वित्तीय सहायता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर थी। यथा 31 मार्च, 2018 को 2 उधारकर्ताओं को एक्सपोजर पूँजी निधि के 15 प्रतिशत से अधिक था, जिसके लिए निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त किया गया था। यथा 31 मार्च, 2018 को इन उधारकर्ताओं को एक्सपोजर बैंक की पूँजी निधियों का क्रमशः 19.56 प्रतिशत तथा 16.91 प्रतिशत था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को यह भी सलाह दी है कि वे विशिष्ट उद्योग क्षेत्रों को ऋण सहायता के लिए अपनी आंतरिक सीमाएं निर्धारित करें ताकि विभिन्न क्षेत्रों को ऋण का समान रूप से फैलाव हो सके। बैंक द्वारा प्रत्येक उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम ऋण सीमा, सभी उद्योग क्षेत्रों को बैंक के ऋण एक्सपोजर की 15 प्रतिशत निर्धारित की गई है। यथा 31 मार्च, 2018 को किसी भी एकल उद्योग को बैंक का एक्सपोजर सभी उद्योग क्षेत्रों को बैंक के कुल एक्सपोजर के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं था।



मॉरिटानिया सरकार को राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत 110 मिलियन यूएस डॉलर के क्रेता ऋण करार पर हस्ताक्षर।



व्यवसाय परिचालन

एक्ज़िम बैंक निर्यातों के वित्तपोषक के रूप में

परियोजना, उत्पाद एवं सेवा निर्यात

बैंक विभिन्न प्रकार की निर्यात ऋण सुविधाएं जैसे परियोजना निर्यात तथा परामर्शी सेवाएं वित्त, पूँजी उपकरण वित्त, निर्यात परियोजना नकदी प्रवाह घाटा वित्तपोषण, गारंटियां तथा साख-पत्र आदि प्रदान करता है। बैंक भारतीय परियोजना निर्यातकों को निधिक सहायता तथा परियोजना संबंधी गारंटी सुविधाओं सहित व्यापक वित्तपोषण पैकेज प्रदान करता है।

निर्यात संविदाएं

वर्ष के दौरान एक्जिम बैंक द्वारा सहयोग प्राप्त कुछ प्रमुख परियोजना निर्यात संविदाओं में मॉरिटानिया और बांग्लादेश में कल्पतरु पॉवर ट्रांसमिशन लि. द्वारा और अफगानिस्तान में केईसी इंटरनेशनल लि. द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों के डिजाइन, आपूर्ति, असेम्बली, परीक्षण और कमीशनिंग; नाइजीरिया में पेट्रोलियम रिफाइनरी एवं पॉलीप्रोपलीन संयंत्र के लिए वीए टेक वाबाग लि. द्वारा दूषित जल शोधन और रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्र के डिजाइन, निर्माण और इंस्टॉलेशन तथा अर्जेंटीना में स्टर्लिंग एंड विल्सन प्रा. लि. द्वारा सौर ऊर्जा परियोजना संबंधी संविदाएं शामिल रहीं।

निर्यात ऋण एवं गारंटियां

वर्ष के दौरान बैंक ने आपूर्तिकर्ता ऋण, क्रेता ऋण तथा परियोजना निर्यातों के वित्त के अंतर्गत कुल ₹ 35.11 बिलियन की राशि मंजूर की। पिछले वर्ष ये मंजूरीयां ₹ 19.88 बिलियन की थीं। संवितरित राशि गत वर्ष के ₹ 20.09 बिलियन की तुलना में ₹ 24.91 बिलियन रही। वर्ष के दौरान जारी की गई गारंटियों की राशि गत वर्ष के ₹ 30.67 बिलियन की तुलना में ₹ 43.97 बिलियन रही। ये गारंटियां मुख्य रूप से बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन तथा वितरण, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सोलर ई पी सी, परामर्शी सेवाओं तथा जल शुद्धिकरण जैसे क्षेत्रों में विदेशी परियोजनाओं से संबंधित हैं।



बांग्लादेश सरकार को प्रदान की गई 862 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत दूसरी भैरब पुल परियोजना।



एक्जिम बैंक ने अरमाडा माडुरा ईपीसी लि. द्वारा निर्मित फ्लोटिंग, प्रोडक्शन, स्टोरेज और ऑफलोडिंग वेसल की खरीद के लिए पीटी अरमाडा गेमा नुसांतारा, इंडोनेशियां को 71 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेता ऋण सुविधा के जरिए सहयोग दिया।

क्रेता ऋण

क्रेता ऋण एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत बैंक भारतीय परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी क्रेताओं को भारत से उनके आयातों के वित्तपोषण के लिए ऋण देता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक द्वारा सात विदेशी कंपनियों को तेल तथा गैस, धातु, उर्वरक, जल, पवन तथा पीट आधारित बिजली, परिवहन वाहन, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, कृषि आधारित उत्पाद एवं वस्तुएं, स्टील तार तथा तार निर्मित रॉड आदि जैसे क्षेत्रों में कुल ₹ 80.49 बिलियन की क्रेता ऋण सुविधाएं प्रदान की गईं। क्रेता ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत इंडोनेशिया, थाइलैंड, यूएई, अमेरिका और अफ्रीका में 14 से अधिक देशों को निर्यात के लिए कुल ₹ 15.60 बिलियन यूएस डॉलर का संवितरण किया गया। वर्ष के दौरान एक्जिम बैंक ने भारत से माल एवं सेवाओं के निर्यात को सुगम बनाने के लिए अफ्रीकन एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक को 125 मिलियन यू एस डॉलर तथा इस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीकन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक को 75 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था भी प्रदान की। एक्जिम बैंक ने भारत से माल एवं सेवाओं के आयात हेतु सहायता प्रदान करने के लिए इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक (आईएडीबी) के व्यापार वित्त सुगमीकरण कार्यक्रम में भी प्रतिभागिता की।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण

बैंक भारत से परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहा है। भारत सरकार के 'राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते' के अंतर्गत क्रेता ऋण (बीसी-एनईआईई) नामक उत्पाद के प्रारम्भ से भारतीय परियोजना निर्यातों को सहायता प्रदान करने में बैंक के इन प्रयासों को बल मिला है। बैंक द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत यथा 31 मार्च, 2018 तक 3.04 बिलियन यूएस डॉलर की 24 परियोजनाओं को 2.83 बिलियन यूएस डॉलर की राशि मंजूर की गई, जिनमें श्रीलंका में एक जल शोधन संयंत्र की स्थापना तथा रिजर्वायर तक जल वितरण परियोजना; बैरा पोर्ट, मोजाम्बिक में एकीकृत एलपीजी स्टोरेज सुविधा की स्थापना; कोत दि'वार, सेनेगल,

तंजानिया और जिम्बाब्वे को वाहनों एवं पुर्जों की आपूर्ति; कैमरून, इथियोपिया, मॉरिटानिया, सेनेगल तथा जाम्बिया में ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाएं; घाना में रेलवे लाइन परियोजना; मालदीव तथा जाम्बिया में सड़क परियोजनाएं तथा सूरीनाम में सिंचाई परियोजना शामिल हैं। बैंक ने बीसी- एनईआईए कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रमुख भारतीय परियोजना निर्यातकों की ओर से 10.09 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 70 परियोजनाओं को कुल 8.65 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता प्रदान करने के लिए सिद्धांततः सहमति दी है।

ऋण-व्यवस्थाएं

एक्जिम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को भारत सरकार की ओर से ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है ताकि इन देशों के क्रेता आस्थगित भुगतान शर्तों पर भारत से विकासपरक तथा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए उपकरणों, माल तथा सेवाओं का आयात कर सकें। वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत से परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात को सहयोग के लिए कुल 6.11 बिलियन यू एस डॉलर की 12 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कीं। एक्जिम बैंक द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान की गई ऋण-व्यवस्थाओं में इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट तथा बांग्लादेश, कंबोडिया, कोत दि'वार, गयाना, मेडागास्कर, मॉरिशस, रवांडा, श्रीलंका तथा जाम्बिया की सरकारों को दी गई ऋण-व्यवस्थाएं शामिल हैं। ये ऋण-व्यवस्थाएं सैन्य अस्पतालों के उन्नयन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्री-फैब्रिकेटेड हेल्थ पोस्ट, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, बिजनेस इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना, जल संसाधनों के विकास, रेलवे के लिए रोलिंग स्टॉक की खरीद, रेलवे ट्रैकों के उन्नयन तथा विभिन्न विकासात्मक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के जरिए निर्यातों को बढ़ावा देंगी। एक्जिम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से 62 देशों को कुल



मेटल इंजेक्शन मोल्डेड पुर्जों की निर्माता इंडो-एमआईएम प्राइवेट लिमिटेड (आईएमपीएल), बंगलूरु को इसकी पूर्ण समनुषंगी कंपनी इंडो-एमआईएम इंक, डेलावेअर, यूएसए में इक्विटी निवेश के लिए विदेशी निवेश वित्त।



नीजर सरकार को नीजर में अर्ध-शहरी और ग्रामीण समुदायों के लिए पेयजल हेतु 25 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था।

21.87 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण-प्रतिबद्धताओं के साथ भारत सरकार की 226 ऋण-व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिनके अंतर्गत परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

रियायती वित्तपोषण योजना

एक्जिम बैंक ने बांग्लादेश के रामपाल, जिला-बागरहाट में टर्नकी आधार पर 1320 मेगावाट (2x660 मेगावाट) की रणनीतिक अल्ट्रा-सुपर क्रिटिकल मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना के वित्तपोषण के लिए 1.60 बिलियन यूएस डॉलर का मीयादी ऋण प्रदान किया है। यह ऋण बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, बांग्लादेश और एनटीपीसी लि., भारत की बराबर हिस्सेदारी वाली संयुक्त उद्यम कंपनी 'बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लि.' (बीआईएफपीसीएल) को प्रदान किया गया है। इस टर्नकी परियोजना का कार्य अंतरराष्ट्रीय बोली के जरिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. को मिला था। इस परियोजना को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का चयन किया गया है। एक बार कमीशन होने के बाद मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना बांग्लादेश की सबसे बड़ी पावर प्लांट परियोजनाओं में से एक होगी। यह पावर प्लांट बांग्लादेश सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र के लिए तैयार की गई योजना का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य बांग्लादेश में ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ देश में बिजली की कमी को दूर करना है।

निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन

बैंक भारतीय कंपनियों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कई वित्तपोषण कार्यक्रमों के जरिए सहायता करता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एक्जिम बैंक ने निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हेतु अपने इन विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल ₹ 256.65 बिलियन के ऋण मंजूर किए और ₹ 290.78 बिलियन की राशि संवितरित की।

निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण

वर्ष के दौरान, बैंक ने 41 निर्यात उन्मुख इकाइयों को ₹ 31.94 बिलियन राशि के मीयादी ऋण मंजूर किए और ₹ 35.42 बिलियन राशि संवितरित की। उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत 13 निर्यातक कंपनियों को उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 9.95 बिलियन की राशि मंजूर की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संवितरणों की राशि ₹ 4.87 बिलियन रही। इसी प्रकार 13 कंपनियों को ₹ 34.30 बिलियन के दीर्घावधि कार्यशील पूँजी ऋण मंजूर किए गए, जिनके अंतर्गत संवितरणों की राशि ₹ 28 बिलियन रही।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक्जिम बैंक को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं की स्थापना हेतु अनुमोदन प्रदान करने तथा अनुमोदित परियोजनाओं को सीधे सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। यथा 31 मार्च, 2018 को बैंक ने ₹ 184.46 बिलियन मूल्य की 229 परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रदान किया। अनुमोदित और संवितरित ऋणों की राशि क्रमशः ₹ 66.94 बिलियन तथा ₹ 56.44 बिलियन रही। वस्त्र उद्योग को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा जिन इकाइयों को सहयोग प्रदान किया गया है वे वस्त्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों तथा भारत के कई राज्यों में फैली हुई हैं।

विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम

भारतीय बाह्य निवेश को सहायता प्रदान करने के लिए इक्रीटी वित्त, ऋण, गारंटियां और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से बैंक के पास कई कार्यक्रम हैं। वर्ष के दौरान 24

कंपनियों को 16 देशों में उनके विदेशी निवेश के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल ₹ 43.77 बिलियन की निधिक तथा गैर-निधिक सहायता मंजूर की गई। एक्जिम बैंक ने अब तक 78 देशों में 462 कंपनियों को 610 उपक्रमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता की है। वर्ष के दौरान सहयोग प्रदान किए गए विदेशी निवेशों में केमैन आइलैंड में एक अस्पताल का अधिग्रहण, यूएसए एवं फिलीपीन्स में व्यवसाय प्रक्रिया आउटसोर्सिंग इकाइयों का अधिग्रहण तथा स्वीडन में इंजीनियरी कंपनी को कार्यशील पूँजी सुविधाएं शामिल हैं। अब तक, बैंक द्वारा विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत कुल ₹ 572.90 बिलियन की राशि प्रदान की गई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र जैसे फार्मास्यूटिकल्स, घर सजा, रेडीमेड कपड़े, निर्माण, कागज, कागज उत्पाद, टेक्सटाइल, गारमेंट, रसायन, रंजक (डाई), कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी सामान, स्वास्थ्य सेवा, प्राकृतिक संसाधन (कोयला तथा वन), धातु तथा धातु प्रसंस्करण, कृषि तथा कृषि आधारित उत्पाद, स्टील, तेल तथा गैस आदि शामिल हैं।

आपाती साख-पत्र/ साख-पत्र

निर्यात उन्मुख इकाइयों के कारोबार को सुगम बनाने के लिए बैंक मुख्य रूप से आयात वित्तपोषण के लिए साख-पत्र (एल सी) जारी करता है। बैंक गारंटियों/एसबीएलसी के जरिए निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए वित्तीय गारंटियां भी प्रदान करता है। बैंक निर्यात उन्मुख इकाइयों को उनके विदेशी उपक्रमों के लिए फंड जुटाने हेतु वित्तीय गारंटियां/एसबीएलसी प्रदान करता है। वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 3.00 बिलियन की वित्तीय गारंटियां प्रदान कीं। यथा 31 मार्च, 2017 की ₹ 43.73 बिलियन की तुलना में यथा 31 मार्च, 2018 को बैंक का वित्तीय गारंटी पोर्टफोलियो ₹ 19.75 बिलियन रहा।



मध्य श्रीलंका के डांबुला क्षेत्र में 30 एमएलडी जल शोधन संयंत्रों और 9 जलाशयों से वितरण के लिए वीए टेक वाबाग लिमिटेड द्वारा निष्पादित परियोजना बैंक के क्रेता ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित है।

व्यवसाय परिचालन

एक्ज़िम बैंक निर्यात सुगमकर्ता के रूप में



एक्जिम बैंक ने हस्तनिर्मित कढ़ाई, कश्मीर क्राफ्ट, पैचवर्क, सबमर्सिबल पंप और मेटलवेयर को विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों पर प्लेस कराने में सहयोग दिया।

ग्रासरूट पहलें एवं विकास

बैंक अपनी ग्रासरूट पहलों के जरिए ग्रामीण भारत में स्थित उद्यमों के वैश्वीकरण में मदद करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों, बुनकरों तथा ग्रामीण उद्यमियों के लिए नए अवसरों का सृजन कर समाज के तुलनात्मक रूप से वंचित वर्गों की मदद करना है। वर्ष के दौरान बैंक ने बेंगलूरु के एक सामाजिक उद्यम को ऋण प्रदान कर सहयोग दिया, जो ई-कॉमर्स के जरिए प्राकृतिक फाइबर और हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल मार्केटप्लेस मुहैया कराता है। इससे सहकारी संस्थाओं, सामुदायिक कारीगरों एवं बुनकरों को अपने उत्पाद ऑनलाइन लिस्ट करने और बेचने में मदद मिलती है। वर्ष के दौरान बैंक ने महाराष्ट्र के एक सामाजिक उद्यम को भी सहयोग प्रदान किया, जो भारत में सीमांत किसानों को उनकी आय को बढ़ाने और जीविकोपार्जन में सुधार लाने हेतु मधुमक्खीपालन को बढ़ावा देता है। बैंक द्वारा दिए गए सहयोग का उद्देश्य संस्था की कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं का आंशिक वित्तपोषण करना है, जो भारत के छह राज्यों में 3,000 से अधिक छोटे मधुमक्खीपालकों को सीधे बाजार तक पहुंचने में सहायता करता है।

वर्ष के दौरान बैंक ने अन्य के साथ-साथ राजस्थान के एक सामाजिक उद्यम को सहयोग जारी रखा, जिसमें लगभग 3,500 कारीगर काम करते हैं। इनमें से अधिकतर पिछड़े समुदायों से आते हैं। साथ ही बैंक ने भागलपुर, बिहार के हैंडलूम उत्पादों को तैयार करने वाले सामाजिक उद्यम और पंजाब के सामाजिक उद्यम को भी सहयोग जारी रखा, जो लगभग 5,000 महिला कारीगरों के सशक्तीकरण और फुलकारी कला के समुत्थान के लिए काम करता है। श्रीकालहस्ती स्थित एक सोसायटी को भी बैंक ने सहयोग जारी रखा, जो लकड़ी के हस्तशिल्प तथा कलमकारी उत्पाद बनाती है।

बैंक कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन कर देशी तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति दर्ज कराने हेतु ग्रामीण हस्तशिल्प कारीगरों एवं शिल्पकारों को सहयोग प्रदान करता रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, बैंक ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय स्तर के विकासात्मक उद्यम को दीमापुर, नागालैंड में 20 मास्टर महिला बुनकरों के लिए एक माह की उत्पाद एवं डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यशाला के आयोजन के लिए सहयोग प्रदान किया। पारंपरिक बुनाई करने वाली हुनरमंद महिलाओं को इस कार्यशाला से स्व-रोजगार मिला तथा उन्हें उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने के लिए अपना हुनर निखारने में मदद मिली। बर्दवान और शांतिपुर, पश्चिम बंगाल के क्लस्टरों के बुनकरों के लिए दो कार्यशालाएं कराई गईं। इनका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा निर्यात चैनलों के जरिए उनके उत्पादों की बिक्री बढ़ाना और उनमें बाजार की जरूरतों के अनुसार डिजाइन एवं उत्पाद विकास क्षमताएं विकसित करना था। बैंक ने मुंबई में आयोजित लैकमे फैशन वीक के दौरान क्राफ्टमार्क पर एक शो प्रस्तुत करने हेतु अखिल भारतीय कारीगर एवं शिल्पकार कल्याण संघ को भी सहयोग दिया। इस शो के दौरान लम्बानी उत्पादों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया, जो कर्नाटक की लम्बानी महिलाओं द्वारा की जाने वाली ट्राइबल कढ़ाई है और विलुप्त होने के कगार पर है। इस शो के जरिए इन कारीगरों को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े डिजाइनरों तथा क्रेताओं से मिलने-जुलने का अवसर मिला।

साशा के साथ मिलकर 20 महिला कारीगरों के लिए कांथा कढ़ाई पर एक डिजाइन एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य नई कलात्मकता एवं तकनीकी से उत्पादों को तैयार करना था। परंपरागत बुनकरों को आधुनिक बुनाई पद्धतियों में प्रशिक्षित करने हेतु चित्रिका के साथ मिलकर मंगलगिरी के 41 बुनकरों और तकनीशियनों के लिए तीन महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुछ लिमिटेड एडिशन कलेक्शन भी बनाए गए।



एक्जिम बैंक ने ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए को क्रमशः लकड़ी के पैनल, नॉन-लेदर हैंडबैग और हस्तनिर्मित टेक्सटाइल के निर्यातों में सहयोग दिया।

एक्जिम बैंक ने जयपुर के साथ मिलकर राजस्थान में मेसर्स चोगन प्रिन्टर्स के साथ ब्लॉक प्रिंटिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रिन्टर्स एवं रंजकों (डायर्स) सहित मास्टर कारीगरों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य उत्पाद विशाखन और आधुनिक उत्पादों के विकास की संभावनाएं तलाशना था। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पूरा हो जाने के बाद, इनमें तैयार किए गए उत्पादों को जयपुर ई-कॉमर्स पर प्रदर्शित किया जाएगा और बेचा जाएगा।

बैंक द्वारा सहायता प्रदान की गई कार्यशालाएं उत्पाद विकास, डिजाइन एवं गुणवत्ता के संबंध में आने वाली दिक्कतों का समाधान करने की दृष्टि से काफी हद तक सफल रहीं और इनसे कारीगरों को उत्पादों के ऐसे प्रोटोटाइप विकसित करने में मदद मिली जिनकी देशी तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी मांग है।

समझौता / सहयोग ज्ञापन

बैंक ने विभिन्न संस्थागत संबंध स्थापित करने, उन्हें विकसित करने और प्रोत्साहन देने की अपनी सुविचारित नीति को जारी रखते हुए चुनिंदा बड़ी एजेंसियों के साथ औपचारिक सहयोग करार किए, ताकि शिल्पियों तक सीधे पहुंचा जा सके और क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, बाजार तक पहुंच और प्रशिक्षण के जरिए उनकी मदद की जा सके।

वर्ष के दौरान, बैंक ने टाटा ट्रस्ट के सेंटर फॉर माइक्रोफायनेंस एंड लाइवलीहुड (सीएमएल) के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सीएमएल टाटा ट्रस्ट द्वारा पूर्वोत्तर भारत में क्षमता निर्माण, शोध और सहयोग आधारित भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष रूप से शुरू किया गया एक मुख्य सहयोगी संगठन है। सहयोग ज्ञापन का उद्देश्य ग्रासरूट उद्यमों को उनकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ गुणवत्ता के वैश्विक मानकों पर खरा उतरना तथा अर्थक्षम वित्तपोषण मॉडल विकसित करना एवं परियोजनाओं/उद्यमों के लिए उच्च कोटि की ऐसी कार्य पद्धतियां विकसित करना है, जिन्हें

अलग-अलग उत्पाद क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अपनाया जा सके।

बैंक ने पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश सरकारों के साथ इन राज्यों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके तहत, बैंक का उद्देश्य अन्य के साथ-साथ इन राज्यों के निर्यातकों को बाजार से जोड़ने और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के लिए सहयोग प्रदान करना है। इन सहमति ज्ञापनों के संदर्भ में बैंक ने जयपुर ई-कॉमर्स प्रा. (जयपुर) लि. के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में मेसर्स साशा एसोसिएशन फॉर क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स (साशा) और आंध्र प्रदेश के मेसर्स चित्रिका को उनके शिल्पकारों के लिए कौशल उन्नयन, नए उत्पाद विकसित करने और खरीदारों को चिह्नित करने के लिए एक मंच मुहैया कराने में सहयोग प्रदान किया है।

मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं

बैंक अपनी मार्केटिंग सलाहकारी सेवाओं के जरिए भारतीय कंपनियों में निर्यात क्षमता लाने, तथा भारतीय कंपनियों के उत्पादों एवं सेवाओं हेतु विदेशों में वितरकों/ खरीदारों/भागीदारों की तलाश के जरिए उनके वैश्वीकरण के प्रयासों में मदद करता है और संवर्धक की भूमिका निभाता है। बैंक अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, अंतरराष्ट्रीय बाजारों की समझ, संस्थागत संबंधों और विदेशों में अपनी मौजूदगी तथा ई-मार्केटिंग प्रयासों से सफलता शुल्क आधार पर भारतीय कंपनियों की मार्केटिंग गतिविधियों में भी मदद करता है।

उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना

वर्ष के दौरान बैंक ने 18 कंपनियों के साथ अधिदेशों (मैंडेट) पर हस्ताक्षर किए। वर्ष के दौरान, विभिन्न उत्पादों के लिए देशी और विदेशी बाजारों में लगभग ₹ 30 मिलियन के 233 ऑर्डर प्राप्त किए गए। इनमें ऑस्ट्रेलिया को लकड़ी के पैनल, यूके को नॉन-लेदर हैंडबैग तथा यूएसए को हैंडलूम टेक्सटाइल का निर्यात शामिल है। भारत और विदेशों में विभिन्न ई-कॉमर्स पोर्टलों पर सबमर्सिबल पंपों, कश्मीरी क्राफ्ट, ढोकरा



पश्चिम बंगाल की कांथा कढ़ाई करने वाली महिला बुनकरों को डिजाइन एवं कौशल विकास प्रशिक्षण।

मेटलवेयर, बनाना फाइबर उत्पादों तथा पारंपरिक एवं लोक कला पेंटिंगों को प्लेस किया गया।

उत्पादों के प्लेसमेंट के अलावा, बैंक ने भारतीय कंपनियों को विदेशों में भागीदार तलाशने में मदद की:

- कॉसलाइट इंडिया लि. ने श्रीलंका में एक टेलीकॉम कंपनी को लिथियम बैटरी की आपूर्ति हेतु एक करार पर हस्ताक्षर किए।
- वावा रस्स ने यू एस बाजार में कालीन एवं दरियों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नोविका के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए।
- सूक्ष्म एवं ग्रासरूट उद्यमों और भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पाद बेचने वाले विशिष्ट ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जयपोर के बीच कई आपूर्तिकर्ता करार हुए।
- रंगसूत्र तथा पुरकल स्त्री शक्ति समिति ने म्यूजियम स्टोर के साथ हाथ से की गई कढ़ाइयों और पैचवर्क उत्पादों को मुंबई हवाई अड्डे पर बेचने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



भारत सरकार की 86.31 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत म्यांमार रेलवेज को राइट्स लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए 32.40 मिलियन यूएस डॉलर के 18 रेलवे लोकोमोटिव सौंपे जाने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह।



एक्जिम बैंक ने विश्व बैंक निधि परियोजनाओं में व्यवसाय अवसरों पर मुंबई में एक सेमिनार का आयोजन किया।

- विशेष रूप से डिजाइन किए गए नॉन-लेदर बैगों के प्रोटोटाइप के लिए आर्चर डिजाइन्स प्रा. लि. तथा कॉमनवेल्थ फैशन काउंसिल, यूके द्वारा एक मैनुफैक्चरिंग करार पर हस्ताक्षर किए गए।
- शक्ति पंप्स (इंडिया) लि. ने औद्योगिक माल के स्टार्ट-अप, मोगलिकस के पोर्टल पर अपने अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- द शिखर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट वीवर्स वेलफेयर पी सी एस इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसायटी लि. ने ऑनलाइन मार्केटप्लेस गोकूप के जरिए अपने ऊनी उत्पाद बेचने के लिए उसके साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- शारदादेवी ग्रामोद्योग उत्पादक सहकारी मंडली लि. (एसजीएस) ने अपने हस्तशिल्प उत्पादों को ई-कॉमर्स पोर्टल क्राफ्टली पर प्रदर्शित करने और बेचने के लिए रजिस्टर कराया।
- अन्वेषा ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ने ऑनलाइन मार्केटप्लेस क्राफ्ट फर्निश, जो शिल्पियों को धातु से बनाए गए उनकी शिल्प कलाकृतियों को प्रदर्शित करने



37.30 मिलियन यूएस डॉलर की भारत सरकार की ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत लाओ पीडीआर में विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाली ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण।



आंध्र प्रदेश में मंगलगिरी बुनकरों के लिए डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।

और बेचने के लिए तकनीकी एवं मार्केटिंग सहयोग प्रदान करता है, पर खुद को रजिस्टर कराया।

- साधना एंटरप्राइज ने ऑनलाइन पोर्टल स्वीटकाउच के ज़रिए अपने हस्तनिर्मित वस्त्रों को बेचने के लिए उसके साथ एक करार किया।

भारतीय कारीगरों को सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से बैंक ने उपहारस्वरूप देने के लिए जूट से बनी चीजें, हस्तनिर्मित एवं रिसाइकल्ड पेपर, हाथ से बुने स्टोल तथा शॉल और लकड़ी एवं धातु से निर्मित उत्पाद भी खरीदे हैं।

कार्यक्रम/प्रदर्शनियां

बैंक ने 'सिक्वोर गिविंग' के साथ मिलकर मुंबई, पुणे, कोलकाता, चेन्नै तथा बेंगलूरु में पारंपरिक, जनजातीय तथा लोक-कला प्रदर्शनियां आयोजित करने में सहयोग किया। इन कला प्रदर्शनियों में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा आंध्र प्रदेश की चित्रकारियां प्रदर्शित की गईं और उनकी बिक्री हुई। बैंक ने झारखंड सरकार के एक उपक्रम को जम्मू, लखनऊ एवं पुणे में कुचई सिल्क एक्सपो लगाने के लिए प्रायोजित किया। प्रदर्शनी ने हैंडलूम बुनकरों को हाथ से बुने हुए टेक्सटाइल एवं कपड़े बेचने हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। बैंक ने स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों तथा छोटी कंपनियों



राजस्थान के सांगानेर में ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए उत्पाद एवं डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।

को सूरजकुंड मेला, काला घोड़ा कला महोत्सव तथा एक्जिम बाजार प्रदर्शनियों में बूथ दिलाकर उन्हें सहयोग प्रदान किया।

एक्जिम मित्र

बैंक भारत और शेष विश्व के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय और क्षेत्रीय बैंकों के साथ मिलकर काम करता है। एक्जिम बैंक भारत के विदेश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में एक उत्प्रेरक और प्रमुख संस्थान के रूप में काम कर रहा है। एक्जिम मित्र एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों में व्यापार वित्त की उपलब्धता तथा ऋण बीमा सुविधाओं के लिए सूचनाओं की कमी को दूर करने का एक प्रयास है। इस पोर्टल का लक्ष्य निर्यातकों के लिए ऋण की उपलब्धता और व्यापार संबंधी जानकारियां प्रदान करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करना है। यह पोर्टल व्यापार वित्त और निर्यात ऋण बीमा विकल्पों तथा निर्यात अवसरों की जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ इस क्षेत्र में एक हेल्पलाइन के रूप में काम करता है। इसमें अन्य के साथ-साथ विभिन्न उत्पादों की मांग और उनके बाजारों; बाजार मानकों; यूएसए और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख बाजारों में सैनिटरी/फाइटोसैनिटरी अपेक्षाओं; विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी प्रोत्साहनों; हैंडहोल्डिंग एजेंसियों के संपर्क सूत्रों; शिपमेंट की लागत और उसमें लगने वाले समय की जानकारी और कंट्री रेटिंग की जानकारियां प्रदान करना

बेहतरीन टूल! कृपया हमें भारतीय हथकरघा उत्पादों के बल्क खरीदार देशों की विस्तृत जानकारी प्रदान करें, ताकि हम किसी मध्यस्थ के बिना उनसे सीधे संपर्क कर सकें।

रजनीश कुमार,
सुरक्षा फायनैशल सर्विसेज
(नई दिल्ली)

निर्यातकों और निर्यात क्षेत्र में कदम रखने वालों के लिए बेहद सूचनापरक और उपयोगी वेबसाइट नए फीचर नए निर्यातकों को अपने उपक्रम स्थापित करने में निश्चित रूप से मददगार होंगे।

प्रमोद संघवी,
एक्जिम रेमेडीज,
कंसल्टैंसी सर्विसेज
(महाराष्ट्र)

मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे इतनी सटीक और उपयोगी जानकारी देने वाली आप पहली सरकारी संस्था हैं। विभिन्न फीचर्स के आपके स्पष्टीकरण से मुझे डाटा सर्वे करने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में बड़ी मदद मिली।

इवा शाह,
शाह एक्सपोर्टर्स एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग
(महाराष्ट्र)

बेहद उपयोगी और उपयुक्त वेबसाइट। साख पत्र और कुछ अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक पारिभाषिक शब्दों की भी जानकारी मिले तो उपयोक्ताओं को भुगतान के तरीके समझने में आसानी होगी।

फेलिक्स मार्टिन,
इंडियन बैंक
(तमिलनाडु)



नारायणा हेल्थ लिमिटेड ने एक्जिम बैंक के विदेशी निवेश वित्त के सहयोग से असेशन, यूएसए के साथ मिलकर संयुक्त रूप से केमन आईलैंड में 104 बेड वाला अस्पताल विकसित किया।

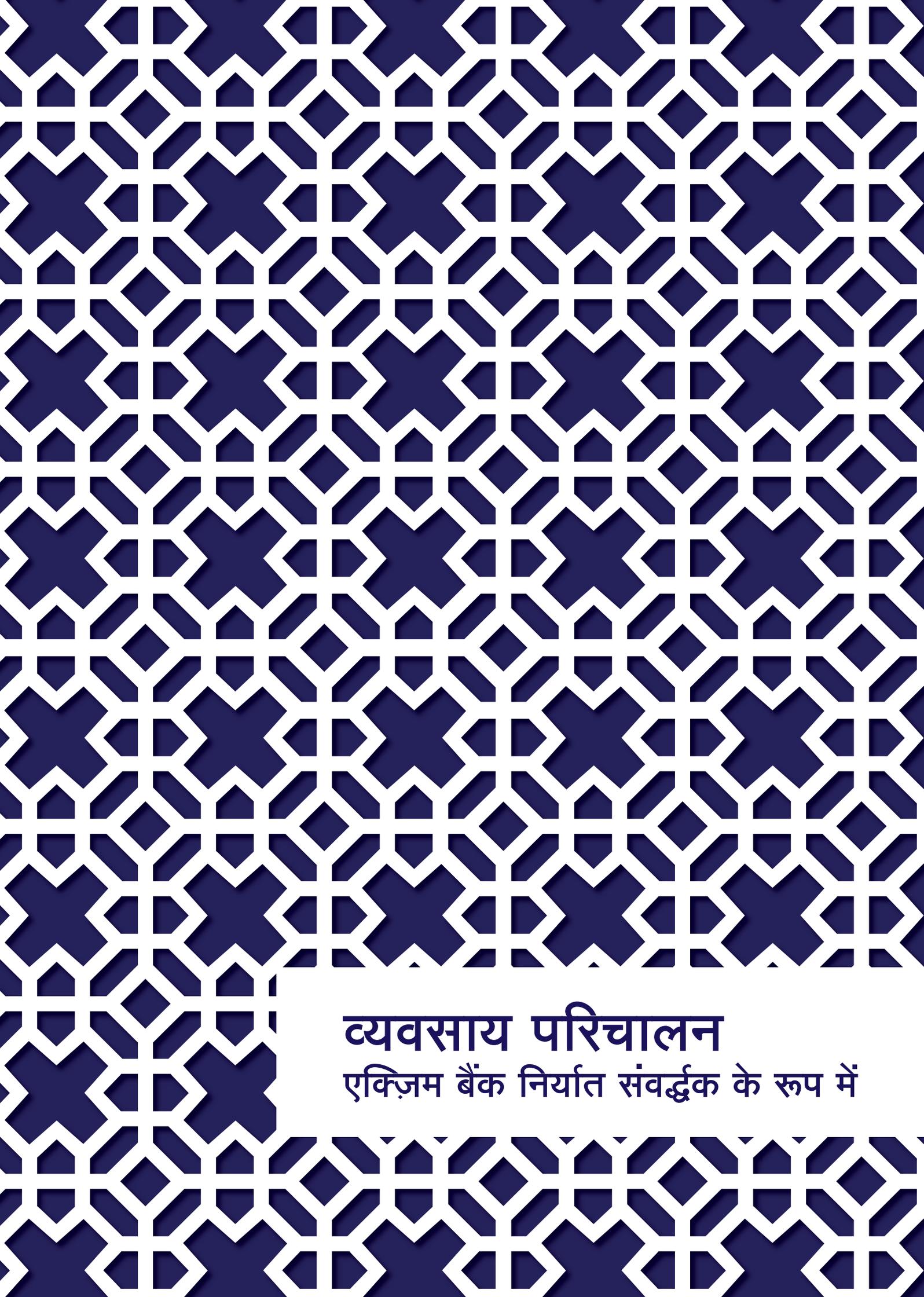
शामिल है। यह पोर्टल अधिकाधिक सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में है।

बैंक निर्यातकों को व्यापार वित्त की जानकारी और मार्गनिर्देशन सुलभ कराने के लिए वाणिज्यिक बैंकों और ऋण बीमा एजेंसियों के साथ भी मिलकर काम करता है। बैंक ने इस पोर्टल के जरिए वित्तीय सेवाएं सुगम बनाने के लिए 15 बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के साथ सहभागिता की है। भावी निर्यातक इस पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो ऋण आवेदनों से संबंधित प्राथमिक डाटा कैप्चर करता है। यह विवरण प्रतिभागी बैंकों से साझा किया जाता है। इस प्रकार यह पोर्टल व्यापार वित्त उपयोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं के

बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है।

एक्जिम बैंक जानकारियों के पूर्ण प्रसार के लिए सूचना के पारस्परिक आदान-प्रदान के महत्त्व को समझता है। सूचनाओं के इस आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए पोर्टल एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म का काम करता है, जो बैंक को निर्यातकों की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझने और उन्हें पूरा करने में मदद करता है।

पोर्टल ऐसे निर्यातकों और आयातकों को प्राथमिक सहयोग प्रदान करता है, जिनके पास व्यापार संबंधी महत्त्वपूर्ण सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं और इस तरह वित्तीय समावेशन में भी सहयोग करता है।



व्यवसाय परिचालन
एक्ज़िम बैंक निर्यात संवर्द्धक के रूप में

शोध एवं विश्लेषण

बैंक का शोध एवं विश्लेषण समूह अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और निवेश पर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव शोध तकनीकों के जरिए शोध अध्ययन करता है। समूह द्वारा क्षेत्रीय, उद्योग खंड और नीति संबंधित तीन विस्तृत श्रेणियों में किए जाने वाले शोध अध्ययन प्रासंगिक आलेखों, कार्यकारी आलेखों और पुस्तकों आदि के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान 18 शोध अध्ययन प्रकाशित किए गए, जो निम्नलिखित हैं:

- जावक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए भारतीय कंपनियों का अंतरराष्ट्रीयकरण: प्रकृति, निर्धारक कारक और विकासात्मक प्रभाव
- वित्तीयकरण और उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं की विनिमय दरों के निर्धारण पर इसका प्रभाव
- व्यापार वित्त को बढ़ावा: विकास बैंकों और निर्यात ऋण एजेंसियों की अग्रणी भूमिका
- लचीले व्यापार वित्त ढांचे का निर्माण: आलेखों का संकलन
- पोषित अफ्रीका: भागीदारी के जरिए प्रगति हासिल करना
- अफ्रीका में जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा: सुविधा में सुधार, वृद्धि को बढ़ावा
- एकीकृत अफ्रीका: बहुआयामी परिदृश्य
- अफ्रीका में विनिर्माण: स्थाई वृद्धि हेतु रूपरेखा
- अफ्रीका में बिजली क्षेत्र: पूर्वांनुमान एवं संभावनाएं
- पूर्व अफ्रीका में भारतीय निवेश: रुझान एवं संभावनाएं
- कनेक्टिंग अफ्रीका: परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका
- पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं में व्यापार: परिदृश्य



एक्विजि बैंक के प्रकाशन लचीले व्यापार वित्त ढांचे का निर्माण: आलेखों का संकलन का विमोचन।



व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए सीआईआई-एक्विजि बैंक पुरस्कार, 25वें सीआईआई राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन में गोदरेज इंटेरियो (गोदरेज एंड बॉयस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड) को दिया गया।

- आसियान-भारत सहयोग का सुदृढीकरण: रुझान और भावी संभावनाएं
- भारत-श्रीलंका व्यापार एवं निवेश संबंध: मौजूदा रुझान एवं संभावनाएं
- लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में भारतीय निवेश: रुझान एवं संभावनाएं
- तेल की कीमत एवं पेट्रोलियम क्रूड व उत्पादों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार: भारतीय परिदृश्य
- औषधि उद्योग:नियामक परिदृश्य तथा भारतीय निर्यातकों के लिए अवसर
- उत्तर प्रदेश से निर्यात: रुझान, अवसर और नीतिगत परिदृश्य

सूचना एवं सलाहकारी सेवाएं

बैंक कई प्रकार की सूचना, सलाहकारी और सहायता सेवाएं प्रदान करता है। ये सेवाएं जहां बैंक के वित्तपोषण कार्यक्रमों की पूरक हैं, वहीं बैंक की पॉलिसी बैंक की भूमिका को भी रेखांकित करती हैं। ये सेवाएं बैंक के हितधारकों को प्रदान की जाती हैं, जिनमें राज्य सरकारें, भारतीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्र तथा विदेशी संस्थाएं शामिल हैं। इन सेवाओं में राज्य सरकारों के लिए नीतिगत सुझाव और शोध अध्ययन, बाजार संबंधी सूचनाएं, क्षेत्र और व्यवहार्यता अध्ययन, प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं की पहचान, भागीदारों की खोज, क्षमता निर्माण, निवेश सुगमीकरण तथा भारत और विदेश में संयुक्त उद्यमों का विकास शामिल हैं।

वर्ष के दौरान, घाना निर्यात-आयात बैंक (एक्विजि घाना) ने अपने विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु एक्विजि बैंक को कार्यदायित्व सौंपा। एक्विजि बैंक अन्य के साथ-साथ समुचित संगठनात्मक ढांचा तथा निर्यात वित्त



एक्जिम बैंक के विशेष प्रकाशन आसियान-भारत सहयोग का सुदृढीकरण: रुझान और भावी संभावनाएं का विमोचन।

कार्यक्रमों की रूपरेखा और इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए योजना भी बनाएगा। साथ ही मानक प्रारूप तैयार करेगा और ऋण प्रस्तावों तथा जोखिम विश्लेषणों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश उपलब्ध कराएगा तथा आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए भी सुझाव देगा। बैंक संबंधित पक्षों के परामर्श ही इस कार्य को पूरा कर रहा है।

विदेशों में बहुपक्षीय निधिक परियोजनाएं

बैंक अपनी सूचना और सहयोग सेवाओं के जरिए भारतीय कंपनियों को विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी), अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (ईबीआरडी) द्वारा निधिक परियोजनाओं में कारोबार प्राप्त करने में मदद करता है। ऐसी बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा निधिक परियोजनाएं आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और परामर्शदाताओं को कारोबार के अच्छे अवसर प्रदान करती हैं। ऐसी परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सहभागिता बढ़ाने की संभावनाओं को देखते हुए एक्जिम बैंक इन एजेंसियों के साथ मिलकर सेमिनार आयोजित करता रहा है।

एशियाई विकास बैंक परिवहन, ऊर्जा, नगरीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन एवं मानव विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए ऋण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। एशियाई विकास बैंक सरकार की प्रमुख परियोजनाओं जैसे सोलर पार्क तथा सोलर रूफटॉप, ऊर्जाक्षम एल ई डी लाइट, स्मार्ट सिटी, मेट्रो लाइन, रेलवे के आधुनिकीकरण तथा सिंचाई प्रणाली में विस्तार आदि के लिए भी सहयोग प्रदान करता है। एडीबी के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बैंक ने एडीबी के साथ मिलकर 'एशियाई विकास बैंक के साथ अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय अवसर' विषय पर चेन्नै तथा मुंबई में दो चर्चापरक सेमिनारों का आयोजन किया।

मार्च 2018 के अंत तक, विश्व बैंक के प्रोक्योरमेंट सिस्टम में 172 देशों में 5675 परियोजनाओं के लिए लगभग 183.6 बिलियन यूएस डॉलर की संविदाओं का पोर्टफोलियो था। विश्व बैंक प्रोक्योरमेंट के लिए भारतीय कंपनियां बिडिंग में भागीदारी करती रही हैं और काफी हद तक सफल रही हैं। जुलाई 2016 से विश्व बैंक ने नई प्रोक्योरमेंट व्यवस्था लागू की है, जो व्यवसाय के ज्यादा अनुकूल है और वेंडरों सहित स्टेकहोल्डरों से मिले फीडबैक का ध्यान रखती है। विश्व बैंक की परियोजनाओं के अंतर्गत बिडिंग अवसरों में भारतीय कंपनियों की प्रभावी भागीदारी बढ़ाने की संभावनाओं को देखते हुए बैंक ने विश्व बैंक समूह के साथ मिलकर मुंबई में 'विश्व बैंक निधिक परियोजनाओं में व्यवसाय अवसर' विषय पर एक चर्चापरक कार्यशाला का आयोजन किया।

एक्जिमिअस शिक्षण केंद्र

बैंक के एक्जिमिअस शिक्षण केंद्र (ईसीएल) द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन, समन्वय और कार्यान्वयन किया जाता है। ईसीएल द्वारा भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को सुगम बनाने और भारतीय निर्यातकों व आयातकों की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सेमिनारों, कार्यक्रमों व कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही समसामयिक विषयों पर निर्यातकों एवं आयातकों के लिए सेमिनारों एवं



एक्जिम बैंक ने अफ्रीकी विकास बैंक के 'हार्ड-फाइव' एजेंडा पर केंद्रित 'अफ्रीका के विकास के लिए परस्पर सहभागिता बढ़ाता भारत' थीम पर कार्यकारी आलेखों का विमोचन किया।

सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता है। इन सेमिनारों में भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (फिओ), इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), ईसीजीसी लि., आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तथा अग्रणी वाणिज्यिक बैंकों के वक्ताओं ने जानकारी प्रदान की।

वर्ष के दौरान ई सी एल द्वारा निर्यातकों के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विषयों पर 24 निर्यात संवर्द्धन सेमिनारों का आयोजन किया गया।

सेवाओं के निर्यात विषय पर आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर मुंबई, बेंगलूरु, अहमदाबाद एवं कोच्चि में चार परिचर्चा सत्रों का श्रृंखलाबद्ध आयोजन किया गया। इन सत्रों में प्रमुख स्टेकहोल्डरों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु प्राथमिक रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन), पर्यटन, रीयल एस्टेट, आवास एवं शिपिंग आदि पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। ये प्रतिक्रियाएं भारत सरकार की सेवा क्षेत्र में निर्यातों पर रणनीति के लिए इनपुट का काम करेंगी।

फिओ के साथ मिलकर पांच श्रृंखलाबद्ध सेमिनारों का आयोजन किया गया। 'पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशी व्यापार में अवसर एवं चुनौतियां', 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण', 'निर्यात वित्त में सुरक्षित भुगतान' तथा 'जीएसटी एवं विदेश व्यापार नीति का असर' जैसे विषयों पर उदयपुर, लुधियाना, भुवनेश्वर, अमृतसर एवं वाराणसी में इन सेमिनारों का आयोजन किया गया।

ईसीएल द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से निर्यात बढ़ाने पर चर्चा करने हेतु सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाने के लिए श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों एवं सेमिनारों का आयोजन किया गया। ईसीएल ने आईसीसी के साथ मिलकर शिलांग में 'एक्ट इस्ट बिजनेस शो' तथा 'उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के



अंतरराष्ट्रीय सौर सहयोग पर नई दिल्ली और मुंबई में स्टेकहोल्डरों के लिए चर्चापरक सेमिनार।



एक्जिम बैंक के निर्यात सुगमीकरण पोर्टल एक्जिम मित्र को एशिया प्रशांत में विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एडफिएप) से पुरस्कार मिला।

लिए प्रोत्साहित करना' विषयों पर आइजोल एवं इंफाल में सेमिनारों का आयोजन किया गया। इसके अलावा, ईसीएल एवं सीआईआई द्वारा संयुक्त रूप से दीमापुर एवं गंगटोक में 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में विदेशी व्यापार में अवसर एवं चुनौतियां' विषय पर सेमिनारों का आयोजन किया गया।

ईसीएल ने सीआईआई के साथ मिलकर बर्द्धी में 'वित्तपोषण विकल्प और स्पर्धात्मकता बढ़ाते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा' तथा भावनगर, महुआ (गुजरात) में 'निर्यात मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग' विषय पर सेमिनारों का आयोजन किया। ईसीएल ने आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर एमएसएमई के लिए नवी मुंबई में 'निर्यात कैसे करें' तथा कोल्हापुर में 'निर्यातों को कैसे बढ़ाएं' विषयों पर सत्रों का आयोजन किया।

अफ्रीका में औषधि निर्यातों को बढ़ाने के लिए ईसीएल ने नई दिल्ली में 'इंडिया-अफ्रीका फार्मा डायलॉग' का आयोजन किया, जिसमें उद्योग के स्टेकहोल्डर तथा भारत में अफ्रीकी मिशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। ईसीएल ने नई दिल्ली में एस्टोनियाई दूतावास के साथ मिलकर 'एस्टोनिया में व्यापार एवं निवेश अवसर' पर मुंबई में एक सेमिनार का आयोजन किया।

संस्थागत संबद्धताएं

देश के व्यापार एवं निवेश हेतु अनुकूल परिवेश तैयार करने के लिए बैंक ने बहुपक्षीय एजेंसियों, निर्यात ऋण एजेंसियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं, व्यापार संवर्द्धन निकायों तथा निवेश संवर्द्धन बोर्डों के साथ अपने संस्थागत संबंधों का एक नेटवर्क विकसित किया है।

ब्रिक्स अंतर बैंक सहयोग तंत्र

एक्जिम बैंक ने ब्रिक्स अंतर बैंक सहयोग तंत्र के अंतर्गत



एक्जिम बैंक के प्रकाशन 'व्यापार वित्त को बढ़ावा: विकास बैंकों और निर्यात ऋण एजेंसियों की अग्रणी भूमिका' का विमोचन।

ब्रिक्स के सदस्य विकास बैंकों के साथ दो बहुपक्षीय करार किए।

- क) अंतर बैंक स्थानीय मुद्रा ऋण-व्यवस्था करार, तथा
- ख) क्रेडिट रेटिंग से संबंधित सहयोग ज्ञापन।

अंतर बैंक स्थानीय मुद्रा ऋण-व्यवस्था करार ब्रिक्स सदस्य बैंकों के बीच राष्ट्रीय कानूनों, हस्ताक्षरकर्ता संस्थाओं के विनियमों और नीतियों के अनुसार द्विपक्षीय करारों को सुगम बनाएगा। वहीं, क्रेडिट रेटिंग से संबंधित सहयोग ज्ञापन के माध्यम से ब्रिक्स सदस्य विकास बैंकों के बीच क्रेडिट रेटिंग साझा की जा सकेगी और यह ब्रिक्स देशों में सीमा पार ऋण प्रदान करते समय जोखिमों को कम करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र की भूमिका निभाएगा। इन करारों पर चीन में आयोजित ब्रिक्स समिट 2017 के दौरान हस्ताक्षर किए गए।

एशियाई एक्जिम बैंक फोरम

एशियाई एक्जिम बैंक फोरम (ईबीएफ) की 23वीं वार्षिक बैठक नवंबर 2017 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। बैठक

की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के निर्यात वित्त एवं बीमा निगम (ईएफआईसी) द्वारा की गई। बैठक की थीम थी- 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मंदी के बावजूद, विश्व के अग्रणी विदेश व्यापार और आर्थिक वृद्धि वाले क्षेत्र के सदस्य देश आगामी वर्षों में विश्व व्यापार को लीड करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।' बैठक की अध्यक्षता ईएफआईसी ने की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाइलैंड, तुर्की तथा वियतनाम की सदस्य संस्थाओं के उच्चाधिकारियों ने हिस्सा लिया। हालांकि फिलीपींस इस बैठक में भाग नहीं ले पाया, बैठक में एशियाई विकास बैंक ने स्थाई अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। द एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक ऑफ टर्की, सदस्यता प्रोटोकॉल के अनुसार सहायक सदस्य के रूप में दो वर्ष पूरे कर लेने पर फोरम का सदस्य बन गया।

ईबीएफ की स्थापना 1996 में एक्जिम बैंक की पहल पर की गई थी। हालांकि निर्यात ऋण एजेंसियों को उनके राष्ट्रीय निर्यातों को सहायता प्रदान करने के कारण उन्हें सामान्यतः एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा जाता है। इस फोरम का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा के दौरान सहयोग प्रदान करना है। एशियाई एक्जिम बैंक फोरम का उद्देश्य परस्पर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देकर एशियाई एक्जिम बैंकों के बीच दीर्घकालिक व सुदृढ़ संबंध बनाना है।

यह फोरम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक सुदृढ़ मंच भी प्रदान करता है। इसके जरिए सदस्य संस्थाओं के स्टाफ को परियोजना वित्तपोषण, पूँजी बाजार, पोत वित्तपोषण, लघु, मध्यम उद्यमों को वित्तपोषण, पण्य वित्तपोषण, देश जोखिम, विदेशों में निवेश जैसे विविध क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियां सीखने में मदद मिलती है। वर्ष के दौरान सदस्य संस्थाओं द्वारा दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का



बांग्लादेश सरकार को विकास परियोजनाओं के लिए 4.50 बिलियन यूएस डॉलर के ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर।



‘पूर्वोत्तर भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में निर्यात स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण’ संबंधी परियोजना के वित्तपोषण के लिए यूएनडीपी के साथ करार पर हस्ताक्षर।

आयोजन किया गया, जिनमें से एक कार्यक्रम की मेजबानी भारतीय एक्जिम बैंक द्वारा की गई। बैंक सहित विभिन्न संस्थाओं की इसमें बड़ी भागीदारी रही।

एक्जिम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं का वैश्विक नेटवर्क

एक्जिम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के वैश्विक नेटवर्क (जी-नेक्सिड) की स्थापना एक्जिम बैंक की पहल पर अंकटाड के तत्वावधान में मार्च 2006 में जेनेवा में की गई थी। नेटवर्क ने विभिन्न विकासशील देशों के एक्जिम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से दक्षिण-दक्षिण सहयोग, व्यापार तथा निवेश को बढ़ाने के प्रयास किए हैं। इसकी वार्षिक आम बैठक जुलाई 2017 में जेनेवा में हुई, जिसके बाद नवंबर 2017 में ब्राजीलियाई विकास बैंक द्वारा एक एक्सचेंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार

भारतीय कंपनियों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक और कंफेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) द्वारा ‘सी आई आई-एक्जिम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार’ की स्थापना 1994 में भारतीय कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों (टीक्यूएम) को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह पुरस्कार यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट (ईएफक्यूएम) मॉडल पर आधारित है। यह वार्षिक पुरस्कार काफी प्रतिष्ठित है तथा उद्योग जगत में इसकी मान्यता है। किसी कंपनी को यह पुरस्कार पारदर्शी एवं कड़ी परीक्षण प्रक्रिया के बाद ईएफक्यूएम मॉडल पर प्रदान किया जाता है। 2017 में 11 कंपनियों को अलग-अलग स्तरों पर पुरस्कृत किया गया। गोदरेज इंटीरियो

डिविजन, गोदरेज एंड बॉयस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लि. ‘अवॉर्ड विजेता’ रही, जबकि गोदरेज अप्लायंस डिविजन, गोदरेज एंड बॉयस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लि. तथा रेकेम आरपीजी (प्रा.) लि. ‘प्राइज़ विजेता’ रहीं।

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार

बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार (ईरा) की स्थापना 1989 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबद्ध वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना है। इस पुरस्कार के अंतर्गत ₹ 0.35 मिलियन की राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2016 का यह पुरस्कार डॉ. ईशा चावला को उनकी डॉक्टोरल थीसिस ‘‘देश से बाहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए भारतीय फर्मों का अंतरराष्ट्रीयकरण: प्रकृति, निर्धारक और विकासात्मक प्रभाव’’ के लिए दिया गया। डॉ. ईशा चावला ने दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से 2015 में डिग्री हासिल की।

भारतीय एक्जिम बैंक ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कार

भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग तंत्र 2016 के अंतर्गत बैंक ने ‘भारतीय एक्जिम बैंक ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कार’ की स्थापना की। इस पुरस्कार का उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य देशों से संबंधित आर्थिक समसामयिक विषयों पर केंद्रित उन्नत शोध अध्ययनों को प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र और ₹ 1.50 मिलियन (लगभग 23,000 यूएस डॉलर) की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। ब्रिक्स के पांचों देशों के नागरिक, जिन्हें डॉक्टोरल थीसिस के लिए डॉक्टरेट डिग्री मिल गई है या उनकी थीसिस को किसी भी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक संस्थान द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान करने हेतु स्वीकार कर लिया गया है, इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्ष 2017 के लिए



एक्जिम बैंक का अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार 2016 डॉ. ईशा चावला को प्रदान करते डॉ. अरविंद सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार।



एक्जिम बैंक का ब्रिक्स आर्थिक शोध पुरस्कार 2017 ब्राजील की डॉ. रैक्रेल एल्मीडा रामोस को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार चाइना डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष श्री हू हुआबैंग द्वारा प्रदान किया गया।

इस पुरस्कार की विजेता डॉ. रैक्रेल एल्मीडा रामोस रहीं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी डॉक्टोरल थीसिस "वित्तीयकरण और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विनिमय दरों के निर्धारण पर इसके प्रभाव" के लिए दिया गया। डॉ. रामोस को 2016 में पेरिस यूनिवर्सिटी 13, सरबोने पेरिस साइट, फ्रांस और यूनिवर्सिटी एस्टाड्यूल दि कैंपिनास, ब्राजील से डिग्री मिली।

एडफिएप पुरस्कार

एशिया प्रशांत में विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एडफिएप) की नई दिल्ली में आयोजित 41वीं वार्षिक बैठक के दौरान बैंक को "प्रौद्योगिकी विकास" श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट विकास परियोजना पुरस्कार (आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अवॉर्ड) 2018 प्रदान किया गया। एडफिएप विकास पुरस्कार उन सदस्य संस्थाओं को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने ऐसी परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया हो, जिनसे संबद्ध देशों में विकासात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ हो। वर्ष 2018 का एडफिएप विकास परियोजना पुरस्कार एक्जिम बैंक द्वारा स्टैल्प्स टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए सहयोग के लिए मिला। यह डेयरी फार्मा के लिए क्लाउड, मोबिलिटी और डाटा एनालिटिक्स से एकीकृत ऑटोमेशन टूल तैयार करने वाली भारत की चुनिंदा डेयरी प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। बैंक को अपने एक्जिम मित्र पोर्टल के लिए "एसएमई विकास" श्रेणी में 'प्लाक ऑफ मेरिट' से नवाजा गया। यह पोर्टल अन्य बातों के साथ-साथ निर्यातकों को वित्तीय उत्पादों की जानकारी उपलब्ध कराता है और व्यापार संबंधी सूचनाएं प्रदान करता है।

स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान

एक्जिम बैंक स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान माला की शुरुआत 1986 में की गई थी। इस व्याख्यान माला को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले समसामयिक व्यापार और

विकास मुद्दों पर विचार-विमर्श तथा चर्चा के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में ख्याति प्राप्त है। वर्ष 2017-18 के लिए यह व्याख्यान हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल स्टडीज एंड इकनॉमिक्स की जॉन ज्वान्सट्रा प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने दिया। प्रो. गोपीनाथ के व्याख्यान का विषय "व्यापार में डॉलर का प्रभुत्व: तथ्य और प्रभाव" था।

निर्यात संवर्द्धन के लिए राज्यों को एक्जिम बैंक द्वारा सहयोग

देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के वित्तपोषण, सुगमीकरण और संवर्द्धन के लिए स्थापित देश की शीर्ष निर्यात वित्त संस्था होने के नाते एक्जिम बैंक देश के राज्यों से निर्यात बढ़ाने तथा क्षेत्रीय उद्यमियों को विदेशों में व्यापार अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की निर्यात संभाव्यता पर उद्योग जगत तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ चर्चापरक सेमिनारों का आयोजन किया। इन सेमिनारों का उद्देश्य इन राज्यों में निर्यातकों के लिए उपलब्ध अवसरों और उनकी चुनौतियों को समझना था। इन चर्चाओं और बैंक द्वारा किए गए आंतरिक अनुसंधान के आधार पर बैंक द्वारा 'उत्तर प्रदेश से निर्यात: रुझान, अवसर और नीतिगत परिप्रेक्ष्य' शीर्षक से एक शोध अध्ययन प्रकाशित किया गया। इसमें उन क्षेत्रों को हाइलाइट किया गया है, जो राज्य में परंपरागत रूप से मजबूत स्थिति में हैं तथा चुनौतियों से निपटते हुए उन्हें और अधिक मजबूत किया जा सकता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में क्षमता निर्माण के लिए एक्जिम बैंक-यूएनडीपी सहयोग

वर्ष के दौरान एक्जिम बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के बीच निर्यात स्पर्धात्मकता के लिए पूर्वोत्तर भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में क्षमता निर्माण संबंधी परियोजना के वित्तपोषण के लिए करार हुआ। परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर से निर्यातों को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन और युवाओं तथा महिलाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई)



एक्जिम बैंक ने विशाखापट्टनम में आयोजित एशियाई एक्जिम बैंक फोरम के 'क्रेता ऋण' विषय पर 36वें प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी की।



एक्जिम बैंक ने इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट को 500 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की।

को मजबूत करना है। इसके लिए प्रमुख रणनीति होगी- भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट नीति' के अंतर्गत उभरते अवसरों का लाभ उठाना। इस नीति के अंतर्गत अन्य के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों, जलविद्युत, एशियाई देशों से नजदीकी जैसे मामलों में क्षेत्र में विद्यमान संभावनाओं को चिह्नित किया गया है। परियोजना की प्रमुख गतिविधियों में पूर्वोत्तर भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उन्हें क्लस्टर आधारित सहयोग प्रदान करना शामिल है। इसके अंतर्गत अन्य के साथ-साथ, क्लस्टर स्तरीय कार्यान्वयन रणनीति; उद्यमियों, उद्योग संघों और निर्यात संवर्धन एजेंसियों के लिए ऑनलाइन सपोर्ट संसाधन; बाजार विश्लेषण; चिह्नित वस्तुओं और उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए स्पष्ट रोडमैप तथा राज्य विशिष्ट निर्यात संवर्धन रणनीति शामिल हैं।

नई पहलें

एक्जिम बैंक ने म्यांमार और कंबोडिया में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर केंद्रित पहला मार्केट आउटरीच कार्यक्रम (ई-मॉप) शुरू किया। ई-मॉप भारतीय उद्यमों के लिए वेल्यू एडिशन और उभरते बाजारों के उभरते क्षेत्रों में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार

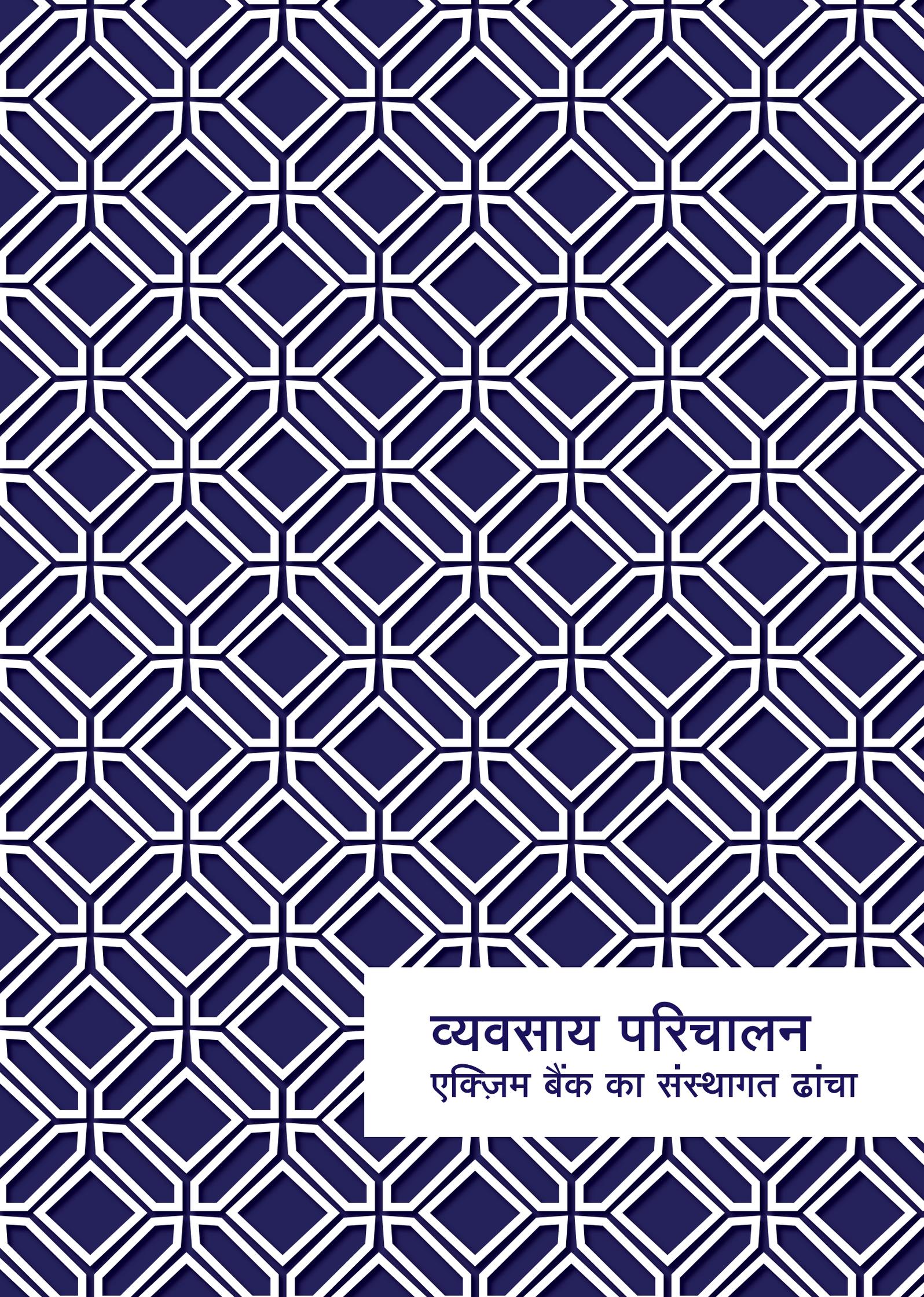
और निवेश को बढ़ाने के लिए की गई एक पहल है। ऐसा पहला कार्यक्रम म्यांमार और कंबोडिया में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर केंद्रित था। एक्जिम बैंक ने यांगून और नॉम पेन्ह के लिए मल्टी स्पेशलिटी और सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों, मेडिकल उपकरणों तथा डिवाइस विनिर्माताओं और पैथोलॉजी लैब तथा जांच केंद्रों के सदस्यों वाले एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रतिनिधिमंडल ने इस आउटरीच कार्यक्रम के दौरान दोनों देशों की सरकारों, बैंकों, व्यापार संस्थाओं और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के परामर्शदाताओं जैसे विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की। भारतीय कंपनियों ने म्यांमार और कंबोडिया के अपने समकक्षों से बिजनेस-टू-बिजनेस बैठकें कीं और स्थानीय अस्पतालों का दौरा किया। इस पहल के जरिए भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए व्यापार और निवेश के कई अवसर चिह्नित किए गए।

एक्जिम बाजार

बैंक ने देशभर की हस्तनिर्मित शिल्प कलाओं तथा टेक्सटाइल्स की विशिष्ट प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन किया। एक्जिम बाजार के नाम से आयोजित इस चार दिवसीय कार्यक्रम में कागज की लुगदी से बनी कश्मीरी वस्तुओं से लेकर मणिपुरी ब्लैक पॉटरी, राजस्थानी गहने, मधुबनी चित्रकारी, पैठणी साड़ियां, कलमकारी चित्रकारी, ब्लॉक प्रिंटेड गारमेंट कोल्हापुरी चप्पलें, ढोकरा कला और बीदरीवेयर जैसे विभिन्न उत्पाद शामिल रहे। इस प्रदर्शनी में 39 शिल्पकारों और उद्यमों को एक मंच पर आने का मौका मिला, जिन्हें बैंक द्वारा पूर्व में मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं प्रदान की गई हैं। एक्जिम बाजार में 5000 से ज्यादा लोग आए और प्रतिभागियों को अपने उत्पादों की हाथों-हाथ बिक्री के साथ-साथ अग्रिम ऑर्डर भी मिले।



म्यांमार और कंबोडिया में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर केंद्रित एक्जिम बैंक के मार्केट आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ।



व्यवसाय परिचालन
एक्जिम बैंक का संस्थागत ढांचा

मानव संसाधन प्रबंधन

यथा 31 मार्च, 2018 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या 340 थी, जिनमें प्रबंधन स्नातक, सनदी लेखाकार, बैंकर, अर्थशास्त्री, विधि, पुस्तकालय एवं प्रलेखीकरण विशेषज्ञ, इंजीनियर, भाषा विशेषज्ञ, मानव संसाधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल हैं। 290 प्रोफेशनल स्टाफ सदस्यों की सहायता कुशल और प्रतिबद्ध प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाती है। बैंक एक 'लर्निंग संस्था' है, जो अपने अधिकारियों के कौशल का निरंतर उन्नयन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के विशिष्ट पोर्टफोलियो संभालने के लिए उनके कौशल विकास के उद्देश्य से विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों के लिए नामित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के 203 अधिकारियों ने बैंक परिचालनों से संबंधित विविध विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भाग लिया। इन कार्यक्रमों में कार्यशील पूँजी प्रबंधन एवं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, प्रोजेक्ट प्लानिंग, परियोजना निगरानी एवं नियंत्रण प्रणाली, व्यापार वित्त, ऋण जोखिम, संप्रेषण कौशल, सांगठनिक कौशल, सूचना सुरक्षा और नेतृत्व विकास आदि शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आयोजित 30 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 60 प्रतिशत अधिकारियों को नामित किया गया था। वित्तीय मॉडलिंग, व्यवसाय आचार-व्यवहार, भारतीय लेखांकन मानकों पर प्रशिक्षण, फ्रेंच और स्पैनिश जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण, उन्नत सांख्यिकी और व्यवसाय हेतु इकॉनॉमेट्रिक्स तथा प्रभावी संप्रेषण कौशल जैसे विषयों पर छह सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

यथा 31 मार्च, 2018 को बैंक की सेवा में कुल 340 स्टाफ सदस्यों में से 34 अनुसूचित जाति, 23 अनुसूचित



बैंक में आयोजित हिन्दी परखाड़े के दौरान टीवी और फिल्म अभिनेत्री सुश्री रेणुका शहाणे ने स्टाफ सदस्यों को संबोधित किया।

जन-जाति और 50 अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से हैं। बैंक ने इन स्टाफ सदस्यों को सूचना प्रौद्योगिकी सहित प्रभावी प्रस्तुति, नेतृत्व, संप्रेषण एवं भाषा कौशल जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया है। बैंक ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना जारी रखा है। साथ ही बैंक कर्लिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ओडिशा; भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली; दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के आरक्षित श्रेणी के छात्रों को के लिए भी छात्रवृत्ति प्रदान करता है। बैंक द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के छात्रों पर ध्यान केंद्रित के लिए नागालैंड विश्वविद्यालय; नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मेघालय; त्रिपुरा विश्वविद्यालय और सिक्किम विश्वविद्यालय में भी नई छात्रवृत्तियां शुरू की गई हैं।

“महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013” के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति

इस अधिनियम के अनुपालन में बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाओं की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है जिसमें एक बाहरी सदस्य है। बैंक अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है और इसके लिए अपने कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य-स्थल प्रदान करता है। समिति की नियमित बैठकें हुई हैं और बैंक के सभी कार्यालयों के सभी कर्मचारियों के लिए इस संबंध में जागरूकता सत्रों का आयोजन भी किया गया है। बैंक के सभी कर्मचारियों ने इस अधिनियम के लिए बैंक द्वारा कार्यान्वित नीति को पढ़ लिया है और वे इससे जागरूक हैं।

ट्रेजरी

बैंक की एकीकृत ट्रेजरी अतिरिक्त निधियों के निवेश,



राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण के जरिए अफ्रीका में छह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए 1.22 बिलियन यूएस डॉलर के ऋण पुष्टि स्टेटमेंट्स पर हस्ताक्षर।



टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई के साथ मिलकर वर्ष के दौरान बैंक में स्कदान शिविर लगाए गए।

मुद्रा बाजार, फॉरेक्स परिचालनों तथा सिक्क्यूरिटीज की खरीद-बिक्री सहित निधि प्रबंधन का कार्य देखती है। बैंक ने फ्रंट, मिडल तथा बैंक ऑफिस कार्यों को अलग किया है और एक आधुनिकतम डीलिंग रूम स्थापित किया है। बैंक की ट्रेजरी अपने उधारकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे विदेशी मुद्रा विनिमय सौदे, निर्यात दस्तावेजों की वसूली/परक्रामण, अंतरदेशीय/विदेशी साख-पत्र/गारंटियां तथा संरचित ऋण आदि प्रदान करती है। बैंक अपने बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से न्यून लागत पर निधियां जुटाने और तुलन पत्र एक्सपोजर की हेजिंग के लिए वित्तीय व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) संव्यवहारों का उपयोग करता है। बैंक भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इंफिनेट) का एक सदस्य है तथा इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी से रजिस्ट्रेशन ऑथरिटी भी प्राप्त है। बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग सेगमेंट (एनडीएस-ओएम) के माध्यम से सौदा करने के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त है। एनडीएस-ओएम भारत सरकार की प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का एक मंच प्रदान करता है। बैंक की प्रतिभूतियां तथा विदेशी मुद्रा लेन-देन मुख्यतः भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा प्रदान की गई गारंटी निपटान सुविधा के जरिए किए जाते हैं। बैंक सीसीआईएल के दायित्व खंड (सीबीएलओ) का भी एक सक्रिय सदस्य है। बैंक सीसीआईएल के रेपो डीलिंग सिस्टम, क्लियर कॉर्प ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस) का भी सदस्य है। यह सीसीआईएल द्वारा शुरू किया गया प्रत्यक्ष ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म है, जो सभी प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों की मार्केट रेपो में खरीद बिक्री में T+0/T+1 आधार पर सहायता प्रदान करता है। सीसीआईएल सभी सीआरओएमएस व्यापारों की केंद्रीय काउंटरपार्टी के रूप काम करती है और उसके द्वारा सभी निपटानों की गारंटी दी जाती है। बैंक ने लंदन शाखा से कनेक्टिविटी के साथ केन्द्रीकृत स्विफ्ट सुविधा कार्यान्वित की है जो 'मल्टिपल बैंक आइडेंटिफायर कोड्स' को संभालने में सक्षम है।



एक्जिम बैंक ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखा है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक कार्यक्रम को लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य-योजना के जरिए कार्यान्वित किया गया। इस संबंध में बैंक के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने राजभाषा कार्यान्वयन में प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की।

अधिकारियों को हिन्दी सीखने और दैनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक में प्रोत्साहन योजना लागू है। बैंक की गृह पत्रिका 'एक्जिमिअस' में हिन्दी खंड भी है। हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में एक्जिमिअस का एक अंक राजभाषा विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया जाता है। अधिकारियों को हिन्दी में अपनी रचनाएं देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को पुरस्कृत किया जाता है।

बैंक ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में सक्रियता से हिस्सा लिया और अपने अधिकारियों को अंतर बैंक हिन्दी प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। अधिकारियों की हिन्दी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को चिह्नित किया गया और उन्हें हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान तथा प्रवीणता प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया। यूनिकोड के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया और अधिकारियों को कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करने के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयरों/सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, बैंक में सितंबर 2017 में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। जनवरी 2018 में विश्व हिन्दी दिवस भी मनाया गया।

बैंक की वेबसाइट और एक्जिम मित्र पोर्टल दोनों हिन्दी और अंग्रेजी में हैं।



यूरोपियन बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष सर सुमा चक्रवर्ती बैंक आर शिष्टाचार भेंट की।

बैंकों के परिचालन और प्रक्रिया साहित्य के अलावा, बैंक के तिमाही प्रकाशन 'एक्जिमिअस एक्सपोर्ट एडवांटेज' के सभी अंकों का हिन्दी रूपांतरण 'एक्जिमिअस निर्यात लाभ' शीर्षक से प्रकाशित किया गया। बैंक के द्विमासिक प्रकाशन 'एग्री एक्सपोर्ट एडवांटेज' के सभी अंकों का हिन्दी रूपांतरण 'कृषि निर्यात लाभ' शीर्षक से प्रकाशित किया गया। हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त इसका प्रकाशन 10 अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया जाता है।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग विषयक भारत सरकार की नीति के अनुसार, बैंक के पुस्तकालय को विदेश व्यापार, वाणिज्य, वित्तपोषण, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य विषयों पर नई पुस्तकों से समृद्ध बनाया गया।

कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए हिन्दी के प्रयोग को तेजी से बढ़ाने के बैंक के प्रयासों को विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा सराहा गया:

- बंगलूरु, हैदराबाद और कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालयों को राजभाषा हिन्दी में सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित अपनी-अपनी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा पुरस्कृत किया गया।
- बैंक की गृह पत्रिका 'एक्जिमिअस' को 32 प्रतिभागी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में द्विभाषिक गृह पत्रिका श्रेणी में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रथम पुरस्कार मिला।

सूचना प्रौद्योगिकी

विभिन्न घटकों के बीच सूचना के बेहतर प्रसार और प्रयोक्ता तथा प्रणाली क्षमताओं को मजबूत करने के लिए बैंक ने ज्ञान प्रबंधन, संचार उपकरणों को उन्नत करना जारी रखा है। कोर बैंकिंग सिस्टम, व्यवसाय आसूचना, डिजिटल प्रलेखन प्रबंधन एवं ऑटोमैटिक कार्य प्रवाह; परिचालन व्यवसाय आसूचना, बैंक व्यापी सिस्टम; प्रलेखन प्रबंधन एवं कार्य प्रवाह; नेटवर्क; ढांचागत सुविधा तथा सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रणालियों को सक्षम बनाया गया है तथा उनका उन्नयन किया गया है।



एफकोंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा घाना में निष्पादित की जा रही 84 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के डिजाइन और निर्माण के लिए बैंक के क्रेता ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजना।

बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपने परिचालन और प्रक्रियाओं को मजबूत किया है। बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट (www.eximbankindia.in) पर बैंक द्वारा किए गए विभिन्न शोध कार्यकलापों, व्यवसाय अवसरों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार अवसरों संबंधी सूचनाओं को व्यवस्थित तरीके से प्रसारित करना जारी रखा गया।

बैंक ने व्यवसाय की बढ़ती जरूरतों के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना और अपने सभी कार्यालयों में नेटवर्क, डाटा सेंटर, कंप्यूटिंग तथा अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों का उन्नयन करना जारी रखा है। बैंक ने कार्यक्षमता और आउटपुट में सुधार के लिए कार्रवाई आधारित विभिन्न अलर्टों तथा रियल टाइम रिपोर्टिंग का कार्यान्वयन किया है। बैंक, भारतीय बैंकिंग उद्योग में ब्लॉक चेन आधारित प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन की व्यवहार्यता परखने के लिए भारतीय बैंकों की फोरम, बैंक चेन के पहले सदस्यों में से एक बन गया है।

कॉर्पोरेट सुशासन

एक्जिम बैंक अपने सभी प्रकार के संप्रेषणों के संबंध में पूरी पारदर्शिता तथा सत्यनिष्ठा बरतता है और सभी संबंधी पार्टियों को पूर्ण, सही और स्पष्ट सूचना प्रदान करता है। बैंक अपने लिए कॉर्पोरेट सुशासन की उत्कृष्ट पद्धतियों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके लिए सदैव तत्पर रहता है, जो बैंक के लिए प्रासंगिक हैं। इस पर समुचित नियंत्रण के लिए बैंक ने एक व्यवस्था विकसित की है तथा इसकी उपादेयता की निरंतर समीक्षा करता रहता है। व्यवसाय/वित्तीय निष्पादन से संबंधित मामले, विश्लेषण आंकड़े/सूचना आदि को निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसी) को समीक्षा के लिए आवधिक आधार पर रिपोर्ट किया जाता है। सभी कानूनों, विनियमों तथा अन्य प्रक्रियाओं, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य विनियमों के पालन के संबंध में बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक अनुपालन नीति है और एक वरिष्ठ अधिकारी को अनुपालन अधिकारी के रूप में उत्तरदायी बनाया गया है, जो किसी भी प्रकार के विचलन को लेखा परीक्षा समिति (एसी) को रिपोर्ट करता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की छह बैठकें तथा प्रबंधन समिति की सात बैठकें आयोजित की गईं।

लेखा परीक्षा समिति

बैंक की लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्यों की देख-रेख करना तथा उसे मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि प्रबंधन के एक माध्यम के रूप में उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि हो और वह सांविधिक/बाहरी/आंतरिक/संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करे। निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरणों की जांच लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है। इसके साथ ही लेखा परीक्षा समिति आवधिक आधार पर बैंक की निधि प्रबंधन समिति तथा आस्ति-देयता समिति की कार्यपद्धति की भी समीक्षा करती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की सात बैठकें हुईं।

आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के मिड-ऑफिस के सहयोग से बाजार जोखिम की निगरानी और प्रबंधन का कार्य देखती है। एल्को द्वारा लिक्विडिटी / ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक एएलएम/लिक्विडिटी नीतियों के अनुसार किया जाता है। एल्को की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक/बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं की तुलना में बैंक की मुद्रा-वार संरचनात्मक नकदी तथा ब्याज दर संवेदनशीलता की स्थितियों की समीक्षा करना, नकदी प्रवाहों के आवधिक दबाव परीक्षणों के परिणामों की निगरानी करना और ब्याज दर जोखिम के आधार पर एक उपयुक्त एएलएम रणनीति तैयार करना शामिल है। ब्याज दर जोखिम को ब्याज दर में उतार-चढ़ाव की तुलना में अवधि अंतराल (ड्यूरेशन-गैप) विश्लेषण के जरिए (क) निवल ब्याज आय



एक्जिज बैंक ने श्रीलंका सरकार को 318 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की।

की संवेदनशीलता के विश्लेषण और (ख) आर्थिक मूल्य की संवेदनशीलता से मापा जाता है। मुद्रा-वार नकदी स्थिति के दबाव परीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं और मुद्राओं की उपलब्धता में कमी का आकलन करने के लिए समय-समय पर एक आकस्मिक फंडिंग योजना बनाई जाती है। जोखिम पर मूल्य की गणना, भारत सरकार की प्रतिभूतियों के बैंक की ट्रेडिंग के लिए रोके गए तथा बिक्री के लिए उपलब्ध पोर्टफोलियो के लिए की जाती है। निधि प्रबंधन समिति (एफएमसी) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में बोर्ड द्वारा अनुमोदित और वर्ष के दौरान समीक्षित निधि प्रबंधन / संसाधन योजना के अनुसार निवेशों / विनिवेशों तथा संसाधन जुटाने पर निर्णय लेती है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति एल्को/एफएमसी की कार्यपद्धति की समय-समय पर समीक्षा करती है।

जोखिम प्रबंधन

बैंक में एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति (आईआरएमसी) गठित की गई है, जो परिचालन समूहों से स्वतंत्र है और यह सीधे शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करती है। आईआरएमसी विभिन्न जोखिमों (पोर्टफोलियो, लिक्विडिटी, ब्याज दर, ऑफ-बैलेंस शीट और परिचालनगत जोखिमों) के संबंध में बैंक की स्थिति की समीक्षा करती है। साथ ही एल्को, एफएमसी और ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) के परिचालनों की देखरेख भी करती है, जिनमें से सभी के क्रॉस-फंक्शनल प्रतिनिधित्व होते हैं।

जहां आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक में आस्ति-देयता प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों को देखती है और बैंक के समग्र बाजार जोखिम (चलनिधि, ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम) का विश्लेषण करती है, वहीं ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), ऋण-नीति और प्रक्रियाओं की देखरेख करती है और बैंक के ऋण जोखिमों का विश्लेषण, प्रबंधन तथा नियंत्रण करती है। बैंक के पास एक उन्नत ऋण जोखिम प्रबंधन



एक्जिज बैंक ने यूएई में अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर नए मिडफील्ड टर्मिनल कॉम्प्लेक्स के लिए एयर साइड निर्माण कार्यों हेतु लार्सेन एंड टुब्रो लिमिटेड को सहयोग प्रदान किया।



विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर ख्यात हिन्दी लेखक और के. के. बिरला फाउंडेशन के निदेशक श्री सुरेश ऋतुपर्ण ने स्टाफ सदस्यों को संबोधित किया।

मॉडल (सीआरएम) है, जिससे (गुणवत्ता तथा मात्रात्मक पैरामीटरों/उपायों की व्यापक श्रेणी के जरिए) बैंक को बेहतर ऋण मूल्यांकन निर्णय लेने और उत्कृष्ट पोर्टफोलियो प्रबंधन क्षमता को बनाए रखने में मदद मिलती है। संबंधित प्रस्तावों के लिए ऋण अधिकारियों द्वारा दी गई रेटिंग की समीक्षा स्वतंत्र रूप से एक रेटिंग समिति द्वारा की जाती है।

बैंक व्यवसाय निरंतरता और अपने सभी कार्यालयों की डिजास्टर रिकवरी योजनाओं की वार्षिक समीक्षा भी करता है। जोखिमों के प्रभाव से बचने के लिए प्रत्येक योजना की भली-भांति जांच की जाती है कि ये योजनाएं संकट की स्थिति में व्यवसाय निरंतरता बनाए रखने के लिए कितनी कारगर हैं और जोखिम से सुरक्षा के उपाय कैसे हैं।

ऋण प्रशासन

दबावग्रस्त ऋण खातों की बेहतर निगरानी तथा अनर्जक आस्तियों की रिकवरी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक में अलग से एक समूह कार्यरत है, ऋण प्रशासन समूह। यह समूह बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण निगरानी और वर्तमान नियामकीय तंत्र पर आधारित वसूली नीति के अनुसार ऋण वसूली के लिए सक्रिय कदम उठाता है और मानक आस्तियों को अनर्जक आस्ति होने से रोकने सहित ऐसी अनर्जक आस्तियों को अर्जक बनाने का काम करता है, जिन्हें अर्जक आस्ति की श्रेणी में लाना व्यवहार्य है। साथ ही ऐसे अनर्जक खातों से वसूली पर भी फोकस करता है, जहां कानूनी कार्रवाई की जानी है। बैंक में अलग-अलग समितियों द्वारा अतिदेय व अनर्जक आस्तियों की मासिक समीक्षा की जाती है।

पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान बैंकिंग क्षेत्र को अधिक स्लिपेज और आस्ति गुणवत्ता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बैंक, अनर्जक आस्तियों की वसूली को पहली प्राथमिकता देता है और अनर्जक आस्तियों के समाधान के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाता है। इनमें कानूनी कार्रवाई, अदालती आदेश के जरिए आस्तियों की बिक्री, निगोशिएशन, एकबारगी निपटान, सरफेसी अधिनियम के



एक्जिम बैंक को गृह पत्रिका 'एक्जिमिअस' के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पुरस्कार मिला।

प्रावधानों के अंतर्गत आस्तियों पर कब्जा और फिर उनकी बिक्री तथा दूसरी पार्टियों को कर्ज का हस्तांतरण / समनुदेशन शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देशों के आने और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता 2016 (आईबीसी) लागू होने के बाद से ही भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण देखा जा रहा है। अब वसूली का पुराना दृष्टिकोण, दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के नए दृष्टिकोण में बदल गया है। बैंकिंग क्षेत्र का फोकस दबावग्रस्त आस्तियों के पूर्व समाधान पर है। बैंक का यह समूह आईबीसी के अंतर्गत सक्रियता से केस संभाल रहा है और संशोधित नियामकीय तंत्र में परिचालनों के लिए सक्षम है।

बैंक में केवाईसी, एएमएल और पीएमएल उपाय

बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों, धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक और आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति है। केवाईसी, एएमएल तथा सीएफटी नीति में शामिल हैं -

- (क) ग्राहक स्वीकार्यता नीति
- (ख) जोखिम प्रबंधन
- (ग) ग्राहक पहचान प्रक्रिया,
- (घ) संव्यवहारों की निगरानी

बैंक द्वारा बैंकों के एक्युटी डेटाबेस को भी एक्सेस किया जाता है जो विश्व के प्रमुख बिजनेस पब्लिशर्स, रीड बिजनेस इंफोर्मेशन, जो रीड एल्सीवियर समूह की इकाई है, की एक ऑनलाइन डेटाबेस सेवा है। यह बैंकों के लिए अनुपालन डेटाबेस है। एक्युटी की ग्लोबल वॉचलिस्ट काफी व्यापक है और इसमें विश्व के सभी प्रमुख मंजूरकर्ता निकायों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वित्तीय नियामकों की चेतावनी सूचियों के संग्रह का समावेश है। बैंक के सभी ग्राहकों को केवाईसी मानकों के अधीन लाया जाता है। इससे स्वाभाविक व्यक्ति/कानूनी व्यक्ति तथा 'हिताधिकारी स्वामित्व' की

पहचान में मदद मिलती है। केवाईसी नीतियां तथा प्रक्रियाएं सावधि जमा खाता धारकों, प्रतिनिधि बैंकों, नए स्टाफ की भर्ती तथा ट्रेजरी संव्यवहारों से संबंधित प्रतिपक्षी पार्टियों पर भी लागू की जाती हैं। केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के संबंध में बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय व्यवहार के अनुरूप वोल्फ्सबर्ग ग्रुप एएमएल प्रशावली के माध्यम से अन्य बैंकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है। बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं तथा तरीकों के अनुसार कतिपय संव्यवहारों के बारे में रिकार्ड/सूचना भी रखता है तथा यह रिकार्ड, संव्यवहार की तारीख से दस वर्षों तक सुरक्षित रखे जाते हैं। बैंक ने केवाईसी, एएमएल तथा सीएफटी के उपायों के लिए एक मुख्य अधिकारी को नियुक्त किया है। केवाईसी, एएमएल तथा सीएफटी नीति को बैंक की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

ऋणदाताओं के लिए आचार संहिता

बैंक में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ऋणदाताओं के लिए उचित आचार संहिता के संबंध में नीति विद्यमान है, जो निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। इस नीति की समीक्षा प्रत्येक वर्ष की जाती है।

पर्यावरणीय, सामाजिक और सुशासन (ईएसजी) फ्रेमवर्क

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन नीति लागू है। एक्विजि बैंक, बैंकों के लिए संपोषी फ्रेमवर्क पर भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की अगुआई वाले मंच का भी सदस्य है। आईबीए ने दिशानिर्देशों के सिद्धांत 2 अर्थात् ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया में ईएसजी आधारित जोखिम विश्लेषण को शामिल करने के साथ-साथ सिद्धांत 4 अर्थात् ग्रीन फायनेंस के नए तरीकों का इस्तेमाल करते हुए हरित निवेश की दिशा में आगे बढ़ने के एक्विजि बैंक के प्रयासों की सराहना की है।

बैंक अपने विभिन्न वित्तपोषण कार्यक्रमों के जरिए भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपोषी बैंकिंग को बढ़ावा दे रहा है। बैंक अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, कचरा प्रबंधन, जन परिवहन



एक्विजि बैंक के अधिकारियों ने मुंबई स्थित वकील और पर्यावरणविद अफरोज शाह के वसोंवा बीच सफाई अभियान में सहयोग का हाथ बढ़ाया।

और कम उर्जा की खपत करने वाले परिवहन जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं का वित्तपोषण कर रहा है। बैंक अपनी ग्रिड पहलों के जरिए समावेशी विकास को भी बढ़ावा दे रहा है।

बैंक ईएसजी संबंधी मानकों के लिए अपने आंतरिक परिचालनों की भी समीक्षा कर रहा है। बैंक ने ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल ऑडिट के साथ-साथ अन्य उपाय भी किए हैं। बैंक बैठकों की कार्यसूची ऑनलाइन भेजने के साथ-साथ ई-ग्रीटिंग; और विभिन्न अवसरों एवं समारोहों के लिए ई-आमंत्रण पत्रों के माध्यम से कागज के प्रयोग को घटा रहा है। वीडियो / टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोग से कार्बन फुटप्रिंट कम करने में भी मदद मिली है। बैंक ने अपने स्टाफ सदस्यों को प्रदान किए आवासों की आवासीय सोसायटियों में पौधारोपण अभियान चलाकर अपने 'गो ग्रीन' प्रयासों को बढ़ावा दिया है। कार्यक्रमों में पुष्पगुच्छ प्रदान करने के विकल्प के रूप में बैंक ने प्राप्तकर्ता के नाम से सामाजिक कार्यों (जैसे अक्षय पात्र) के लिए योगदान प्रमाण पत्र देना शुरू किया है। गैर-लाभकारी संगठन अक्षय पात्र फाउंडेशन सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मील योजना चलाते हुए भारत में भूख और कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए प्रयासरत है।

बैंक के स्टाफ ने मुंबई स्थित श्री अफरोज शाह के साथ मिलकर वसोंवा बीच सफाई अभियान में हिस्सा लिया, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम: द चैंपियन ऑफ अर्थ अवॉर्ड 2016 पाने वाले पहले भारतीय हैं। बैंक ने वसोंवा बीच सफाई अभियान जारी रखा है और बैंक के स्टाफ सदस्य अपने परिजनों के साथ इसमें हिस्सा लेते हैं।

बैंक अपने अभियानों, नए घटनाक्रमों और उपलब्धियों से अपने ग्राहकों को अवगत कराने के लिए अन्य के साथ-साथ सोशल मीडिया का सदुपयोग भी करता है। ये प्लेटफॉर्म विभिन्न पक्षों को अपना फीडबैक प्रदान करने और बैंक तक सीधे पहुंच बनाने का जरिया भी हैं। बैंक में व्हिसलब्लोअर नीति; महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न: निवारण,



प्रतिषेध और प्रतितोष नीति, उधारकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र और ऋणदाता की देयता के लिए उचित व्यवहार संहिता जैसी विभिन्न नीतियां हैं।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित अनुसार एक्जिम बैंक एक लोक प्राधिकरण है और इस अधिनियम का अनुपालन करता है। अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय नागरिक सूचना प्राप्त करने के लिए बैंक के लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारियों को अपने आवेदन भेज सकते हैं। इनके पते बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

संयुक्त उद्यम

भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा स्थापित ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टेंट्स लि. (जीपीसीएल) एक्जिम बैंक तथा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली 11 अन्य प्रतिष्ठित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच एक संयुक्त उपक्रम है जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। जीपीसीएल एक नवोन्मेषी संकल्पना थी जिसकी स्थापना कृषि, ऊर्जा, उद्योग, खनन, परिवहन, जल संसाधन आदि क्षेत्रों से जुड़ी अग्रणी कंपनियों की भागीदारी में की गई थी। जीपीसीएल ने गत वर्ष अपनी प्रोक्योरमेंट सेवा संबंधी कार्यों के दायरे को बढ़ाया है जिनमें बोली परामर्श, प्रोक्योरमेंट प्रशिक्षण, ई-प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन परियोजना की पहचान करना, पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन, रिपोर्टों को तैयार और उनकी समीक्षा करना, ऋणदाता इंजीनियर के रूप में काम करना, परियोजना का ड्यू

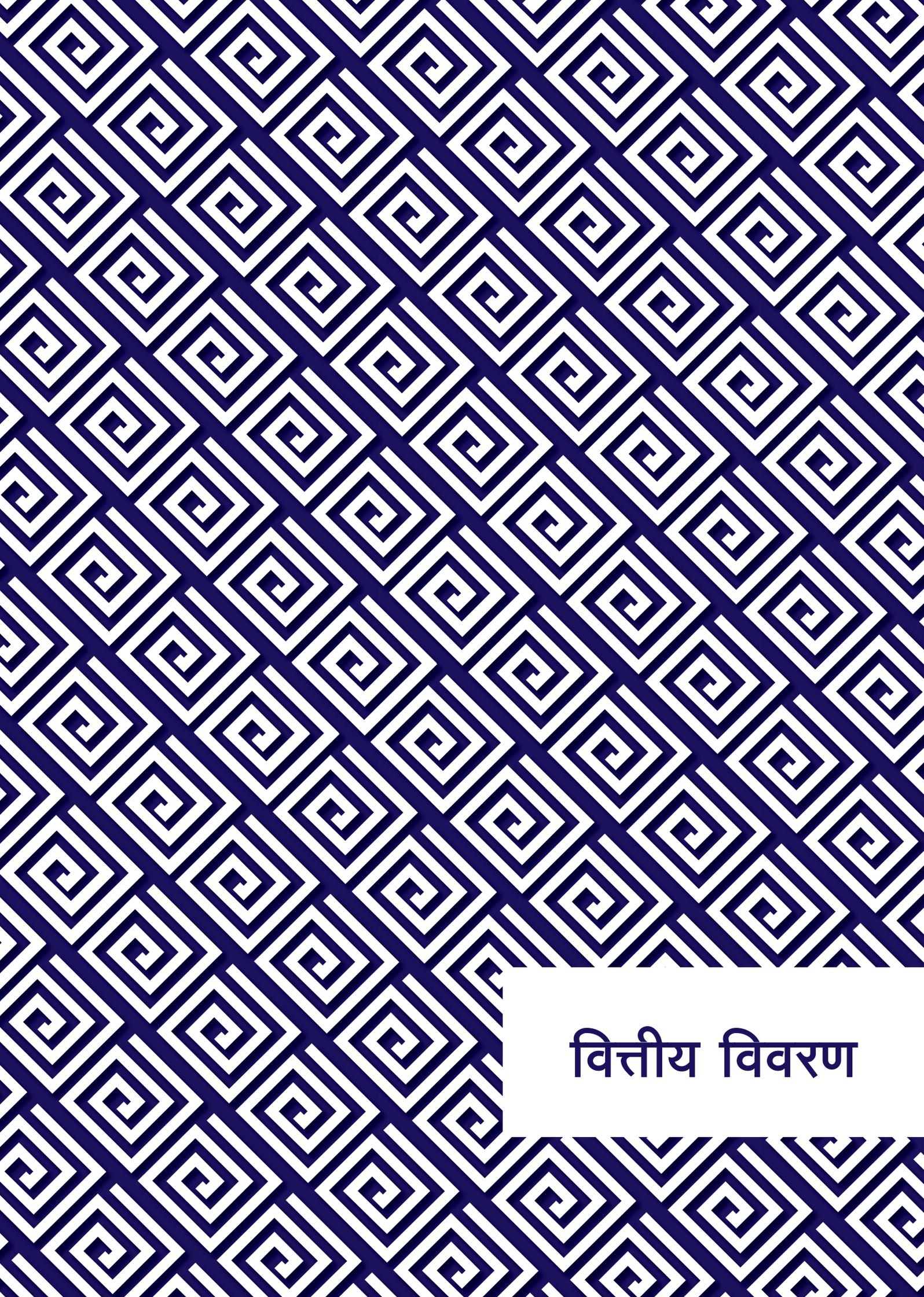
डिलीजेंस करना, परियोजना की निगरानी करना, मूल्यांकन, क्षमता निर्माण तथा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ऋण एजेंसियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना शामिल है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 15.02 मिलियन के कर पूर्व लाभ के साथ ₹ 50.38 मिलियन की आय दर्ज की है।

बैंक ने अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आईएल एंड एफएस, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और अफ्रीकी विकास बैंक (एफडीबी) के साथ मिलकर एक परियोजना विकास कंपनी स्थापित की है। कुकुजा पीडीसी की प्रारंभिक पूंजी 25 मिलियन यूएस डॉलर है और इस पूंजी में बैंक का हिस्सा 4.88 मिलियन यूएस डॉलर का है। कंपनी मॉरीशस में रजिस्टर्ड है और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान इसका परिचालन शुरू हुआ है।

कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम (सीएलएमवी) में भारतीय निवेशों को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के परामर्श से परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) का फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस पहल के अंतर्गत, कंबोडिया और म्यांमार में स्वास्थ्य सेवा, म्यांमार में शिक्षा और वियतनाम में फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में चार परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है, जिनके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के निष्कर्षों के आधार पर पीडीएफ सीएलएमवी पहल के अंतर्गत विशेष निधियां (स्पेशल पर्पज व्हीकल) स्थापित कर संबंधित देशों में चुनिंदा परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा।



एशियाई एक्जिम बैंक फोरम की 23वीं वार्षिक बैठक सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई।



वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

- हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') की सामान्य निधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2018 को तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि लेखे तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक आंकड़े शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन उत्तरदायित्व

- बैंक प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 ('अधिनियम') तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस जिम्मेवारी में बैंक की आस्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं से बचने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित लेखा अभिलेख रखने; उचित लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; उचित एवं तार्किक आकलन पद्धति अपनाने; तथा उसकी डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आवश्यक आंतरिक नियंत्रण शामिल है ताकि वित्तीय विवरण तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने हेतु उपयुक्त लेखा रिकॉर्डों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि लेखा रिकॉर्ड धोखाधड़ी अथवा भूलवश आई गलत सूचनाओं से रहित सत्य और न्यायसंगत स्थिति बताते हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेवारी

- हमारी जिम्मेवारी इन वित्तीय विवरणों के बारे में हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।
- हमने यह लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन

मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार निष्पादित और नियोजित करें ताकि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण सूचना गलत नहीं है।

- लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है। इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पूर्णतया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है जिसमें महत्वपूर्ण विवरणों के संबंध में भूल अथवा धोखाधड़ी के चलते भ्रामक मिथ्याकथन जोखिमों का आकलन करना शामिल है। इन जोखिमों के मूल्यांकन के संबंध में लेखा परीक्षकों के विचार से इन विवरणों को त्रुटिरहित ढंग से तैयार करने में बैंक के आंतरिक नियंत्रणों तथा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों एवं बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।
- हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य पर्याप्त और समुचित हैं तथा हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए तर्क संगत आधार प्रदान करते हैं।

अभिमत

- हमारी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखा विवरण, अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं तथा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा मानकों के अनुरूप सच्ची और सही स्थिति प्रदर्शित करते हैं:
 - यथा 31 मार्च, 2018 को बैंक की सामान्य निधि के तुलन-पत्र के मामले में;
 - यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा के मामले में;
 - 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणों के मामले में।

अन्य विधिक तथा विनियामक मामलों पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।
9. हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (i) लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।
 - (ii) बैंक के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, बैंक की शक्तियों के अन्दर हैं।
10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरणी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं।
11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (i) इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा बैंक की लेखा बहियों और विवरणियों के अनुरूप हैं।
 - (ii) हमारे विचार में और हमारे परीक्षण के आधार पर बैंक द्वारा विधि निर्धारित अनुसार इन बहियों का उचित अभिलेख रखा गया है।

कृते सोराब एस. इंजीनियर एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 110417डब्ल्यू

सीए एन. डी. अंकलेसरिया
पार्टनर
सदस्यता सं-10250
मुंबई, 18 मई, 2018

तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2018 को

		सामान्य निधि	
		इस वर्ष (यथा 31.03.2018 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2017 को) ₹
देयताएं	अनुसूचियां		
1. पूँजी	I	73,593,663,881	68,593,663,881
2. आरक्षित निधियां	II	22,407,896,155	51,645,199,126
3. लाभ और हानि खाता	III	-	41,300,000
4. नोट, बॉन्ड एवं डिबेंचर		865,817,469,885	806,929,554,112
5. देय बिल		-	-
6. जमा राशियां	IV	2,860,514,358	3,726,434,552
7. उधार राशियां	V	172,972,652,705	150,072,777,722
8. चालू देयताएं एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		57,705,066,214	46,637,552,503
9. अन्य देयताएं		39,832,319,272	44,427,210,251
योग		1,235,189,582,470	1,172,073,692,147
आस्तियां			
1. नकदी एवं बैंक शेष	VI	28,154,996,173	36,908,866,611
2. निवेश	VII	56,969,220,517	51,029,294,879
3. ऋण एवं अग्रिम	VIII	1,046,570,568,346	1,017,159,983,605
4. भुनाये गये/पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन पत्र	IX	28,750,000,000	9,250,000,000
5. अचल आस्तियां	X	1,259,022,689	1,298,367,915
6. अन्य आस्तियां	XI	73,485,774,745	56,427,179,137
योग		1,235,189,582,470	1,172,073,692,147
आकस्मिक देयताएं			
i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांजन तथा अन्य दायित्व		116,927,666,502	78,177,713,070
ii) वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर		2,929,986,250	3,573,212,731
iii) हामीदारी वचनबद्धताओं पर		-	-
iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं		163,491,675	152,677,850
v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		2,305,300,000	1,971,000,000
vi) संग्रहण के लिए बिल		-	-
vii) सहभागिता प्रमाण-पत्रों पर		-	-
viii) भुनाये गये/पुनः भुनाए गए बिल		-	-
ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है		15,771,727,879	47,274,958,286
योग		138,098,172,306	131,149,561,937

‘लेखों पर टिप्पणियां’ संलग्न हैं।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

श्री देबाशिस मल्लिक
उप प्रबंध निदेशक

श्री टी. एस. तिरुमूर्ति

श्री राजीव ऋषि

श्री डेविड रस्कीना
प्रबंध निदेशक

श्री पंकज जैन

श्रीमती गीता मुरलीधर

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सोराब एस. इंजीनियर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 110417डब्ल्यू

(सीए एन. डी. अंक्लेसरिया)

पार्टनर

एम. सं. 010250

श्री रजनीश कुमार

लाभ और हानि लेखा यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

सामान्य निधि

व्यय	अनुसूचियां	इस वर्ष ₹	गत वर्ष ₹
1. ब्याज		65,862,992,191	65,022,307,778
2. ऋण बीमा, शुल्क एवं प्रभार		540,074,685	628,067,389
3. स्टाफ़ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		488,732,271	563,929,962
4. निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय		-	-
5. लेखा परीक्षा की फीस		1,008,000	1,008,000
6. भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमिया		247,951,472	213,215,395
7. संचार विषयक व्यय		35,038,993	43,815,361
8. विधि विषयक व्यय		67,774,140	78,086,494
9. अन्य व्यय	XII	1,043,004,526	825,636,786
10. मूल्यहास		184,786,313	170,933,494
11. ऋण हानियों/आकस्मिकताओं, निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान		61,609,573,457	21,679,974,939
12. नीचे ले जाया गया लाभ/(हानि)		(42,298,164,654)	3,126,382,006
योग		87,782,771,394	92,353,357,604
आयकर के लिए प्रावधान [आस्थगित कर राशि ₹ 14,706,937,458 सहित (गत वर्ष आस्थगित कर राशि ₹ 4,052,096,329)]		(13,060,861,683)	2,714,263,830
तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ/(हानि)		(29,237,302,971)	412,118,176
		(42,298,164,654)	3,126,382,006
आय			
1. ब्याज और बट्टा	XIII	82,383,628,713	84,410,889,852
2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस		3,849,952,278	4,687,969,751
3. अन्य आय	XIV	1,549,190,403	3,254,498,001
योग		87,782,771,394	92,353,357,604
नीचे लाया गया लाभ/(हानि)		(42,298,164,654)	3,126,382,006
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज-कर प्रावधान का प्रतिलेखन		-	-
		(42,298,164,654)	3,126,382,006

'लेखों पर टिप्पणियां' संलग्न हैं।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

श्री देबाशिस मल्लिक
उप प्रबंध निदेशक

श्री टी. एस. तिरुमूर्ति

श्री राजीव ऋषि

श्री डेविड रस्कीना
प्रबंध निदेशक

श्री पंकज जैन

श्रीमती गीता मुरलीधर

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सोराब एस. इंजीनियर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 110417डब्ल्यू

(सीए एन. डी. अंकलेसरिया)

पार्टनर

एम. सं. 010250

श्री रजनीश कुमार

तुलन-पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2018 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2017 को) ₹
अनुसूची I: पूँजी:		
1. प्राधिकृत	100,000,000,000	100,000,000,000
2. निर्गमित एवं प्रदत्त: (केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	73,593,663,881	68,593,663,881
अनुसूची II: आरक्षित निधियां:		
1. आरक्षित निधि	6,812,577,091	36,049,880,062
2. सामान्य आरक्षित राशियां	-	-
3. अन्य आरक्षित राशियां: निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि	-	-
ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाएं)	1,955,319,064	1,955,319,064
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	13,640,000,000	13,640,000,000
	22,407,896,155	51,645,199,126
अनुसूची III: लाभ और हानि लेखा:		
1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखा के अनुसार शेष	(29,237,302,971)	412,118,176
2. घटाएं: विनियोजन:		
- आरक्षित निधि को अंतरित	(29,237,302,971)	370,818,176
- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित	-	-
- ऋण शोधन निधि को अंतरित	-	-
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	-	-
3. निवल लाभ का शेष (एक्ज़िम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23 (2) के अनुसार केंद्र सरकार को अंतरणीय)	-	41,300,000
अनुसूची IV: जमा राशियां:		
(क) भारत में	2,860,514,358	3,726,434,552
(ख) भारत के बाहर	-	-
	2,860,514,358	3,726,434,552

	इस वर्ष (यथा 31.03.2018 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2017 को) ₹
अनुसूची V: उधार राशियां:		
1. भारतीय रिज़र्व बैंक से:		
(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	-	-
(ख) विनिमय बिलों पर	-	-
(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	-	-
2. भारत सरकार से	-	-
3. अन्य स्रोतों से:		
(क) भारत में	30,464,595,133	27,626,427,635
(ख) भारत के बाहर	142,508,057,572	122,446,350,087
	172,972,652,705	150,072,777,722
अनुसूची VI: नकदी एवं बैंक में शेष:		
1. हाथ में नकदी	267,322	504,612
2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	1,062,376,412	242,081,708
3. अन्य बैंकों में शेष:		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	2,753,482,451	782,330,730
ii) अन्य जमा खातों में	265,000,000	265,000,000
(ख) भारत के बाहर	24,073,869,988	35,618,949,561
4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ सीबीएलओ के अंतर्गत ऋण	-	-
	28,154,996,173	36,908,866,611

	इस वर्ष (यथा 31.03.2018 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2017 को) ₹
अनुसूची VII: निवेश: (मूल्य में हास का निवल, यदि कोई है)		
1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	38,985,454,430	30,635,592,765
2. इक्विटी शेयर और स्टॉक	3,147,214,811	2,646,452,566
3. अधिमान शेयर एवं स्टॉक	259,796,800	23,234,000
4. नोट, डिबेंचर एवं बॉन्ड	14,076,754,476	17,224,015,548
5. अन्य	500,000,000	500,000,000
	56,969,220,517	51,029,294,879
अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम:		
1. विदेशी सरकारें	347,918,475,333	325,481,477,107
2. बैंक:		
(क) भारत में	183,265,470,679	145,670,664,885
(ख) भारत के बाहर	-	10,573,270
3. वित्तीय संस्थाएं:		
(क) भारत में	-	-
(ख) भारत के बाहर	31,726,150,308	29,630,693,336
4. अन्य	483,660,472,026	516,366,575,007
	1,046,570,568,346	1,017,159,983,605
अनुसूची IX: भुनाये गये/पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन-पत्र:		
(क) भारत में	28,750,000,000	9,250,000,000
(ख) भारत के बाहर	-	-
	28,750,000,000	9,250,000,000

अनुसूची X: अचल आस्तियां:
(लागत पर मूल्यहास घटाकर)

1. परिसर

सकल राशि (आगे लाया गया)	2,064,028,557	1,734,522,255
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	29,133,407	329,506,302
वर्ष के दौरान निपटान	1,661,130	-
वर्ष के अंत में सकल राशि	2,091,500,834	2,064,028,557
संचित हास	1,008,738,347	928,184,582
निवल राशि	1,082,762,487	1,135,843,975

2. अन्य

सकल राशि (आगे लाया गया)	1,013,059,162	896,880,632
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	121,392,454	135,003,614
वर्ष के दौरान निपटान	97,809,713	18,825,084
वर्ष के अंत में सकल राशि	1,036,641,903	1,013,059,162
संचित हास	860,381,701	850,535,222
निवल राशि	176,260,202	162,523,940

इस वर्ष
(यथा 31.03.2018 को)
₹

गत वर्ष
(यथा 31.03.2017 को)
₹

1,259,022,689

1,298,367,915

अनुसूची XI: अन्य आस्तियां:

1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज:

(क) निवेशों/बैंक जमाओं पर	11,120,355,964	10,791,054,440
(ख) ऋण एवं अग्रिम	15,936,763,898	14,151,386,600

2. विविध पक्षों के पास जमा राशियां

43,378,422	37,238,334
------------	------------

3. प्रदत्त अग्रिम आयकर (निवल)

7,095,229,016	7,930,845,159
---------------	---------------

4. अन्य [आस्थगित कर आस्तियों सहित
₹ 33,274,681,260
(गत वर्ष ₹ 18,567,743,802)]

39,290,047,445	23,516,654,604
----------------	----------------

73,485,774,745

56,427,179,137

अनुसूची XII: अन्य व्यय:

1. निर्यात संवर्द्धन व्यय

19,460,137	34,330,480
------------	------------

2. डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय

6,694,221	14,547,043
-----------	------------

3. मरम्मत और रखरखाव

208,816,959	197,215,272
-------------	-------------

4. मुद्रण और लेखन सामग्री

13,396,427	12,261,031
------------	------------

5. अन्य

794,636,782	567,282,960
-------------	-------------

1,043,004,526

825,636,786

	इस वर्ष (यथा 31.03.2018 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2017 को) ₹
अनुसूची XIII: ब्याज एवं बट्टा:		
1. ऋणों और अग्रिमों/बिलों की भुनाई/ पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा	53,302,677,483	54,462,592,775
2. निवेशों/बैंक शेष राशियों पर आय	29,080,951,230	29,948,297,077
	82,383,628,713	84,410,889,852
अनुसूची XIV: अन्य आय:		
1. निवेशों की बिक्री/पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ	1,520,032,565	3,108,552,970
2. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	18,042,191	944,930
3. अन्य	11,115,647	145,000,101
	1,549,190,403	3,254,498,001

टिप्पणी:

'देयताओं' [अनुसूची IV (क) देखिए] के अंतर्गत 34.92 मिलियन यूएस डॉलर की 'ऑन शोर' विदेशी मुद्रा जमा राशियां (गत वर्ष 39.66 मिलियन यूएस डॉलर) शामिल हैं जो प्रतिपक्षी पार्टी बैंकों/संस्थाओं द्वारा एक्जिम बैंक के पास रेसीप्रोकल रुपया जमा/बॉन्डों के पेटे रखी गई हैं। 'आस्तियों' [अनुसूची सं. VI 3.(क) (ii) देखिए] के अंतर्गत नकदी तथा बैंक जमाओं में "शून्य" (गत वर्ष शून्य) की रुपया जमा राशि शामिल है जो स्वैप्स संव्यवहारों के चलते है। 'आस्तियों' के अंतर्गत निवेश में [अनुसूची सं. VII 4. देखिए] कुल ₹ 1.58 बिलियन (गत वर्ष ₹ 1.79 बिलियन) की बॉन्ड राशि शामिल है जो स्वैप्स के चलते है।

यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी

विवरण	राशि (₹ मिलियन में)	
	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2018	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2017
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) और असाधारण मदें	(42,298.2)	3,126.4
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(18.0)	(0.9)
- निवेशों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(1,520.0)	(3,108.6)
- मूल्यहास	184.8	170.9
- बट्टे में डाले गए बॉन्ड निर्गमों पर छूट/व्यय	184.3	229.2
- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतर	-	-
- ऋणों/निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान/बट्टे खाते डालना	61,609.5	21,680.0
- अन्य उल्लेख करें	-	-
	18,142.4	22,097.0
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
- अन्य आस्तियां	(3,254.0)	(2,040.7)
- चालू देयताएं	(49,785.8)	(33,434.1)
परिचालनों से नकदी निर्माण	(34,897.4)	(13,377.8)
आय कर/ब्याज कर का भुगतान	(6,161.2)	(6,280.2)
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(41,058.6)	(19,658.0)
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
- अचल आस्तियों की निवल खरीद	(127.4)	(466.5)
- निवेशों में निवल परिवर्तन	(4,419.9)	5,634.6
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी/से अर्जित निवल नकदी	(4,547.3)	5,168.1
वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
- प्राप्त इक्विटी पूँजी	5,000.0	5,000.0
- लिए गए ऋण (चुकौती घटाकर)	80,803.9	27,519.5
- दिए गए ऋण, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त चुकौती घटाकर)	(48,910.6)	(35,242.7)
- इक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर (केन्द्र सरकार को अंतरित निवल लाभ अधिशेष)	(41.3)	(315.8)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त/से अर्जित निवल नकदी प्रवाह	36,852.0	(3,039.0)
नकदी और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(गिरावट)	(8,753.9)	(17,528.9)
प्रारंभिक नकदी एवं समतुल्य	36,908.9	54,437.8
अंतिम नकदी एवं समतुल्य	28,155.0	36,908.9

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

श्री देबाशिस मल्लिक
उप प्रबंध निदेशक

श्री टी. एस. तिरुमूर्ति

श्री राजीव ऋषि

श्री डेविड रस्कीना
प्रबंध निदेशक

श्री पंकज जैन

श्रीमती गीता मुरलीधर

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सोराब एस. इंजीनियर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 110417डब्ल्यू

(सीए एन. डी. अंक्लेसरिया)

पार्टनर

एम. सं. 010250

श्री रजनीश कुमार

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

I. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

i) वित्तीय विवरण

क) तैयारी का आधार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा (सामान्य निधि एवं निर्यात विकास कोष), भारत में प्रचलित लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किए गए हैं। बैंक द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियां गत वर्ष प्रयोग की गई लेखा नीतियों के अनुरूप हैं। एक्जिम बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 में दिए गए अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसे भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डीबीएस.एफआईडी. सं. सी-108/01.02.000/2015-16, दिनांकित 23 जून, 2016 और उसके बाद में अपेक्षित अनुसार कतिपय महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात/आंकड़े, "लेखों पर टिप्पणियां" के खंड के रूप में दर्शाए गए हैं।

ख) आकलन का प्रयोग

निर्धारित अनर्जक तिथि को वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा आय और व्यय को रिपोर्ट करने के दौरान आस्ति तथा देयताओं की राशि रिपोर्ट करने के लिए (आकस्मिक देयताओं सहित) प्रबंधन को कुछ अनुमानों/आकलनों का सहारा लेना पड़ता है। प्रबंधन की राय के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयोग किए गए यह आकलन/अनुमान समुचित और तार्किक हैं।

ii) राजस्व की गणना

अनर्जक आस्तियों, अनर्जक निवशों और "दबावग्रस्त आस्तियों" पर ब्याज, एसडीआर के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज, वचनबद्धता प्रभार और लाभांश जिन्हें नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर आय/व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। अनर्जक आस्तियों का निर्धारण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है। एक्जिम बैंक के बॉन्डों पर दिया जाने वाला बट्टा/मोचन प्रीमियम बॉन्ड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

तुलन-पत्र में दर्शायी गई ऋण और अग्रिम राशियों में अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधानों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियां शामिल हैं। प्राप्य ब्याज को "अन्य आस्तियों" में समूहित किया गया है।

ऋण चुकौती और वसूली हेतु कोलैटरल सिक्यूरिटी पर निर्भरता के अनुसार ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है: मानक आस्तियां, अवमानक आस्तियां, संदिग्ध आस्तियां और हानि आस्तियां। ऋण आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है।

iv) निवेश

संपूर्ण निवेश-पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- क) "परिपक्वता तक धारित" (परिपक्वता तक रखने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियां),
- ख) "क्रय-विक्रय के लिए धारित" (प्रतिभूतियां इस इरादे से अर्जित की जाती हैं कि अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय-विक्रय किया जाए) और
- ग) "बिक्री के लिए उपलब्ध" (शेष निवेश)।

निवेशों को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है:

- i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
- iii) शेयरों में निवेश
- iv) डिबेंचर और बॉन्ड में निवेश
- v) सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेश
- vi) अन्य (वाणिज्यिक-पत्र, म्युचुअल फंड इकाइयों आदि में) निवेश

निवेशों के विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन, मूल्य निर्धारण और निवेशों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किए गए मानदंडों के अनुसार किया गया है।

v) अचल आस्तियां तथा मूल्यहास

- क) अचल आस्तियों को संचित मूल्यहास घटाकर परंपरागत लागत अर्जन के समय मूल लागत पर दर्शाया गया है।
- ख) मूल्यहास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया गया है:

आस्तियां	मूल्यहास दर
स्वयं के भवन	5%
फर्नीचर एवं फिक्चर	25%
कार्यालय उपकरण	25%
अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	25%
कम्प्यूटर व कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25%
मोटर वाहन	25%
मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर मूल्यहास प्रौद्योगिकी के पुराने होने के आधार पर लिया गया है।	33.33%

- ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में, मूल्यहास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के संबंध में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यहास नहीं किया गया है।
- घ) जहां किसी अवक्षयी आस्ति को बेच दिया गया है, त्याग दिया गया है, ढहा दिया गया है अथवा नष्ट कर दिया गया है ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित किया गया है।

vi) अवक्षय

आस्तियों के रख-रखाव की राशि को हर तुलन-पत्र की तारीख को आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से आस्ति के मूल्य में हुए अवक्षय के लिए प्रावधान अथवा गत अवधियों में हुई अवक्षय हानियों के प्रावधानों को रिवर्स करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है। अवक्षय हानि तब होती है जब किसी आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

vii) विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखांकन

- क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दर पर अंतरित किया गया है।
- ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर अंतरित किया गया है।
- ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है तथा इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया गया है।
- घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

viii) गारंटियां

ईसीजीसी पॉलिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

ix) डेरिवेटिव

बैंक अपनी आस्तियों और देयताओं की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव संविदाएं जैसे ब्याज दर स्वैप, करंसी स्वैप, अंतर करंसी ब्याज दर स्वैप तथा वायदा दर करार करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ये संव्यवहार हेजिंग के उद्देश्य से किए जाते हैं तथा उपचित आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। बकाया डेरिवेटिव संविदाओं के बारे में मात्रात्मक तथा गुणात्मक प्रकटन "लेखों पर टिप्पणियों" में "वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटन मानक" विषयक भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुरूप रिपोर्ट किए जाते हैं।

x) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान

- क) बैंक में भविष्य निधि, ग्रेच्युटी निधि और पेंशन बैंक द्वारा चलाई जा रही परिभाषित कर्मचारी लाभ निधि योजनाएं हैं। इन निधियों में बैंक का अंशदान संबंधित वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते को डेबिट कर किया जाता है।
- ख) ग्रेच्युटी तथा पेंशन परिभाषित कर्मचारी लाभ देयताएं हैं। इन देयताओं के लिए प्रावधान बीमांकिक द्वारा किए गए मूल्यांकन आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुमानित एकक जमा पद्धति के आधार पर किया जाता है।
- ग) छुट्टी नकदीकरण के प्रति देयता के लिए वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है।

xi) आय पर करों का लेखांकन

क) संबंधित संविधि के अधीन भुगतान योग्य कर के अनुसार वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया गया है।

ख) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतर की दृष्टि से आस्थगित कर की गणना विद्यमान कर दरों पर तथा अधिनियमित विधि अथवा तुलन-पत्र की सम दिनांक को प्रमुखतः अधिनियमित विधि के अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उसी सीमा तक हिसाब में लिया गया है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।

xii) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

“प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां” की गणना भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 29 के अनुसार की जाती है। बैंक केवल उन प्रावधानों को हिसाब में लेता है जब वर्तमान दायित्व किसी विगत घटना का परिणाम हो। हालांकि यह संभव है कि इस दायित्व से उपजे आर्थिक भार संबंधी राशि का भुगतान दायित्व की राशि के सही आकलन के निर्धारण के बाद किया जाए।

आकस्मिक देयताएं तभी प्रकट की जाती हैं जब आर्थिक लाभ संबंधी राशि का भुगतान किए जाने की संभावना बहुत ही कम हो।

आकस्मिक आस्तियों को न ही हिसाब में लिया जाता है तथा न ही उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

II. लेखों पर टिप्पणियां – सामान्य निधि

1. एजेंसी लेखा

चूंकि एक्जिम बैंक इराक में भारतीय संविदाकारों से संबंधित कतिपय सौदों को सुगम बनाने के लिए केवल एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, अतएव भारत सरकार को समनुदेशित ₹ 44.79 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 44.57 बिलियन) की राशि सहित बैंक को सूचित की गई एजेंसी खाते में धारित ₹ 40.48 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 40.27 बिलियन) की समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियां उपर्युक्त तुलन-पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. आयकर

बैंक की पूंजी संपूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा धारित है तथा बैंक में कोई अन्य शेयर पूंजी नहीं है। अतः भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 की धारा 23 (2) के अनुसार केन्द्र सरकार को अंतरणीय लाभ अधिशेष को लाभांश नहीं कहा जा सकता। परिणामस्वरूप वाद सं. आईटीए सं. 2025/मुंबई/2000 में 18 दिसंबर, 2006 को कर अपील न्यायाधीकरण द्वारा पारित निर्णय के आलोक में लाभांश वितरण पर कोई कर देय नहीं है, अतः इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3. क) आकस्मिक देयताएं

गारंटियों में ₹ 1.24 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 2.01 बिलियन) की समाप्त गारंटियां शामिल हैं, जिन्हें बहियों में से निरस्त किया जाना बाकी है।

ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत "बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है" के रूप में दिखाई गई ₹ 2.31 बिलियन (पिछले वर्ष ₹ 1.97 बिलियन) की राशि अधिकांशतः बैंक के डिफाल्टिंग उधारकर्ताओं के विरुद्ध बैंक द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के जवाब में उन उधारकर्ताओं द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर किए गए दावों/प्रतिदावों से संबंधित है। बैंक के सॉलिसिटर्स की राय में कोई भी दावा/प्रतिदावा गुणवत्ता योग्य नहीं है तथा कोई भी मामला अभी तक अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है; अतः विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर इस संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

ग) वायदा विनिमय संविदाएं, मुद्रा/ब्याज दर स्वैप

- i) यथा 31 मार्च, 2018 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूर्ण हेजिंग की गई है। बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 जुलाई, 1999 के परिपत्र संदर्भ सं. एमपीडी.बीसी.187/07.01.279/1999-2000 एवं उसके बाद जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति-देयता प्रबंधन के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव सौदे (ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा मुद्रा-सह-ब्याज दर स्वैप) करता है। बैंक अपनी आवश्यकताओं तथा बाजार स्थितियों के आधार पर सौदे करता है तथा उनका निपटान करता है। बकाया डेरिवेटिव सौदों को ब्याज दर के उतार-चढ़ाव के आधार पर निपटाया जाता है जिसकी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) द्वारा निगरानी और बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है। डेरिवेटिव के ऋण समतुल्य की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'विद्यमान ऋण जोखिम' पद्धति के अनुसार की जाती है। डेरिवेटिव के आधार बिंदु (पीवी 01) के फेयर वैल्यू तथा प्राइस वैल्यू को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार 'लेखों पर टिप्पणियों' में अलग से प्रकट किया गया है। वायदा दर संविदाओं से होने वाले लाभ या हानि को संविदा की पूरी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के निरस्तीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय/व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।
- ii) बैंक को ग्राहकों/गैर-ग्राहकों के लिए 'लॉन्ग डेटेड फॉरेन करंसी - रूपी स्वैप्स' संव्यवहारों के लिए 'मार्केट मेकर' की भूमिका निभाने की अनुमति प्राप्त है।

घ) मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव पर लाभ/हानि

विदेशी मुद्रा में उल्लिखित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दरों पर अंतरित किया जाता है। आय तथा व्यय मदों को वार्षिक औसत विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा परिचालनों से अर्जित एवं धारित आय के अंतरणों पर सांकेतिक लाभ ₹ 0.13 बिलियन (गत वर्ष ₹ 0.22 बिलियन) है।

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों संबंधित प्रकटीकरण: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

5. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अनुसार अतिरिक्त सूचना

5.1 पूँजी

क)

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2018 को	यथा 31 मार्च, 2017 को
(i)	जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर)	10.35%	15.81%
(ii)	मुख्य सीआरएआर	8.82%	14.29%
(iii)	अनुपूरक सीआरएआर	1.53%	1.52%

ख) यथा 31 मार्च, 2018 को टीयर-II पूँजी के रूप में जुटाए गए और बकाया गौण ऋण की राशि: ₹ कुछ नहीं (गत वर्ष: ₹ कुछ नहीं)

ग) जोखिम भारित आस्तियां

(₹ बिलियन)

	विवरण	यथा 31 मार्च, 2018 को	यथा 31 मार्च, 2017 को
(i)	तुलन-पत्र में 'शामिल' मर्दे	579.05	590.05
(ii)	तुलन-पत्र में 'शामिल नहीं की गई' मर्दे	73.80	126.71

घ) तुलन-पत्र की तारीख को शेयरधारिता का स्वरूप: भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त पूँजी।

- जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) और अन्य संबंधित मानदंडों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार किया गया है।
- बासेल III मानकों सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित संशोधित रूपरेखा अभी मसौदा चरण में है। बैंक सीआरएआर के निर्धारण हेतु बासेल III मानकों को इनके प्रभावी होने की तारीख से लागू करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक से अंतिम अधिसूचना प्रतीक्षित है।

5.2 निर्बंध आरक्षित निधियां एवं प्रावधान

क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ बिलियन)

	विवरण	2017-18	2016-17
(i)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	14.08	(9.22)

ख) अस्थायी प्रावधान

(₹ बिलियन)

	विवरण	2017-18	2016-17
(क)	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	-	-
(ख)	लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
(ग)	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कम हुई राशि	-	-
(घ)	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	-	-

5.3 आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

क) अनर्जक अग्रिम

(₹ बिलियन)

	विवरण	2017-18	2016-17
(i)	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	3.75%	4.688%
(ii)	अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ (सकल)		
(क)	प्रारंभिक शेष	99.62	42.75
(ख)	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	43.24	68.10
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	23.10	11.23
(घ)	अंतिम शेष	119.76	99.62
(iii)	निवल अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़		
(क)	प्रारंभिक शेष	48.04	8.55
(ख)	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	24.87	45.85
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	32.63	6.36
(घ)	अंतिम शेष	40.28	48.04
(iv)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क)	प्रारंभिक शेष	51.59	34.20
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	39.27	31.94
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	11.38	14.55
(घ)	अंतिम शेष	79.48	51.59

ख) अनर्जक निवेश

(₹ बिलियन)

	विवरण	2017-18	2016-17
(i)	निवल निवेशों की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.80%	0.008%
(ii)	अनर्जक निवेशों में घट-बढ़ (सकल)		
(क)	प्रारंभिक शेष	1.63	0.65
(ख)	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	1.95	1.01
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	0.54	0.03
(घ)	अंतिम शेष	3.04	1.63
(iii)	निवल अनर्जक निवेशों में घट-बढ़		
(क)	प्रारंभिक शेष	0.0042	-
(ख)	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	0.4554	0.0042
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	0.0042	-
(घ)	अंतिम शेष	0.4554	0.0042
(iv)	अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क)	प्रारंभिक शेष	1.63	0.65
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1.51	1.01
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	0.56	0.03
(घ)	अंतिम शेष	2.58	1.63

ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(₹ बिलियन)

	विवरण	2017-18	2016-17
(i)	निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम + निवेश) (%)	3.60%	4.688%
(ii)	अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क)	प्रारंभिक शेष	101.25	43.40
(ख)	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	45.19	69.11
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	23.64	11.26
(घ)	अंतिम शेष	122.80	101.25
(iii)	अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़		
(क)	प्रारंभिक शेष	48.0442	8.55
(ख)	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	25.3254	45.8542
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	32.6342	6.36
(घ)	अंतिम शेष	40.7354	48.0442
(iv)	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधानों को छोड़कर)		
(क)	प्रारंभिक शेष	53.22	34.85
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	40.78	32.95
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/प्रतिलेखन	11.94	14.58
(घ)	अंतिम शेष	82.06	53.22

5.4 पुनर्संचित किए गए खातों का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पुनर्संचना का प्रकार	विवरण	कंपनी कर्ज पुनर्संचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत				एसएमई ऋण पुनर्संचना प्रक्रिया के अंतर्गत				अन्य				कुल			
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक		संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्संचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि उस पर प्रारंभिक	15 11.12 3.85	- - -	11 5.47 3.98	- - -	26 16.59 7.83	2 0.03 0.006	- - -	3 0.11 0.08	- - -	5 0.14 0.08	2 8.23 0.90	1 1.09 0.26	9 9.20 6.30	- - -	22 18.52 15.37	53 35.25
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्संचना/बढ़त	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि उस पर प्रारंभिक	1 1.24 0.54	- - -	2 0.58 0.76	- - -	3 1.82 1.30	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1.07 0.17	2 1.89 0.48	5 4.29 4.77	- - -	8 7.25 6.72	11 9.07
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि उस पर प्रारंभिक	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1.09 0.26	- - -	1 1.09 0.26	1 1.09 0.26	
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संचित मानक अग्रिम, निम्न से उच्चतर प्रारंभिक ह्रास और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि उस पर प्रारंभिक	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संचित खातों का डाउनग्रेडेशन/ घटत	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि उस पर प्रारंभिक	6 7.01 2.11	- - -	5 3.71 2.55	- - -	11 10.72 4.66	1 0.02 0.004	- - -	1 0.09 0.053	- - -	2 0.11 0.06	7 3.87 0.58	- - -	3 2.08 1.53	- - -	10 5.95 6.83	23 16.78
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संचित खातों को बड़े खाते डालना	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि उस पर प्रारंभिक	- - -	- - -	1 0.73 0.65	- - -	1 0.73 0.65	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 0.73 0.65
7	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्संचित खाते (अंतिम आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या बकाया राशि उस पर प्रारंभिक	10 5.35 2.28	- - -	7 1.61 1.54	- - -	17 6.96 3.82	1 0.01 0.002	- - -	2 0.02 0.02	- - -	3 0.03 0.02	6 5.43 0.49	2 1.89 0.48	11 11.41 9.54	- - -	19 18.73 10.51	39 25.72 14.35

5.5 अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़

(₹ बिलियन)

विवरण	2017-18	2016-17
यथा 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष)	99.62	42.75
वर्ष के दौरान बढ़त (नई अनर्जक आस्तियां)	40.93	68.10
ब्याज निधीयन	2.06	(0.39)
विनिमय दर घट-बढ़	0.25	-
उपखंड योग (क)	142.86	110.46
घटाएं:		
(i) उन्नयन	3.13	1.55
(ii) वसूली (उन्नत खातों से वसूली को छोड़कर)	5.38	2.70
(iii) तकनीकी/विवेकसम्मत बढ़े खाते	14.34	5.31
(iv) बढ़े खाते, उपर्युक्त (iii) के अलावा	0.25	0.76
(v) विनिमय दर घट-बढ़	-	0.52
उपखंड योग (ख)	23.10	10.84
यथा आगामी वर्ष की 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (क-ख)	119.76	99.62

डीबीआर परिपत्र संख्या डीबीआर सं. बीपी. बीसी. 2/21.04.048/2015-16 दिनांकित 1 जुलाई, 2015 के अनुलग्नक भाग सी-2 के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां

5.6 बढ़े खाते और वसूली

(₹ बिलियन)

विवरण	2017-18	2016-17
बढ़े खाते डाले गए खातों का यथा 1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष तकनीकी/विवेकसम्मत बढ़े खाते	6.04	0.75
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत बढ़े खाते	14.34	5.31
उपखंड योग (क)	20.38	6.06
घटाएं: वर्ष के दौरान पुराने तकनीकी/विवेकसम्मत बढ़े खाते डाले गए खातों से की गई वसूली (ख)	0.0007	0.02
यथा 31 मार्च को अंतिम शेष (क-ख)	20.38	6.04

5.7 विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

(₹ बिलियन)

विवरण	2017-18	2016-17
कुल आस्तियां	95.26	121.52
कुल अनर्जक आस्तियां	5.62	6.64
कुल राजस्व	6.99	7.20

उपर्युक्त आंकड़े बैंक की लंदन शाखा से संबंधित हैं, जिसका परिचालन अक्टूबर 2010 में शुरू हुआ।

5.8 निवेशों पर मूल्यहास और प्रावधान

(₹ बिलियन)

	विवरण	2017-18	2016-17
(1)	निवेश		
(i)	सकल निवेश	73.11	61.54
(क)	भारत में	73.11	61.54
(ख)	भारत से बाहर	-	-
(ii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान	16.14	10.52
(क)	भारत में	16.14	10.52
(ख)	भारत से बाहर	-	-
(iii)	निवल निवेश	56.97	51.03
(क)	भारत में	56.97	51.03
(ख)	भारत से बाहर	-	-
(2)	निवेशों पर मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधानों में घट-बढ़		
(i)	प्रारंभिक शेष	10.52	5.07
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	5.62	5.47
(iii)	वर्ष के दौरान निवेश अस्थिर आरक्षित निधि खाते से विनियोजन, यदि कोई है	-	-
(iv)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों पर बढ़ा खाता/प्रतिलेखन	-	0.02
(v)	घटाएं: अस्थिर आरक्षित निधि खाते में हस्तांतरण, यदि कोई है	-	-
(vi)	अंतिम शेष	16.14	10.52

5.9 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

(₹ बिलियन)

लाभ एवं हानि शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए प्रावधानों और आकस्मिक व्यय का विवरण	2017-18	2016-17
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	5.58	5.50
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	26.84	17.91
आयकर के लिए किए गए प्रावधान	(13.06)	2.71
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय (विवरण सहित)	0.0024	(0.07)

5.10 प्रावधान कवरेज अनुपात

विवरण	2017-18	2016-17
प्रावधान कवरेज अनुपात	71.26%	54.54%

6. निवेश पोर्टफोलियो: संघटक एवं परिचालन

6.1 रेपो लेन-देन

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2018 को बकाया
रेपो अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2017 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

6.2 ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निवेशकर्ता की जमा राशियों का प्रकटीकरण

वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

क्र.सं.	निवेशकर्ता	राशि	राशि			
			निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	“निवेश ग्रेड से नीचे” धारित प्रतिभूतियां	धारित “अश्रेणीकृत” प्रतिभूतियां	धारित “असूचीबद्ध” प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	0.032	-	-	0.03	0.03
2	वित्तीय संस्थाएं	1.82	1.58	-	0.24	1.82**
3	बैंक	0.17	-	-	0.17	0.16
4	निजी कॉर्पोरेट	29.91	29.85	-	29.91	26.15*
5	अनुषंगी संस्थाएं/ संयुक्त उपक्रम	0.0032	-	-	0.0032	0.0032
6	अन्य	0.50	-	-	-	0.50
7	मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान [#]	14.45	-	-	-	-
	कुल	32.43	31.43	-	30.35	28.67

कॉलम 3 में प्रकट किए जाने वाले प्रावधान की केवल कुल राशि

* जिसमें से ₹ 21.61 बिलियन जमा राशियां आस्टि पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश को दर्शाती हैं और ₹ 4.19 बिलियन का निवेश ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/ऋण पत्रों (डिबेंचरों) में है।

** जिसमें से ₹ 1.58 बिलियन जमा राशियां भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से किए गए यूएस डॉलर/भारतीय रुपए में स्वैप के जरिए थीं। उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से संबंधित नहीं हैं।

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	निवेशकर्ता	राशि	राशि			
			निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	“निवेश ग्रेड से नीचे” धारित प्रतिभूतियां	धारित “अश्रेणीकृत” प्रतिभूतियां	धारित “असूचीबद्ध” प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	0.04	-	-	0.04	0.04
2	वित्तीय संस्थाएं	2.03	1.79	-	0.24	2.03**
3	बैंक	0.27	0.10	-	0.17	0.17
4	निजी कॉर्पोरेट	27.47	27.41	-	27.47	24.94*
5	अनुषंगी संस्थाएं/ संयुक्त उपक्रम	0.0032	-	-	0.0032	0.0032
6	अन्य	0.50	-	-	-	0.50
7	मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान [#]	9.92	-	-	-	-
	कुल	30.31	29.30	-	27.92	27.68

कॉलम 3 में केवल प्रावधान की कुल राशि प्रकट की गई है।

* जिसमें से ₹ 22.13 बिलियन जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूत रसीदों में निवेश और ₹ 2.76 बिलियन ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/ऋण पत्रों (डिबेंचरों) में निवेश को दर्शाती हैं।

** जिसमें से ₹ 1.79 बिलियन राशि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से किए गए यूएस डॉलर/भारतीय रुपए में स्वैप के जरिए थीं।

उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से संबंधित नहीं हैं।

6.3 एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण

कोई बिक्री या अंतरण नहीं हुआ।

7. खरीदी/बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

7.1 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. बिक्री का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2016-17
(i)	खातों की संख्या	-	2
(ii)	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण के लिए बेचे गए खातों (प्रावधानों का निवल) का कुल मूल्य	-	0.39
(iii)	कुल प्राप्ति	-	0.34
(iv)	गत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त राशि	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल प्राप्ति/(हानि)	-	(0.05)

- "आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई आस्तियों" को आरबीआई के मास्टर परिपत्र डीबीओडी संख्या एफआईडी.एफआईसी.2/01.02.00/2006-07 दिनांकित 01 जुलाई, 2006 और उसके बाद परिभाषित अनुसार माना गया है।

ख. प्रतिभूति जमा में निवेशों के बही मूल्य का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य	
		2017-18	2016-17
(i)	बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटी	10.04	13.67
(ii)	बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटी	-	-
	कुल	10.04	13.67

7.2 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2016-17
1)	क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	-	-
	ख) कुल बकाया	-	-
2)	क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संचित खातों की संख्या	-	-
	ख) कुल बकाया	-	-

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2016-17
1)	बेचे गए खातों की संख्या	1	-
2)	कुल बकाया	1.96	-
3)	कुल प्राप्त राशि	1.71	-

8. परिचालन परिणाम

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2016-17
(i)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.24	7.63
(ii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.47	0.72
(iii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.70	2.24
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल	(2.42)	0.04
(v)	प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ/(हानि) (₹ बिलियन में)	(0.086)	0.001

- परिचालन परिणामों के लिए कार्यशील निधियों और कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत तथा रिपोर्ट के अंतर्गत लेखा वर्ष के अंत के आंकड़ों को औसत के रूप में लिया गया है ('कार्यशील निधियों' का संदर्भ कुल आस्तियों से है)।
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ/(हानि) की गणना के लिए सभी कैडरों के स्थायी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को लिया गया है।

9. ऋण संकेंद्रण जोखिम

9.1 पूँजी बाजार एक्सपोजर

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2016-17
(i)	इक्रिटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डों/डिबेंचरों और इक्रिटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स में प्रत्यक्ष निवेश, जिनका निवेश केवल कॉर्पोरेट ऋण में ही नहीं है;	-	-
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित) परिवर्तनीय बॉन्डों/डिबेंचरों और इक्रिटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स में निवेश के लिए बेजमानती अग्रिम;	-	-
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों/डिबेंचरों या इक्रिटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-

(iv)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों/ डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की कोलैटरल सिक्युरिटी, अर्थात ऐसे उद्देश्य जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्डों/ डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर नहीं करती;	-	-
(v)	शेयर दलालों को जमानती और गैर-जमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों और मार्केटमेकर्स की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधन जुटाने के लिए कॉर्पोरेट्स को नई कंपनियों में प्रवर्तक इक्विटी लेने के लिए शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बेजमानती ऋणों की मंजूरी;	-	-
(vii)	संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के बदले पूरक ऋण;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों/डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की प्राथमिक निर्गम की खरीद के संबंध में बैंक द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	-	-
(ix)	शेयर दलालों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण;	-	-
(x)	उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए सभी एक्सपोजर	-	-
	पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर	-	-

9.2 देशगत जोखिम एक्सपोजर

(₹ बिलियन)

जोखिम श्रेणी	यथा मार्च 2018 को एक्सपोजर (नेट)	मार्च 2018 को प्रावधान [®]	यथा मार्च 2017 को एक्सपोजर (नेट)	मार्च 2017 को प्रावधान [®]
नगण्य	98.42	-	108.78	-
न्यून	325.94	-	452.30	-
मध्यम	249.59	-	626.28	-
उच्च	97.22	-	73.55	-
बहुत ज्यादा	-	-	-	-
प्रतिबंधित	90.73	-	114.78	-
ऑफ क्रेडिट	-	-	-	-
कुल	861.90	-	1,375.69	-

[®] बैंक द्वारा देश संकेंद्रण जोखिम के लिए प्रावधान किया जाना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि वित्तीय संस्थाओं के लिए इस संबंध में कोई परिपत्र नहीं है।

9.3 रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) योजना

(₹ बिलियन)

खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	इक्रिटी में परिवर्तित ऋण की राशि
2	0.61	0.98

एसडीआर - एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में बदलाव

(₹ बिलियन)

खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	इक्रिटी में परिवर्तित ऋण की राशि
1	0.50	0.51

9.4 दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना योजना (एस4ए) के अंतर्गत एक्सपोजर

(₹ बिलियन)

विवरण	एस4ए लागू खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	बकाया राशि		किया गया प्रावधान
			भाग क में	भाग ख में	
मानक के रूप में वर्गीकृत	3	3.22	4.32	3.51	2.14
अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत	-	-	-	-	-

9.5 बैंक द्वारा विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण देने संबंधी मामले-एकल उधारकर्ता सीमा/समूह उधारकर्ता सीमा

क. वर्ष के दौरान विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण संबंधी मामले- संख्या और राशि

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन नंबर	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजी निधियों के % के रूप में एक्सपोजर
1.	AAACM5132A	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.*	11101	पेट्रो-केमिकल्स	सार्वजनिक	22.16	-	19.56
2.	AADCV1810B	वीओवीएल लि.*	40201	तेल एवं गैस	निजी	19.16	-	16.91

* टीसीएफ के 5% के अतिरिक्त एक्सपोजर के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया था।

ख. पूँजी निधियों और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर

	विवरण	पूँजी निधियों का प्रतिशत*	कुल ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत (टीसीई) [®]	कुल अस्तियों का प्रतिशत
i)	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	19.56	1.20	1.79
ii)	सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	33.40	2.06	3.06
iii)	20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	222.36	13.68	20.40
iv)	20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	282.30	17.37	25.90

* यथा 31 मार्च, 2017 को पूँजी निधियां

[®] टीसीई: ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरीयां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर ऋण एक्सपोजर

- 1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोजर में शामिल नहीं किया गया है।
- 2) यथा 31 मार्च, 2018 को 2 उधारकर्ता थे, जिनके लिए एक्सपोजर बोर्ड के अनुमोदन से पूँजी निधियों के 15% से ज्यादा स्वीकृत किया गया था। यथा 31 मार्च, 2018 को इन उधारकर्ताओं को एक्सपोजर बैंक की पूँजी निधियों का क्रमशः 19.56% और 16.91% रहा।

गत वर्ष:

	विवरण	पूँजी निधियों की तुलना में प्रतिशत*	कुल ऋण एक्सपोजर की तुलना में प्रतिशत (टीसीई) [®]	कुल अस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i)	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	16.01	0.77	1.46
ii)	सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	31.45	1.52	2.87
iii)	20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	193.26	9.35	17.61
iv)	20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	281.99	13.65	25.70

* यथा 31 मार्च, 2016 को पूँजी निधियां

[®] टीसीई: ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरीयां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर ऋण एक्सपोजर

- 1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोजर में शामिल नहीं किया गया है।
- 2) यथा 31 मार्च, 2017 को 1 उधारकर्ता था, जिसके लिए एक्सपोजर बोर्ड के अनुमोदन से पूँजी निधियों के 15% से ज्यादा स्वीकृत किया गया था। यथा 31 मार्च, 2017 को इस उधारकर्ता को एक्सपोजर बैंक की पूँजी निधियों का 16.01% रहा।

ग. पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण

	क्षेत्र	कुल ऋण एक्सपोजर की तुलना में प्रतिशत (टीसीई)	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i)	इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण सेवाएं	12.26	9.28
ii)	लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	9.84	7.45
iii)	पेट्रोलियम उत्पाद	6.87	5.20
iv)	टेक्सटाइल और गारमेंट	6.10	4.62
v)	तेल और गैस	5.64	4.27

गत वर्ष:

	क्षेत्र	कुल ऋण एक्सपोजर की तुलना में प्रतिशत (टीसीई)	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i)	इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और निर्माण सेवाएं	10.09	7.49
ii)	लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	9.68	7.18
iii)	तेल और गैस	7.68	5.70
iv)	टेक्सटाइल और गारमेंट	6.53	4.85
v)	निर्माण	5.16	3.83

- “ऋण एक्सपोजर” की गणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार की गई है।
- उद्योग एक्सपोजर की गणना के लिए बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिया गया वह ऋण जिसके लिए भारत सरकार द्वारा/भारत सरकार की ओर से गारंटी दी गई है को, भारत सरकार की ओर से दिया गया ऋण माना गया है और उसे इसमें शामिल नहीं किया गया है।

घ. गैर जमानती अग्रिम

कुल ₹ 6.81 बिलियन के गैर जमानती अग्रिमों के लिए कॉर्पोरेट/व्यक्तिगत गारंटियां, वचन पत्र, ट्रस्ट रसीदें आदि ली गई हैं, जिसका आकलित मूल्य ₹ 1.74 बिलियन है।

ड. फैक्टरिंग एक्सपोजर

फैक्टरिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंक का कुल ऋण एक्सपोजर ₹ 1.4 बिलियन रहा।

च. ऐसे मामले जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान निर्धारित एक्सपोजर सीमा को पार किया

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	पैन नंबर	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजी निधियों के % के रूप में एक्सपोजर
1.	AAACM5132A	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि.	11101	पेट्रो-केमिकल्स	सार्वजनिक	22.16	-	19.56
2.	AADCV1810B	वीओवीएल लि.	40201	तेल एवं गैस	निजी	19.16	-	16.91

यथा 31 मार्च, 2018 को 2 उधारकर्ता थे, जिनके लिए एक्सपोजर बोर्ड के अनुमोदन से पूँजी निधियों के 15% से ज्यादा स्वीकृत किया गया था। यथा 31 मार्च, 2018 को इन उधारकर्ताओं को एक्सपोजर बैंक की पूँजी निधियों का क्रमशः 19.56% और 16.91% रहा।

10. उधारियों/ऋण-व्यवस्थाओं, ऋण एक्सपोजरों और अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(क) उधारियों और ऋण-व्यवस्थाओं का संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

विवरण	2017-18	2016-17
20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां	132.30	103.48
बैंक की कुल उधारियों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियों का प्रतिशत	12.70%	10.77%

(ख) ऋण एक्सपोजरों का संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

विवरण	2017-18	2016-17
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल उधारियां	251.94	206.45
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं को कुल उधारियों का प्रतिशत	21.82%	19.15%
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	251.94	206.45
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत	13.68%	9.35%
एक्जिम बैंक के मामले में, कुल एक्सपोजर की तुलना में शीर्ष 10 देशों के एक्सपोजर का प्रतिशत	27.56%	37.30%

ऋण और निवेश एक्सपोजर की गणना वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोजर मानदंडों पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र संख्या डीबीआर.एफआईडी.एफआईसी.संख्या 4/01.02.00/2015-16 दिनांकित 01 जुलाई, 2015 के अनुसार की गई है।

(ग) ऋणों और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार संकेंद्रण

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	क्षेत्र	2017-18			2016-17		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
क	घरेलू क्षेत्र	370.61	84.13	23%	356.40	62.02	17%
1	कुल निर्यात वित्त	330.56	72.65	22%	307.51	60.52	20%
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	<u>औद्योगिक क्षेत्र</u>	294.46	61.42	21%	272.88	49.25	18%
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	44.41	21.04	47%	44.26	20.39	46%
	तेल और गैस	-	-	-	7.89	0.93	12%
	टेक्सटाइल और गारमेंट	41.80	6.61	16%	-	-	-
	अन्य	208.25	33.77	16%	220.73	27.94	13%
	<u>सेवा क्षेत्र</u>	36.10	11.23	31%	34.63	11.27	33%

(₹ बिलियन)

	उड्डयन सेवाएं	-	-	-	2.94	-	-
	ईपीसी सेवाएं	13.61	9.78	72%	14.75	10.04	68%
	जहाजरानी सेवाएं	11.54	0.62	5%	9.29	0.62	7%
	अन्य	10.95	0.83	8%	7.65	0.61	8%
2	कुल आयात वित्त	40.05	11.48	29%	48.89	1.50	3%
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	35.20	11.48	33%	41.97	0.01	0.02%
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	1.54	1.54	100%	1.44	-	-
	तेल और गैस	-	-	-	11.37	-	-
	अन्य	33.66	9.94	29.53%	29.17	0.01	0.02%
	सेवा क्षेत्र	4.85	-	-	6.92	1.49	22%
	ईपीसी सेवाएं	0.34	-	-	1.92	1.49	78%
	जहाजरानी सेवाएं	3.47	-	-	3.51	-	-
	अन्य	1.04	-	-	1.49	-	-
3	(क) में से भारत सरकार द्वारा गारंटीत एक्सपोजर	-	-	-	-	-	-
ख	बाह्य क्षेत्र	146.07	35.63	24%	184.67	37.60	20%
1	कुल निर्यात वित्त	146.07	35.63	24%	184.67	37.60	20%
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	114.65	24.68	22%	152.74	25.03	16%
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	24.35	2.39	10%	26.29	1.62	6%
	तेल और गैस	-	-	-	29.98	8.19	27%
	टेक्सटाइल और गारमेंट	3.20	-	-	-	-	-
	अन्य	87.10	22.29	26%	96.47	15.22	16%
	सेवा क्षेत्र	31.42	10.95	35%	31.93	12.56	39%
	उड्डयन सेवाएं	-	-	-	5.10	-	-
	ईपीसी सेवाएं	10.94	4.50	41%	12.25	4.33	35%
	जहाजरानी सेवाएं	4.31	3.37	78%	4.45	3.38	76%
	अन्य	16.17	3.08	19%	10.13	4.85	48%
2	कुल आयात वित्त	-	-	-	-	-	-
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	सेवा क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3	(ख) में से भारत सरकार द्वारा गारंटीत एक्सपोजर	-	-	-	-	-	-
ग	अन्य एक्सपोजर[#]	638.12	-	-	536.93	-	-
घ	कुल एक्सपोजर (क+ख+ग)	1,154.80	119.76	10.37%	1,078.00	99.62	9.24%

[#] इसमें ऋण-व्यवस्थाओं, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण, रियायती वित्त योजना, वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त और बैंकों द्वारा प्रति-गारंटीत अग्रिम शामिल हैं।

11. डेरिवेटिव

11.1 वायदा दर करार एवं ब्याज दर स्वैप

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2017-18		2016-17	
		हेजिंग	ट्रेडिंग	हेजिंग	ट्रेडिंग
1.	स्वैप करारों का मूल कल्पित मूल्य	348.12	-	290.75	-
2.	प्रतिपक्षी पार्टि द्वारा करार के दायित्वों का निर्वहन न करने पर संभावित हानि	0.10	-	0.37	-
3.	स्वैप करारों के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित कोलैटरल	-	-	-	-
4.	स्वैप्स से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।		सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।	
5.	स्वैप बही का सही मूल्य	(11.28)	-	(6.73)	-

स्वैप की प्रकृति तथा शर्तें: सभी संव्यवहार बैंक की आस्तियों/देयताओं से संबंधित हैं तथा इन्हें बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन स्थिति की हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है।

11.2 एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की सांकेतिक मूल राशि (लिखत-वार)	-
2.	यथा 31 मार्च, 2018 को एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि (लिखत-वार)	-
3.	एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि किंतु "हाइली इफेक्टिव" नहीं	-
4.	एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव का बकाया मार्क-टू-मार्केट मूल्य किंतु "हाइली इफेक्टिव" नहीं	-

11.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

क. गुणात्मक प्रकटीकरण

- 1) बैंक बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से मुख्यतः अपने तुलन-पत्र जोखिमों को हेज करने तथा प्रभावी न्यून लागत निधियों को जुटाने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव का उपयोग करता है। बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत केवल ओवर दि काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स का ही उपयोग करता है।
- 2) डेरिवेटिव संव्यवहारों में दो जोखिम (i) बाजार जोखिम अर्थात् ब्याज दरों/विनिमय दरों के प्रतिकूल प्रचलन से बैंक को संभावित हानि तथा (ii) ऋण जोखिम अर्थात् प्रतिपक्षी पार्टि द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में चूक से हानि की संभावना, विहित रहते हैं। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक डेरिवेटिव नीति लागू है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण आस्ति देयता स्थिति तथा संव्यवहार स्तर पर ही जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने, नियंत्रण तथा निगरानी उपायों की स्थापना सहित नियामक प्रलेखन तथा लेखा संबंधी मुद्दों को परिभाषित किया गया है। इसमें बाजार जोखिम को नियंत्रित करने तथा प्रबंध करने (स्टॉप लॉस लिमिट, ओपन पोजिशन लिमिट, टेनर लिमिट, सेटलमेंट तथा प्री-सेटलमेंट लिमिट, पीवी01 लिमिट आदि) संबंधी जोखिम मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है।
- 3) बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के मिड ऑफिस, जो डेरिवेटिव संव्यवहारों से जुड़े बाजार जोखिमों का आकलन और निगरानी करता है, की सहायता से बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य की देखरेख करती है।
- 4) यथा 31 मार्च, 2018 को बैंक की बहियों में बकाया सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों को हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है तथा आस्ति-देयता बहियों में दर्शाया गया है। इन संव्यवहारों पर आय को बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- 5) आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत बकाया वायदा दर संविदाओं में ब्याज दर स्वैप/करंसी स्वैप्स शामिल नहीं हैं जो कि डेरिवेटिव नीति के अनुपालन के संदर्भ में है।

ख. मात्रात्मक प्रकटन

(₹ बिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2017-18		2016-17	
		करंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	करंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
1	डेरिवेटिव (कल्पित मूल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	392.45	348.12	371.84	290.75
	ख) ट्रेडिंग के लिए	-	-	-	-
2	मार्कड-टू-मार्केट स्थितियां				
	क) आस्ति (+)	-	-	-	-
	ख) देयता (-)	28.75	11.28	32.72	6.73
3	ऋण एक्सपोजर	19.42	1.72	21.50	1.64
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी 01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	13.54	20.26	13.69	16.44
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान 100*पीवी01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर				
	(i) अधिकतम	13.67	20.52	14.66	18.22
	(ii) न्यूनतम	12.77	14.47	13.69	8.98
	ख) ट्रेडिंग पर				
	(i) अधिकतम	-	-	-	-
	(ii) न्यूनतम	-	-	-	-

12. बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को कुल ₹ 0.58 बिलियन (गत वर्ष पंजाब नेशनल बैंक को कुल ₹ 2.00 बिलियन) के चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए गए। यथा 31 मार्च 2018 को इन प्रतिबद्धताओं पर बैंक का कोई चुकौती उत्तरदायित्व नहीं है। यथा 31 मार्च, 2018 इसके तहत कुल बकाया राशि ₹ 2.58 बिलियन रही।

13. आस्ति-देयता प्रबंधन
वर्तमान वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	कुल
रुपया अग्रिम	36.77	22.54	21.41	47.61	39.62	52.22	25.14	32.89	278.20
रुपया निवेश	-	0.95	0.07	0.04	2.51	0.11	0.99	52.30	56.97
रुपया अन्य आस्तियां	25.18	1.61	48.04	23.32	78.64	128.49	102.49	331.79	739.56
रुपया जमा राशियां	0.01	0.004	0.14	21.48	22.00	0.41	0.05	-	44.09
रुपया उधारियां	35.43	5.00	54.75	24.10	57.77	44.23	72.67	143.96	437.91
रुपया अन्य देयताएं	21.91	22.97	28.73	24.63	78.20	89.99	35.55	193.84	495.82
विदेशी मुद्रा आस्तियां	53.35	25.88	37.78	48.05	124.49	254.16	211.44	375.34	1,130.49
विदेशी मुद्रा देयताएं	41.09	8.32	45.43	53.50	126.76	284.32	249.88	316.52	1,125.82

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	कुल
रुपया अग्रिम	4.72	10.22	105.12	48.39	47.17	30.41	23.17	37.44	306.64
रुपया निवेश	-	0.10	0.57	0.56	0.11	2.85	1.53	45.24	50.96
रुपया अन्य आस्तियां	26.22	4.71	27.18	17.71	29.87	154.99	95.15	298.10	653.93
रुपया जमाराशियां	1.37	0.02	0.37	23.93	9.50	0.54	0.19	-	35.92
रुपया उधारियां	27.63	0.40	100.89	6.00	7.30	83.27	52.43	158.97	436.89
रुपया अन्य देयताएं	3.20	4.94	28.81	26.56	33.76	103.78	32.88	194.31	428.24
विदेशी मुद्रा आस्तियां	36.95	10.40	39.91	95.66	115.11	185.74	168.12	320.54	972.43
विदेशी मुद्रा देयताएं	5.69	2.49	11.08	89.38	90.06	246.75	209.80	304.98	960.23

14. आरक्षित निधियों से आहरण

बैंक द्वारा आरक्षित निधियों से कोई राशि नहीं निकाली गई है।

15. व्यवसाय अनुपात

विवरण	2017-18	2016-17
इक्रिटी पर रिटर्न	(39.94)%	0.62%
आस्तियों पर रिटर्न	(2.42)%	0.04%
प्रति कर्मचारी निवल लाभ/(हानि) (₹ बिलियन)	(0.086)	0.001

16. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने अथवा अधिनियम, आदेश, नियम अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अपेक्षित शर्त के उल्लंघन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया।

17. शिकायतों का प्रकटीकरण

ग्राहक शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2016-17
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	-	-
(ख)	वर्ष के दौरान मिली शिकायतें	1	2
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	1	2
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	-	-

18. तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुरूप समेकित किया जाना है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
-	-

विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

19. अचल आस्तियों के विवरण

अचल आस्तियों के विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखा मानक-10 के अनुसार नीचे दिए गए हैं।

(₹ बिलियन)

विवरण	परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक			
यथा 31 मार्च, 2017 को लागत	2.06	1.02	3.08
परिवर्द्धन	0.03	0.12	0.15
निपटान	0.00	0.10	0.10
यथा 31 मार्च, 2018 को लागत (क)	2.09	1.04	3.13
मूल्यहास			
यथा 31 मार्च, 2017 को संचित	0.92	0.86	1.78
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.09	0.10	0.19
निपटान पर हटाया गया	0.00	0.10	0.10
यथा 31 मार्च, 2018 को संचित (ख)	1.01	0.86	1.87
निवल ब्लॉक (क-ख)	1.08	0.18	1.26

गत वर्ष:

(₹ बिलियन)

विवरण	परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक			
यथा 31 मार्च, 2016 को लागत	1.73	0.90	2.63
परिवर्द्धन	0.33	0.14	0.47
निपटान	0.00	0.02	0.02
यथा 31 मार्च, 2017 को लागत (क)	2.06	1.02	3.08
मूल्यहास			
यथा 31 मार्च, 2016 को संचित	0.84	0.79	1.63
वर्ष के दौरान प्रावधान	0.08	0.09	0.17
निपटान पर हटाया गया	0.00	0.02	0.02
यथा 31 मार्च, 2017 को संचित (ख)	0.92	0.86	1.78
निवल ब्लॉक (क-ख)	1.14	0.16	1.30

20. सरकारी अनुदानों का लेखा

भारत सरकार ने बैंक द्वारा विदेशी सरकारों, विदेशी बैंकों/संस्थाओं को प्रदान की गई विशिष्ट ऋण-व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे उपचय (अक्रुअल) आधार पर हिसाब में लिया गया है।

21. व्यवसाय खंड रिपोर्टिंग

बैंक के परिचालनों में केवल वित्तीय कार्यकलाप शामिल हैं अतः इसे एकल व्यवसाय खंड में शामिल किया गया है। बैंक के भौगोलिक परिचालन खंडों को घरेलू परिचालनों एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालनों में वर्गीकृत किया गया है। इन परिचालनों का घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय खंड में वर्गीकरण मुख्यतः संव्यवहार के जोखिम तथा प्रतिफल पर आधारित हैं।

(₹ बिलियन)

विवरण	घरेलू परिचालन		अंतरराष्ट्रीय परिचालन		कुल	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
राजस्व	80.79	85.15	6.99	7.20	87.78	92.35
आस्तियां	1,139.90	1,050.53	95.29	121.54	1,235.19	1,172.07

22. संबंधित पक्षकार प्रकटन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अंतर्गत संबंधित पक्षकार प्रकटन किया गया है:

• संबंध

(i) संयुक्त उपक्रम:

- ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टैंट्स लिमिटेड

(ii) मुख्य कार्मिक अधिकारी:

- श्री डेविड रस्कीना (प्रबंध निदेशक - अतिरिक्त प्रभार) (15 अगस्त, 2017 तक) और (प्रबंध निदेशक) (16 अगस्त, 2017 से)
- श्री देबाशिस मल्लिक (उप प्रबंध निदेशक)

- बैंक से संबंधित पक्षकार शेष राशियां तथा लेन-देनों का सारांश नीचे दिया गया है:

(₹ मिलियन)

विवरण	संयुक्त उपक्रम		मुख्य कार्मिक अधिकारी	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
मंजूर ऋण	-	-	-	-
जारी गारंटियां	1.58	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-
प्राप्त गारंटी कमीशन	0.004	0.02	-	-
प्रदत्त सेवाओं के एवज में प्राप्त भुगतान	0.05	-	-	-
स्वीकार की गई जमा राशियां	-	6.62	-	0.50
सावधि जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज	0.31	0.81	0.42	0.49
बट्टाकृत/अपलेखीकृत की गई राशि	-	-	-	-
बकाया सावधि जमा राशियां	-	6.62	3.24	3.44
वर्ष के अंत में बकाया ऋण राशि	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां	1.58	3.26	-	-
वर्ष के दौरान बकाया निवेश राशि	3.23	3.23	-	-
प्राप्त लाभांश	0.42	0.28	-	-
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम ऋण राशि	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम गारंटियां	4.45	3.26	-	-
भत्ते सहित वेतन	-	-	7.32	9.36
भाड़े का भुगतान	-	-	0.30	0.25

23. आय पर कर का लेखांकन

(क) चालू वर्ष के लिए कर प्रावधान का विवरण:

(₹ बिलियन)

(i) आय पर कर	1.65
(ii) घटाकर: निवल आस्थगित कर आस्ति	(14.71)
	(13.06)

(ख) आस्थगित कर आस्ति:

प्रमुख करों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का संयोजन नीचे दिया गया है:

(₹ बिलियन)

विवरण		
आस्थगित कर आस्तियां		
1.	अस्वीकार्य प्रावधान (निवल)	38.32
2.	अचल आस्तियों पर मूल्यह्वस	0.07
		38.39
घटाएं: आस्थगित कर देयता		
1.	बॉन्ड निर्गम खर्च का परिशोधन	0.56
2.	धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधियां	4.56
		5.12
निवल आस्थगित कर आस्तियां तुलन-पत्र के 'आस्तियां' पक्ष में 'अन्य आस्तियों' में शामिल		33.27

24. संयुक्त उपक्रमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

I.

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था	देश	धारिता का प्रतिशत	
		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सलटेंट्स लिमिटेड	भारत	28%	28%

II. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में हित से संबंधित आस्तियों, देयताओं और आय तथा व्यय की कुल राशि निम्नलिखित है:

(₹ मिलियन)

देयताएं	2017-18	2016-17	आस्तियां	2017-18	2016-17
पूँजी एवं आरक्षित निधियां	26.67	24.40	अचल आस्तियां	0.07	0.09
ऋण	-	-	निवेश	14.95	10.09
अन्य देयताएं	8.24	5.62	अन्य आस्तियां	19.89	19.84
कुल	34.91	30.02	कुल	34.91	30.02

आकस्मिक देयताएं: शून्य (गत वर्ष: शून्य)

(₹ मिलियन)

व्यय	2017-18	2016-17	आय	2017-18	2016-17
अन्य व्यय	11.36	12.52	परामर्शी आय	14.13	15.62
प्रावधान	1.26	1.26	ब्याज आय तथा निवेश से आय	0.34	0.35
कर पश्चात लाभ	2.85	2.93	अन्य आय	1.00	0.74
कुल	15.47	16.71	कुल	15.47	16.71

नोट: जीपीसीएल के वित्तीय वर्ष 2017-18 के आंकड़े अलेखापरीक्षित एवं अनंतिम हैं।

25. आस्तियों का अनर्जन

बैंक की आस्तियों में से अधिकांश आस्तियां वित्तीय आस्तियां हैं जिन पर "आस्तियों के अनर्जन" संबंधी लेखामानक-28 लागू नहीं होता है। बैंक के मत से यथा 31 मार्च, 2018 को आस्तियों जिन पर ये मानक लागू हैं, का कोई अनर्जन नहीं हुआ है जिससे इस लेखा मानक के अंतर्गत प्रावधान किया जाए।

26. कर्मचारी लाभ

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संगठन द्वारा कर्मचारी लाभों पर, यथा 01 अप्रैल, 2007 से जारी लेखामानक -15 को अपनाया है। कर्मचारी लाभों से उत्पन्न देयता को बैंक की बहियों में दायित्व के विद्यमान मूल्य पर हिसाब में लिया गया है, जिसमें तुलन-पत्र की तारीख को आयोजनागत आस्तियों के सही मूल्य को घटाया गया है।

क) तुलन-पत्र में हिसाब में ली गई राशि

(₹ बिलियन)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी
अवधि के अंत में आयोजनागत आस्तियों का सही मूल्य	0.952	0.138
अवधि के अंत में हित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	0.907	(0.154)
निधीयन स्थिति	0.045	(0.016)
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई परिवर्ती देयता	-	-
अवधि के अंत में तुलन पत्र में हिसाब में ली गई निवल देयता	(0.045)	0.016

ख) लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय

(₹ बिलियन)

विवरण	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी
वर्तमान सेवा लागत	0.024	0.012
ब्याज मूल्य	0.007	0.001
नियोजित आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	0.059	0.009
बीमांकिक हानि/(लाभ)	(0.158)	0.003
विगत सेवा लागत - गैर निहित लाभ	-	-
विगत सेवा लागत - निहित लाभ	-	-
परिवर्ती दायित्व	-	-
लाभ एवं हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय	(0.127)	0.016
नियोक्ता द्वारा योगदान	(0.011)	(0.019)

ग) बीमांकिक अनुमानों का सारांश

विवरण	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.70%	7.85%
आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर (प्रति वर्ष)	7.70%	7.85%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निधिक देयताओं के वर्तमान मूल्य में वृद्धि के लिए छुट्टी नकदीकरण की परिभाषित लाभ देयता ₹ 0.072 बिलियन है, जिसके लिए ₹ 0.099 बिलियन का पहले से ही प्रावधान कर दिया गया है, इसलिए और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

27. सेबी के दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के परिपत्र के अनुपालन में भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा जारी किए गए विभिन्न बॉन्डों के लिए डिबेंचर ट्रस्टियों का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:

डिबेंचर ट्रस्टी

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि.

प्राधिकृत व्यक्ति: श्री जयेंद्र पी. शेटी, मुख्य परिचालन अधिकारी

पता:

एक्सिस हाउस,
बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड,
पांडुरंग बुधकर मार्ग,
वर्ली, मुंबई - 400 025.

फोन: (022) 6226 0050/54

फैक्स: (022) 2425 3000

ईमेल: debenturetrustee@axistrustee.com

वेबसाइट: www.axistrustee.com

28. जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

श्री देबाशिस मल्लिक
उप प्रबंध निदेशक

श्री टी. एस. तिरुमूर्ति

श्री राजीव ऋषि

श्री डेविड रस्कीना
प्रबंध निदेशक

श्री पंकज जैन

श्रीमती गीता मुरलीधर

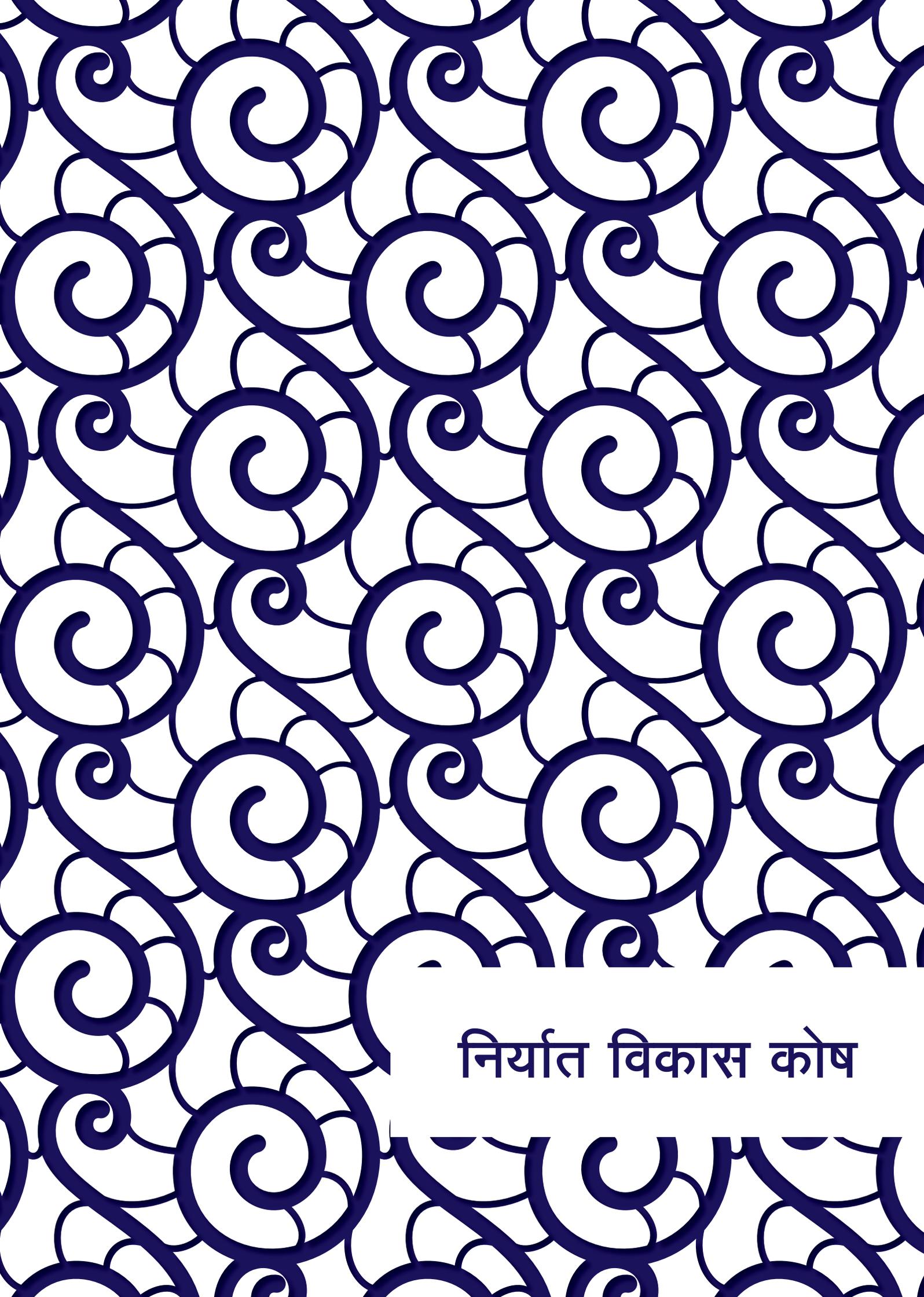
हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सोराब एस. इंजीनियर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 110417डब्ल्यू

(सीए एन. डी. अक्लेसरिया)

पार्टनर

एम. सं. 010250

श्री रजनीश कुमार



निर्यात विकास कोष

निदेशकों की रिपोर्ट

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (एक्विजिमेंट बैंक अधिनियम) की धारा 15 के अनुसार एक्विजिमेंट बैंक अपनी स्थापना या ऐसी किसी तिथि से जब भारत सरकार इस संबंध में अधिसूचित करे, एक विशेष निधि को स्थापित करेगी जिसे निर्यात विकास कोष (ईडीएफ) के नाम से जाना जाएगा। तदनुसार सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार इसे 31 मार्च, 1986 को बैंक द्वारा निर्यात विकास कोष (ईडीएफ) की विधिवत स्थापना की गई।

भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 1986 को इस कोष में ₹ 100 मिलियन की प्रारंभिक राशि अंतरित की गई। इसके बाद भारत सरकार द्वारा 23 मार्च, 1987 को इस कोष में ₹ 35 मिलियन तथा 29 मार्च, 1989 को ₹ 6.52 मिलियन उपचित ब्याज और कर आदि को निकाल कर यथा 31 मार्च, 1996 को कुल राशि बढ़कर ₹ 350.60 मिलियन हो गई थी। बोर्ड/भारत सरकार के अनुमोदन से इस कोष में से ₹ 250 मिलियन की राशि बैंक की सामान्य निधि के एक रिज़र्व फंड जिसे 'सिंकिंग फंड (एसएफ) रिज़र्व' नाम दिया गया, में अंतरित कर दी गई। इस सिंकिंग फंड का उद्देश्य ऐसी ऋण-व्यवस्थाओं/क्रेता-ऋणों से उत्पन्न हानियों को समायोजित करना था जिन्हें भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) द्वारा बीमा कवर प्राप्त नहीं हो सकता है। 31 मार्च, 1997 से 31 मार्च, 2018 तक इस ईडीएफ के अंतर्गत राशि बढ़कर ₹ 8.60 बिलियन हो गई।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करते समय दिए गए कथन के उद्देश्यों में यह उल्लिखित है कि निर्यात विकास निधि का उपयोग मुख्य रूप से देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयोजित शोध, प्रशिक्षण, सर्वेक्षण, मार्केट इंटेलीजेंस सहित ऐसे वित्तपोषण प्रस्तावों को सहयोग देने के लिए किया जाएगा जिन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अन्यथा सहयोग किया जाना संभव नहीं होगा। निर्यात विकास कोष के उपयोग संबंधी शर्तें एक्विजिमेंट बैंक अधिनियम की धारा 17 में उल्लिखित हैं। जो इस प्रकार हैं:

अधिनियम की धारा 17(1) एक्विजिमेंट बैंक को यह अनुमति देती है कि बैंक केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत से या भारत के बाहर ऋण अथवा अग्रिम मंजूर कर सकता है।

अधिनियम की धारा 17(2) में यह अपेक्षित है कि ऐसे किसी प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजने से पहले एक्विजिमेंट बैंक स्वयं इस बात से संतुष्ट होगा कि "... बैंकों या वित्तीय संस्थाओं या अन्य एजेंसियों द्वारा सामान्य व्यावसायिक शर्तों पर प्रस्तावित ऋण या अग्रिम दिया जाना या इस तरह की कोई व्यवस्था करना संभव नहीं है।"

अधिनियम की धारा 17(3) में यह निर्देशित किया गया है कि ऐसा अनुमोदन देने से पहले भारत सरकार इस तथ्य से संतुष्ट होगी कि भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यह सुविधा दी जानी आवश्यक है और यह इसके हित में है।

अतः इस प्रकार निर्यात विकास कोष (ईडीएफ) सुविधा भारत सरकार को ऐसे विदेशी व्यापार या निवेश को करने के लिए एक रास्ता देती है जिसे सामान्य व्यावसायिक सिद्धांतों पर एक्विजिमेंट बैंक या अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाना संभव नहीं है।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा एक्विजिमेंट बैंक अधिनियम की धारा 17(1) के अधीन ईडीएफ के अंतर्गत राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता-ऋण सुविधा जिसकी राशि ₹ 9 बिलियन होगी, स्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया। इस सुविधा का उद्देश्य चुनिंदा ईरानी बैंकों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना था ताकि वे भारत से ईरान को माल व सेवाओं के निर्यात का वित्तपोषण कर सकें। सभी आवश्यक अनुमोदनों को प्राप्त करने के उपरान्त 23 दिसम्बर, 2014 को ईडीएफ के अंतर्गत ईरान के सात बैंकों को ₹ 9 बिलियन राशि की क्रेता-ऋण सुविधा हेतु एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर किए गए। यह सुविधा 12 वर्ष के लिए दी गई जिसमें 4 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि (मोरेटोरियम) ईरानी बैंकों को दी गई। इस ऋण सुविधा को ईरान सरकार की संप्रभु गारंटी प्राप्त है। फ्रेमवर्क करार की शर्तों के अनुसार ₹ 9 बिलियन की इस राशि को भारत सरकार की अनुमति और परस्पर सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है।

तत्पश्चात, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा इस फ्रेमवर्क करार के तहत दी गई ऋण सुविधा को ₹ 9 बिलियन से बढ़ाकर ₹ 30 बिलियन करने का अनुमोदन दिया गया। तदनुसार, ईडीएफ द्वारा 04 मई, 2016 को इस फ्रेमवर्क करार के अंतर्गत संशोधन करते हुए उक्त 7 ईरानी बैंकों के साथ ₹ 30 बिलियन की ऋण सुविधा प्रदान करने संबंधी करार किया गया। इस ऋण का उपयोग फ्रेमवर्क करार के अनुसार किया जाएगा।

इस फ्रेमवर्क करार के अंतर्गत भारत से ईरान को बैंक ऑफ इंडस्ट्री एंड माइन, ईरान के जरिए 150,000 टन स्टील रेल की आपूर्ति के लिए ₹ 8.19 बिलियन का पहला कॉन्ट्रैक्ट क्रेता ऋण सुविधा के अंतर्गत मंजूर किया जा चुका है। यथा 31 मार्च, 2018 को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ईडीएफ द्वारा ₹ 8.11 बिलियन का संवितरण किया जा चुका है। ईडीएफ में फंड जुटाने हेतु भारत सरकार की गारंटी के लिए मंजूरी प्राप्ति लंबित रहते, ईडीएफ द्वारा ये संवितरण बैंक के जनरल फंड से उपलब्ध कराए गए अंतरिम ऋण से फंड किए जा रहे हैं। शेष

स्टील रेल कॉन्ट्रैक्ट और चाबहार बंदरगाह विकास परियोजना के कॉन्ट्रैक्ट के लिए वित्तपोषण निगोशिएशन / अंतिम रूप दिए जाने के चरण में है।

ईरान की ओर से चाबहार बंदरगाह विकास परियोजना के लिए 12.88 मिलियन यूरो के छह (6) न्यूमैटिक शिप-अनलोडर की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है।

निर्यात विकास कोष का कर पूर्व लाभ वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹ 101.67 मिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹ 114.54 मिलियन रहा। कर हेतु ₹ 39.64 मिलियन प्रदान करने के बाद कर पश्चात लाभ वित्तीय वर्ष 2016-17 के ₹ 66.49 मिलियन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 74.90 मिलियन रहा। लाभ के रूप में प्राप्त ₹ 74.90 मिलियन की इस राशि को अगले वर्ष के खाते में ले जाया गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') की निर्यात विकास निधि के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2018 को तुलन-पत्र और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की निर्यात विकास कोष के लाभ और हानि लेखे एवं समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश एवं अन्य विवरणात्मक आंकड़े शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेवारी

2. बैंक प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों को भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 ('अधिनियम') तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस जिम्मेवारी में बैंक की आस्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रखने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित लेखा प्रविष्टियां; उचित लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; उचित एवं मितव्ययी अनुमानों को तैयार करना; तथा उसकी डिजाइन, कार्यान्वयन तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने में आवश्यक आंतरिक नियंत्रण शामिल है ताकि इन विवरणों में धोखाधड़ी अथवा भूलवश भी कोई मिथ्या सूचना न आने पाए।

लेखा परीक्षक की जिम्मेवारी:

3. हमारी जिम्मेवारी इन वित्तीय विवरणों के बारे में हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।

4. हमने यह लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार

निष्पादित और नियोजित करें ताकि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है।

5. लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है। इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पूर्णतया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है जिसमें महत्वपूर्ण विवरणों के संबंध में भूल अथवा धोखाधड़ी के चलते भ्रामक मिथ्याकथन जोखिमों का आकलन करना शामिल है। इन जोखिमों के मूल्यांकन के संबंध में लेखा परीक्षकों के विचार से इन विवरणों को त्रुटिरहित ढंग से तैयार करने में बैंक के आंतरिक प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों एवं बैंक के प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।
6. हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए साक्ष्य पर्याप्त और समुचित हैं तथा हमारे लेखा परीक्षा अभिमत के लिए तर्क संगत आधार प्रदान करते हैं।

अभिमत

7. हमारी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखा विवरण तथा उन पर लेखा टिप्पणियां अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं तथा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा मानकों के अनुरूप सच्ची और सही स्थिति प्रदर्शित करते हैं:
- (i) यथा 31 मार्च, 2018 को बैंक के निर्यात विकास कोष के मामले में;
- (ii) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते के मामले में;

अन्य विधिक तथा विनियामक मामलों पर रिपोर्ट

8. तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता, अधिनियम तथा उसके अंतर्गत विरचित विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए हैं।
9. हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:
 - i) लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक पाए गए हैं।
 - ii) बैंक के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं।
10. हमारी राय में तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप हैं।
11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:
 - i) तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता बैंक की लेखा बहियों और विवरणों के अनुरूप हैं।
 - ii) हमारे विचार में और हमारे परीक्षण के आधार पर बैंक द्वारा विधि निर्धारित अनुसार इन बहियों का उचित अभिलेख रखा गया है।

कृते **सोराब एस. इंजीनियर एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 110417डब्ल्यू

सीए एन.डी. अंकलेसरिया
पार्टनर
सदस्यता सं -10250
मुंबई, 18 मई, 2018.

तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2018 को

निर्यात विकास निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2018 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2017 को) ₹
देयताएं		
1. ऋण:		
क) सरकार से	-	-
ख) अन्य स्रोतों से	6,932,011,546	5,374,610,504
2. अनुदान:		
क) सरकार से	128,307,787	128,307,787
ख) अन्य स्रोतों से	-	-
3. उपहार, दान, उपकृतियां:		
क) सरकार से	-	-
ख) अन्य स्रोतों से	-	-
4. अन्य देयताएं	951,143,165	309,162,861
5. लाभ और हानि लेखा	585,967,085	511,063,467
योग	8,597,429,583	6,323,144,619
आस्तियां		
1. बैंक की शेष राशियां		
क) चालू खातों में	116,549	163,809
ख) अन्य जमा खातों में	-	204,000,000
2. निवेश	-	-
3. ऋण एवं अग्रिम:		
क) भारत में	-	-
ख) भारत के बाहर	8,116,580,978	5,809,030,094
4. भुनाए गए, पुनर्भुनाए गए विनिमय बिल और वचन-पत्र:		
क) भारत में	-	-
ख) भारत के बाहर	-	-
5. अन्य आस्तियां		
क) निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
i) ऋण एवं अग्रिम	238,400,353	98,617,251
ii) निवेश/बैंक शेष	-	10,301,762
ख) प्रदत्त अग्रिम आय कर	242,331,703	201,031,703
ग) अन्य	-	-
योग	8,597,429,583	6,323,144,619

निर्यात विकास निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2018 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2017 को) ₹
आकस्मिक देयताएं		
i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व	-	-
ii) वायदा विनियम संविदाओं की बकाया राशियों पर	-	-
iii) हामीदारी एवं वचनबद्धताओं पर	-	-
iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं	-	-
v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	-	-
vi) संग्रहण के लिए बिल	-	-
vii) सहभागिता प्रमाण-पत्रों पर	-	-
viii) भुनाए गए/पुनः भुनाए गए बिल	-	-
ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	-	-

टिप्पणी:

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (अधिनियम) की धारा 15 की शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा निर्यात विकास निधि की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 17 की शर्तों के अनुसार, किसी भी ऋण अथवा अग्रिम की मंजूरी से पहले अथवा ऐसी कोई व्यवस्था करने से पहले भारतीय निर्यात-आयात बैंक को केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

श्री देबाशिस मल्लिक
उप प्रबंध निदेशक

श्री टी. एस. तिरुमूर्ति

श्री राजीव ऋषि

श्री डेविड रस्कीना
प्रबंध निदेशक

श्री पंकज जैन

श्रीमती गीता मुरलीधर

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सोराब एस. इंजीनियर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 110417डब्ल्यू

(सीए एन. डी. अंक्लेसरिया)

पार्टनर
एम. सं. 010250

श्री रजनीश कुमार

लाभ और हानि लेखा यथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

निर्यात विकास निधि

	इस वर्ष ₹	गत वर्ष ₹
व्यय		
1. ब्याज	555,196,969	90,924,855
2. अन्य व्यय	3,143,189	794,779
3. आगे ले जाया गया लाभ	114,545,618	101,673,294
योग	672,885,776	193,392,928
आयकर के लिए प्रावधान	39,642,000	35,187,000
तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ	74,903,618	66,486,294
	114,545,618	101,673,294
आय		
1. ब्याज और बट्टा		
क) ऋण एवं अग्रिम	663,567,960	98,617,251
ख) निवेश/बैंक शेष	4,697,714	43,277,262
2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस	4,620,102	51,498,415
3. अन्य आय	-	-
4. तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि	-	-
योग	672,885,776	193,392,928
लाभ नीचे लाया गया	114,545,618	101,673,294
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज कर के प्रावधान का प्रतिलेखन	-	-
	114,545,618	101,673,294

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

श्री देबाशिस मल्लिक
उप प्रबंध निदेशक

श्री टी. एस. तिरुमूर्ति

श्री राजीव ऋषि

श्री डेविड रस्कीना
प्रबंध निदेशक

श्री पंकज जैन

श्रीमती गीता मुरलीधर

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सोराब एस. इंजीनियर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. नं. 110417डब्ल्यू

(सीए एन. डी. अंक्लेसरिया)

पार्टनर

एम. सं. 010250

श्री रजनीश कुमार

नोट्स

PROMOTING PROJECT EXPORTS TO BOOST EXPORTS AND JOB CREATION

Export of projects and services is an indicator of a country's advancement in technology and upward movement in the value chain of export performance. Project export contracts are generally of high value and exporters undertaking them are required to offer competitive credit terms to be able to secure orders from foreign buyers in the face of stiff competition. Long term deferred credit thus plays an important role in securing project export contracts. With industrial demand slowing down globally, governments around the world are now targeting energy and infrastructure projects as vital conduits for exporting high-value machinery, labour, expertise and technology packaged as engineering, procurement and construction (EPC) projects.

Project exports are an effective instrument for expanding geo-commercial influence in the host countries, as they give an impetus to domestic industry to manufacture for exports and stimulate demand for domestic firms, particularly SMEs, resulting in a multiplier effect on employment and economic growth. Project exports, thus, support the Government of India's "Make in India" initiative by giving a boost to domestic manufacturing through backward linkages, while at the same time generating employment in related industries.

Project Exports from India have evolved since a modest beginning in the 1970s. Today Indian companies are executing a variety of projects in diverse markets overseas, demonstrating capabilities and expertise spanning a wide range of sectors. Exim Bank has been closely associated with the growth of India's project exports. Projects funded by the multilateral development banks (MDBs), both in India and in borrower countries, present attractive business opportunities for Indian suppliers, contractors and consultants. These opportunities are spread across an array of sectors, including power, water supply, transport, telecommunication, agriculture, education and health. Due to their technical expertise and relevant experience in such sectors, Indian companies are often well-placed to secure contracts in projects funded by MDBs. Successful project exports are the outcome of exemplary vision.

CONTENTS

Board of Directors	02
Statement of the Managing Director	03
Economic Environment	09
Directors' Report	19
Business Operations	23
Financial Statements	49
The Export Development Fund	93

BOARD OF DIRECTORS

(As on May 18, 2018)

Directors representing the Government of India



Ms. Rita Teatota
Secretary
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry



Shri Ramesh Abhishek
Secretary
Department of Industrial Policy
& Promotion
Ministry of Commerce & Industry



Shri T. S. Tirumurti
Secretary (ER)
Ministry of External Affairs



Dr. Arvind Subramanian
Chief Economic Adviser
Ministry of Finance



Shri Pankaj Jain
Joint Secretary (IF)
Department of Financial Services

Directors from the Reserve Bank of India, Institutions and Commercial Banks



Dr. M. D. Patra
Executive Director
Reserve Bank of India



Shri Rajnish Kumar
Chairman
State Bank of India



Smt. Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing
Director, ECGC Ltd.



Shri Rajeev Rishi
Chairman & Managing Director
Central Bank of India



Shri M. K. Jain
Managing Director & CEO
IDBI Bank Ltd.



Shri Dinabandhu Mohapatra
Managing Director & CEO
Bank of India

Whole-time Directors



Shri David Rasquinha
Managing Director



Shri Debasish Mallick
Deputy Managing Director

STATEMENT OF THE MANAGING DIRECTOR



The year gone by has not been the best of the years, both for the Indian banking sector in general, and Exim Bank, as an institution, in particular. The Government of India (GOI) and the Reserve Bank of India (RBI) introduced a slew of measures during the last few months, towards cleaning up the financial system in the country. The corrective measures, though good for the financial sector from a long-term perspective, have brought in challenges to the Indian banking sector, and Exim Bank was not immune to it.

The gross bank credit which was growing at double digits till FY 2014, suddenly tapered to single digit growth in FY 2015, declining further during FY 2016 and FY 2017. In FY 2018, the gross bank credit growth experienced a modest recovery of 0.80%, touching an 8.20% growth over the previous year. These tepid figures are largely due to the prevailing non-performing loans, coupled with weak debt-

servicing ability of the corporates, leading to twin balance sheet issues.

In merchandise exports the Indian economy breached US\$ 300 billion mark after a gap of two years, after having reached a high of US\$ 314 billion in FY 2014. With the spike in crude oil prices and the increase in non-oil imports, the trade deficit is expected to widen further.

On the other hand, the external environment has been showing some signs of recovery, with the developed economies like US experiencing some growth traction. Global trade which has seen some decline in the past, showed some green shoots in 2017. However, given the increasing protectionism sentiments across the globe, and signals of trade wars, concerns remain for a sustainable trade environment going forward.

Business Results

The impact of the new domestic regulatory measures got reflected in the state of the financial sector, which in turn was mirrored in Exim Bank's performance.

The Bank's net loan portfolio has grown marginally to ₹ 1075 billion as on March 31, 2018, compared to ₹ 1026 billion as on March 31, 2017, indicating a net asset growth of 4.76%. The Policy Business i.e. business carried out on behalf of, or at the behest of the GOI, constituted 38% of the total loan portfolio, while the Commercial Business constituted 62% of the total loan portfolio of the Bank as on March 31, 2018. The regulatory changes and continued subdued business environment brought in fresh slippages of assets as non-performing in the last quarter of FY 2017-18. The Bank has provisioned aggressively with a vision of putting the NPA problems behind it and moving forward. However, the Bank's Capital to Risk Weighted Assets Ratio

(CRAR) as on March 31, 2018 remained at 10.35%, well above the RBI norm of minimum 9.00% for total capital.

During the year, the Bank received capital of ₹ 5 billion from the GOI. As on March 31, 2018, the Bank's paid-up capital stood at ₹ 73.59 billion, and the reserves stood at ₹ 22.41 billion. The Bank's international credit rating remained at par with the sovereign, at Baa2 by Moody's, BBB- by Standard & Poor's, BBB- by Fitch Ratings, and BBB+ by Japan Credit Rating Agency.

Over the last few years, there has been consistent support from the GOI in the form of regular infusion of capital in the Bank, and this is expected to be at a greater level, as the role and expectations from the institution have been scaled up, especially for strategic project exports.

Policy Business

The Bank currently is involved in a host of concessional finance programmes, which are typically medium to long term in nature.

The Lines of Credit (LOC) is the largest such programme, being extended since its inception in 2003, on behalf of the ministry of external affairs and the ministry of finance, GOI. Exim Bank, as on date has an exposure to 62 developing and less developed countries in Africa, Asia, Latin America and the CIS regions, under this programme, for financing crucial infrastructure projects in sectors as diverse as power, roads, health systems, and information technology.

Since 2011, the Bank has been supporting Indian project exports under an innovative programme, the Buyer's Credit under National Export Insurance Account (BC-NEIA), jointly with ECGC Ltd., under the aegis of the Ministry of Commerce and Industry, GOI. The programme envisages promotion of India's project exports to traditional as well as new markets in developing countries which need deferred credit on medium or long-term basis. The BC-NEIA programme has received a remarkable response since its inception.

Exim Bank is the country's key export policy institution, and has been instrumental in playing a vital role furthering the GOI's geo-economic strategic initiatives. In this connection, pursuant to the approval of the GOI, Export Development Fund (EDF - a fund administered by Exim Bank) has extended a Buyer's Credit Facility of ₹ 30 billion to Iran (Framework Agreement signed between EDF and seven Iranian banks). As approved by the GOI, the entire credit facility would be utilized for export of steel rails from India and the Chabahar Port Development Project.

Since 2015, the Bank is operating another programme, Concessional Financing Scheme, on behalf of the ministry of finance, GOI, towards supporting strategically important projects which have been secured by Indian companies abroad. Under this Scheme, the Bank has extended a term loan of US\$ 1.60 billion to the Bangladesh-India Friendship Power Company Pvt. Ltd. (BIFPCL, a 50:50 joint venture between the Bangladesh Power Development Board, Bangladesh and NTPC Ltd., India) for financing the strategic 1320 MW (2*660 MW) ultra-super-critical Maitree Super Thermal Power Project on turnkey basis at Rampal, District-Bagerhat, Bangladesh. Once commissioned, the thermal power project is expected to be the largest power plant in Bangladesh ameliorating lives of thousands of its citizens.

Exim Bank has also been working alongside the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, GOI, as the Empowered Institution, in implementing the 'Project Development Fund (PDF)', with an initial corpus of ₹ 5 billion, for catalysing Indian investments in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam (CLMV). Under this initiative, the Bank has identified potential sectors in the CLMV region for undertaking preparation of Detailed Project Reports, based on which Special Purpose Vehicles will be set up in the region for implementing the identified projects. The PDF initiative is well aligned with the GOI's 'Act East Policy'.

Commercial Business

A barometer for success of any firm in these days of global integration is the extent of its footprints worldwide, more so in the context of an emerging country environment. Recognising this, and in an endeavour to encourage and support Indian firms in their quest for globalisation, Exim Bank has been supporting Indian investments abroad under the Overseas Investment Finance program since its formative years. Besides, the Bank has been offering funding solutions for setting up new export oriented units, their expansion, modernisation, purchase of equipment, and also research and development, towards creation of export capability in the domestic economy. One such support extended recently was to a firm which has been involved in pharmaceutical and vaccine manufacturing and is amongst the top-five pure play vaccine manufacturers globally and among the top-three in the emerging markets. Our lending programs for export capability creation and the OIF programme have led to several success stories in the past. Exim Bank is proud to be associated with some of such Indian corporates, which have scaled new heights in partnership with the Bank.

The Bank, at the same time, is conscious of its obligation towards facilitating the latent business potential at the grassroots level. The Bank supports the globalisation of enterprises based in rural areas of the country. The Bank has assisted micro, small and medium enterprises with marketing support for their products in overseas markets. During the year, the Bank has signed a Memorandum of Co-operation with the Centre for Microfinance & Livelihood, an initiative of Tata Trusts. Besides placing such products in traditional brick-and-mortar outlets, the Bank has also engaged with e-commerce platforms to extend the reach of the MSME sector beyond India's boundaries.

While working with micro and grassroot enterprises, the Bank has also had to address some key issues, especially related to product development and design. The Bank has been supporting and assisting

rural artisans and craftsmen of handicraft products to gain domestic as well as international presence by organising skill building and training workshops. Besides, a dedicated team has been working with such enterprises supporting their international marketing efforts. The Bank's success in generating export orders for Indian manufacturers and rural entrepreneurs is a matter of immense satisfaction.

Resources

During the year, the Bank raised foreign currency resources aggregating US\$ 3.26 billion equivalent through a variety of instruments, different investor bases and across various geographies.

The Bank successfully launched a 5-year Reg-S floating rate Formosa Bond issue of US\$ 400 million in August 2017. The issue was priced at 100 basis points over 3 months US\$ Libor resulting in the largest Formosa Bond issuance out of India and first Formosa transaction by an Indian financial institution.

In January 2018, the Bank successfully priced a 10-year Bond issue of US\$ 1 billion, its second transaction in the 144A/Reg-S format. The issue was hugely oversubscribed as it attracted a total order book in excess of US\$ 1.8 billion from over 100 high-quality global investors. Having initially marketed the deal at 150 basis points over US Treasuries, the Bank was able to achieve a final pricing of 125 basis points over US Treasuries, to yield 3.897 per cent on a coupon of 3.875 per cent. The Notes achieved the tightest ever spread over US Treasury for an Indian entity for a 10-year issuance.

Research and Analysis

Towards diffusion of information on potential sectors, regions and countries, Exim Bank's dedicated team of researchers is involved in analysing areas of concomitant interest to the Bank and the country. Some of the studies that have been published during the year are: Trade in Environmental Goods: A Perspective; The Internationalization of Indian firms through outbound Foreign Direct Investment: Nature, determinants

and developmental consequences; Oil Price and International Trade in Petroleum Crude and Products: An Indian Perspective; Financialisation and its Implications on the Determination of Exchange Rates of Emerging Market Economies; Strengthening ASEAN - India Partnership: Trends and Future Prospects; Indo-Sri Lanka Trade and Investment Relations: Current Trends and Prospects; Indian Investments in Latin America and Caribbean: Trends and Prospects; International Trade in Processed Foods: An Indian Perspective; amongst many others.

Exim Bank, taking cognizance of the African Development Bank's High-Five strategy, brought out a set of five Working Papers on: Feed Africa; Water, Sanitation and Healthcare in Africa; Integrate Africa; Manufacturing in Africa and Power Sector in Africa delineating the opportunities for India to co-operate with Africa in each of these areas.

The Bank, leveraging its knowledge-base, and understanding of the export opportunities from various States in India, has partnered the UNDP in formulating a programme aimed at promoting export potential of MSMEs in the industrial clusters of the North-East region. The Bank has also conducted a Study titled, Exports from Uttar Pradesh: Trends, Opportunities and Policy Perspectives during the year.

Being a Policy Bank, the Bank has been pivotal in sharing knowledge and providing information as and when sought by the GOI on matters related to trade and investment. Amongst others, the Bank's officials have been part of India's negotiating team at the International Working Group Meetings on Export Credit.

Institutional Interaction

With an encouraging track record in building institutions in other developing countries, the Bank continues to secure fee-based consultancy assignments in developing countries. The Bank's exemplary experience of over three decades in introducing new products and services in a

developing country context has been crucial in advising other developing countries towards setting up Exim Banks and development financial institutions, and structuring of financial products. In FY 2017-18, the Ghana Export-Import Bank (Exim Ghana) commissioned the Bank to provide technical assistance across various operational areas of Exim Ghana.

The Bank further strengthened its traditional bonds with partner institutions around the world. With a view to providing a common platform to multilateral institutions and Indian companies, the Bank organized a series of seminars on business opportunities in projects funded by the World Bank and the Asian Development Bank. The seminars attracted suppliers, contractors and consultants from India, making it possible for them to have direct interface with officials from multilateral institutions.

The 9th BRICS Summit was held in 2017, in China. During the Summit, Exim Bank entered into two multilateral agreements with other member development banks of BRICS nations under the BRICS Interbank Cooperation Mechanism, namely, Interbank Local Currency Credit Line Agreement which would serve as an enabler to enter into bilateral agreements among the member banks subject to national laws, regulations and policies of the signatory institutions; and Co-operation Memorandum relating to Credit Ratings which would enable sharing of internal ratings amongst the BRICS development banks, and would serve as an ideal mechanism to take informed decisions for cross border lending in BRICS countries.

The Bank participated in the Annual General Meeting of the Global Network of Exim Banks and Development Finance Institutions, held in Geneva, in July 2017, which was followed by an Exchange Programme hosted by the BNDES (Brazilian Development Bank), in Brazil in November 2017. The Bank also participated in the Twenty Third Annual Meeting of the Asian Exim Banks Forum (AEBF), hosted by EFIC in Sydney, Australia, in November, 2017. The Bank played a leadership role

to set up the AEBF in 1996. Over the years it has evolved as an effective mechanism for economic co-operation and sharing best practices in various aspects of export credit agency operations.

The Bank is also a member of the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific, and co-hosted its Annual Meetings in New Delhi in February 2018. The theme of the Meeting was 'Promoting Inclusive and Sustainable Development - Role of DFI's'. On this occasion the Bank released two studies – Revitalizing Trade Finance: Development Banks and Export Credit Agencies at the Vanguard; and Creating a Resilient Trade Finance Architecture: A Compendium of Articles.

The Bank has an esteemed list of Directors on its Board, who have been guiding the Bank towards attaining its chartered objectives. They include, Ms. Rita Teotia, Commerce Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry; Shri Ramesh Abhishek, Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce & Industry; Shri T. S. Tirumurti, Secretary, Economic Relations, Ministry of External Affairs; Dr. Arvind Subramanian, Chief Economic Adviser, Government of India; Shri Pankaj Jain, Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance; Dr. M.D. Patra, Executive Director, Reserve Bank of India; Smt. Geetha Muralidhar, Chairman cum Managing Director, ECGC Ltd., Shri Rajnish Kumar, Chairman, State Bank of India; Shri M. K. Jain, Managing Director & CEO, IDBI Bank Ltd., Shri Rajeev Rishi, Chairman & Managing Director, Central Bank of India; and Shri Dinabandhu Mohapatra, Managing Director & CEO, Bank of India.

There have also been changes on the Board of the Bank. Shri M. K. Jain, Managing Director & CEO, IDBI Bank Ltd., Shri Dinabandhu Mohapatra, Managing Director and CEO, Bank of India, Shri Rajnish Kumar, Chairman, State Bank of India, Shri Vijay Keshav Gokhale, Secretary (ER), Ministry of External Affairs, and Shri T. S. Tirumurti, Secretary (ER), Ministry of External Affairs have been appointed as Directors on the Board.

Shri Amar Sinha, Secretary (Economic Relations), Ministry of External Affairs, Smt. Arundhati Bhattacharya, Chairperson, State Bank of India, Shri Vijay Keshav Gokhale, Secretary (ER) Ministry of External Affairs, Shri Kishor Kharat, Managing Director & CEO, IDBI Bank Ltd., and Smt. Usha Ananthasubramanian, Managing Director & CEO, Punjab National Bank relinquished their directorships consequent upon completion of their term or change in office. The Bank gratefully acknowledges their invaluable contribution as Directors.

Despite a challenging business environment, the Bank has vigorously pursued with its mission to promote Brand India and support Indian companies in their expeditions overseas in their pursuit to have a global footprint. The Bank has been proactive in pursuing the Government's policy business with the objective of creating socio-economic impact in the borrowing countries, while generating employment locally. The Bank, I am certain, will continue to serve as the principal financial institution promoting India's international trade and investment, besides playing the role of goodwill ambassador for India in foreign territories.



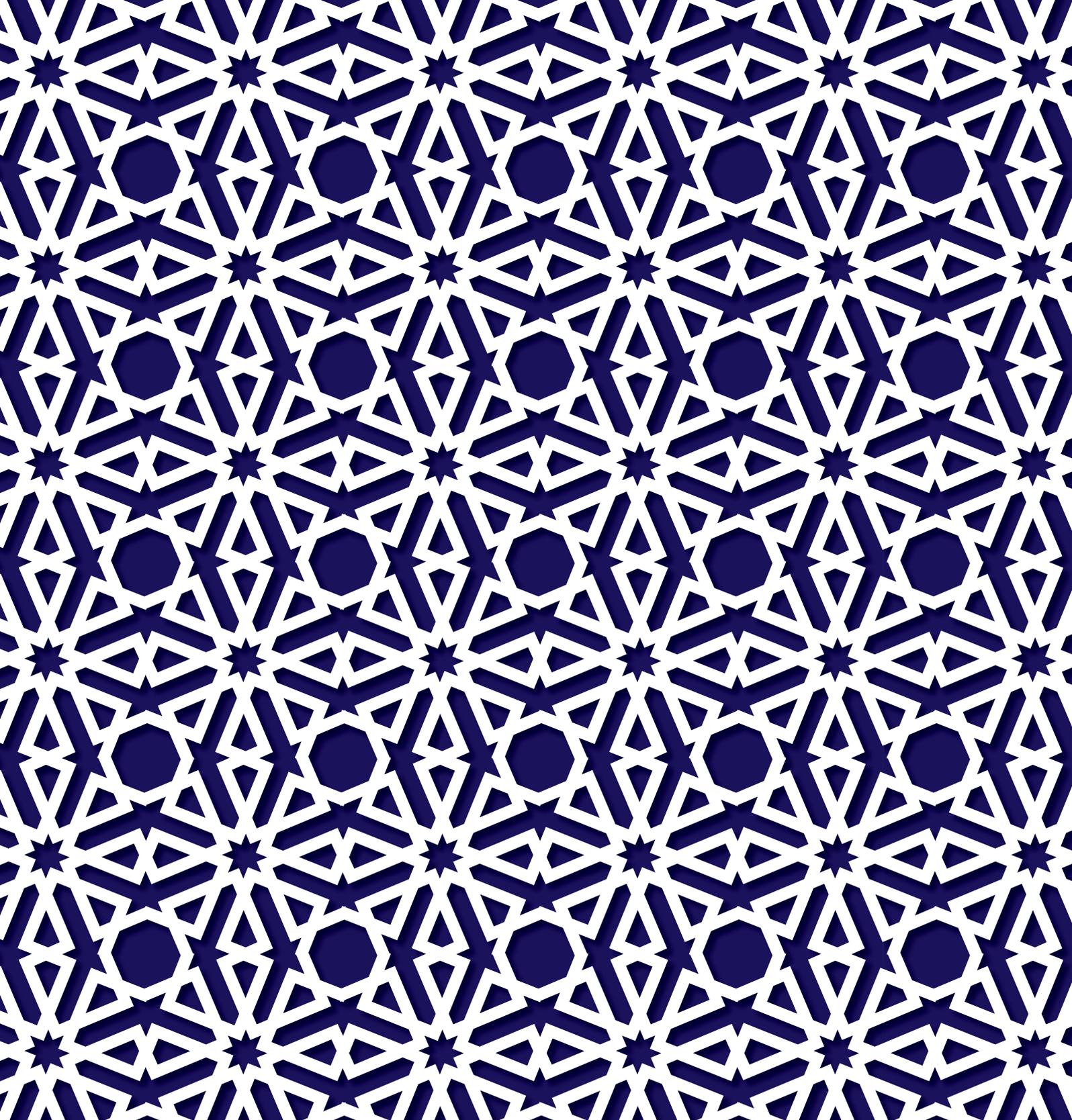
David Rasquinha

MANAGEMENT



Sitting from left to right- Sudatta Mandal, Samuel Joseph, Prahalathan Iyer, Harsha Bangari, Sangeeta Sharma,
David Rasquinha, Debasish Mallick, Rima Marphatia, Sunita Sindwani, Nadeem Panjetan,
David Sinate, C. P. Ravindranath Menon

Standing from left to right- Gaurav Bhandari, Vikramaditya Ugra, Dharmendra Sachan, Sriram Subramaniam, Manjiri Bhalerao,
Deepali Agrawal, Meena Verma, Tarun Sharma, Sujeet Bhale, T. D. Sivakumar, Utpal Gokhale,
P. J. Manjunaath



**ECONOMIC
ENVIRONMENT**

GLOBAL ECONOMY

According to the International Monetary Fund, the year 2017 marked the strongest global growth rate since 2011, at 3.8 per cent, as compared to 3.2 per cent in 2016, owing to a notable rebound in global trade, driven by recovery in investments in the advanced economies, coupled with continued strong growth in emerging Asia and a notable upswing in emerging Europe. Among the advanced economies, growth in 2017 was notably higher in Canada, South Korea, Singapore, Hong Kong, Germany, and the United States. Emerging market and developing economies, including China, Bangladesh, India and ASEAN-4 (Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam) also witnessed stronger upsurges in output growth, while other emerging economies such as Brazil, Argentina, Russia, and Nigeria witnessed a rebound to positive growth rates in 2017.

WORLD TRADE

Global trade growth (goods and services), in volume terms, is estimated to have more than doubled to 4.9 per cent in 2017, up from 2.3 per cent in 2016, after two consecutive years of decline, supported by a pickup in investment, particularly among advanced economies, and increased manufacturing output in Asia. The world trade prices of non-fuel commodities have grown by 6.8 per cent year-on-year in 2017, a five-fold increase as compared to negative growth of 1.5 per cent in 2016, owing to stronger demand for metals from China, tight supply conditions for food, and a general pickup in global demand. On the other hand, the extension of the OPEC+ agreement to limit oil production has led to a multi-fold increase in world oil prices by 23.3 per cent year-on-year in 2017, as compared to negative growth 15.7 per cent in 2016.

PRIVATE CAPITAL FLOWS IN EMERGING MARKET ECONOMIES

Net private capital inflows to emerging markets increased by more than 50 per cent to reach US\$ 1.2 trillion in 2017, from US\$ 795 billion in 2016, mainly driven by a strong pickup in portfolio debt flows, on the back of favourable global financial conditions and synchronised global growth.

CURRENT ACCOUNT BALANCE OF EMERGING MARKET ECONOMIES

The current account surplus for 2017 is estimated to have decreased to US\$ 172 billion, from US\$ 197 billion in the previous year, marking two consecutive years of falling surplus, owing to increased current account deficits in Turkey and India as compared to the previous year.

EXTERNAL DEBT IN EMERGING MARKET ECONOMIES

External debt of emerging market economies increased by 13.8 per cent to US\$ 63.4 trillion in 2017, as compared to US\$ 55.7 trillion in 2016, mainly driven by increase in government indebtedness as well as household indebtedness in these economies.

INDIAN ECONOMY

Continued stress in the corporate sector and weak capacity utilisation in the Indian economy resulted in sluggish investment growth during FY 2017-18. Accordingly, as per the Central Statistics office, real GDP growth moderated to 6.7 per cent during the year vis-a-vis 7.1 per cent in the previous year. Growth in FY 2017-18 was mainly sustained by pick up in activities in sub-sectors such as construction, trade, hotel, transport, communication and services related to broadcasting, and financial, real estate and professional services, and sustained high growth of public administration, defence and other services.

Agriculture

The agricultural sector is estimated to have grown at 3.4 per cent in its real gross value added (GVA) in FY 2017-18, as compared to 6.3 per cent in the previous year. In fact, food grains production had registered a modest growth of 1.6 per cent compared to 9.4 per cent in the previous agriculture year due to the high base effect. Accordingly, sectoral share of agriculture and allied sectors in GDP, declined to 17.1 per cent in FY 2017-18, from 17.9 per cent in the previous year.

Industry

The industrial sector growth moderated to 5.5 per cent in FY 2017-18 compared to 6.8 per cent in the previous year, reflecting significant slowdown in mining and quarrying activities, and moderation in the growth of manufacturing activities, electricity, gas and water supply. There was, however, a pick-up in construction activity, which witnessed a higher growth of 5.7 per cent, up from 1.3 per cent in the preceding year. The share of industrial sector witnessed a marginal decline from 29.3 per cent in FY 2016-17 to 29.1 per cent in FY 2017-18. Similarly, index of industrial production (IIP) growth also moderated to 4.3 per cent during FY 2017-18 as compared to 4.6 per cent in FY 2016-17, due to sluggish growth in mining and electricity. Eleven out of the twenty three industry groups in the manufacturing sector have shown negative growth during this period vis-a-vis the corresponding period of the previous year. Output of tobacco products and electrical equipment witnessed the largest contraction during this period.

According to the user-based classification of the IIP, moderation in growth was witnessed among primary goods, intermediate goods, and consumer durables at 3.7 per cent, 2.2 per cent and 0.6 per cent respectively, in FY 2017-18. On the other hand, capital goods and infrastructure/construction goods registered a growth of 3.9 per cent and 5.6 per cent compared to 3.2 per cent and 3.9 per cent respectively, during FY 2016-17.

Services

The services sector witnessed significant pick up in its growth, which increased to 7.9 per cent in FY 2017-18 compared to 7.5 per cent in the previous year. Services growth was mainly driven by improved growth in hotels, transport, communication and services related to broadcasting, which increased from 7.2 per cent in FY 2016-17 to 8.0 per cent in FY 2017-18. Growth in financial, real estate and professional services increased from 6.0 per cent to 6.6 per cent, during the same period. Public administration, defence and other services, continued to witness high growth of 10.0 per cent

in FY 2017-18, though moderately lower compared to 10.7 per cent witnessed in the previous year. The share of services sector in GDP stood higher at 53.8 per cent in FY 2017-18, compared to 52.8 per cent in the previous year.

Infrastructure

The eight core infrastructure supportive industries viz., coal, crude oil, natural gas, petroleum refinery products, fertilisers, steel, cement and electricity comprise nearly 40.3 per cent of the weight of items included in the IIP. These eight industries saw a cumulative growth of 4.3 per cent during FY 2017-18, decreasing from 4.8 per cent in the preceding year. During FY 2017-18, growth in the steel industry moderated to 5.6 per cent compared to 10.7 per cent during FY 2016-17, followed by refinery products at 4.6 per cent declining from 4.9 per cent and electricity at 5.3 per cent declining from 5.8 per cent in the previous year. Natural gas and cement registered an increase in growth of 2.9 per cent and 6.3 per cent during FY 2017-18 compared to a negative growth of 1.0 per cent and 1.2 per cent, respectively. Sectors like crude oil contracted by 0.9 per cent and fertilisers remained stagnant during the same period.

Inflation

The headline inflation, based on the consumer price index (CPI) stood at 3.6 per cent during FY 2017-18, compared to 4.5 per cent in the last year. The fall was associated with the moderation in food prices during the year, which was mainly due to good monsoons. Core CPI inflation, which excludes food and fuel groups, remained sticky. The average inflation based on WPI, which was at 1.7 per cent in FY 2016-17, picked up by 2.9 per cent during FY 2017-18. This trend is on the back of rising global commodity and energy prices.

Capital Markets

India's Net Foreign Direct Investment (FDI), during FY 2017-18 stood lower at US\$ 31.1 billion as against US\$ 35.6 billion in the previous year. Net portfolio investment during FY 2017-18, on the other hand, increased

significantly to US\$ 22.1 billion, compared with US\$ 7.6 billion in the last year.

Foreign Trade and Balance of Payments

India's merchandise exports stood higher at US\$ 303.3 billion during FY 2017-18, witnessing a growth of 9.9 per cent over the previous year. Exports, mainly non-oil, have now grown for two consecutive years. At the same time, India's imports also increased to US\$ 464.7 billion during FY 2017-18, witnessing a growth of 20.9 per cent over the previous year.

Export of petroleum and petroleum products increased by 18.5 per cent to US\$ 37.4 billion during FY 2017-18, whereas non-oil exports witnessed a growth of 8.7 per cent in the same period. Commodities such as agriculture and allied products, marine products, chemicals & related products, base metals, machinery, and petroleum and its products made significant improvements in terms of export growth. India's import of petroleum and its products (mainly crude) stood at US\$ 108.6 billion, during FY 2017-18, registering a growth of 24.9 per cent, over the last year. Non-

oil imports stood higher at US\$ 356.1 billion during FY 2017-18, registering an increase of 19.7 per cent over the last year. Import of gems & jewellery, electronic items, chemicals and related products, machinery and ores & minerals were the major items that registered significant increase in the non-oil import category.

Overall, India's trade deficit widened to US\$ 161.4 billion during FY 2017-18, as compared to US\$ 108 billion in the last year. India's services exports increased by 19.6 per cent to US\$ 195.1 billion during FY 2017-18, as compared to US\$ 163.1 billion in the preceding year. Software services exports in FY 2017-18 rose to US\$ 77.3 billion, compared to US\$ 73.7 billion in the last year. During the same period, net inflows under the capital and financial account increased from US\$ 14.8 billion to US\$ 47.8 billion.

India's foreign exchange reserves increased to US\$ 424.4 billion as at end March 2018, from US\$ 370 billion as at end March 2017. At the same time, external debt also witnessed an increase, to US\$ 529.7 billion as at end of March 2018 from US\$ 471.3 billion in March 2017.

MAJOR POLICY CHANGES DURING FY 2017-18

Monetary Policy

- The Repo rate was reduced, from 6.25 per cent as on March 2017 to 6.00 per cent as on March 2018. The Reverse repo rate stands adjusted at 5.75 per cent as on March 2018, while the marginal standing facility rate and the Bank Rate were reduced to 6.25 per cent, each.
- The Statutory Liquidity Ratio was also reduced in a phased manner from 20.50 per cent to 19.50 per cent as on March 2018.

Trade Policy

- Under the revised FTP 2015-2020, after the mid-term review in December 2017, Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) incentives for two sub-sectors of textiles, namely readymade garments and made-ups was hiked from 2% to 4%. Existing MEIS incentives for exports by MSMEs/labour intensive industries, which include sectors like leather, agriculture, hand tools, marine products, electronic and telecom components, among others, were increased by 2%.
- To provide an impetus to services trade, the Services Exports from India (SEIS) incentive was increased by 2% for notified services like Business, Legal, Accounting, Architecture, Engineering, Education, Hospitals, Hotels and Restaurants.
- The validity period of the Duty Credit Scrips has increased from 18 months to 24 months to enhance their utility under the GST framework. GST rates for transfer/sale of scrips has been reduced to zero from earlier rate of 12%.
- A new scheme of Self-Assessment based duty free procurement of inputs required for exports has been introduced. There will be no need of Standard Input Output Norms in such cases and this will eliminate delays. It is based on trust. Exporters will self-certify the requirement of duty free raw materials/inputs. The scheme would initially be available to the Authorized Economic Operators (AEOs) and will get expanded as more exporters join the AEO program. The scheme will improve ease of doing business.
- Contact@DGFT service has been launched on the DGFT website (www.dgft.gov.in) as a single window contact point for exporters and importers for resolving all foreign trade related issues and also to give suggestions. Exporters/Importers can track status of their queries through the assigned reference number. Feedback mechanism has also been provided.
- A new Logistics Division has been created in the Department of Commerce to develop and coordinate integrated development of the logistics sector, by way of policy changes, improvement in existing procedures, identification of bottlenecks and gaps, and introduction of technology based interventions in this sector. These steps would improve India's ranking in the Logistics Performance Index and promote exports and enhanced growth.
- To focus on improving Ease of Trading across Borders for exporters and importers, a professional team was constituted to handhold, assist and support exporters with their export related problems, accessing export markets and meeting regulatory requirements.
- A negative list of capital goods which are not permitted under the Export Promotion on Capital Goods (EPCG) scheme has been notified.
- The concept of Domestic Tariff Area (DTA) sale from Export Oriented Units (EoUs) on concessional and full duty has been removed and hence, the limit on entitlement of DTA

sale has also been removed. Consequently, restriction on DTA sale of motor cars, alcoholic liquors, books and tea has been removed.

- Restrictions removed on import of second hand goods imported for the purpose of repair/refurbishing/re-conditioning or re-engineering to facilitate generation of employment in the repair services sector.
- Issue of working capital blockage of the exporters due to upfront payment of GST on inputs has been addressed. Under advance authorisation EPCG Scheme, 100% EoUs, exporters have been extended the benefit of sourcing inputs/capital goods from abroad as well as domestic suppliers for exports without upfront payment of GST.
- Special package for employment generation in leather and footwear sector was introduced for implementation of Central Sector Scheme “Indian Footwear, Leather & Accessories Development Programme” with an approved expenditure of ₹ 26 billion over the three years from FY 2017-18 to FY 2019-20. The scheme would lead to development of infrastructure for the leather sector, address environment concerns specific to the leather sector, facilitate additional investments, employment generation and increase in production. The Special Package has the potential to generate 0.324 million new jobs in 3 years and assist in formalisation of 0.20 million jobs as cumulative impact in Footwear, Leather & Accessories Sector.
- Custom Duty has been increased in the Union Budget of FY 2018-19 in certain sectors which have substantial potential for domestic value addition like food processing, electronics, auto components, footwear and furniture. This would give a boost to domestic value addition (Make

in India) and therefore promote value-added exports.

Investment Policy

- According to the FDI Policy of August 2017, more than 90% of the total FDI inflows are now through the automatic route.
- The Foreign Investment Promotion Board (FIPB) has successfully implemented e-filing and online processing of FDI applications. The most significant amendment to the FDI regime has been the institutional change brought by notification dated June 5th, 2017 issued by the Department of Economic Affairs confirming the abolition of the FIPB (the erstwhile government body authorised to approve proposals for FDI requiring government approval); and the introduction of the ‘Foreign Investment Facilitation Portal’, an administrative body to facilitate FDI applicants.
- E-Commerce: 100% FDI in B2B e-commerce, Single brand retail trading entity permitted for B2C e-commerce and e-commerce food retailing.
- Retail: 100% FDI and 49% under automatic route is allowed. In case of ‘state-of-art’ and ‘cutting-edge technology’ sourcing norms can be relaxed subject to Government approval. 100% FDI under government approval route was allowed for retail trading, including through e-commerce and also food products manufactured and/or produced in India. Sourcing norms applicable for FDI in Single Brand Retailing were relaxed and will not be applicable up to three years from commencement of the business.
- Civil Aviation: 100% FDI allowed under automatic route in both Greenfield and Brownfield Projects.

WORLD OUTPUT, TRADE & WORLD TRADE PRICES

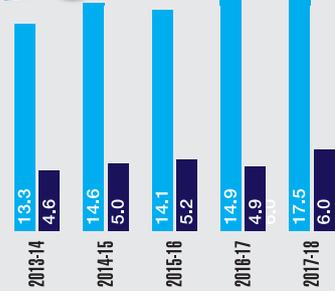
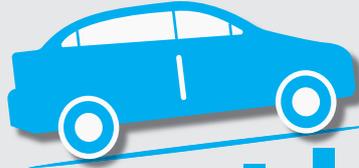
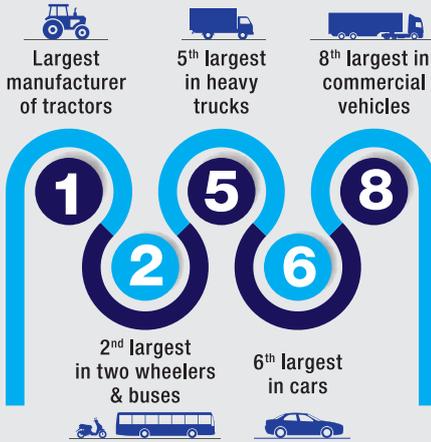
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (P)	2019 (P)
I. World Output (real GDPs, % change)	4.3	3.5	3.5	3.6	3.5	3.2	3.8	3.9	3.9
(A) Advanced Economies	1.7	1.2	1.3	2.1	2.3	1.7	2.3	2.5	2.2
United States	1.6	2.2	1.7	2.6	2.9	1.5	2.3	2.9	2.7
Canada	3.1	1.7	2.5	2.6	0.9	1.4	3.0	2.1	2.0
Euro Area	1.6	-0.9	-0.2	1.3	2.0	1.8	2.3	2.4	2.0
UK	1.5	1.3	1.9	3.1	2.2	1.9	1.8	1.6	1.5
Japan	-0.1	1.5	2.0	0.3	1.1	0.9	1.7	1.2	0.9
(B) Emerging & Developing Economies	6.4	5.4	5.1	4.7	4.3	4.4	4.8	4.9	5.1
Emerging and Developing Asia	7.9	7.0	6.9	6.8	6.8	6.5	6.5	6.5	6.6
China	9.5	7.9	7.8	7.3	6.9	6.7	6.9	6.6	6.4
India	6.6	5.5	6.4	7.4	8.2	7.1	6.7	7.4	7.8
Latin America and the Caribbean	4.7	3.0	2.9	1.2	0.1	-0.6	1.3	2.0	2.8
Middle East and North Africa	4.6	5.3	2.5	2.6	2.6	4.9	2.6	3.4	3.7
Sub-Saharan Africa	5.0	4.3	5.3	5.1	3.4	1.4	2.8	3.4	3.7
CIS Countries	5.3	3.6	2.5	1.1	-2.2	0.4	2.1	2.2	2.1
Russia	5.1	3.7	1.8	0.7	-2.8	-0.2	1.5	1.7	1.5
Emerging and Developing Europe	6.5	2.4	4.9	3.9	4.7	3.2	5.8	4.3	3.7
II. World Merchandise Trade (Vol. Gr. %)	7.0	2.3	3.3	3.1	2.2	2.2	5.4	5.3	4.8
<i>Global Merchandise Exports (US\$ billion)</i>	17,931	18,135	18,549	18,635	16,223	15,757	17,422	19,474	20,515
III. World Trade Prices (US\$, % change)									
Manufactures	4.2	2.8	-3.0	-0.4	-2.3	-5.2	1.4	1.9	1.3
Oil	31.6	1.0	-0.9	-7.5	-47.2	-15.7	23.3	18.0	-6.5
Non-fuel primary commodities	18.0	-10.1	-1.4	-3.9	-17.5	-1.5	6.8	5.6	0.5

Note: P = Projections

Source: IMF, World Economic Outlook (WEO) April 2018.

PERFORMANCE OF SELECT SECTORS

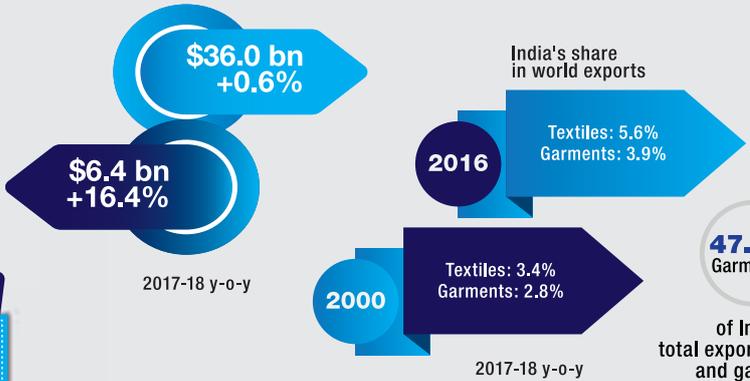
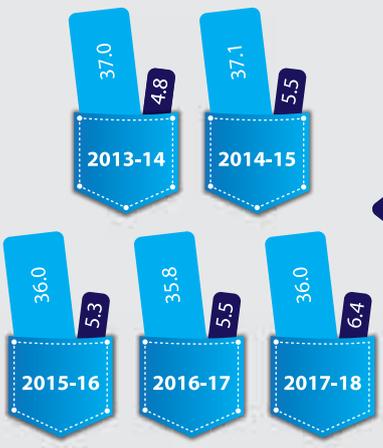
AUTOMOTIVE PRODUCTS



2017-18 y-o-y

7.1% of India's GDP

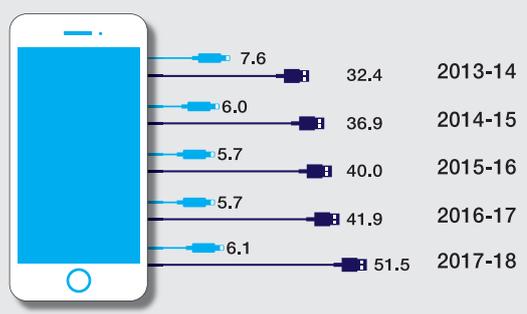
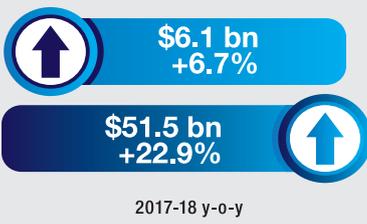
TEXTILE AND GARMENTS



47.7% of India's total exports of textile and garments

- India is world's largest cotton and jute producer
- 2nd largest textile & garments exporter
- 2nd largest textile manufacturing capacity

ELECTRONICS



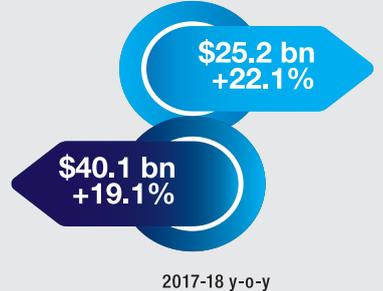
2020 The electronics market of India is anticipated to reach **US\$ 400 billion**

60.2% of India's total imports of electronic goods is from China

CAPITAL GOODS



4.4% Increase in the index of industrial production of capital goods during 2017-18



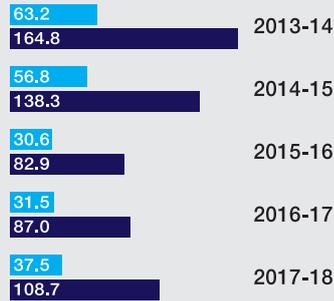
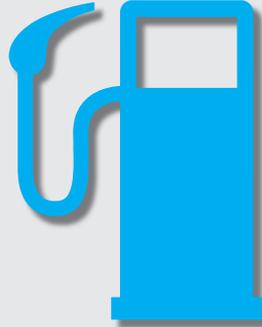
PERFORMANCE OF SELECT SECTORS

PETROLEUM (CRUDE AND PRODUCTS)

\$37.5 bn
+18.7%

\$108.7 bn
+24.9%

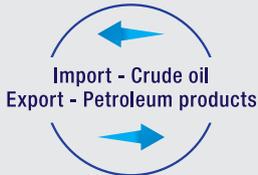
2017-18 y-o-y



635 million metric tonnes of proven oil reserves

54 trillion cubic feet of proven natural gas reserves

96 trillion cubic feet of estimated shale gas reserves



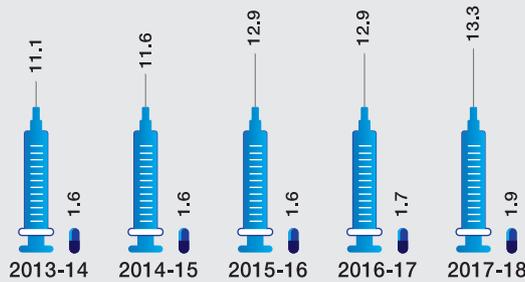
Import content in oil & gas sector (Approx range)

15% - Refinery
67% - Upstream segment

PHARMACEUTICAL PRODUCTS



12 12th largest exporter in 2017, with a share of 1.8% in global exports



\$13.3 bn
+2.5%

\$1.9 bn
+10.5%

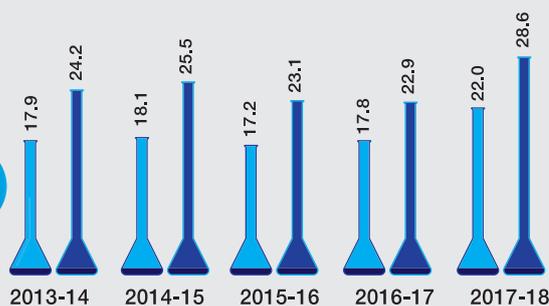
2017-18 y-o-y

CHEMICAL AND RELATED PRODUCTS

\$22.0 bn
+24.0%

\$28.6 bn
+24.9%

2017-18 y-o-y

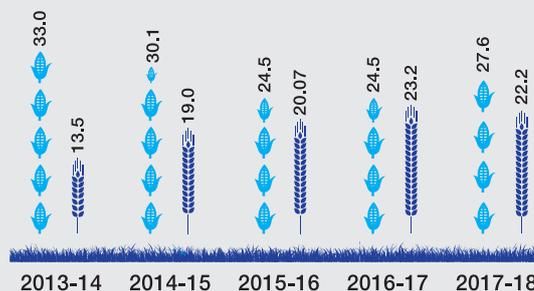


3 3rd largest producer of chemicals in Asia

7th largest in the world

67.3% of India's total exports of chemicals & related products

AGRI AND ALLIED PRODUCTS



\$27.6 bn
+12.4%

\$22.2 bn
-4.3%

2017-18 y-o-y

STATISTICAL SNAPSHOT OF THE INDIAN ECONOMY

INDICATORS	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
GDP (at current prices, US\$ billion)	1708.5	1874.3	1863.6	1919.4	2043.3	2147.2	2271.0 ^e	2585.0 ^f
GDP Per capita (US\$)	1411.7	1502.7	1475.5	1501.2	1579.2	1640.3	1714.2	1929.0 ^f
Real GDP Growth (%)	8.9	6.7	5.5**	6.4**	7.5**	8.0**	7.1 ^{re**}	6.7 ^{re}
<i>Agriculture & allied activities</i>	8.6	5.0	1.5**	5.6**	-0.2**	0.7**	4.9 ^{re**}	3.4 ^{re}
<i>Industry</i>	7.6	7.8	3.3**	3.8**	7.5**	8.8**	5.6 ^{re**}	5.5 ^{re}
<i>Services</i>	9.7	6.6	8.3**	7.7**	9.7**	9.7**	7.7 ^{re**}	7.9 ^{re}
Sectoral Share in GDP (%)								
<i>Agriculture & allied activities</i>	14.6	18.5**	18.3**	18.6**	18.0**	17.5**	17.4 ^{re**}	17.1 ^{re}
<i>Industry</i>	27.9	32.5**	31.7**	30.8**	30.2**	29.6**	28.8 ^{re**}	29.1 ^{re}
<i>Services</i>	57.5	49.0**	50.0**	50.6**	51.8**	52.9**	53.8 ^{re**}	53.8 ^{re}
Population (million)	1210.2	1247.24	1263.1	1278.6	1293.9	1309.1	1324.8	1340.1 ^f
Inflation rate (CPI, annual avg. %)	10.4	8.3	10.1**	9.3**	5.8**	4.9**	4.5**	3.6**
Inflation rate (WPI, annual avg. %)	9.6	8.9	6.9**	5.2**	1.3**	-3.7**	1.7**	2.9**
Gross Fiscal Deficit (% of GDP)	4.8	5.9	4.9	4.5	4.1	3.9	3.5 ^e	3.5 ^e
Exchange Rate (₹/US\$, avg.)	45.6	47.9	54.4	60.5	61.1	65.5	67.1	64.4
Exchange Rate (₹/€, avg.)	60.2	65.9	70.1	81.2	77.5	72.3	73.6	72.1
Exports (US\$ billion)	249.8	306.0	300.4	314.4	310.3	262.3	276.3	303.3
% change	39.8	22.5	-1.8	4.7	-1.3	-15.5	5.3	9.9 ^e
Oil Exports (US\$ billion)	36.4	56.7	60.9	63.2	56.7	30.6	31.7	37.4
% change	29.0	55.9	7.3	3.8	-10.2	-46.1	3.7	18.5 ^e
Non-oil Exports (US\$ billion)	213.4	249.2	239.5	251.2	253.6	231.7	244.6	265.4
% change	41.8	16.8	-3.9	4.9	0.9	-8.6	5.5	8.5 ^e
Imports (US\$ billion)	369.8	489.3	490.7	450.2	448.0	381.0	384.3	464.7
% change	28.2	32.3	0.3	-8.3	-0.5	-15.0	0.9	20.9 ^e
Oil Imports (US\$ billion)	106.0	155.0	164.0	164.8	138.3	82.9	86.9	108.6
% change	21.6	46.2	5.9	0.4	-16.0	-40.0	4.8	24.9 ^e
Non-oil Imports (US\$ billion)	263.8	334.3	326.7	285.4	309.7	298.1	297.4	356.1
% change	31.1	26.7	-2.3	-12.6	8.5	-3.8	-0.2	19.7 ^e
Trade Balance (US\$ billion)	-120.0	-183.3	-190.3	-135.8	-137.7	-118.7	-108.0	-161.4
Services Exports (US\$ billion)	124.6	140.9	145.7	151.8	158.1	154.3	163.1	195.1
Software Exports (US\$ billion)	53.1	62.2	65.9	69.4	73.1	74.2	73.7	77.3
Services Imports (US\$ billion)	80.6	76.9	80.8	78.7	81.6	84.6	95.7	117.5
Services Balance (US\$ billion)	44.0	64.0	64.9	73.1	76.5	69.7	67.4	77.6
Current Account Balance (US\$ billion)	-47.9	-78.2	-87.8	-32.4	-26.8	-22.1	-15.2	-48.7
CAB as percentage of GDP (%)	-2.8	-4.2	-4.8	-1.7	-1.3	-1.1	-0.7	-1.9
Forex Reserves (US\$ billion)	304.8	294.4	292.0	304.2	341.6	360.2	370.0	424.4
External Debt (US\$ billion)	317.9	360.8	409.4	446.2	474.7	485.0	471.9	529.7
External Debt to GDP Ratio (%)	18.2	20.5	22.3	23.9	23.2	23.5	20.2	20.5
Short Term Debt (US\$ billion)	65.0	78.2	96.7	91.7	85.5	83.4	88.0	102.2
Short Term Debt/Total Debt (%)	20.4	21.7	23.6	20.5	18.0	17.2	18.6	19.3
Total Debt Service Ratio (%)	4.4	6.0	5.9	5.9	7.6	8.8	8.3	7.5
FDI (US\$ billion)	36.0	46.6	34.3	36.0	45.1	55.6	60.2	61.0
GDRs/ADRs (US\$ billion)	2.0	0.6	0.2	0.02	1.3	0.4	-	-
FII (net) (US\$ billion)	29.4	16.8	27.6	5.0	40.9	-4.0	7.8	22.1
FDI Outflows (US\$ billion)	17.2	10.9	7.1	9.2	4.0	8.9	6.6	9.3
Memo Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017^f	2018^f
Global GDP (% change)	4.3	3.5	3.5	3.6	3.4	3.2	3.7	3.9
Advanced Economies	1.7	1.2	1.3	2.1	2.2	1.7	2.3	2.5
Emerging and Developing Economies	6.4	5.4	5.1	4.7	4.3	4.4	4.7	4.9
World Merch. Trade (Vol., % change)	7.0	2.3	3.3	3.1	2.3	2.3	4.3	5.3
World Merch. Exports (US\$ trillion)	17.9	18.1	18.5	18.6	16.2	15.8	17.1	19.5
Growth in Value of World Merch. Exports (%)	20.2	1.0	2.1	0.5	-12.9	-2.3	8.2	14.0

Note: ^e - GOI's estimates; ^{re} - EAC, GOI's revised estimates; ^f - IIF Estimates - Not Available; [^] - % change is over corresponding period of the previous year; ** - Data as per the revised base year 2011-12.

Source: Economic Survey, Various issues; Union Budget, RBI Monthly Bulletin, Annual Report & Weekly Statistical Supplement; Ministry of Finance; CSO; Ministry of Commerce & Industry; Institute of International Finance (IIF); and International Monetary Fund (IMF).



**DIRECTORS'
REPORT**

The Directors are pleased to present the report of the working of the Bank with the audited Balance Sheet and accounts for the year ended March 31, 2018.

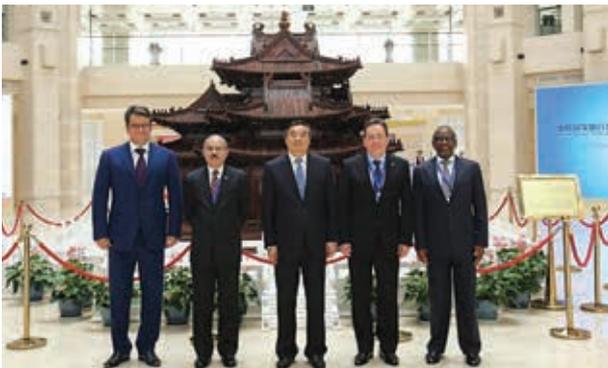
REVIEW OF OPERATIONS AND FINANCIAL PERFORMANCE

Loan Assets

The Bank approved loans aggregating ₹ 978.26 billion under various lending programmes during FY 2017-18 as against ₹ 647.78 billion during FY 2016-17. Loan disbursements during FY 2017-18 were ₹ 685.35 billion as against ₹ 446.94 billion during FY 2016-17, while loan repayments during FY 2017-18 amounted to ₹ 598.35 billion, as against ₹ 371.14 billion in FY 2016-17. Net loan assets as of March 31, 2018, were ₹ 1,075.32 billion, registering an increase of 4.76 per cent over the previous year. Rupee loans and advances accounted for 28 per cent of the net loan assets as on March 31, 2018, while the balance 72 per cent were in foreign currency. Short-term loans accounted for 25 per cent of the net loans and advances as on March 31, 2018.

Non-Funded Facilities

During the year, the Bank sanctioned non-funded facilities aggregating ₹ 107.81 billion as against ₹ 61.15 billion in FY 2016-17, comprising project guarantees, financial guarantees and Letters of Credit. The Bank's aggregate non-funded portfolio, comprising Guarantees, Letters of Credit and Standby Letters of Credit, as of March 31, 2018, stood at ₹ 132.40 billion as against ₹ 122.31 billion as of March 31, 2017, representing a growth of 8.25 per cent. Guarantees issued during



Heads of the member development banks at the BRICS Interbank Cooperation Mechanism meeting held at Beijing, China.

FY 2017-18 amounted to ₹ 53.80 billion as against ₹ 45.13 billion in FY 2016-17. Letters of Credit issued during FY 2017-18 amounted to ₹ 2.07 billion as against ₹ 7.49 billion in FY 2016-17. Guarantees in the books of the Bank as of March 31, 2018, were ₹ 128.36 billion as against ₹ 112.36 billion as of March 31, 2017, and Letters of Credit as of March 31, 2018, amounted to ₹ 4.04 billion as against ₹ 9.95 billion as of March 31, 2017.

Income/Expenditure

The Bank registered loss before tax of ₹ 42.30 billion on account of the General Fund during FY 2017-18, as against a profit of ₹ 3.13 billion for the FY 2016-17. After providing for income tax of ₹ 13.06 billion, loss after tax amounted to ₹ 29.24 billion during FY 2017-18, as against profit after tax of ₹ 0.41 billion during FY 2016-17. Profit before tax of the Export Development Fund during 2017-18 was ₹ 114.55 million as against ₹ 101.67 million during FY 2016-17. After providing for tax of ₹ 39.64 million, the post-tax profit amounted to ₹ 74.90 million as against ₹ 66.49 million during FY 2016-17. The profit of ₹ 74.90 million is carried forward to next year.

Business income including interest on loans, exchange, commission, brokerage and fees, etc. during FY 2017-18 was ₹ 56.56 billion, as compared to ₹ 59.14 billion in FY 2016-17. Investment income, interest on bank deposits, etc. during FY 2017-18 was ₹ 31.23 billion, as compared to ₹ 33.21 billion in FY 2016-17. Interest expenses in FY 2017-18 at ₹ 66.40 billion were higher by ₹ 0.75 billion mainly due to the increase in borrowings. Administrative expenses as a per



Construction of 225 kV transmission lines in different regions of Senegal being executed by Kalpataru Power Transmission Ltd. and financed through Buyer's Credit from Exim Bank.



Exchange of the Facility Agreement of US\$ 1.60 billion for 1320 MW Maitree super thermal power project in Bangladesh.

cent of total expenses (excluding provisions for contingencies) worked out to 2.75 per cent during FY 2017-18 as against 2.56 per cent during FY 2016-17.

Borrowings

Total borrowings of the Bank were ₹ 1,041.65 billion as on March 31, 2018, higher by 8.42 per cent compared to total borrowings of ₹ 960.73 billion as on March 31, 2017.

Resources

During the year, the Bank received capital of ₹ 5 billion from the Government of India. As on March 31, 2018, the Bank's total Resources including paid-up capital of ₹ 73.59 billion and reserves of ₹ 22.41 billion aggregated ₹ 1,137.65 billion. Exim Bank's Resource base inter-alia includes Rupee Bonds, Certificates of Deposit, Commercial Papers, Term Deposits, FC Bonds, FC Loans and long-term swaps. During the year, the Bank raised borrowings of varying maturities (excluding raised and repaid during the year) aggregating ₹ 399.15 billion comprising Rupee Resources of ₹ 186.70 billion and foreign currency resources of US\$ 3.26 billion equivalent. Foreign currency resources aggregating US\$ 2.83 billion equivalent were raised through bonds, bilateral / club / syndicated loans and US\$ 0.43 billion by way of Buy-Sell swaps (excluding raised and repaid during the year). As on March 31, 2018, the Bank had a pool of foreign currency resources equivalent to US\$ 12.84 billion and outstanding Rupee Resources of ₹ 482 billion. Market borrowings as on March 31, 2018, constituted 100 per cent of the total borrowings and 92 per cent of the total resources of the Bank.



Line of Credit agreement signed for US\$ 71.40 million for upgradation of four military hospitals in Cote d'Ivoire.

Foreign Currency Resources

During FY 2017-18, the Bank raised foreign currency resources aggregating US\$ 3.26 billion. The Bank successfully raised a 5-year Reg S floating rate Formosa Bond of US\$ 400 million in August 2017. The bond issue was the largest Formosa issuance out of India and first Formosa transaction by an Indian financial institution. In January 2018, the Bank successfully priced a 10-year Bond issue of US\$ 1 billion, its second transaction in the 144A/Reg S format. The issue attracted a total order book in excess of US\$ 1.8 billion from over 100 high-quality global investors. The Bond issue achieved the tightest ever spread over US Treasury for an Indian entity for a 10-year issuance. The issue has also set a benchmark for other Indian issuers to access the 144A/RegS markets. So far, the Bank has raised foreign currency resources in diverse currencies including Australian Dollars, Euros, Great Britain Pounds, Japanese Yen, Mexican Peso, Offshore Renminbi, Singapore Dollars, South African Rands, Swiss Francs, Turkish Lira and United States Dollars.

International and Domestic Rating

The Bank is rated Baa2 (Stable) by Moody's, BBB- (Stable) by Standard and Poor, BBB- (Stable) by Fitch Ratings and BBB+ (Stable) by Japan Credit Rating Agency (JCRA). During the year, Moody's upgraded the rating to Baa2 from Baa3, consequent to upgrade of Government of India's issuer rating. All the above ratings are of investment grade or above and are at par with the sovereign rating. The Bank's domestic debt instruments continued to enjoy the highest rating viz., 'AAA' from the rating agencies, CRISIL, ICRA and CARE for long term instruments and A1+ from the rating agencies CRISIL, ICRA and CARE for short term instruments.

Asset Quality

As per the Reserve Bank of India (RBI) prudential norms for Financial Institutions, a credit / loan facility in respect of which interest and/or principal has remained overdue for more than 90 days, is defined as a Non Performing Asset (NPA). The Bank's gross NPAs at ₹ 119.76 billion worked out to 10.37 per cent of the total loans and advances as of March 31, 2018. The Bank's NPAs (net of provisions) of ₹ 40.28 billion as on March 31, 2018, were at 3.75 per cent of the net loans and advances (net of provisions) as on March 31, 2018. The Provision Coverage Ratio (PCR) as on March 31, 2018, was 71.26 per cent.

Asset Classification

'Non Performing Assets' are those where interest and/or principal remains overdue for more than 90 days. Sub-standard assets that have remained as NPAs for a period exceeding 12 months are classified as 'doubtful assets.' 'Loss assets' are those considered uncollectable. The gross NPAs as on March 31, 2018, comprised sub-standard assets of 24.96 per cent, and doubtful assets of 75.04 per cent. The net NPAs as on March 31, 2018, comprised sub-standard assets of 56.59 per cent, and doubtful assets of 43.41 per cent. The Bank did not have any loss assets as on March 31, 2018.

Capital Adequacy

The Capital to Risk Assets Ratio (CRAR) was 10.35 per cent as on March 31, 2018, as compared to 15.81 per cent as on March 31, 2017, as against a minimum 9 per cent norm stipulated by RBI. The Debt-Equity Ratio as on March 31, 2018 was 10.85 as compared to 7.99 as on March 31, 2017.



Signing of a Line of Credit agreement of US\$ 81 million for establishment of 10 vocational training centres in Rwanda.

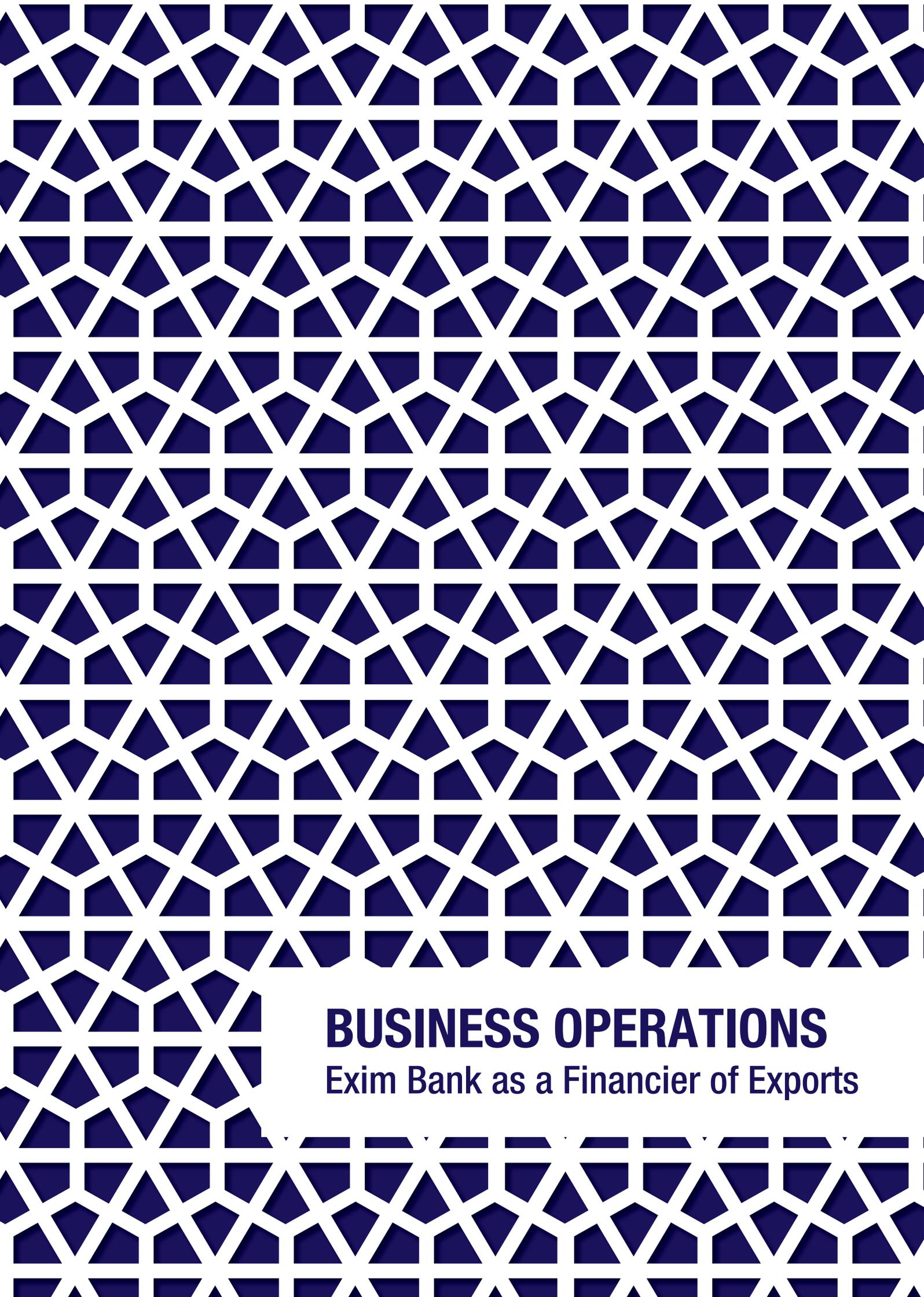
Exposure Norms

RBI has prescribed credit exposure limits for all-India term lending institutions, at 15 per cent of the financial institutions' capital funds, effective from March 31, 2002, for exposure to individual borrowers and at 40 per cent for group borrowers. An additional exposure up to 5 per cent (i.e. a total exposure up to 20 per cent of capital funds of the financial institution for Single Borrowers and 45 per cent of capital funds for Borrower Groups) can be taken in exceptional circumstances, with the prior approval of the Board. The exposure ceilings for individual borrowers and borrower groups can be exceeded by an additional five percentage points (i.e. 5 per cent of total capital funds) and ten percentage points (i.e. 10 per cent of total capital funds) respectively (over and above the maximum limits of 20 per cent and 45 per cent, respectively), provided the additional credit exposure is on account of infrastructure projects in India. The Bank's credit exposures to single and group borrowers as on March 31, 2018, were within the limits stipulated by RBI. There were 2 borrowers as on March 31, 2018, for whom exposure over 15 per cent of capital funds was assumed with the approval of the Board. Exposure to these borrowers as on March 31, 2018, stood at 19.56 per cent and 16.91 per cent of the capital funds of the Bank respectively.

RBI has advised financial institutions to adopt internal limits on exposures to specific industry sectors so that the exposures are evenly spread over various sectors. The industry exposure limits adopted by the Bank for each industry sector are 15 per cent of the Bank's credit exposure to all industry sectors. The Bank's exposure to a single industry sector was not more than 15 per cent of its total exposure as on March 31, 2018.



Signing of Buyer's Credit agreement of US\$ 110 million under the National Export Insurance Account to the Government of Mauritania.



BUSINESS OPERATIONS

Exim Bank as a Financier of Exports

PROJECTS, PRODUCTS AND SERVICES EXPORTS

The Bank provides a range of export credit products like finance for export of projects and consultancy services, capital equipment finance, export project cash flow deficit finance, guarantees and letter of credits. The Bank is equipped to offer a comprehensive financing package to Indian project exporters including funded support and project related guarantee facilities.

Export Contracts

Some major project exports contracts supported by Exim Bank during the year included Design, supply, assembly, testing and commissioning of transmission lines in Mauritania, and Bangladesh by Kalpataru Power Transmission Ltd.; and in Afghanistan by KEC International Ltd.; design, manufacture, installation of raw water treatment plant and reverse osmosis for petroleum refinery and polypropylene plant in Nigeria by VA Tech Wabag Ltd.; and solar power project in Argentina by Sterling and Wilson Pvt. Ltd.

Export Credits and Guarantees

During the year, the Bank approved loans aggregating ₹ 35.11 billion by way of supplier's credit, buyer's credit and finance for Project Exports, as against ₹ 19.88 billion during the previous year. Disbursements amounting to ₹ 24.91 billion were made during the year, as compared to ₹ 20.09 billion during the previous year. Guarantees issued during the year amounted to ₹ 43.97 billion, as against ₹ 30.67 billion during the previous year. These guarantees mainly pertain to overseas projects in sectors such as power generation, transmission and distribution, infrastructure development, solar EPC, consultancy services, water purification, etc.



The 2nd Bhairab Bridge project was financed under a Line of Credit of US\$ 862 million to the Government of Bangladesh.



Exim Bank supported PT Armada Gema Nusantara, Indonesia by way of a Buyer's Credit facility of US\$ 71 million for the purchase of a Floating, Production, Storage and Offloading vessel constructed by Armada Madura EPC Ltd.

Buyer's Credit

Buyer's Credit is a programme under which the Bank facilitates Indian project exports by extending credit to overseas buyers for financing their imports from India. During FY 2017-18, the Bank extended Buyer's Credit facilities aggregating ₹ 80.49 billion to seven overseas companies in sectors such as oil and gas, metals, fertiliser, hydro, wind and peat-based power, transport vehicles, auto spare parts, agro-based products and commodities, steel wires and wire rods, etc. Disbursements under the Buyer's Credit programme aggregated ₹ 15.60 billion for exports to countries that include Indonesia, Thailand, UAE, the United States and more than 14 countries in Africa. During the year, Exim Bank has also extended a credit line of US\$ 125 million to the African Export-Import Bank and US\$ 75 million to the Eastern and Southern African Trade and Development Bank to facilitate export of goods and services from India. Exim Bank also participated in Trade Finance Facilitation Programme of Inter-American Development Bank (IADB) for supporting import of goods and services from India.

Buyer's Credit under the National Export Insurance Account

The Bank has laid strong emphasis on enhancing India's project exports, the funding options for which have been strengthened with the introduction of the Buyer's Credit under GOI's National Export Insurance Account (BC-NEIA) Programme. The Bank has sanctioned an aggregate amount of US\$ 2.83 billion, for twenty-four projects, valued at US\$ 3.04 billion, as on March 31, 2018, including a water treatment plant and distribution to reservoirs

project in Sri Lanka; integrated LPG storage facility at the Beira Port in Mozambique; supply of vehicles and spares to Cote d'Ivoire, Senegal, Tanzania and Zimbabwe; transmission line projects in Cameroon, Ethiopia, Mauritania, Senegal and Zambia; a railway line project in Ghana; road projects in Maldives and Zambia; and an irrigation project in Suriname. The Bank has also given in-principle commitments for an aggregate amount of US\$ 8.65 billion supporting 70 projects valued at US\$ 10.09 billion, under BC-NEIA at the behest of several leading Indian project exporters.

Lines of Credit

Exim Bank extends on behalf of GOI Lines of Credit (LOCs) to overseas financial institutions, regional development banks, sovereign governments and other entities overseas, to enable buyers in those countries to source developmental and infrastructure projects, equipment, goods and services from India, on deferred credit terms. During the year, the Bank extended 12 LOCs, aggregating US\$ 6.11 billion, to support export of projects, goods and services from India. LOCs extended by Exim Bank during the year include LOCs to the ECOWAS Bank for Investment and Development and the Governments of Bangladesh, Cambodia, Cote d'Ivoire, Guyana, Madagascar, Mauritius, Rwanda, Sri Lanka and Zambia. The LOCs will finance and catalyse exports by financing projects such as upgradation of military hospitals, primary health centers, pre-fabricated health posts, establishment of vocational training centers, business incubation centres, water resources development, procurement of rolling stock for railways, up-gradation of railway tracks



Overseas Investment Finance to Indo-MIM Private Ltd., Bengaluru, a manufacturer of metal injection moulded parts, for equity investment in its 100% subsidiary, Indo-MIM Inc., Delaware, USA.



A portable water project for semi-urban and rural communities in Niger was executed under a Line of Credit of US\$ 25 million to the Government of Niger.

and various developmental and infrastructure projects. Exim Bank has built up a portfolio of 226 GOI LOCs spread across 62 countries, with credit commitments aggregating US\$ 21.87 billion, under which projects are at various stages of implementation.

Concessional Financing Scheme

Exim Bank has extended a term loan of US\$ 1.60 billion to the Bangladesh-India Friendship Power Company Pvt. Ltd. (a 50:50 joint venture between the Bangladesh Power Development Board, Bangladesh and NTPC Ltd., India) for financing the strategic 1320 MW (2*660 MW) ultra-super-critical Maitree Super Thermal Power Project on turnkey basis at Rampal, District-Bagerhat, Bangladesh. The contract was awarded to Bharat Heavy Electricals Ltd., following an International Competitive Bidding process. State-of-the-art technologies have been selected for this project to make it an environment friendly project. Once commissioned, the Maitree Super Thermal Power Project is expected to be one of the largest power plants in Bangladesh. The power plant is part of the Government of Bangladesh's plan for infrastructure development in the country, particularly in the power sector, augmenting the power generation capacity and reducing the current power deficit.

BUILDING EXPORT COMPETITIVENESS

The Bank operates a range of financing programmes aimed at enhancing the export competitiveness of Indian companies. During FY 2017-18, Exim Bank sanctioned loans aggregating ₹ 256.65 billion under programmes for enhancing export competitiveness. Disbursements amounted to ₹ 290.78 billion under these programmes.

Loans to Export Oriented Units

During the year, the Bank approved term loans of ₹ 31.94 billion to 41 export oriented units. Disbursements amounted to ₹ 35.42 billion. Under the Production Equipment Finance Programme, thirteen exporting companies were sanctioned ₹ 9.95 billion for financing acquisition of production equipment. Disbursements amounted to ₹ 4.87 billion. Thirteen companies were sanctioned long-term working capital loans aggregating ₹ 34.30 billion. Disbursements amounted to ₹ 28 billion.

Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)

Exim Bank is one of the nodal agencies appointed by the Ministry of Textiles, GOI, to establish and approve the eligibility of projects under TUFS, and release subsidy directly to the approved projects. As on March 31, 2018, the Bank has accorded approval for 229 projects with aggregate cost of ₹ 184.46 billion. Loans approved and disbursed aggregate ₹ 66.94 billion and ₹ 56.44 billion, respectively. The Bank's assistance under TUFS to the textile industry is spread across various segments in textile manufacturing and covers several states in India.

Overseas Investment Finance Programme

The Bank has a comprehensive programme covering equity finance, loans, guarantees and advisory services, to support Indian outward investment. During the year, 24 corporates were sanctioned

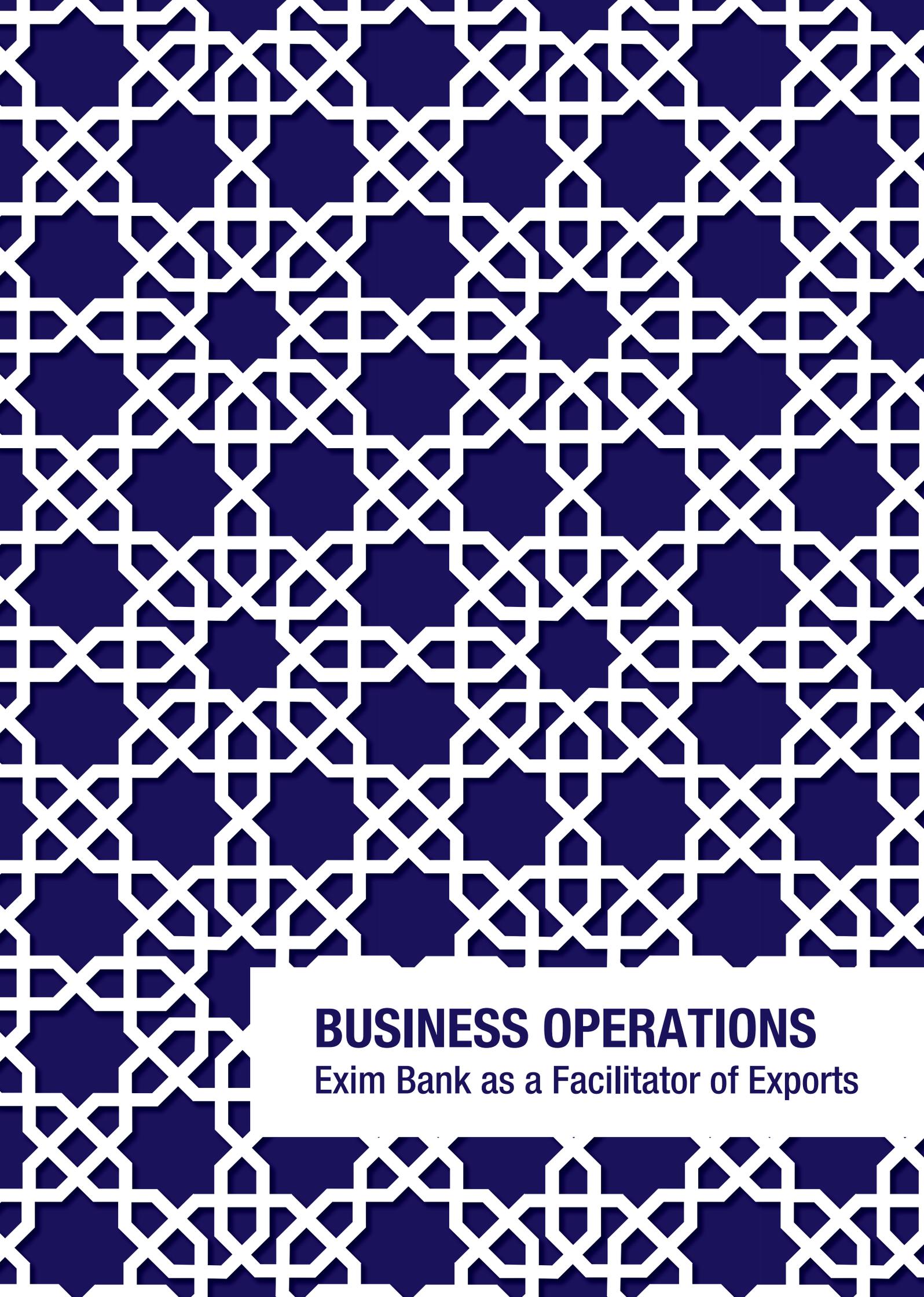
funded and non-funded assistance aggregating ₹ 43.77 billion for part financing their overseas investments in 16 countries. So far, Exim Bank has provided finance to 610 ventures set up by 462 companies in 78 countries. Overseas investments supported during the year include acquisition of a hospital in Cayman Islands, acquisition of business process outsourcing units in USA and Philippines and working capital facilities to an engineering company in Sweden, among others. Aggregate assistance extended towards overseas investment amounts to ₹ 572.90 billion covering various sectors including pharmaceuticals, home furnishings, readymade garments, construction, paper, paper products, textiles, garments, chemicals, dyes, computer software and IT, engineering goods, healthcare, natural resources (coal and forests), metal and metal processing, agriculture, agro-based products, steel, oil and gas.

STANDBY LETTERS OF CREDIT (SBLCs) / LETTERS OF CREDIT (LCs)

To facilitate the transactions of export-oriented units, the Bank issues LCs mainly for imports financed by the Bank. The Bank also extends financial guarantees/SBLCs to enable export-oriented units to raise funds for their overseas ventures. During the year, the Bank issued financial guarantees amounting to ₹ 3.00 billion. The Bank's financial guarantee portfolio stood at ₹ 19.75 billion as on March 31, 2018, as against ₹ 43.73 billion as on March 31, 2017.



A project for a 30 MLD water treatment plant and distribution to 9 reservoirs across Dambulla region in Central Sri Lanka being executed by VA Tech Wabag Ltd., is financed under the Bank's Buyer's Credit Programme.



BUSINESS OPERATIONS

Exim Bank as a Facilitator of Exports



Exim Bank supported placement of hand-embroidery, Kashmir craft, patchwork, submersible pump and metalware at several e-commerce companies.

GRASSROOTS INITIATIVES & DEVELOPMENT

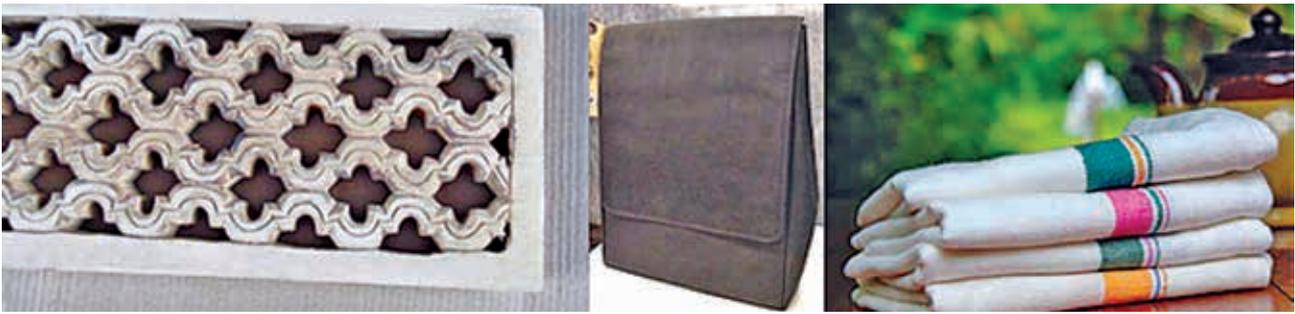
The Bank, through its grassroots initiatives, envisages supporting globalisation of enterprises based out of rural India. The programme seeks to address the needs of the relatively disadvantaged sections of society while creating expanded opportunities for traditional craft-persons, artisans and rural entrepreneurs of the country. During the year, the Bank provided lending support to a Bengaluru based social enterprise that provides a digital marketplace for easy and transparent sourcing of natural fibre and craft products through an e-commerce platform, which enables co-operatives, community-based artisans and weavers to list and sell their produce online. During the year, the Bank also provided support to a social enterprise in Maharashtra that promotes beekeeping, to enhance income and improve livelihoods of marginal farmers in India. The intervention by the Bank is aimed at part financing the working capital requirements of the organisation, which provides direct market access to over 3,000 small beekeepers across six states of India.

During the year, the Bank, inter alia, continued its support for a Rajasthan based social enterprise, which works with nearly 3,500 artisans, most of whom come from some of the most disadvantaged communities, a social enterprise sourcing off-the-loom products from handlooms in Bhagalpur; a social enterprise in Punjab that works with around 5,000 women artisans for their empowerment and also for the revival of the languishing Phulkari art; a society based in Sri Kalahasthi, which is engaged in the production of wooden handicrafts and Kalamkari products.

The Bank has been supporting and assisting rural artisans and craftsmen of handicraft products to

gain domestic as well as international presence by organising skill building and training workshops. In this context, the Bank supported national level development support enterprise in Guwahati to organise a month-long product and design development training workshop for 20 master women weavers in Dimapur, Nagaland. The workshop provided self-employment to women weavers who have traditional weaving skills and helped them upgrade their existing skills to produce superior quality finished products. Two training workshops were conducted for weavers in Burdwan and Shantipur clusters of West Bengal to enable the weavers to increase their sales through digital platform and export channels and equip them with design and product development capabilities, based on market requirements. The Bank also supported the All India Artisans and Craftworkers Welfare Association to present a show on Craftmark at the Lakme Fashion Week in Mumbai. Prominent among the displayed products at the show was Lambani, a vanishing art form of tribal embroidery practised by Lambani women from Karnataka. The platform provided an opportunity for artisans to interact with high-end national and international designers and buyers.

A design and skill development training programme was organised with Sasha on Kantha embroidery for around 20 women artisans. The objective of this training programme was to develop products with new aesthetics and techniques. A training programme with Chitrika was organized for Mangalagiri weavers including 41 weavers and technicians for a period of three months, to upgrade weaving skills from traditional to contemporary methods, and also create limited edition collections.



Exim Bank facilitated exports of wooden panels, non-leather handbags and handwoven textiles to Australia, UK and USA respectively.

Exim Bank, in collaboration with Jaypore, organized a Block Printing training programme along with M/s Chogan Printers in Rajasthan. Master artisans including printers and dyers participated in the training, with an objective to tap the potential for product diversity and development of contemporary products. Upon completion of these training programmes, the products being developed will be displayed and sold via Jaypore's e-commerce platform.

The workshops supported by the Bank have been immensely successful in addressing the key issues related to product development, design and quality and have helped the artisans develop product prototypes, which have wider appeal in both the domestic and international markets.

Memoranda of Understanding/Co-operation

The Bank has consciously sought to establish, nurture and foster various institutional linkages and has entered into formal cooperation arrangements with select broad-based agencies in order to directly reach out to the artisans, by helping in capacity-building, technological up-gradation, quality improvement, market access and training. During the year, the Bank signed a Memorandum of Cooperation (MOC) with the Centre for Microfinance & Livelihood (CML), an initiative of Tata Trusts. CML was conceptualized by Tata Trusts as a specialized umbrella support organisation for capacity building, research and collaborative direct interventions in the development space in North East India. The objective of the MOC is to help grassroots enterprises improve their export competitiveness, inter alia, by complying with global standards of quality and work towards developing viable financing models and best practices for projects/enterprises, which

can be replicated across different sectors and geographical locations in the North East.

The Bank has signed MOUs with the Government of West Bengal and the Government of Andhra Pradesh for promoting exports from these states. Under the MoUs, among many other objectives, the Bank also seeks to support the exporters from these states in facilitating market linkages and capacity building workshops. With regard to these MOUs, the Bank along with Jaypore E-Commerce Pvt. (Jaypore) Ltd. assisted M/s Sasha Association for Craft Producers (Sasha) in West Bengal and M/s Chitrika in Andhra Pradesh by providing a platform for their craftsmen in skill upgradation, new product development and identification of buyers.

MARKETING ADVISORY SERVICES

The Bank plays a promotional role to create and enhance export capabilities of Indian firms and seeks to help them in their globalisation efforts by assisting in locating overseas distributor(s)/ buyer(s)/ partner(s) for their products and services. The Bank leverages its international standing, knowledge and established institutional linkages, coupled with its physical presence and e-marketing efforts to support Indian companies in their marketing initiatives on a success fee basis.

Product Placement

During the year, the Bank signed mandates with 18 companies. A total of 233 orders of approximately ₹ 30 million in domestic as well as overseas markets were generated for various products during the year. These include exports of wooden panels to Australia, non-leather handbags to UK and handloom textiles to USA. Submersible pumps, Kashmiri craft, Dhokra metalware, banana fibre products and traditional



Design and skill development training for women Kantha embroiders of West Bengal.

and folk art paintings were placed with several e-commerce portals in India and abroad.

Besides product placement, the Bank assisted Indian companies in identifying partners overseas:

- Coslight India Ltd. signed an agreement to supply lithium batteries to a telecom company in Sri Lanka.
- Wawa Rugs signed an agreement with Novica, an e-commerce platform, to showcase and sell carpets and dhurries in the US market.
- Several supplier agreements were signed between micro and grassroots enterprises and Jaypore, an exclusive online marketing platform selling Indian handicraft and handloom products.
- Rangutra and Purkal Stree Shakti Samiti signed a Memoranda of Understanding with the Museum store to sell their hand-embroidered and patchwork products at the Mumbai Airport.
- Arture Designs Pvt. Ltd. and Commonwealth Fashion Council in the UK signed a manufacturing



Handing over ceremony of 18 railway locomotives worth US\$ 32.40 million, supplied by RITES Ltd. to Myanmar Railways under GOI Line of Credit of US\$ 86.31 million.



Exim Bank organised a Business Opportunities Seminar on World Bank funded projects at Mumbai.

agreement for prototyping exclusively designed non-leather bags.

- Shakti Pumps (I) Ltd. signed an MOU with Moglix, a start-up for industrial goods, to showcase its products on the portal.
- The Shikhar Handloom and Handicraft Weavers Welfare PCS Industrial Co-operative Society Ltd. signed an MOU with GoCoop, an online marketplace, to sell its woollen products through the e-commerce portal.
- Shardadevi Gramudyog Utpadak Sahakari Mandali Ltd. (SGS) registered with Kraftly, an e-commerce portal, to showcase and sell its handicraft products via the platform.
- Anwasha Tribal Arts and Crafts registered itself on Craft Furnish, an online marketplace that provides technical and marketing support to craft artisans, to display and sell its metal artwork.
- Sadhna Enterprise entered into an agreement



Construction of transmission lines connecting different regions in Lao PDR under a GOI Line of Credit of US\$ 37.30 million.



Design development training programme for Mangalagiri weavers in Andhra Pradesh.

with Sweetcouch, online portal, to sell its handmade apparels through the platform.

With a view to support Indian artisans, the Bank also procured handcrafted items made of jute, handmade and recycled paper, handwoven stoles and shawls, wood and metal ware for the purpose of gifting.

Events and Exhibitions

The Bank, in association with Secure Giving, supported traditional, tribal and folk art exhibitions in Mumbai, Pune, Kolkata, Chennai and Bengaluru. These art exhibitions showcased paintings originating from Tamil Nadu, West Bengal, Gujarat, Odisha, Madhya Pradesh, Rajasthan, Bihar and Andhra Pradesh, leading to sale of a number of paintings.

The Bank supported a Government of Jharkhand undertaking, sponsoring a Kuchai Silk Expo in Jammu, Lucknow and Pune. The exhibition provided a platform to handloom weavers to sell handwoven textiles and garments. The Bank also offered assistance to Self Help Groups, Non-Governmental Organisations, and micro and grassroots companies by offering space at the Surajkund Mela, Kala Ghoda Art Festival and Exim Bazaar exhibitions.



Product and design development training programme for block printing in Sanganer, Rajasthan.

Exim Mitra

The Bank works in close coordination with multilateral and regional banks and financial institutions to promote trade between India and the rest of the World. Exim Bank has been both a catalyst and a key player in the promotion of cross border trade and investment. Exim Mitra is an endeavour to the ongoing efforts towards reducing the asymmetry in information, availability of trade finance and credit insurance facilities amongst MSME entrepreneurs. The portal aims to make a concerted effort towards fulfilling twin objectives, namely providing information on credit availability for exports and delivering trade related information. The portal seeks to provide information on export-import intelligence, Trade Finance and Export Credit Insurance. This, inter alia, includes assessment of demand across products and markets; information pertaining to market standards, sanitary/phytosanitary requirements, and other rules and regulations in key markets like the USA and the EU; Government incentives across various sectors; relevant contact information for handholding agencies; cost and duration of shipments from across the globe, and country ratings. This portal is expected to evolve towards providing more services.

Excellent tools!
Please give me detailed information about target countries with bulk buyers of Indian handicrafts, so that we can contact them directly without middlemen.

Rajnish Kumar,
Suraksha Financial Services
(New Delhi)

Very informative and useful website for beginners as well as existing exporters. Newly added features will surely help the beginners to establish firm footing in their new ventures.

Pramod Sanghavi,
Exim Remedies,
Consultancy Services,
(Maharashtra)

I would like to tell you that you are the first government body that helped me with such accurate and useful information. Your explanation of various features helped me in data searching and using it appropriately.

Eva Shah, Shah Exporters,
Agro & Food Processing
(Maharashtra)

Very useful and relevant website. Some information about letter of credit and Incoterms may also be provided so that payment methods can be easily understood by users.

Felix Martin,
Indian Bank
(Tamil Nadu)

Testimonial by users of Exim Mitra

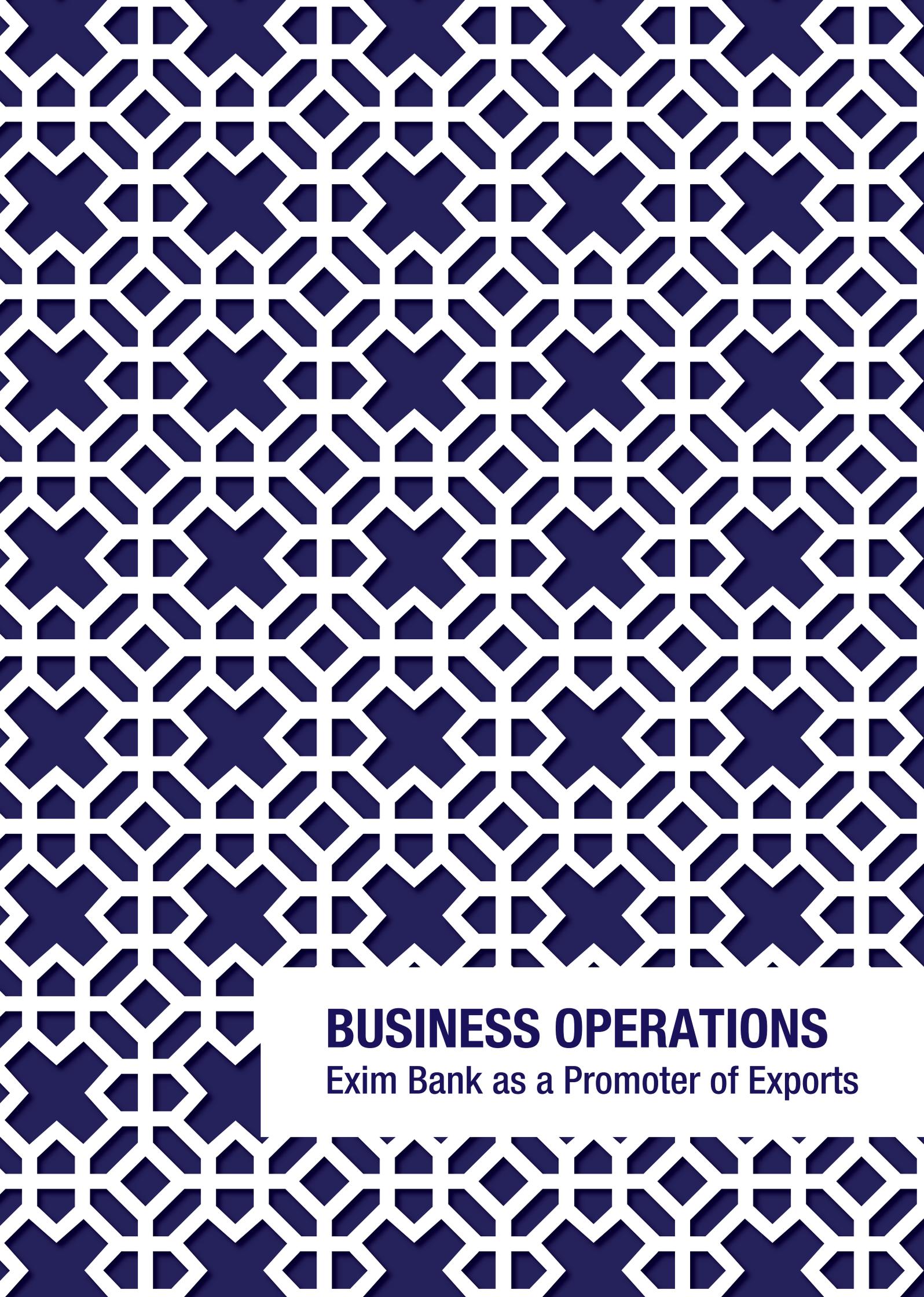


Narayana Health Ltd. developed a 104-bed hospital in Cayman Islands jointly with Ascension, USA, with Overseas Investment Finance from Exim Bank.

The Bank also works closely with commercial banks and credit insurance agencies to provide information and guidance to exporters. The Bank has partnered with 15 banks/financial institutions for facilitating financial services through the portal. Prospective exporters can fill and submit an online form on the portal, which captures preliminary data pertaining to loan applications. These details are then shared with participating banks. The portal therefore acts as a much needed intermediary between suppliers and users of trade finance.

Exim Bank recognises that the full potential of knowledge dissemination can be fructified only through a two-way exchange of information. To facilitate this, the portal has an interactive platform which allows the Bank to better understand the needs of the exporters and address their queries.

The Portal also contributes towards the objective of financial inclusion by providing preliminary help to a number of exporters and importers who may not have access to an array of crucial trade related information on a single platform.



BUSINESS OPERATIONS

Exim Bank as a Promoter of Exports

RESEARCH AND ANALYSIS

The Bank's Research and Analysis Group offers a range of research insights on aspects of international economics, trade and investments through qualitative and quantitative research techniques. The research work carried out in the Group under the broad classification of regional, sectoral and policy related studies, are published in the form of Occasional Papers, Working Papers, Books, etc. Eighteen research studies were published during the year. These include the following:

- The Internationalisation of Indian firms through outbound Foreign Direct Investment: Nature, determinants and developmental consequences
- Financialisation and its Implications on The Determination of Exchange Rates of Emerging Market Economies
- Revitalizing Trade Finance: Development Banks & Export Credit Agencies at the Vanguard
- Creating a Resilient Trade Finance Architecture: A Compendium of Articles
- Feed Africa: Achieving Progress through Partnership
- Water, Sanitation and Healthcare in Africa: Enhancing Facility, Enabling Growth
- Integrate Africa: A Multidimensional Perspective
- Manufacturing in Africa: A Road for Sustainable Growth
- Power Sector in Africa: Prospect and Potential
- Indian Investments in East Africa: Recent Trends and Prospects
- Connecting Africa: Role of Transport Infrastructure



Release of Exim Bank's publication, *Creating A Resilient Trade Finance Architecture: A Compendium of Articles*.



The CII-Export-Import Bank of India Award for Business Excellence was presented to Godrej Interio (Godrej & Boyce Manufacturing Co. Ltd.) at the 25th CII National Quality Summit.

- Trade in Environmental Goods: A Perspective
- Strengthening ASEAN - India Partnership: Trends and Future Prospects
- Indo-Sri Lanka Trade and Investment Relations: Current Trends and Prospects
- Indian Investments in Latin America and Caribbean: Trends and Prospects
- Oil Price and International Trade in Petroleum Crude and Products: An Indian Perspective
- Pharmaceutical Industry: Regulatory Landscape and Opportunities for Indian Exporters
- Exports from Uttar Pradesh: Trends, Opportunities and Policy Perspectives

INFORMATION AND ADVISORY SERVICES

The Bank provides a wide range of information, advisory and support services, which only complements its financing programmes whilst also underlining its role as a policy Bank. These services are provided to the Bank's stakeholders including state governments, Indian public and private sector and overseas entities. The scope of services include policy inputs and papers for state governments, market-related information, sector and feasibility studies, technology supplier identification, partner search, capacity building exercises, investment facilitation and development of joint ventures both in India and abroad.

During the year, the Ghana Export-Import Bank (Exim Ghana) commissioned Exim Bank to undertake an assignment for providing technical assistance across various operational areas of Exim Ghana. Exim Bank will, inter alia, suggest an appropriate



Release of Exim Bank's special publication, *Strengthening ASEAN-India Partnership: Trends and Future Prospects*.

organisational structure, design the modalities of export financing programmes, develop a plan for implementation of these programmes, prepare standardised formats and provide guidelines for appraisal of credit proposals and risk analysis, and advice for setting up IT infrastructure. The Bank is in consultation with relevant stakeholders for taking this assignment to its fruition.

MULTILATERAL FUNDED PROJECTS OVERSEAS

The Bank provides a package of information and support services to Indian companies to help improve their prospects for securing business in projects funded by the World Bank, Asian Development Bank (ADB), African Development Bank (AfDB) and European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Projects funded by such multilateral funding agencies present attractive business opportunities for suppliers, contractors and consultants. Recognising the potential for increasing effective participation by Indian firms in such multilateral funded projects, Exim Bank has been organising seminars in association with multilateral agencies.

ADB, through loans and technical assistance, supports projects encompassing various sectors viz. transport, energy, urban agriculture, natural resources and human development. ADB also supports flagship government projects such as solar parks and solar rooftops, energy efficiency using LED lighting, smart cities, metro lines, railways modernisation, and irrigation system expansion. In order to create greater awareness on the ADB's national and international business opportunities, Exim Bank in partnership with ADB, organized two interactive seminars at Chennai and Mumbai.

The World Bank's procurement system had a portfolio of 5675 projects in 172 countries with total contracts amounting to US\$ 183.6 billion at the end of March 2018. Indian companies have been participating in bids of the World Bank procurement system and have been reasonably successful. The World Bank has a new procurement framework with effect from July 2016, which is more business friendly and takes in to account feedback received from stakeholders, including vendors. Recognising the potential for increasing effective participation by Indian companies in bidding opportunities under World Bank funded projects, Exim Bank, in association with the World Bank Group, organised an interactive workshop on 'Business Opportunities in World Bank Funded Projects' in Mumbai.

EXIMIUS CENTRE FOR LEARNING

The Eximius Centre for Learning (ECL) is responsible for the overall conduct, coordination and implementation of programmes, seminars and workshops for Indian exporters and importers with a view to enhance their awareness, as also to facilitate India's international trade and investment. Seminars and conferences for exporters and



Exim Bank released working papers on the central theme of *India – Forging Mutual Partnership for Africa's Development*, focusing on 'AfDB's High 5s' Agenda.

importers are organised on topics of contemporary interest. The seminars were conducted with speakers from trade associations such as Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Indian Chamber of Commerce (ICC); Confederation of Indian Industry (CII), Directorate General of Foreign Trade (DGFT), ECGC Ltd., IMC Chamber of Commerce and Industry and leading commercial banks.

The ECL conducted 24 export promotion seminars for exporters across the country on various topics during the year.

A series of four interactive sessions was organised on Services Exports in association with the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, in Mumbai, Bengaluru, Ahmedabad and Kochi. The sessions, which primarily focussed on sectors such as information technology (business process management), tourism, real estate, housing and shipping services, were organised to elicit responses from key stakeholders, which would serve as inputs for the Government of India's strategy on services sector exports.

A series of five seminars was conducted in association with FIEO on topics such as 'Opportunities and Challenges in Foreign Trade in the North-East Region', 'International Trade Facilitation', 'Safest Payment Terms with Export Finance' and 'Implication of GST and Foreign Trade Policy' at Udaipur, Ludhiana, Bhubaneswar, Amritsar and Varanasi.

ECL organised a series of events and seminars to bring all stakeholders on a common platform to



Interactive Stakeholders' Seminars on the International Solar Alliance were held in New Delhi and Mumbai.



Exim Bank's export facilitation portal 'Exim Mitra' won an award from the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific.

deliberate on increasing exports from the North-Eastern region of India. ECL partnered with ICC to organise the 'Act East Business Show' in Shillong, and seminars on 'Energizing Entrepreneurs in International Trade' in Aizawl and Imphal. Further, ECL and CII jointly organised seminars on 'Opportunities and Challenges in Foreign Trade in the North-East Region' in Dimapur and Gangtok.

ECL organised seminars on 'Fuelling Growth of MSMEs through Financing Options and Enhancing Competitiveness' in Baddi and 'Export Marketing and Digital Marketing' in Bhavnagar and Mahuva (Gujarat), in association with CII. ECL partnered with the IMC Chamber of Commerce & Industry to organise a session for MSMEs on 'How to Export' in Navi Mumbai and 'How to Enhance Exports' in Kolhapur.

With a view to boost pharmaceutical exports to Africa, ECL organised an 'India-Africa Pharma Dialogue' in New Delhi, which was attended by stakeholders from the industry and African missions in India. ECL partnered with the Embassy of Estonia in New Delhi to organise a seminar on 'Trade and Investment Opportunities in Estonia' in Mumbai.

INSTITUTIONAL LINKAGES

The Bank has fostered a network of alliances and institutional linkages with multilateral agencies, export credit agencies, banks and financial institutions, trade promotion bodies and investment promotion boards to help create an enabling environment to support trade and investment.



Release of Exim Bank's publication, *Revitalising Trade Finance: Development Banks and Export Credit Agencies at the Vanguard.*

BRICS Interbank Co-operation Mechanism

Exim Bank entered into two multilateral agreements with other member development banks of BRICS nations under the BRICS Interbank Co-operation Mechanism:

- a) Interbank Local Currency Credit Line Agreement; and
- b) Co-operation Memorandum Relating to Credit Ratings.

The umbrella Interbank Local Currency Credit Line Agreement would serve as an enabler to enter into bilateral agreements between member banks subject to national laws, regulations and policies of the signatory institutions. The Co-operation Memorandum relating to Credit Ratings would enable sharing of internal credit ratings amongst the BRICS development banks, based on requests received. The Co-operation Memorandum relating to Credit Ratings would serve as an ideal mechanism to mitigate the credit risks associated with cross-

border financing. These agreements were signed during the BRICS Summit 2017, held in China.

Asian Exim Banks Forum

The Twenty Third Annual Meeting of the Asian Exim Banks Forum (AEBF) was hosted by Export Finance and Insurance Corporation in Sydney, Australia, in November 2017. The theme of the Meeting was "Despite a marked slowdown in international trade, members within the leading cross-border trade and economic growth region of the world are well-positioned to lead global trade in the years to come." The meeting was chaired by EFIC and had representatives at the highest level from member institutions, viz., Australia, China, India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Thailand, Turkey and Vietnam. While Philippines could not attend the meeting, the Asian Development Bank participated as a permanent invitee. The Export Credit Bank of Turkey, became a member of the Forum after completing two years as an Associate Member, in line with the Membership Protocol.

In 1996, Exim Bank took the initiative of forming the AEBF. While export credit agencies are generally considered competitors as they support their respective national exports, the objective of the Forum is to collaborate while competing. AEBF seeks to enhance economic co-operation and forge stronger linkages among its member institutions, thereby fostering a long-term relationship within the Asian Exim Banks' community. The Forum also



Signing of Line of Credit agreement of US\$ 4.50 billion to the Government of Bangladesh for development projects.



Signing of an agreement for financing a project on “Capacity Building of MSMEs in North East India for Export Competiveness” with United Nations Development Programme.

provides a sound platform for knowledge sharing by way of training programmes that have helped the staff of the member institutions learn the best practices in areas as diverse as project financing, capital markets, ship financing, SME financing, commodity financing, country risk, cross border investment, etc. Two training programmes were hosted during the year by the member institutions, of which one was hosted by Exim Bank of India, which saw a wide participation.

Global Network of Exim Banks and Development Finance Institutions

The Global Network of Exim Banks and Development Finance Institutions (G-NEXID) was set up in Geneva in March 2006, through the Bank’s initiative, under the auspices of United Nations Conference on Trade and Development. With the active support of a number of other Exim Banks and Development Finance Institutions from various developing countries, the network has endeavoured to foster enhanced South-South trade and investment and co-operation. The Network held its Annual General Meeting in Geneva in July 2017, which was followed by an Exchange Programme hosted by the Brazilian Development Bank, in November 2017.

Award for Business Excellence

Exim Bank and the Confederation of Indian Industry (CII) joined hands in 1994, to promote ‘excellence’ among Indian companies through the ‘CII-Exim Bank Award for Business Excellence’ for best Total Quality Management (TQM) practices adopted by an Indian company. The Award is based on the European

Foundation for Quality Management (EFQM) Model. The annual award is a prestigious and befitting industry recognition given to a company after being assessed by panels of trained assessors through a transparent and rigorous methodology based on the EFQM Model. In 2017, there were 11 companies which received varying levels of recognition. Godrej Interio Division, Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd. was adjudged as the ‘Award winner’, while Godrej Appliance Division, Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.; and Raychem RPG (P) Ltd. were adjudged as the ‘Prize winners’.

International Economic Research Annual Award

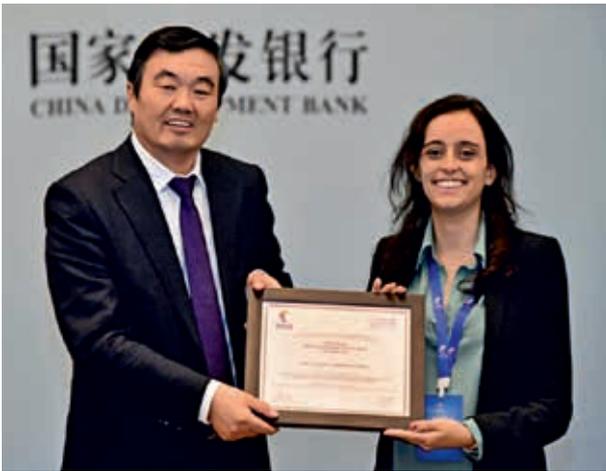
The International Economic Research Annual Award was instituted by the Bank in 1989. The objective of the Award is to promote research in international economics, trade, development and related financing, by Indian nationals at universities and academic institutions in India and abroad. The Award consists of a sum of ₹ 0.35 million and a citation. The winner for the year 2016 was Dr. Isha Chawla, for her doctoral thesis titled “The Internationalization of Indian Firms through Outbound Foreign Direct Investment: Nature, Determinants and Developmental Consequences”. Dr. Chawla received her degree in 2015 from the Delhi School of Economics, University of Delhi.

Exim Bank of India BRICS Economic Research Award

During India’s Presidency of the BRICS Interbank Co-operation Mechanism in 2016, the Bank had instituted the Exim Bank of India BRICS Economic Research Award, with the objective of encouraging and stimulating advanced research on economics



Presentation of Exim Bank’s International Economic Research Annual Award 2016 to Dr. Isha Chawla by Dr. Arvind Subramanian, Chief Economic Adviser, Government of India.



Presentation of Exim Bank's BRICS Economic Research Award 2017 by Mr. Hu Huaibang, Chairman, China Development Bank, to Dr. Raquel Almeida Ramos from Brazil.

related topics of contemporary relevance to the member nations of BRICS. The Award, comprising of prize money of ₹ 1.50 million (approximately US\$ 23,000) is sponsored by the Bank, along with a medal and a citation. The Award is open to nationals of any of the five member nations of BRICS, whose doctoral thesis have been awarded a doctorate, or accepted for award of a doctorate from any nationally accredited University or academic institution globally. The winner for the year 2017 was Dr. Raquel Almeida Ramos, for her doctoral thesis titled "Financialisation and its Implications on the Determination of Exchange Rates of Emerging Market Economies". Dr. Ramos received her degree in 2016 from the Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité, France and Universidade Estadual de Campinas, Brazil.

ADFIAP Award

The Bank was conferred the Outstanding Development Project Award 2018 under the "Technology Development" category by the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) during its 41st Annual Meeting held in New Delhi. The ADFIAP Development Award recognizes and honours ADFIAP member institutions, which have assisted projects that have created a development impact in their respective countries. The 2018 ADFIAP Development Project Award was in recognition of Exim Bank's support to Stellapps Technologies Pvt. Ltd., one of the few dairy technology solutions companies in India building automation tools,

integrated with cloud, mobility, and data analytics for dairy farms. A Plaque of Merit was also bestowed to the Bank under the "SME Development" category for its portal 'Exim Mitra'.

Commencement Day Annual Lecture

Exim Bank's Commencement Day Annual Lecture series, instituted in 1986, has earned recognition as an important milestone in contributing to the debate and discussions on contemporary trade and development issues impacting the global economy. The lecture for the year 2017-18 was delivered by Prof. Gita Gopinath, the John Zwaanstra Professor of International Studies and of Economics at Harvard University. Prof. Gopinath spoke on the topic "Dollar Dominance in Trade: Facts and Implications."

Exim Bank's support to States for promotion of exports

The Bank has been actively engaged in promoting exports from Indian states and supporting regional entrepreneurs to explore opportunities overseas. During the year, the Bank organised two Interactive Sessions with various stakeholders, including industry and senior level state Government functionaries, on the export potential of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, to understand the opportunities and challenges for exporters in these states. Based on these interactions and in-house research, the Bank brought out a study titled, 'Exports from Uttar Pradesh: Trends, Opportunities and Policy Perspectives', highlighting export sectors which are traditionally strong in the state and which could be further strengthened, while addressing the challenges faced by them.

Exim Bank - UNDP Co-operation on Capacity Building of MSMEs in the Northeast Region

During the year, Exim Bank and the United Nations



Exim Bank hosted the 36th Training Programme of the Asian Exim Banks Forum, on the topic of 'Buyer's Credit', at Vishakhapatnam.



Exim Bank extended a Line of Credit of US\$ 500 million to ECOWAS Bank for Investment and Development.

Development Programme (UNDP) entered into an agreement to finance a project on “Capacity Building of MSMEs in North East India for Export Competitiveness”, which aims at creating stronger MSMEs in the Northeast Region to boost exports, generate employment and provide livelihood opportunities, especially for the youth and women. The key strategy would be to take advantage of the emerging opportunities under the Government of India’s ‘Act East Policy’ that recognises the potential of the region in terms of natural resources, hydropower and close proximity to East Asian countries, among others. The key activities of the project include cluster-based support to MSMEs in Northeast Region in improving their export competitiveness. Key deliverables would include, among others, cluster level implementation strategy; online support resources for entrepreneurs, industry associations and export promotion agencies; in-depth market analysis; and state-specific export promotion strategy with clear roadmap for increase in export volumes in identified commodities and products.

NEW INITIATIVES

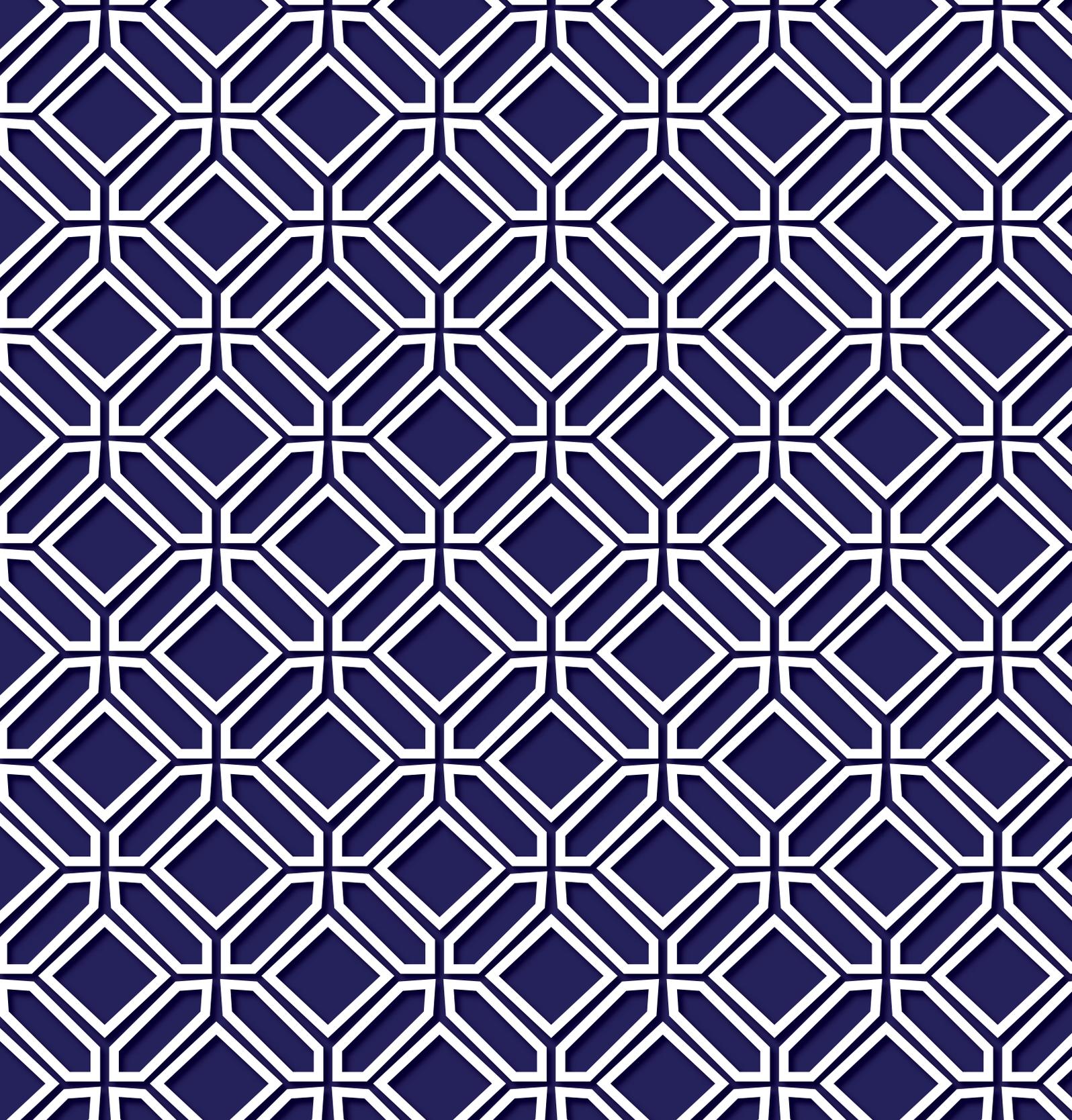
Exim Bank launched a Market Outreach Programme (E-MOP), to promote India's international trade and investment in emerging markets in sunrise sectors, providing value addition for Indian enterprises. The first such programme focussed on the healthcare sector in Myanmar and Cambodia. Exim Bank led an Indian delegation of multi-specialty and super-specialty hospitals, medical equipment manufacturers, pathology labs, diagnostic centres and clinics to Yangon and Phnom Penh. The delegation interacted with various stakeholders from the government, chambers, trade bodies and consultants from the healthcare sector of the two countries. Indian companies held business-to-business meetings with their counterparts from Myanmar and Cambodia and visited local hospitals. The initiative led to several trade and investment opportunities for the Indian healthcare sector.

Exim Bazaar

The Bank organised an exclusively curated exhibition-cum-sale of handmade arts, crafts and textiles from across India. Exim Bazaar, a four-day event brought together the best of crafts like Kashmir’s papier-mâché, Manipuri black pottery, Rajasthani jewellery, Madhubani paintings, Paithani sarees, Kalamkari paintings, Block printed garments, Kolhapuri footwear, Dhokra and Bidriware and many more of such exquisite crafts. The exhibition had 39 artisans and enterprises under a single roof, who had in the past benefitted from the Bank’s Marketing Advisory Services. Exim Bazaar had a huge footfall of around 5000 visitors and was successful in generating on-spot sales and future orders for the participants.

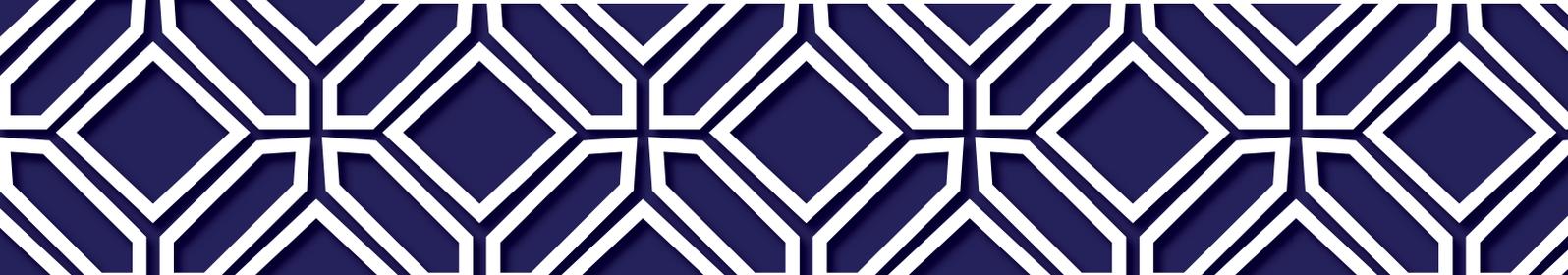


Launch of Exim Bank's Market Outreach Programme focusing on the healthcare sector in Myanmar and Cambodia.



BUSINESS OPERATIONS

Exim Bank's Institutional Infrastructure



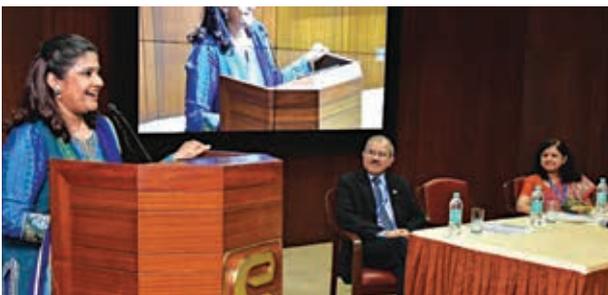
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

The Bank's staff, comprising management graduates, chartered accountants, bankers, economists, legal, library and documentation experts, engineers, linguists, human resources and IT specialists, numbered 340 on March 31, 2018. The professional team of 290, is supported by administrative officers. As a "learning organisation", the Bank organises various group training programmes, facilitating continuous upgradation of skills of its staff. Officers are also nominated for customised training programmes and seminars, aimed at developing and enhancing skill sets for handling highly specialised portfolios. During FY 2017-18, 203 officers attended training programmes and seminars on various subjects relevant to the Bank's operations ranging from working capital management and interpretation of financial statements, project planning, project monitoring and control systems, trade finance, credit risk, interpersonal communication and organisational effectiveness, information security and leadership development.

During FY 2017-18, 60 per cent of the Bank's officers were nominated for 30 training programmes conducted by reputed institutes. Six group training programmes were arranged on topics including financial modelling, business etiquette, IndAS training on Indian Accounting Standards, foreign languages such as French and Spanish, Advanced Statistics and Econometrics for business and effective communication skills.

REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES

Of the total staff of 340 in the Bank's service as on March 31, 2018, there were 34 Scheduled Caste,



Ms. Renuka Shahane, TV and film personality, addressed the staff during the Hindi fortnight celebrations at the Bank.

23 Scheduled Tribe and 50 Other Backward Class staff members. Training in Information Technology and other areas such as effective presentation, leadership, communication and language skills, was also provided to these staff members. The Bank continues to grant scholarships for students from Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Arunachal Pradesh, and has also instituted scholarships for reserved category students of the Kalinga Institute of Industrial Technology University, Odisha; Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi; the Delhi School of Economics and the Jawaharlal Nehru University, New Delhi. The Bank has instituted new scholarships at Nagaland University; North Eastern Hill University, Meghalaya; Tripura University and Sikkim University, to focus on the North Eastern region, and particularly for students from tribal communities.

INTERNAL COMPLAINTS COMMITTEE UNDER "THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013"

In compliance with the Act, the Bank has constituted an Internal Complaints Committee which includes an external member, for considering complaints of sexual harassment of women at workplace as defined under the Act. The Bank considers the safety of its employees to be of paramount importance and seeks to provide a safe working environment at the workplace. The committee held regular meetings and also organised awareness sessions for employees at all offices of the Bank. All employees of the Bank have read, acknowledged and are aware of the policy for the Act implemented by the Bank.



Signing of "Credit Confirmation Statements" aggregating US\$ 1.22 billion for providing financial assistance for six infrastructure projects in Africa through Buyer's Credit under the National Export Insurance Account.



Blood Donation Camps were held during the year at the Bank's premises in collaboration with Tata Memorial Hospital, Mumbai.

TREASURY

The Bank's integrated treasury handles fund management functions, including investment of surplus funds, money market and forex operations and securities trading. The Bank has segregated front, middle and back office functions and has a state-of-the-art dealing room. The range of products offered by the Bank's treasury to its borrowers includes foreign exchange deals, collection/negotiation of export documents, issuance of inland/foreign letters of credit/guarantees, structured loans, etc. The Bank uses financial derivative transactions for raising cost effective funds and hedging its balance sheet exposures, with an objective of reducing market risks. The Bank is a member of the Indian Financial Network (INFINET) and has registration authority status from the Institute for Development Research in Banking Technology, the certifying authority. The Bank holds a digital certificate to deal through the Negotiated Dealing System -Order Matching segment (NDS-OM) of the RBI, which provides the electronic dealing platform for trading in GOI securities. The securities/foreign exchange transactions of the Bank are routed through the Guaranteed Settlement Facility provided by the Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL). The Bank is an active member of Collateralised Borrowing and Lending Obligation (CBLO) segment of CCIL. The Bank is also a member of Clearcorp Order Matching System (CROMS), the Repo Dealing System of CCIL. CROMS is a Straight Through Processing enabled anonymous order matching platform launched by CCIL for facilitating dealing in market repos in all kinds of Government Securities on T+0/ T+1 basis. CCIL acts as a central counterparty to all CROMS trades and settlements are guaranteed by CCIL. The Bank has centralised



Exim Bank observed the International Day of Yoga.

SWIFT facility (with connectivity to the London Branch) which is capable of handling multiple Bank Identifier Codes.

PROGRESS IN IMPLEMENTATION OF THE OFFICIAL LANGUAGE POLICY

During FY 2017-18, the Bank continued its efforts to strengthen the implementation of the Official Language Policy of the Government of India.

The Annual Programme for FY 2017-18, received from the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, was implemented through an action plan to achieve targets. Towards this end, Official Language Implementation Committees at Bank's Head Office and Regional Offices reviewed and monitored the progress on regular basis.

A scheme offering incentives aimed at encouraging officers to learn and use Hindi in their day-to-day work is in place in the Bank. The Bank's in-house magazine 'Eximius' includes a Hindi section. A special issue of Eximius is brought out as Rajbhasha Visheshank on the occasion of Hindi Day. Officers are encouraged to contribute articles in Hindi and best articles are rewarded.

The Bank has actively participated in the meetings of Town Official Language Implementation Committees and has increasingly encouraged its officers to participate in the inter-bank Hindi competitions. Hindi training needs of the officers were identified and they were nominated for training to attain working knowledge as well as proficiency in Hindi. Use of Unicode was encouraged and officers were given training to use software/facilities available for working in Hindi on computers. In pursuance of the Government's



Sir Suma Chakrabarti, President, European Bank for Reconstruction and Development, visited the Bank.

directives, a Hindi fortnight was celebrated in the Bank in September 2017. World Hindi Day was also celebrated in January 2018. The Bank maintains its corporate website and a portal named Exim Mitra, both in Hindi and English.

Apart from literature on the Bank's operations and procedures, Hindi versions of all the issues of 'Eximius Export Advantage', a quarterly publication of the Bank, were published under the title 'Eximius: Niryaat Laabh'. Issues of 'Agri Export Advantage', a bi-monthly publication of the Bank, were also published in Hindi under the title 'Krishi Niryaat Laabh'. In addition to Hindi and English, it is translated in 10 other Indian languages.

In pursuance of Government policy regarding progressive use of Hindi, new Hindi books, particularly on foreign trade, commerce, finance, banking, information technology and other subjects were added to the Bank's library.

The Bank's efforts for accelerating the use of Hindi for official purposes received recognition from various authorities:

- Offices in Bengaluru, Hyderabad and Kolkata were awarded by their respective Town Official Language Implementation Committees, constituted under the aegis of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, for commendable performance in implementing the Official Language.
- The Bank's in-house journal 'Eximius' was awarded the first prize by the Reserve Bank of India under the bilingual magazine category amongst 32 participating Banks/Financial Institutions, for FY 2016-17.

INFORMATION TECHNOLOGY

The Bank continued its initiatives in enhancing



A project for design and construction of an 84 km railway line in Ghana, financed under the Bank's Buyer's Credit, being executed by Afcons Infrastructure Ltd.

the use of knowledge based tools, authentic communication across its various constituents for better sharing of information, customer empowerment and system intelligence capabilities. Systems were supported and upgraded in various areas including those of the core banking system, business intelligence, digital documentation, automatic workflows, networks, infrastructure and security. The Bank strengthened its practices and procedures in compliance with international standards for IT Governance. The Bank's corporate website (www.eximbankindia.in) continued to disseminate information in an organized manner on business opportunities and leads in international trade and also on the various research activities conducted by the Bank. The Bank continued to invest on infrastructure to support the growing need of the business and upgraded networks across the offices, data center, computing and other crucial equipment. The Bank has implemented various action based alerts and real time reporting to improve the efficiency and output. The Bank became one of the early members of Bank Chain which is a forum of Indian banks to explore the feasibility of implementation of block chain based technology in the Indian banking industry.

CORPORATE GOVERNANCE

Exim Bank ensures transparency and integrity in communication and makes available full, accurate and clear information to all concerned. The Bank is committed to and is continuously striving to ensure compliance with best practices of corporate governance as relevant to the Bank. The Bank has established a framework of strategic control and is continuously reviewing its efficacy. Business/financial performance matters related and analytical data/information are reported to the Board/Management Committee of the Board periodically for review. The Bank has put in place

a Board approved Compliance Policy and a senior official has been made responsible in respect of compliance issues with all applicable statutes, regulations and other procedures, policies as laid down by the GOI/RBI and other regulators and the Board, and report deviation, if any, to the Audit Committee. The Bank's Board held six meetings and the MC held seven meetings during FY 2017-18.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee (AC) of the Bank's Board provides direction to the total audit function of the Bank in order to enhance its effectiveness as a management tool and to follow-up on all issues raised in the statutory/external/internal/ concurrent audit reports and RBI inspection reports. The AC reviews the annual financial statements every year before submission of the same to the Board. AC also periodically reviews the functioning of the Bank's Fund Management Committee (FMC) and Asset-Liability Management Committee (ALCO). The AC met seven times during FY 2017-18.

ASSET-LIABILITY MANAGEMENT (ALM)

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) of the Bank oversees the monitoring and management of market risk with support from the Bank's mid-office. Liquidity/interest rate risks are managed by ALCO as per the comprehensive ALM/liquidity policies approved by the Board. The role of ALCO includes, *inter alia*, reviewing the Bank's currency-wise structural liquidity and interest-rate sensitivity positions vis-a-vis prudential limits prescribed by the RBI/Board, monitoring results of periodical stress testing of cash flows and identifying a suitable ALM strategy based on the quantum of interest-rate risk as measured



Exim Bank extended a GOI Line of Credit of US\$ 318 million to the Government of Sri Lanka.

through (a) assessment of sensitivity of net interest income and (b) sensitivity of economic value, using duration-gap analysis, to interest rate movement. Regular stress testing of the currency-wise liquidity position is carried out and a Contingency Funding Plan is drawn up periodically to estimate the worst-case fund shortfall in each currency. Value-at-risk is computed for the Bank's held-for-trading and available-for-sale portfolio of GOI securities. The FMC decides on the investments/disinvestments and raising of resources as per the Fund Management/Resources Plan approved by the Board at the beginning of each financial year and reviewed during the year. The AC of the Board periodically reviews the functioning of ALCO/FMC.

RISK MANAGEMENT

The Bank has an Integrated Risk Management Committee (IRMC), which is independent of operating groups and reports directly to the top management. The IRMC reviews the Bank's position in regard to various risks (portfolio, liquidity, interest rate, off-balance sheet and operational risks) and oversees the operations of the ALCO, the FMC and the Credit Risk Management Committee (CRMC), all of which have cross-functional representation. While ALCO deals with issues relating to ALM policy and processes and analyses the overall market risk (liquidity, interest-rate risk and currency risk) of the Bank, CRMC deals with credit policy and procedures and analyses, manages and controls credit risk on a Bank-wide basis. The Bank has in place an advanced Credit Risk Model (CRM) that enables a broad-based credit decision support (by incorporating a range of qualitative as well as quantitative parameters/measures) and better portfolio management capability. A Rating



Exim Bank has supported Larsen & Toubro Ltd., for air side construction works for the new midfield terminal complex at the Abu Dhabi International Airport, UAE.



Dr. Suresh Rituparna, renowned Hindi writer and Director of K. K. Birla Foundation gave a talk to the staff of Exim Bank on the occasion of World Hindi Day.

Committee is in place to independently review the credit ratings assigned by sponsor officers to the respective proposals. The Bank also undertakes an annual review of the Business Continuity and Disaster Recovery Plans of all its offices. Each of the plans is vetted for completeness with regard to critical Business Continuity Risk Events and safeguards in place, for mitigating the impact thereof.

LOAN ADMINISTRATION

To provide focused attention to monitoring of loan accounts which are under stress and also strengthening of recovery measures for NPAs, the Bank has a dedicated group, Loan Administration Group, which takes pro-active steps towards loan recovery including preventing slippage of standard assets into NPAs, rehabilitation of NPAs which are viable and also focuses on recovery from NPA accounts where legal action is to be pursued for recovery as per the Board-approved Loan Monitoring and Recovery Policy, which is framed based on the extant regulatory framework. Monthly review of overdue and NPAs is being done by separate committees in the Bank.

During the last two fiscals, the banking sector as a whole has been dealing with higher slippages and asset quality issues. The Bank accords highest priority to recovery of NPAs and adopts a multi-dimensional approach for resolution of NPAs. These include legal action, sale of assets through court receiver, negotiations, one-time settlements, possession and subsequent sale of assets under the provisions of the Securitizations Act, and transfer/assignment of debt to other parties.

Indian Banking sector has been observing a paradigm shift in approach towards stressed assets



Exim Bank received the prize for in-house magazine 'Eximius' from RBI.

from earlier approach of recovery to the new shift being of resolution of stressed assets with the introduction of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) together with the latest guidelines from Reserve Bank of India focusing on early resolution of stressed assets. Bank's Group has been actively pursuing cases under IBC and is well equipped to operate within the revised regulatory framework.

KYC, AML AND PML MEASURES OF THE BANK

The Bank has a policy approved by the Board on 'Know your Customer (KYC) norms, Anti Money Laundering (AML) standards, and Combating Financing of Terrorism (CFT)'. The Policy conforms to the RBI guidelines in the matter. The KYC, AML and CFT policy covers:

- (a) Customer Acceptance Policy
- (b) Risk Management
- (c) Customer Identification Procedure
- (d) Monitoring of transactions

The Bank also has access to the Bankers Accuity Database, an online database service, a product of one of the world's leading business publishers, Reed Business Information, of the Reed Elsevier Group. It is a compliance database for bankers. Accuity's enhanced Global Watch List is a comprehensive collection of caution lists from all major sanctioning bodies, law enforcement agencies and financial regulators worldwide. All the customers of the Bank are subjected to KYC standards, which establish the identity of the natural / legal person and those of the 'beneficial owners'. Implementation of KYC policies and procedures covers identification of term deposit holders, correspondent banks, recruitment of new staff members and counterparty identification with regard to treasury transactions. The Bank obtains data required for ensuring compliance by

its counterparty banks with regard to KYC norms through the Wolfsberg Group AML Questionnaire, in line with international market practice. The Bank also maintains information in respect of certain transactions in accordance with the procedure and manner as may be specified by the RBI and SEBI, as the case may be, from time to time, and the records are maintained for a period of ten years from the date of the transaction. The Bank has appointed a Principal Officer responsible for its KYC, AML and CFT measures. The KYC, AML and CFT Policy is posted on the Bank's website.

FAIR PRACTICES CODE FOR LENDERS

The Bank has in place, a Board approved policy on Fair Practices Code for Lenders framed in line with RBI guidelines. The policy is reviewed every year.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) FRAMEWORK

The Bank has in place a Board-approved "Environment, Social and Governance (ESG) Policy". The Bank is also a part of the deliberations led by the Indian Banks Association (IBA) on a sustainability framework for Banks. The IBA has appreciated the efforts of the Bank, among others, for moving forward on principle two of the Guidelines, i.e. integrating ESG based risk assessment into the credit appraisal process, as well as making forward strides on aspects of green investment using new modes of green finance which is Principle 4 of the Guidelines.

The Bank has been promoting sustainable banking both in India as well as internationally through its various financing programmes. The Bank has been funding projects in areas such as renewable energy, energy efficiency, waste management, mass transportation, and energy efficient transport. The



Employees of Exim Bank lent a helping hand at the Versova beach clean up campaign of Afroz Shah, Mumbai-based lawyer and environmentalist.

Bank is also promoting inclusive growth through its Grassroots Initiatives and Development.

The Bank has also been reviewing its internal operations for ESG-related parameters. The Bank has taken up electrical audit and associated measures for optimising energy consumption. The Bank aims to minimise use of paper through digitisation of workflows including circulation of agenda papers for meetings; e-Greetings; and e-Invites for various occasions and functions. Use of video/tele conferencing helps reduce the carbon footprint. The Bank has also showcased its initiative of "Go Green" by sapling plantation drives in housing societies where the Bank provides accommodation to staff members. As an alternative to presenting bouquets at events, donation certificates in the name of the recipient for a social cause (such as Akshaya Patra) have been introduced in the Bank. The Akshaya Patra Foundation, a not-for-profit organisation headquartered in Bengaluru, strives to fight issues like hunger and malnutrition in India, by implementing the mid-day meal scheme in the government schools and government-aided schools.

In line with the 'Swachh Bharat Mission' of GOI, the staff of Bank participated in Versova beach clean up drive with Mr. Afroz Shah, a lawyer based in Mumbai who is the first Indian recipient of the highest international environmental award by the UN Environment Programme: the Champion of Earth Award for 2016. The Bank has taken up the Versova beach clean-up as an ongoing project where the Bank's staff and their families assist in cleaning the beach.

The Bank also leverages social media to reach out to customers for campaigns, new developments



and achievements, among others. The platforms are also avenues for stakeholders to provide feedback and reach out to the Bank directly. The Bank has in place various policies which include Whistleblower Policy; Policy for Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of Women at the Workplace; Grievance Redressal Mechanism for Borrowers and Fair Practices Code for Lenders' Liability.

RIGHT TO INFORMATION

Exim Bank, as a public authority as defined in the Right to Information Act, 2005, is compliant with the Act. Citizens of India may apply for information under the provisions of the Act by communicating the same to the Central Public Information Officer of the Bank or any of the Assistant Public Information Officers of the Bank as mentioned on the website.

JOINT VENTURE

Global Procurement Consultants Ltd. (GPCL) conceived and promoted by Exim Bank as a private sector outfit in the year 1996, is a joint venture between Exim Bank and 11 other reputed private and public sector companies. GPCL was a pioneering concept, brought to reality through a synergetic partnership among industry leaders in sectors such as agriculture, energy, industries, mining, transportation, water resources and others. GPCL, in the past year, has broadened its range of services built around the procurement function to cover areas such as bid advisory, procurement training, e-procurement solutions, project identification, pre-

feasibility studies, preparation and review of reports, functioning as a lender's engineer, undertaking due diligence of a project, project monitoring, evaluation, capacity building and a variety of support services to the bilateral and multilateral lending agencies. The company recorded a consultancy income of ₹ 50.38 million in FY 2017-18 with a pre-tax profit of ₹ 15.02 million.

The Bank along with Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd., the State Bank of India and the African Development Bank has set up a project development company (PDC) to focus on the development of infrastructure projects in Africa. Kukuza PDC's initial capital is US\$ 25 million and the Bank's share in the capital is US\$ 4.88 million. The Company is registered in Mauritius and has commenced operations in FY 2017-18.

In order to catalyse Indian investments in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam (CLMV), the Bank in consultation with the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, has developed a framework of a Project Development Fund (PDF). Under the initiative, four projects, in sectors like healthcare in Cambodia and Myanmar, education in Myanmar and pharmaceutical in Vietnam, have been identified for preparation of Detailed Project Reports (DPRs). Based on the findings of the DPRs, the selected projects will be implemented in the respective countries, by setting up of special purpose vehicles under the PDF CLMV initiative.



The 23rd Annual Meeting of the Asian Exim Banks Forum was held in Sydney, Australia.



FINANCIAL STATEMENTS

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,

The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of the General Fund of the Export-Import Bank of India ('the Bank'), which comprises of the Balance Sheet as at 31st March, 2018 and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The Management of the Bank is responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the Export-Import Bank of India Act, 1981 ('the Act') and the Regulations framed thereunder. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements, that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
4. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
5. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Bank's Management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
6. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

7. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements, give the information in accordance with the requirements of the Act and the Regulations framed thereunder and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the General Fund of the Bank as at 31st March, 2018;
 - (ii) In the case of the Profit and Loss Account, of the loss for the year ended 31st March, 2018; and
 - (iii) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended 31st March, 2018.
- (ii) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the mandatory Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
11. We further report that:

Report on Other Legal and Regulatory Matters

8. The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement have been drawn up in accordance with the provisions of the Act and the Regulations framed thereunder.
9. We report that:
- (i) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

- (i) The Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report, are in agreement with the books of account and the returns.
- (ii) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books.

For **SORAB S. ENGINEER & CO.**
Chartered Accountants
 Firm Registration No. 110417W

CA N. D. ANKLESARIA
PARTNER
 MEMBERSHIP NO. 10250

Mumbai, 18th May, 2018.

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2018

		GENERAL FUND	
		This year (As at 31.03.2018) ₹	Previous year (As at 31.03.2017) ₹
LIABILITIES			
	SCHEDULES		
1. Capital	I	73,593,663,881	68,593,663,881
2. Reserves	II	22,407,896,155	51,645,199,126
3. Profit and Loss Account	III	-	41,300,000
4. Notes, Bonds and Debentures		865,817,469,885	806,929,554,112
5. Bills Payable		-	-
6. Deposits	IV	2,860,514,358	3,726,434,552
7. Borrowings	V	172,972,652,705	150,072,777,722
8. Current Liabilities and Provision for Contingencies		57,705,066,214	46,637,552,503
9. Other Liabilities		39,832,319,272	44,427,210,251
Total		1,235,189,582,470	1,172,073,692,147
ASSETS			
1. Cash and Bank Balances	VI	28,154,996,173	36,908,866,611
2. Investments	VII	56,969,220,517	51,029,294,879
3. Loans and Advances	VIII	1,046,570,568,346	1,017,159,983,605
4. Bills of Exchange and Promissory Notes Discounted/Rediscounted	IX	28,750,000,000	9,250,000,000
5. Fixed Assets	X	1,259,022,689	1,298,367,915
6. Other Assets	XI	73,485,774,745	56,427,179,137
Total		1,235,189,582,470	1,172,073,692,147
CONTINGENT LIABILITIES			
i) Acceptances, Guarantees, Endorsements and other obligations		116,927,666,502	78,177,713,070
ii) On outstanding forward exchange contracts		2,929,986,250	3,573,212,731
iii) On underwriting commitments		-	-
iv) Uncalled Liability on partly paid investments		163,491,675	152,677,850
v) Claims on the Bank not acknowledged as debts		2,305,300,000	1,971,000,000
vi) Bills for collection		-	-
vii) On participation certificates		-	-
viii) Bills Discounted/Rediscounted		-	-
ix) Other monies for which the Bank is contingently liable		15,771,727,879	47,274,958,286
Total		138,098,172,306	131,149,561,937

'Notes to Accounts' attached.

For and on behalf of the Board

Shri Debasish Mallick
Deputy Managing Director

Shri T. S. Tirumurti

Shri Rajeev Rishi

Shri David Rasquinha
Managing Director

Shri Pankaj Jain

Smt. Geetha Muralidhar

Shri Rajnish Kumar

As per our attached report of even date
For **Sorab S. Engineer & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 110417W

(CA N. D. Anklesaria)
Partner
M. No. 010250

Mumbai, May 18, 2018

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

EXPENDITURE	SCHEDULES	GENERAL FUND	
		This year ₹	Previous year ₹
1. Interest		65,862,992,191	65,022,307,778
2. Credit Insurance, Fees and Charges		540,074,685	628,067,389
3. Staff Salaries, Allowances, etc. and Terminal Benefits		488,732,271	563,929,962
4. Directors' and Committee Members' Fees and Expenses		-	-
5. Audit Fees		1,008,000	1,008,000
6. Rent, Taxes, Electricity and Insurance Premia		247,951,472	213,215,395
7. Communication Expenses		35,038,993	43,815,361
8. Legal Expenses		67,774,140	78,086,494
9. Other Expenses	XII	1,043,004,526	825,636,786
10. Depreciation		184,786,313	170,933,494
11. Provision for loan losses/contingencies, depreciation on investments		61,609,573,457	21,679,974,939
12. Profit/(Loss) carried down		(42,298,164,654)	3,126,382,006
Total		87,782,771,394	92,353,357,604
Provision for Income Tax [net of Deferred tax credit of ₹ 14,706,937,458 (previous year - Deferred tax credit of ₹ 4,052,096,329)]		(13,060,861,683)	2,714,263,830
Balance of Profit/(Loss) transferred to Balance Sheet		(29,237,302,971)	412,118,176
		(42,298,164,654)	3,126,382,006
INCOME			
1. Interest and Discount	XIII	82,383,628,713	84,410,889,852
2. Exchange, Commission, Brokerage and Fees		3,849,952,278	4,687,969,751
3. Other Income	XIV	1,549,190,403	3,254,498,001
Total		87,782,771,394	92,353,357,604
Profit/(Loss) brought down		(42,298,164,654)	3,126,382,006
Excess Income/Interest tax provision of earlier years written back		-	-
		(42,298,164,654)	3,126,382,006

'Notes to Accounts' attached.

For and on behalf of the Board

Shri Debasish Mallick
Deputy Managing Director

Shri T. S. Tirumurti

Shri Rajeev Rishi

Shri David Rasquinha
Managing Director

Shri Pankaj Jain

Smt. Geetha Muralidhar

Shri Rajnish Kumar

As per our attached report of even date
For **Sorab S. Engineer & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 110417W

(CA N. D. Anklesaria)
Partner
M. No. 010250

Mumbai, May 18, 2018

SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET**GENERAL FUND**

	This year (As at 31.03.2018) ₹	Previous year (As at 31.03.2017) ₹
Schedule I: Capital:		
1. Authorised	100,000,000,000	100,000,000,000
2. Issued and Paid-up: (Wholly subscribed by the Central Government)	73,593,663,881	68,593,663,881
Schedule II: Reserves:		
1. Reserve Fund	6,812,577,091	36,049,880,062
2. General Reserve	-	-
3. Other Reserves:		
Investment Fluctuation Reserve	-	-
Sinking Fund (Lines of Credit)	1,955,319,064	1,955,319,064
4. Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	13,640,000,000	13,640,000,000
	22,407,896,155	51,645,199,126
Schedule III: Profit and Loss Account:		
1. Balance as per annexed accounts	(29,237,302,971)	412,118,176
2. Less: Appropriations:		
- Transferred to Reserve Fund	(29,237,302,971)	370,818,176
- Transferred to Investment Fluctuation Reserve	-	-
- Transferred to Sinking Fund	-	-
- Transferred to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	-	-
3. Balance of the net profits (Transferable to the Central Government in terms of Section 23(2) of the Exim Bank Act, 1981)	-	-
	-	41,300,000
Schedule IV: Deposits:		
(a) In India	2,860,514,358	3,726,434,552
(b) Outside India	-	-
	2,860,514,358	3,726,434,552

	This year (As at 31.03.2018) ₹	Previous year (As at 31.03.2017) ₹
Schedule V: Borrowings:		
1. From Reserve Bank of India:		
a) Against Trustee Securities	-	-
b) Against Bills of Exchange	-	-
c) Out of the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	-	-
2. From Government of India	-	-
3. From Other Sources:		
a) In India	30,464,595,133	27,626,427,635
b) Outside India	142,508,057,572	122,446,350,087
	172,972,652,705	150,072,777,722
Schedule VI: Cash and Bank Balances:		
1. Cash in Hand	267,322	504,612
2. Balance with Reserve Bank of India	1,062,376,412	242,081,708
3. Balances with other Banks:		
a) In India		
i) In current accounts	2,753,482,451	782,330,730
ii) In other deposit accounts	265,000,000	265,000,000
b) Outside India	24,073,869,988	35,618,949,561
4. Money at call and short notice/ Lending under CBLO	-	-
	28,154,996,173	36,908,866,611

	This year (As at 31.03.2018) ₹	Previous year (As at 31.03.2017) ₹
Schedule VII: Investments: (net of diminution in value, if any)		
1. Securities of Central and State Governments	38,985,454,430	30,635,592,765
2. Equity Shares and Stocks	3,147,214,811	2,646,452,566
3. Preference Shares and Stocks	259,796,800	23,234,000
4. Notes, Debentures and Bonds	14,076,754,476	17,224,015,548
5. Others	500,000,000	500,000,000
	56,969,220,517	51,029,294,879
Schedule VIII: Loans and Advances:		
1. Foreign Governments	347,918,475,333	325,481,477,107
2. Banks:		
a) In India	183,265,470,679	145,670,664,885
b) Outside India	-	10,573,270
3. Financial Institutions:		
a) In India	-	-
b) Outside India	31,726,150,308	29,630,693,336
4. Others	483,660,472,026	516,366,575,007
	1,046,570,568,346	1,017,159,983,605
Schedule IX: Bills of Exchange and Promissory Notes Discounted/Rediscounted:		
a) In India	28,750,000,000	9,250,000,000
b) Outside India	-	-
	28,750,000,000	9,250,000,000

	This year (As at 31.03.2018) ₹	Previous year (As at 31.03.2017) ₹
Schedule X: Fixed Assets: (At cost less depreciation)		
1. Premises		
Gross Block b/f	2,064,028,557	1,734,522,255
Additions during the year	29,133,407	329,506,302
Disposals during the year	1,661,130	-
Gross Block as at the end of the year	2,091,500,834	2,064,028,557
Accumulated Depreciation	1,008,738,347	928,184,582
Net Block	1,082,762,487	1,135,843,975
2. Others		
Gross Block b/f	1,013,059,162	896,880,632
Additions during the year	121,392,454	135,003,614
Disposals during the year	97,809,713	18,825,084
Gross Block as at the end of the year	1,036,641,903	1,013,059,162
Accumulated Depreciation	860,381,701	850,535,222
Net Block	176,260,202	162,523,940
	1,259,022,689	1,298,367,915
Schedule XI: Other Assets:		
1. Accrued interest on:		
a) investments/bank balances	11,120,355,964	10,791,054,440
b) loans and advances	15,936,763,898	14,151,386,600
2. Deposits with sundry parties	43,378,422	37,238,334
3. Advance Income Tax paid (net)	7,095,229,016	7,930,845,159
4. Others [including Deferred tax asset of ₹ 33,274,681,260 (previous year ₹ 18,567,743,802)]	39,290,047,445	23,516,654,604
	73,485,774,745	56,427,179,137
Schedule XII: Other Expenses:		
1. Export Promotion Expenses	19,460,137	34,330,480
2. Expenses on and related to Data Processing	6,694,221	14,547,043
3. Repairs and Maintenance	208,816,959	197,215,272
4. Printing and Stationery	13,396,427	12,261,031
5. Others	794,636,782	567,282,960
	1,043,004,526	825,636,786

	This year (As at 31.03.2018) ₹	Previous year (As at 31.03.2017) ₹
Schedule XIII: Interest and Discount:		
1. Interest and Discount on loans and advances/bills discounted/rediscounted	53,302,677,483	54,462,592,775
2. Income on Investments/bank balances	29,080,951,230	29,948,297,077
	82,383,628,713	84,410,889,852
Schedule XIV: Other Income:		
1. Net Profit on sale/revaluation of investments	1,520,032,565	3,108,552,970
2. Net Profit on sale of land, buildings and other assets	18,042,191	944,930
3. Others	11,115,647	145,000,101
	1,549,190,403	3,254,498,001

Note:

Deposits under 'Liabilities' [ref. Schedule IV (a)] include 'on shore' foreign currency deposits aggregating US\$ 34.92 million (Previous year US\$ 39.66 million) kept by counter party banks / institutions with Exim Bank against reciprocal rupee deposits / bonds. Cash & Bank Balances under 'Assets' [ref. Schedule VI 3. (a) ii)] include rupee deposits aggregating "NIL" (Previous year NIL) on account of swaps. Investments under 'Assets' [ref. Schedule VII 4.] include bonds aggregating ₹ 1.58 billion (Previous year ₹ 1.79 billion) on account of swaps.

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

Particulars	Amount (₹ million)	
	Year ended March 31, 2018	Year ended March 31, 2017
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Net Profit/(Loss) before tax and extra-ordinary items	(42,298.2)	3,126.4
Adjustments for:		
- (Profit)/Loss on sale of Fixed Assets (Net)	(18.0)	(0.9)
- (Profit)/Loss on sale of Investments (Net)	(1,520.0)	(3,108.6)
- Depreciation	184.8	170.9
- Discount/Expenses on bond issues written off	184.3	229.2
- Transfer from Investment Fluctuation Reserve	-	-
- Provisions/Write Off of Loans/Investments and other provisions	61,609.5	21,680.0
- Others - to specify	-	-
	18,142.4	22,097.0
Adjustments for:		
- Other Assets	(3,254.0)	(2,040.7)
- Current Liabilities	(49,785.8)	(33,434.1)
CASH GENERATED FROM OPERATIONS	(34,897.4)	(13,377.8)
Payment of income tax/interest tax	(6,161.2)	(6,280.2)
NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	(41,058.6)	(19,658.0)
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
- Net purchase of fixed assets	(127.4)	(466.5)
- Net change in investments	(4,419.9)	5,634.6
NET CASH USED IN/RAISED FROM INVESTING ACTIVITIES	(4,547.3)	5,168.1
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
- Equity capital infusion	5,000.0	5,000.0
- Loans borrowed (net of repayments made)	80,803.9	27,519.5
- Loans lent, bills discounted and rediscounted (net of repayments received)	(48,910.6)	(35,242.7)
- Dividend on equity shares and tax on dividend (Balance of Net profits transferred to Central Government)	(41.3)	(315.8)
Net cash used in/raised from Financing Activities	36,852.0	(3,039.0)
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	(8,753.9)	(17,528.9)
OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS	36,908.9	54,437.8
CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS	28,155.0	36,908.9

For and on behalf of the Board

Shri Debasish Mallick
Deputy Managing Director

Shri T. S. Tirumurti

Shri Rajeev Rishi

Shri David Rasquinha
Managing Director

Shri Pankaj Jain

Smt. Geetha Muralidhar

Shri Rajnish Kumar

As per our attached report of even date
For **Sorab S. Engineer & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 110417W

(CA N. D. Anklesaria)
Partner
M. No. 010250

Mumbai, May 18, 2018

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

I. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

i) Financial Statements

a) Basis of preparation

The Balance Sheet and Profit and Loss account of Export-Import Bank of India (Exim Bank) (General Fund and Export Development Fund) have been prepared in accordance with the accounting principles followed in India. The financial statements have been prepared under the historical cost convention on an accrual basis unless otherwise stated. The accounting policies that are applied by the Bank are consistent with those used in the previous year. The form and manner in which the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of Exim Bank are prepared have been provided in the Export-Import Bank of India, General Regulations, 1982 approved by the Board of Directors with the previous approval of Government of India under Section 39 (2) of Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981). Certain important financial ratios/data are disclosed as part of the “Notes to Accounts” in terms of Reserve Bank of India (RBI) Circular DBS.FID.No.108/01.02.000/2015-16 dated June 23, 2016 and thereafter.

b) Use of estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. The management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

ii) Revenue Recognition

Income/Expenditure is recognised on accrual basis except in respect of interest on Non-performing Assets (NPA) / Non-performing Investments and “Stressed Assets”, interest on loans under Strategic Debt Restructuring, fee income, commission, commitment charges and dividend which are accounted on cash basis. NPAs are determined as per RBI guidelines issued to All-India Term Lending Institutions. Discount / redemption premium offered on Exim Bank Bonds has been amortised over the tenure of the bond and included in interest expenses.

iii) Asset Classification and Provisioning

Loans and Advances shown in Balance Sheet comprise only principal outstanding net of provisions for Non-Performing Assets (NPA). Interest receivables are grouped under “Other Assets”.

Loan Assets are classified into the following groups: Standard Assets, Sub-standard Assets, Doubtful Assets and Loss Assets, taking into consideration the degree of credit weaknesses and extent of dependence on collateral security for realisation of dues. Classification of loan assets and provisioning are as per RBI guidelines issued to All-India Term Lending Institutions.

iv) Investments

The entire investment portfolio is classified under three categories:

- a) “Held to Maturity” (the securities acquired with the intention to hold them to maturity),
- b) “Held for Trading” (the securities acquired with the intention to trade by taking advantage of the short term price/interest rate movements, etc.) and
- c) “Available for Sale” (the balance investments).

The investments are further classified as:

- i) Government securities
- ii) Other approved securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Subsidiaries/Joint Ventures
- vi) Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, etc.)

The classification of various instruments of investments, categorisation, shifting among categories, valuation and provisioning of investments are done in accordance with the norms laid down by RBI to All-India Term Lending Institutions.

v) Fixed Assets and Depreciation

- a) Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation.
- b) Depreciation is provided for on straight-line method basis at the following rates:

Asset	Depreciation Rate
Owned Buildings	5%
Furniture and Fixtures	25%
Office Equipments	25%
Other Electrical Equipments	25%
Computers and Computer Software	25%
Motor Vehicles	25%
Mobile Phones and other electronic items subject to rapid technological obsolescence	33.33%

- c) In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided for the entire year in the year of purchase and in respect of assets sold during the year, no depreciation is provided in the year of sale.
- d) When a depreciable asset is disposed off, discarded, demolished or destroyed, the net surplus or deficit is adjusted in the Profit and Loss Account.

vi) Impairment

The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date based on internal/external factors to provide for impairment in the value of the assets or reverse impairment losses recognised in previous periods, as applicable. Impairment loss is recognised when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

vii) Accounting for Foreign Currency Transactions

- a) Assets and liabilities denominated in foreign currency are translated at the exchange rate notified by the Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at year end.
- b) Income and expenditure items are translated at the average rates of exchange during the year.
- c) Outstanding foreign exchange contracts are revalued at rates of exchange notified by the FEDAI for specified maturities and the resulting profits/losses are included in the Profit and Loss account.
- d) Contingent liabilities in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the rates of exchange notified by FEDAI at year end.

viii) Guarantees

Provisioning for guarantees is made taking into account the likely losses on projects till their completion, for uncovered portion under ECGC policies.

ix) Derivatives

The Bank presently deals in derivative contracts such as Interest Rate Swaps, Currency Swaps, Cross-Currency Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements, for hedging its assets and liabilities. Based on RBI Guidelines, the above derivatives undertaken for hedging purposes are accounted on accrual basis. Qualitative and Quantitative disclosures pertaining to outstanding derivative contracts are reported in the "Notes to Accounts" in accordance with RBI's Master Circular "Disclosure norms for Financial Institutions" on the Balance Sheet date.

x) Provision for Employee Benefits

- a) Provident Fund, Gratuity Fund and Pension Fund are defined benefit schemes administered by the Bank and the Bank's contributions to these funds are charged to the Profit and Loss Account for the year.
- b) Gratuity and Pension are defined benefit obligations. Liabilities towards these obligations are provided for on the basis of actuarial valuation at the end of each financial year based on the projected unit credit method.
- c) Liability towards leave encashment is provided for on the basis of actuarial valuation at year end.

xi) Accounting for Taxes on Income

- a) Provision for current tax is made, based on the tax payable under the relevant statute.
- b) Deferred tax on timing difference between taxable income and accounting income is accounted for, using the tax rates and the tax law enacted or substantially enacted as on the Balance Sheet date. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a virtual certainty of realisation.

xii) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

As per AS 29 – “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liabilities are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

II. NOTES TO ACCOUNTS – GENERAL FUND**1. Agency Account**

As Exim Bank is acting only in the capacity of an agency to facilitate certain transactions in Iraq relating to Indian contractors, foreign currency receivables advised to the Bank equivalent to ₹ 44.79 billion (previous year ₹ 44.57 billion) held on agency account including a sum of ₹ 40.48 billion (previous year ₹ 40.27 billion) assigned to Government of India (GOI) are not included in the above Balance Sheet.

2. Income-Tax

The capital of the Bank is wholly subscribed by the Central Government and the Bank does not have any share capital. The balance of profit transferable to the Central Government in accordance with Section 23 (2) of the Export-Import Bank of India Act, 1981 is not termed as dividend. Consequently, dividend distribution tax is considered not payable, in the light of the judgement passed by the Income Tax Appellate Tribunal in case no. ITA No. 2025 / Mum / 2000 on December 18, 2006 and hence, no provision has been made for the same.

3. a) Contingent Liabilities

Guarantees include expired guarantees of ₹ 1.24 billion (previous year ₹ 2.01 billion), yet to be cancelled in the books.

b) Claims not acknowledged as debts

The amount of ₹ 2.31 billion (previous year ₹ 1.97 billion) shown under Contingent Liabilities as “Claims on the Bank not acknowledged as debts”, pertains to claims/counter-claims filed against the Bank mostly by Bank’s defaulting borrowers in response to legal action initiated against them by the Bank. None of the claims / counter-claims is considered as maintainable in the opinion of Bank’s solicitors and none of them has reached the stage of final hearing. Based on professional advice, no provision is considered necessary.

c) Forward Exchange Contracts, Currency / Interest Rate Swaps

- i) The outstanding forward exchange contracts as at March 31, 2018 have been fully hedged. The Bank undertakes derivatives transactions (Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Currency-cum-interest rate swaps), for the purpose of Asset-Liability Management as per RBI guidelines issued vide circular Ref. No. MPD.BC.187/07.01.279/1999-2000 dated July 7, 1999 and thereafter. The Bank also unwinds and re-enters such transactions based on requirements/market conditions. The outstanding derivative transactions are captured in the interest rate sensitivity position, which is monitored by the Asset Liability Management Committee (ALCO) and reviewed by the Board. The credit equivalent of derivatives is arrived at as per ‘Current Exposure’ method prescribed by RBI. The fair value and the price value of a basis point (PV01) of derivatives are disclosed separately in the ‘Notes to Accounts’ as stipulated by RBI. The premium or discount arising at inception of forward exchange contracts is amortised over the life of the contracts. Any profit or loss arising on cancellation of forward exchange contracts is recognized as income/expense for the year.
- ii) The Bank is permitted to be a ‘market maker’ for offering long-dated Foreign Currency-Rupee Swaps to clients/non-clients.

d) Profit/Loss on Exchange fluctuation

Assets and liabilities denominated in foreign currency are translated at the exchange rate notified by the Foreign Exchange Dealers’ Association of India (FEDAI) at year end. Income and expenditure items are translated at the average rates of exchange during the year. The notional loss on such translation of the retained earnings on FC operations during the current year is ₹ 0.13 billion (previous year notional profit of ₹ 0.22 billion).

4. Disclosure relating to Micro, Small and Medium Enterprises under the Micro, Small and Medium Enterprises Act, 2006: There have been no reported cases of delayed payments to Micro, Small and Medium Enterprises.

5. Additional Information as required by Reserve Bank of India

5.1 Capital

(a)

	Particulars	As on March 31, 2018	As on March 31, 2017
(i)	Capital to Risk Assets Ratio (CRAR)	10.35%	15.81%
(ii)	Core CRAR	8.82%	14.29%
(iii)	Supplementary CRAR	1.53%	1.52%

(b) The amount of subordinated debt raised and outstanding as on March 31, 2018 as Tier-II capital: ₹ NIL (previous year: ₹ NIL).

(c) Risk weighted assets

(₹ billion)

	Particulars	As on March 31, 2018	As on March 31, 2017
(i)	'On' balance sheet items	579.05	590.05
(ii)	'Off' balance sheet items	73.80	126.71

(d) The share holding pattern as on the date of the balance sheet: Capital wholly subscribed by the Government of India.

- The CRAR and other related parameters have been determined as per the extant capital adequacy norms prescribed by RBI for the Financial Institutions (FIs).
- The revised Framework to be prescribed by the RBI, including the Basel III norms, are still at draft stage. The Bank will implement Basel III norms for determining CRAR from the date they become effective. However, the final notification from RBI is awaited.

5.2 Free Reserves and Provisions

(a) Provisions on Standard Assets

(₹ billion)

	Particulars	2017-18	2016-17
(i)	Provisions towards Standard Assets	14.08	(9.22)

(b) Floating Provisions

(₹ billion)

	Particulars	2017-18	2016-17
(a)	Opening balance in the floating provisions accounts	-	-
(b)	The quantum of floating provisions made in the accounting year	-	-
(c)	Amount of draw down made during the accounting year	-	-
(d)	Closing balance in the floating provisions account	-	-

5.3 Asset Quality and Specific Provisions**(a) Non-Performing Advances**

(₹ billion)

	Particulars	2017-18	2016-17
(i)	Net NPAs to Net Advances (%)	3.75%	4.688%
(ii)	Movement of NPAs (Gross)		
(a)	Opening balance	99.62	42.75
(b)	Additions during the year	43.24	68.10
(c)	Reductions during the year	23.10	11.23
(d)	Closing balance	119.76	99.62
(iii)	Movement of Net NPAs		
(a)	Opening balance	48.04	8.55
(b)	Additions during the year	24.87	45.85
(c)	Reductions during the year	32.63	6.36
(d)	Closing balance	40.28	48.04
(iv)	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a)	Opening balance	51.59	34.20
(b)	Provisions made during the year	39.27	31.94
(c)	Write off/write back of excess provisions	11.38	14.55
(d)	Closing balance	79.48	51.59

(b) Non-Performing Investments

(₹ billion)

	Particulars	2017-18	2016-17
(i)	Net NPIs to Net Investments (%)	0.80%	0.008%
(ii)	Movement of NPIs (Gross)		
(a)	Opening balance	1.63	0.65
(b)	Additions during the year	1.95	1.01
(c)	Reductions during the year	0.54	0.03
(d)	Closing balance	3.04	1.63
(iii)	Movement of Net NPIs		
(a)	Opening balance	0.0042	-
(b)	Additions during the year	0.4554	0.0042
(c)	Reductions during the year	0.0042	-
(d)	Closing balance	0.4554	0.0042
(iv)	Movement of Provisions for NPIs (excluding provisions on standard assets)		
(a)	Opening balance	1.63	0.65
(b)	Provisions made during the year	1.51	1.01
(c)	Write off/write back of excess provisions	0.56	0.03
(d)	Closing balance	2.58	1.63

(c) Non-Performing Assets (a+b)

(₹ billion)

	Particulars	2017-18	2016-17
(i)	Net NPAs to Net Assets (Advances + Investments) (%)	3.60%	4.688%
(ii)	Movement of NPAs (Gross Advances + Gross Investments)		
(a)	Opening balance	101.25	43.40
(b)	Additions during the year	45.19	69.11
(c)	Reductions during the year	23.64	11.26
(d)	Closing balance	122.80	101.25
(iii)	Movement of Net NPAs		
(a)	Opening balance	48.0442	8.55
(b)	Additions during the year	25.3254	45.8542
(c)	Reductions during the year	32.6342	6.36
(d)	Closing balance	40.7354	48.0442
(iv)	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a)	Opening balance	53.22	34.85
(b)	Provisions made during the year	40.78	32.95
(c)	Write off/write back of excess provisions	11.94	14.58
(d)	Closing Balance	82.06	53.22

5.4 Particulars of Accounts Restructured

(₹ billion)

Sr. No.	Type of Restructuring	Details	Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				Total			
			Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard		Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on date of opening of the FY (opening figures)*	No. of borrowers	15	-	11	-	26	2	-	3	-	5	12	1	9	-	22	53
		Amount outstanding	11.12	-	5.47	-	16.59	0.03	-	0.11	-	0.14	8.23	1.09	9.20	-	18.52	35.25
		Provision thereon	3.85	-	3.98	-	7.83	0.006	-	0.08	-	0.08	0.90	0.26	6.30	-	7.46	15.37
2	Fresh restructuring / Additions during the year	No. of borrowers	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	1	2	5	-	8	11
		Amount outstanding	1.24	-	0.58	-	1.82	-	-	-	-	-	1.07	1.89	4.29	-	7.25	9.07
		Provision thereon	0.54	-	0.76	-	1.30	-	-	-	-	-	0.17	0.48	4.77	-	5.42	6.72
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09	-	-	1.09	1.09
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	-	-	0.26	0.26
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Downgradations/Reductions of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	6	-	5	-	11	1	-	1	-	2	7	-	3	-	10	23
		Amount outstanding	7.01	-	3.71	-	10.72	0.02	-	0.09	-	0.11	3.87	-	2.08	-	5.95	16.78
		Provision thereon	2.11	-	2.55	-	4.66	0.004	-	0.053	-	0.06	0.58	-	1.53	-	2.11	6.83
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Amount outstanding	-	-	0.73	-	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.73
		Provision thereon	-	-	0.65	-	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65
7	Restructured Accounts as on date of closing of the FY (closing figures)*	No. of borrowers	10	-	7	-	17	1	-	2	-	3	6	2	11	-	19	39
		Amount outstanding	5.35	-	1.61	-	6.96	0.01	-	0.02	-	0.03	5.43	1.89	11.41	-	18.73	25.72
		Provision thereon	2.28	-	1.54	-	3.82	0.002	-	0.02	-	0.02	0.49	0.48	9.54	-	10.51	14.35

5.5 Movement of Non-Performing Assets

(₹ billion)

Particulars	2017-18	2016-17
Gross NPAs as on 1 st April (Opening balance)	99.62	42.75
Additions (Fresh NPAs) during the year	40.93	68.10
Interest funding	2.06	(0.39)
Exchange Fluctuation	0.25	-
Sub Total (A)	142.86	110.46
Less:		
(i) Upgradations	3.13	1.55
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	5.38	2.70
(iii) Technical/Prudential write offs	14.34	5.31
(iv) Write offs other than those under (iii) above	0.25	0.76
(v) Exchange Fluctuation	-	0.52
Sub Total (B)	23.10	10.84
Gross NPAs as on 31 st March (closing balance) (A-B)	119.76	99.62

Gross NPAs as per Appendix Part C-2 of DBR circular DBR.No.BP.BC.2/21.04.048/2015-16 dated July 01, 2015.

5.6 Write-offs and Recoveries

(₹ billion)

Particulars	2017-18	2016-17
Opening balance of Technical/Prudential written off accounts as at 1 st April	6.04	0.75
Add: Technical/Prudential write offs during the year	14.34	5.31
Sub Total (A)	20.38	6.06
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written off accounts during the year (B)	0.0007	0.02
Closing balance as on 31 st March (A-B)	20.38	6.04

5.7 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ billion)

Particulars	2017-18	2016-17
Total Assets	95.26	121.52
Total NPAs	5.62	6.64
Total Revenue	6.99	7.20

The above figures pertain to Bank's London branch, which started operations in October, 2010.

5.8 Depreciation and Provision on Investments

(₹ billion)

	Particulars	2017-18	2016-17
(1)	Investments		
(i)	Gross Investments	73.11	61.54
a)	In India	73.11	61.54
b)	Outside India	-	-
(ii)	Provision for Depreciation	16.14	10.52
a)	In India	16.14	10.52
b)	Outside India	-	-
(iii)	Net Investments	56.97	51.03
a)	In India	56.97	51.03
b)	Outside India	-	-
(2)	Movement of provision held towards depreciation on investments		
(i)	Opening balance	10.52	5.07
(ii)	Add: Provisions made during the year	5.62	5.47
(iii)	Appropriation, if any, from Investment Fluctuation Reserve Account during the year	-	-
(iv)	Less: Write off/write back of excess provisions during the year	-	0.02
(v)	Less: Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve Account	-	-
(vi)	Closing balance	16.14	10.52

5.9 Provisions and Contingencies

(₹ billion)

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2017-18	2016-17
Provision for depreciation on Investment	5.58	5.50
Provision towards NPA	26.84	17.91
Provision made towards Income tax	(13.06)	2.71
Other Provisions and Contingencies	0.0024	(0.07)

5.10 Provision Coverage Ratio

Particulars	2017-18	2016-17
Provision Coverage Ratio	71.26%	54.54%

6. Investment Portfolio: Constitution and Operations

6.1 Repo Transactions

Current Year:

(₹ billion)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2018
Securities sold under repos				
i) Government Securities	-	-	-	-
ii) Corporate Debt Securities	-	-	-	-
Securities Purchased under reverse repos				
i) Government Securities	-	-	-	-
ii) Corporate Debt Securities	-	-	-	-

Previous Year:

(₹ billion)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2017
Securities sold under repos				
i) Government Securities	-	-	-	-
ii) Corporate Debt Securities	-	-	-	-
Securities Purchased under reverse repos				
i) Government Securities	-	-	-	-
ii) Corporate Debt Securities	-	-	-	-

6.2 Disclosure of Issuer Composition for Investment in Debt Securities

Current Year:

(₹ billion)

Sr. No.	Issuer	Amount	Amount of			
			Investment made through private placement	“Below investment grade” Securities held	“Unrated” Securities held	“Unlisted” Securities held
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	0.032	-	-	0.03	0.03
2	FIs	1.82	1.58	-	0.24	1.82**
3	Banks	0.17	-	-	0.17	0.16
4	Private corporates	29.91	29.85	-	29.91	26.15*
5	Subsidiaries/ Joint ventures	0.0032	-	-	0.0032	0.0032
6	Others	0.50	-	-	-	0.50
7	Provision held towards depreciation [#]	14.45	-	-	-	-
	Total	32.43	31.43	-	30.35	28.67

[#] Only aggregate amount of provision held is disclosed in column 3

^{*} Out of which ₹ 21.61 billion represents investment in security receipts issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) and ₹ 4.19 billion of investments are in shares/debentures acquired as part of loan restructuring.

^{**} Out of which ₹ 1.58 billion were by way of US\$/INR Swap undertaken with RBI approval.

Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

Previous Year:

(₹ billion)

Sr. No.	Issuer	Amount	Amount of			
			Investment made through private placement	“Below investment grade” Securities held	“Unrated” Securities held	“Unlisted” Securities held
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	0.04	-	-	0.04	0.04
2	FIs	2.03	1.79	-	0.24	2.03**
3	Banks	0.27	0.10	-	0.17	0.17
4	Private corporates	27.47	27.41	-	27.47	24.94*
5	Subsidiaries/ Joint ventures	0.0032	-	-	0.0032	0.0032
6	Others	0.50	-	-	-	0.50
7	Provision held towards depreciation#	9.92	-	-	-	-
	Total	30.31	29.30	-	27.92	27.68

Only aggregate amount of provision held is disclosed in column 3

* Out of which ₹ 22.13 billion represents investment in security receipts issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) and ₹ 2.76 billion of investments are in shares/debentures acquired as part of loan restructuring.

** Out of which ₹ 1.79 billion were by way of US\$/INR Swap undertaken with RBI approval.

Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

6.3 Sale and Transfer to/from HTM Category

There has been no sale or transfer.

7. Details of Financial Assets Purchased/Sold

7.1 Details of Financial Assets sold to Securitisation (SC)/Reconstruction (RC) Company for Asset Reconstruction

A. Details of Sales

(₹ billion)

Sr. No.	Particulars	2017-18	2016-17
(i)	No. of Accounts	-	2
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	-	0.39
(iii)	Aggregate consideration	-	0.34
(iv)	Consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	-	-
(v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	-	(0.05)

- The "Assets sold to Reconstruction Companies" have been reckoned as defined in RBI Master Circular DBOD No. FID.FIC.2/01.02.00/2006-07 dated July 01, 2006 and thereafter.

B. Details of Book value of Investments in Security Receipts

(₹ billion)

Sr. No.	Particulars	Book value of Investments in Security receipts	
		2017-18	2016-17
(i)	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	10.04	13.67
(ii)	Backed by NPAs sold by banks/other financial institutions/ non-banking financial companies as underlying	-	-
	Total	10.04	13.67

7.2 Details of Non Performing Financial Assets Purchased/Sold

A. Details of Non Performing financial assets purchased

(₹ billion)

Sr. No.	Particulars	2017-18	2016-17
1)	a) No. of accounts purchased during the year	-	-
	b) Aggregate outstanding	-	-
2)	a) Of these, number of accounts restructured during the year	-	-
	b) Aggregate outstanding	-	-

B. Details of Non Performing financial assets sold

(₹ billion)

Sr. No.	Particulars	2017-18	2016-17
1)	No. of accounts sold	1	-
2)	Aggregate outstanding	1.96	-
3)	Aggregate consideration received	1.71	-

8. Operating Results

Sr. No.	Particulars	2017-18	2016-17
(i)	Interest income as a percentage to average working funds	7.24	7.63
(ii)	Non-interest income as a percentage to average working funds	0.47	0.72
(iii)	Operating profit as a percentage to average working funds	1.70	2.24
(iv)	Return on average assets	(2.42)	0.04
(v)	Net Profit/(Loss) per (permanent) employee (in ₹ billion)	(0.086)	0.001

- For operating results, the working funds and total assets have been taken as the average of the figures as at the end of the previous accounting year and the end of the accounting year under report (The “working funds” refer to the total assets).
- All permanent, full-time employees in all cadres have been reckoned for computing per employee net profit/(loss).

9. Credit Concentration Risk**9.1 Capital Market Exposure**

Sr. No.	Particulars	2017-18	2016-17
(i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	-	-
(ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds;	-	-
(iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-

(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	-	-
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	-	-
(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	-	-
(viii)	Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
(ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	-	-
	Total Exposure to Capital Market	-	-

9.2 Exposure to Country Risk

(₹ billion)

Risk Category	Exposure (net) as at March 2018	Provision held as at March 2018 [®]	Exposure (net) as at March 2017	Provision held as at March 2017 [®]
Insignificant	98.42	-	108.78	-
Low	325.94	-	452.30	-
Moderate	249.59	-	626.28	-
High	97.22	-	73.55	-
Very High	-	-	-	-
Restricted	90.73	-	114.78	-
Off-credit	-	-	-	-
Total	861.90	-	1,375.69	-

[®] The Bank is not required to provide for country concentration risk, as there is no circular addressed to FIs.

9.3 Strategic Debt Restructuring (SDR) Scheme

(₹ billion)

No. of accounts	Aggregate amount outstanding	Amount of exposure converted into equity
2	0.61	0.98

SDR - Change in Ownership Outside SDR Scheme

(₹ billion)

No. of accounts	Aggregate amount outstanding	Amount of exposure converted into equity
1	0.50	0.51

9.4 Exposure on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A)

(₹ billion)

Particulars	No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount Outstanding		Provision Held
			In Part A	In Part B	
Classified as Standard	3	3.22	4.32	3.51	2.14
Classified as NPA	-	-	-	-	-

9.5 Prudential Exposure Limits – Single Borrower Limit (SGL)/Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

A. The number and amount of exposures in excess of the prudential exposure limits during the year

(₹ billion)

Sr. No.	PAN No.	Borrower Name	Industry Code	Industry Name	Sector	Amount Funded	Amount Non-Funded	Exposure as a % to Capital Funds
1.	AAACM5132A	Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd.*	11101	Petrochemicals	Public	22.16	-	19.56
2.	AADCV1810B	VOVL Ltd.*	40201	Oil and Gas	Private	19.16	-	16.91

* Approval of the Board was obtained, for additional exposure of 5% of TCF in line with RBI guidelines

B. Credit exposure as percentage to capital funds and as percentage to total assets

	Particulars	Percentage to Capital Funds*	Percentage to Total Credit Exposure (TCE) [®]	Percentage to Total Assets
i)	Largest single borrower	19.56	1.20	1.79
ii)	Largest borrower group	33.40	2.06	3.06
iii)	20 largest single borrowers	222.36	13.68	20.40
iv)	20 largest borrower groups	282.30	17.37	25.90

*Capital Funds as on March 31, 2017

[®]TCE: Loans + Advances + Unutilised Sanctions + Guarantees + LCs + Credit exposure on account of derivatives.

- 1) Credit exposure to banks and overseas institutions guaranteed by GOI/assumed at the behest of GOI, not considered for single/group borrower exposure.
- 2) There were 2 borrowers as on March 31, 2018 for whom exposure over 15% of capital funds was assumed with the approval of the Board. Exposure to these borrowers as on March 31, 2018 stood at 19.56% and 16.91% of the capital funds of the Bank, respectively.

Previous Year:

	Particulars	Percentage to Capital Funds*	Percentage to Total Credit Exposure (TCE) [®]	Percentage to Total Assets
i)	Largest single borrower	16.01	0.77	1.46
ii)	Largest borrower group	31.45	1.52	2.87
iii)	20 largest single borrowers	193.26	9.35	17.61
iv)	20 largest borrower groups	281.99	13.65	25.70

* Capital Funds as on March 31, 2016

[®]TCE: Loans + Advances + Unutilised Sanctions + Guarantees + LCs + Credit exposure on account of derivatives.

- 1) Credit exposure to banks and overseas institutions guaranteed by GOI/assumed at the behest of GOI, not considered for single/group borrower exposure.
- 2) There was 1 borrower as on March 31, 2017 for whom exposure over 15% of capital funds was assumed with the approval of the Board. Exposure to this borrower as on March 31, 2017 stood at 16.01% of the capital funds of the Bank.

C. Credit exposure to the five largest industrial sectors

	Sector	Percentage to Total Credit Exposure (TCE)	Percentage to Loan Assets
i)	EPC Services	12.26	9.28
ii)	Ferrous Metals and Metal Processing	9.84	7.45
iii)	Petroleum Products	6.87	5.20
iv)	Textiles and Garments	6.10	4.62
v)	Oil and Gas	5.64	4.27

Previous Year:

	Sector	Percentage to Total Credit Exposure (TCE)	Percentage to Loan Assets
i)	EPC Services	10.09	7.49
ii)	Ferrous metals and Metal Processing	9.68	7.18
iii)	Oil and Gas	7.68	5.70
iv)	Textiles and Garments	6.53	4.85
v)	Construction	5.16	3.83

- The “credit exposure” has been reckoned as defined by RBI.
- Credit exposure to banks and overseas institutions guaranteed by GOI/assumed at the behest of GOI, excluded for computing industry exposure.

D. Unsecured Advances

Unsecured advances aggregating ₹ 6.81 billion were secured by corporate/personal guarantees, promissory notes, trust receipts, etc. the estimated value of which is at ₹ 1.74 billion.

E. Factoring Exposures

The Bank had an exposure aggregating ₹ 1.4 billion under factoring arrangement.

F. Exposures where the Bank had exceeded the prudential Exposures Limits during the year

(₹ billion)

Sr. No.	PAN No.	Borrower Name	Industry Code	Industry Name	Sector	Amount Funded	Amount Non-Funded	Exposure as a % to Capital Funds
1.	AAACM5132A	Mangalore Refinery And Petrochemicals Ltd.	11101	Petro-chemicals	Public	22.16	-	19.56
2.	AADCV1810B	VOVL Ltd.	40201	Oil and Gas	Private	19.16	-	16.91

There were 2 borrowers as on March 31, 2018 for whom exposure over 15% of capital funds was assumed with the approval of the Board. Exposure to these borrowers as on March 31, 2018 stood at 19.56% and 16.91% of the capital funds of the Bank, respectively.

10. Concentration of borrowings/lines of credit, credit exposures and NPAs

(a) Concentration of borrowings and lines of credit

(₹ billion)

Particulars	2017-18	2016-17
Total borrowings from twenty largest lenders	132.30	103.48
Percentage of borrowings from twenty largest lenders to total borrowings of the Bank	12.70%	10.77%

(b) Concentration of Credit exposures

(₹ billion)

Particulars	2017-18	2016-17
Total exposures to twenty largest borrowers	251.94	206.45
Percentage of exposures to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	21.82%	19.15%
Total exposure to twenty largest borrowers/customers	251.94	206.45
Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to Total exposure of the Bank on borrowers/customers	13.68%	9.35%
In the case of Exim Bank, percentage of total of top ten country exposures to total exposures	27.56%	37.30%

Exposure computed based on credit and investment exposure as prescribed vide RBI Master Circular on Exposure norms for financial institutions: DBR.FID.FIC.No.4/01.02.00/2015-16 dated July 01, 2015 and thereafter.

(c) Sector-wise concentration of exposures and NPAs

(₹ billion)

Sr. No.	Sector	2017-18			2016-17		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Domestic Sector	370.61	84.13	23%	356.40	62.02	17%
1	Total Export Finance	330.56	72.65	22%	307.51	60.52	20%
	Agricultural Sector	-	-	-	-	-	-
	<u>Industrial Sector</u>	294.46	61.42	21%	272.88	49.25	18%
	Ferrous Metals & Metal Processing	44.41	21.04	47%	44.26	20.39	46%
	Oil and Gas	-	-	-	7.89	0.93	12%
	Textiles & Garments	41.80	6.61	16%	-	-	-
	Others	208.25	33.77	16%	220.73	27.94	13%
	<u>Services Sector</u>	36.10	11.23	31%	34.63	11.27	33%

(₹ billion)

	Aviation Services	-	-	-	2.94	-	-
	EPC Services	13.61	9.78	72%	14.75	10.04	68%
	Shipping Services	11.54	0.62	5%	9.29	0.62	7%
	Others	10.95	0.83	8%	7.65	0.61	8%
2	Total Import Finance	40.05	11.48	29%	48.89	1.50	3%
	Agricultural Sector	-	-	-	-	-	-
	Industrial Sector	35.20	11.48	33%	41.97	0.01	0.02%
	Ferrous Metals & Metal Processing	1.54	1.54	100%	1.44	-	-
	Oil and Gas	-	-	-	11.37	-	-
	Others	33.66	9.94	29.53%	29.17	0.01	0.02%
	Services Sector	4.85	-	-	6.92	1.49	22%
	EPC Services	0.34	-	-	1.92	1.49	78%
	Shipping Services	3.47	-	-	3.51	-	-
	Others	1.04	-	-	1.49	-	-
3	Of (A), exposures guaranteed by the Government of India	-	-	-	-	-	-
B	External Sector	146.07	35.63	24%	184.67	37.60	20%
1	Total Export Finance	146.07	35.63	24%	184.67	37.60	20%
	Agricultural Sector	-	-	-	-	-	-
	Industrial Sector	114.65	24.68	22%	152.74	25.03	16%
	Ferrous Metals & Metal Processing	24.35	2.39	10%	26.29	1.62	6%
	Oil and Gas	-	-	-	29.98	8.19	27%
	Textiles & Garments	3.20	-	-	-	-	-
	Others	87.10	22.29	26%	96.47	15.22	16%
	Services Sector	31.42	10.95	35%	31.93	12.56	39%
	Aviation Services	-	-	-	5.10	-	-
	EPC Services	10.94	4.50	41%	12.25	4.33	35%
	Shipping Services	4.31	3.37	78%	4.45	3.38	76%
	Others	16.17	3.08	19%	10.13	4.85	48%
2	Total Import Finance	-	-	-	-	-	-
	Agricultural Sector	-	-	-	-	-	-
	Industrial Sector	-	-	-	-	-	-
	Services Sector	-	-	-	-	-	-
3	Of (B), exposures guaranteed by the Government of India	-	-	-	-	-	-
C	Other Exposures[#]	638.12	-	-	536.93	-	-
D	Total Exposures (A+B+C)	1,154.80	119.76	10.37%	1,078.00	99.62	9.24%

[#] includes advances under Lines of Credit, Buyer's Credit - National Export Insurance Account, Concessional Finance Scheme, Refinance to Commercial Banks and Advances Counter-guaranteed by Banks.

11. Derivatives

11.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(₹ billion)

Sr. No.	Particulars	2017-18		2016-17	
		Hedging	Trading	Hedging	Trading
1.	The Notional Principal of swap agreements	348.12	-	290.75	-
2.	Losses, which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	0.10	-	0.37	-
3.	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	-	-	-	-
4.	Concentration of credit risk arising from Swaps	All transactions fall within approved credit exposure limits	-	All transactions fall within approved credit exposure limits	-
5.	The fair value of the swap book	(11.28)	-	(6.73)	-

Nature and Terms of Swaps: All transactions have underlying assets/liabilities and have been undertaken for the purpose of hedging the Bank's ALM position.

11.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ billion)

Sr. No.	Particulars	Amount
1.	Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	-
2.	Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2018	-
3.	Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	-
4.	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	-

11.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

A. Qualitative disclosures

- 1) The Bank uses financial derivative transactions predominantly for raising cost-effective funds and hedging its balance sheet exposures, with the objective of reducing market risk. The Bank currently deals only in over-the-counter (OTC) interest rate and currency derivatives, of the type permitted by RBI.
- 2) Derivative transactions carry (i) market risk i.e. the probable loss that the Bank may incur as a result of adverse movements in interest rates / exchange rates and (ii) credit risk i.e. the probable loss the Bank may incur if the counter-parties fail to meet their obligations. The Bank has in place a Derivative Policy approved by the Board, which aims at synchronising the risk management objectives at the transaction level with those of the overall ALM position. The policy defines the use of permitted derivative products consistent with business goals of the Bank, lays down the control and monitoring systems and deals with regulatory, documentation and accounting issues. The policy also prescribes suitable risk parameters to control and manage market risk on derivative trades undertaken in the treasury book (stop-loss limits, open position limits, tenor limits, settlement and pre-settlement risk limits, PV01 limits).
- 3) The ALCO of the Bank oversees management of market risks with support from the Bank's Mid-Office, which measures, monitors and reports market risk associated with derivative transactions.
- 4) All derivative transactions outstanding in the Bank's books as on March 31, 2018 have been undertaken for hedging purposes and are in the ALM book. The income on such transactions has been accounted for on accrual basis.
- 5) Interest Rate Swaps (IRS) and Currency Swaps are not included in Outstanding Forward Exchange Contracts under Contingent Liabilities as per the Derivative Policy.

B. Quantitative Disclosures

(₹ billion)

Sr. No.	Particulars	2017-18		2016-17	
		Currency Derivatives	Interest rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest rate Derivatives
1	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For hedging	392.45	348.12	371.84	290.75
	b) For trading	-	-	-	-
2	Marked to Market Positions				
	a) Asset (+)	-	-	-	-
	b) Liability (-)	28.75	11.28	32.72	6.73
3	Credit Exposure	19.42	1.72	21.50	1.64
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	13.54	20.26	13.69	16.44
	b) On trading derivatives	-	-	-	-
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) On hedging				
	(i) Maximum	13.67	20.52	14.66	18.22
	(ii) Minimum	12.77	14.47	13.69	8.98
	b) On trading				
	(i) Maximum	-	-	-	-
	(ii) Minimum	-	-	-	-

12. Letters of comfort issued by the Bank

During the year, the Bank has issued Letter of Comfort to ICICI Bank aggregating ₹ 0.58 billion (previous year to Punjab National Bank aggregating ₹ 2.00 billion). As on March 31, 2018, no financial obligation has arisen on the above commitments. As on March 31, 2018, total Letters of Comfort outstanding aggregate ₹ 2.58 billion.

13. Asset Liability Management

Current Year:

(₹ billion)

Particulars	1 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 months & up to 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Rupee Advances	36.77	22.54	21.41	47.61	39.62	52.22	25.14	32.89	278.20
Rupee Investments	-	0.95	0.07	0.04	2.51	0.11	0.99	52.30	56.97
Rupee Other Assets	25.18	1.61	48.04	23.32	78.64	128.49	102.49	331.79	739.56
Rupee Deposits	0.01	0.004	0.14	21.48	22.00	0.41	0.05	-	44.09
Rupee Borrowings	35.43	5.00	54.75	24.10	57.77	44.23	72.67	143.96	437.91
Rupee Other Liabilities	21.91	22.97	28.73	24.63	78.20	89.99	35.55	193.84	495.82
Foreign Currency Assets	53.35	25.88	37.78	48.05	124.49	254.16	211.44	375.34	1,130.49
Foreign Currency Liabilities	41.09	8.32	45.43	53.50	126.76	284.32	249.88	316.52	1,125.82

Previous Year:

(₹ billion)

Particulars	1 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 months & up to 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Rupee Advances	4.72	10.22	105.12	48.39	47.17	30.41	23.17	37.44	306.64
Rupee Investments	-	0.10	0.57	0.56	0.11	2.85	1.53	45.24	50.96
Rupee Other Assets	26.22	4.71	27.18	17.71	29.87	154.99	95.15	298.10	653.93
Rupee Deposits	1.37	0.02	0.37	23.93	9.50	0.54	0.19	-	35.92
Rupee Borrowings	27.63	0.40	100.89	6.00	7.30	83.27	52.43	158.97	436.89
Rupee Other Liabilities	3.20	4.94	28.81	26.56	33.76	103.78	32.88	194.31	428.24
Foreign Currency Assets	36.95	10.40	39.91	95.66	115.11	185.74	168.12	320.54	972.43
Foreign Currency Liabilities	5.69	2.49	11.08	89.38	90.06	246.75	209.80	304.98	960.23

14. Draw Down from Reserves

The Bank has not drawn any amount from the Reserves.

15. Business Ratios

Particulars	2017-18	2016-17
Return on Equity	(39.94)%	0.62%
Return on Assets	(2.42)%	0.04%
Net Profit/(Loss) per employee (₹ billion)	(0.086)	0.001

16. Disclosure of Penalties Imposed by RBI

There are no penalties imposed by the Reserve Bank of India under the Reserve Bank of India Act, 1934, for contraventions of any of the provisions of the Act or non-compliance with any other requirements of the Act, order, rule or condition specified by Reserve Bank of India.

17. Disclosure of Complaints

Customer Complaints

Sr. No.	Particulars	2017-18	2016-17
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	-	-
(b)	No. of complaints received during the year	1	2
(c)	No. of complaints redressed during the year	1	2
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	-	-

18. Off-Balance Sheet SPVs Sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
-	-

Disclosure as per specific Accounting Standards

19. Details of Fixed Assets

Details of Fixed Assets are given below as prescribed in AS-10 Accounting for Fixed Assets issued by the ICAI.

(₹ billion)

Particulars	Premises	Others	Total
Gross Block			
Cost as on 31 st March 2017	2.06	1.02	3.08
Additions	0.03	0.12	0.15
Disposals	0.00	0.10	0.10
Cost as on 31 st March 2018 (A)	2.09	1.04	3.13
Depreciation			
Accumulated as on 31 st March 2017	0.92	0.86	1.78
Provided during the year	0.09	0.10	0.19
Eliminated on Disposals	0.00	0.10	0.10
Accumulated as on 31 st March 2018 (B)	1.01	0.86	1.87
Net Block (A-B)	1.08	0.18	1.26

Previous Year:

(₹ billion)

Particulars	Premises	Others	Total
Gross Block			
Cost as on 31 st March 2016	1.73	0.90	2.63
Additions	0.33	0.14	0.47
Disposals	0.00	0.02	0.02
Cost as on 31 st March 2017 (A)	2.06	1.02	3.08
Depreciation			
Accumulated as on 31 st March 2016	0.84	0.79	1.63
Provided during the year	0.08	0.09	0.17
Eliminated on Disposals	0.00	0.02	0.02
Accumulated as on 31 st March 2017 (B)	0.92	0.86	1.78
Net Block (A-B)	1.14	0.16	1.30

20. Accounting for Government Grants

The Government of India has agreed to pay interest equalisation amount to the Bank towards specific Lines of Credit extended by the Bank to foreign governments, overseas banks/institutions and the same is accounted on accrual basis.

21. Segment Reporting

The operations of the Bank predominantly comprise of only one business segment i.e. financial activities and hence, have been considered as representing a single business segment.

The geographic segments of the Bank are categorised as Domestic Operations and International Operations. The categorisation of operations as domestic or international is primarily based on the risk and reward associated with the place of the transaction.

(₹ billion)

Particulars	Domestic Operations		International Operations		Total	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Revenue	80.79	85.15	6.99	7.20	87.78	92.35
Assets	1,139.90	1,050.53	95.29	121.54	1,235.19	1,172.07

22. Related Party Disclosures

As per AS-18 Related Party Disclosure issued by the ICAI, the Bank's related parties are disclosed below:

- Relationship

- (i) Joint Ventures:
 - Global Procurement Consultants Limited
 - (ii) Key Managerial Personnel:
 - Shri David Rasquinha (Managing Director – additional charge) (upto August 15, 2017) and (Managing Director) (from August 16, 2017)
 - Shri Debasish Mallick (Deputy Managing Director)
- The Bank's related party balances and transactions are summarised as follows:

(₹ million)

Particulars	Joint Venture		Key Managerial Personnel	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Loans granted	-	-	-	-
Guarantees issued	1.58	-	-	-
Interest received	-	-	-	-
Guarantee commission received	0.004	0.02	-	-
Receipts towards services rendered	0.05	-	-	-
Term Deposit Accepted	-	6.62	-	0.50
Interest on Term Deposits	0.31	0.81	0.42	0.49
Amounts written-off/written-back	-	-	-	-
Term Deposit Outstanding	-	6.62	3.24	3.44
Loans outstanding at year-end	-	-	-	-
Guarantees outstanding at year-end	1.58	3.26	-	-
Investments outstanding at year end	3.23	3.23	-	-
Dividend Received	0.42	0.28	-	-
Maximum Loan outstanding during the year	-	-	-	-
Maximum Guarantees outstanding during the year	4.45	3.26	-	-
Salary including perquisites	-	-	7.32	9.36
Rent paid	-	-	0.30	0.25

23. Accounting for Taxes on Income

(a) Details of Provision for Tax for current year:

(₹ billion)

(i)	Tax on Income	1.65
(ii)	Less: Net deferred tax Asset	(14.71)
		(13.06)

(b) Deferred Tax Asset:

The composition of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

(₹ billion)

Particulars		
Deferred Tax Assets		
1.	Provision Disallowed (Net)	38.32
2.	Depreciation on Fixed Assets	0.07
		38.39
Less: Deferred Tax Liability		
1.	Amortisation of Bond issue expenses	0.56
2.	Special Reserve created under section 36(1)(viii)	4.56
		5.12
Net Deferred Tax Assets [included in 'Other Assets' in the 'Assets' side of the Balance Sheet]		33.27

24. Financial Reporting of Interest in Joint Ventures**I.**

	Jointly Controlled Entities	Country	Percentage of holding	
			Current Year	Previous Year
A	Global Procurement Consultants Ltd. (GPCL)	India	28%	28%

II. Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the interest in the jointly controlled entities using Equity method is as under:

(₹ million)

Liabilities	2017-18	2016-17	Assets	2017-18	2016-17
Capital & Reserves	26.67	24.40	Fixed Assets	0.07	0.09
Loans	-	-	Investments	14.95	10.09
Other Liabilities	8.24	5.62	Other Assets	19.89	19.84
Total	34.91	30.02	Total	34.91	30.02

Contingent Liabilities: NIL (previous year: NIL)

(₹ million)

Expenses	2017-18	2016-17	Income	2017-18	2016-17
Other Expenses	11.36	12.52	Consultancy Income	14.13	15.62
Provisions	1.26	1.26	Interest income and Income from investment	0.34	0.35
Profit after Tax	2.85	2.93	Other Income	1.00	0.74
Total	15.47	16.71	Total	15.47	16.71

Note: Figures for GPCL for FY 2017-18 are unaudited and provisional

25. Impairment of Assets

A substantial portion of the Bank's assets comprise of 'financial assets' to which Accounting Standard 28 "Impairment of Assets" is not applicable. In the opinion of the Bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) as at March 31, 2018, requiring recognition in terms of the said standard.

26. Employee Benefits

The Bank has adopted Accounting Standard 15 – Employee Benefits, issued by the ICAI w.e.f. April 01, 2007. The Bank recognises in its books the liability arising out of Employee Benefits as present value of obligations as reduced by the fair value of plan assets on the Balance Sheet date.

A) Amount to be recognised in the Balance Sheet

(₹ billion)

Particulars	Pension Fund	Gratuity
Fair value of Plan Assets at the end of the period	0.952	0.138
Present value of Benefit Obligation at the end of the period	0.907	(0.154)
Funded Status	0.045	(0.016)
Unrecognised past service cost at the end of the period	-	-
Unrecognised transitional liability at the end of the period	-	-
Net Liability recognised in the Balance Sheet	(0.045)	0.016

B) Expense to be recognised in the Profit and Loss Account

(₹ billion)

Particulars	Pension Fund	Gratuity
Current Service Cost	0.024	0.012
Interest Cost	0.007	0.001
Expected Return on Plan Assets	0.059	0.009
Actuarial Losses/(Gains)	(0.158)	0.003
Past Service Cost – Non-vested Benefit	-	-
Past Service Cost – vested benefit	-	-
Transitional liability	-	-
Expense recognised in Profit and Loss Account	(0.127)	0.016
Contributions by Employer	(0.011)	(0.019)

C) Summary of Actuarial Assumptions

Particulars	Pension Fund	Gratuity
Discount Rate (p.a.)	7.70%	7.85%
Expected Rate of Return on Assets (p.a.)	7.70%	7.85%
Salary Escalation Rate (p.a.)	7.00%	7.00%

In addition to the above, for the year FY 2017-18 the amount of Defined Benefit Obligation of Leave Encashment works out to ₹ 0.072 billion, however provision for an amount of ₹ 0.099 billion has already been made, hence, no further provision is required.

27. In terms of SEBI circular dated October 29, 2013 the contact details of the Debenture Trustee for various Bonds issued by Export-Import Bank of India is as given below:

DEBENTURE TRUSTEE**AXIS Trustee Services Ltd.**

Designated Person: Mr. Jayendra P. Shetty, Chief Operating Officer

Address:

Axis House,
Bombay Dyeing Mills Compound,
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400 025.

Tel.: (022) 6226 0050/54

Fax: (022) 2425 3000

E-mail: debenturetrustee@axistrustee.com

Website: www.axistrustee.com

28. Previous year's figures have been regrouped, wherever necessary.

For and on behalf of the Board

Shri Debasish Mallick
Deputy Managing Director

Shri T. S. Tirumurti

Shri Rajeev Rishi

Shri David Rasquinha
Managing Director

Shri Pankaj Jain

Smt. Geetha Muralidhar

Shri Rajnish Kumar

As per our attached report of even date
For **Sorab S. Engineer & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 110417W

(CA N. D. Anklesaria)
Partner
M. No. 010250

Mumbai, May 18, 2018



**THE EXPORT
DEVELOPMENT FUND**

DIRECTORS' REPORT

As per Section 15 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (Exim Bank Act), Exim Bank, with effect from such date as the Central Government may, by notification, appoint, shall establish a special fund to be called the Export Development Fund (EDF). The EDF was duly notified by the Central Government on March 31, 1986, and was accordingly established as on the same date.

The Central Government, on March 31, 1986, transferred an initial corpus of ₹ 100 million to the EDF. Subsequently, the Central Government transferred further amounts of ₹ 35 million on March 23, 1987, and ₹ 6.52 million on March 29, 1989. This corpus, along with interest accrued by way of investment, and net of tax paid to the Central Government, had grown to an aggregate bank balance of ₹ 350.60 million by March 31, 1996. Out of the total EDF corpus, an amount of ₹ 250 million was transferred, with Board and GOI approval, to a Reserve, termed the 'Sinking Fund (SF) Reserve', under the Bank's General Fund. The purpose of the SF Reserve was to absorb losses pertaining to Exim Bank's lending under export Lines of Credit (LOCs) / Buyer's Credit, which did not enjoy insurance cover from the Export-Credit Guarantee Corporation of India (ECGC). Since March 31, 1997, up to March 31, 2018, the total assets of EDF have grown to ₹ 8.60 billion.

As per the Statement of Objects and Reasons in the Bill placed before the Parliament seeking setting up of Export-Import Bank of India, the Export Development Fund is to be utilised mainly for the purposes of research, training, survey, market intelligence, etc. in connection with the country's international trade as well as for financing proposals which are unlikely to be supported by banks and financial institutions. Utilisation of the EDF is governed by Section 17 of the Exim Bank Act, as under:

Section 17(1) of the Act permits Exim Bank to (inter alia) extend loans and advances in or outside India for the purpose of exports, with the prior approval of the Central Government.

Section 17(2) of the Act requires that Exim Bank, prior to seeking such approval of the Central Government, shall satisfy itself that "..... banking or financial institutions or other agencies are not likely to grant such loan or advance, or to enter into any such arrangement in the ordinary course of business."

Section 17(3) of the Act mandates that before giving its approval, the Central Government shall satisfy itself that such a facility would be necessary as a matter of priority in the interests of the international trade of India.

The EDF, thus, offers itself as a useful avenue for the GOI to facilitate international trade and cross-border investment related activities that may not be amenable to standard financing by Exim Bank or other bank / financial institutions.

The Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance conveyed the approval of the Central Government under Section 17 (1) of the Exim Bank Act, for domiciling in the EDF a Buyer's Credit Facility (under NEIA) of ₹ 9 billion for extending to select Iranian banks for financing export of goods and services from India to Iran. Pursuant to receipt of all necessary approvals, the EDF, on December 23, 2014, concluded an umbrella Framework Agreement with seven Iranian banks for a Buyer's Credit Facility of ₹ 9 billion with a tenure of up to 12 years, including a moratorium of up to 4 years, to finance the export of goods and services from India to Iran. The Buyer's Credit Facility to the Iranian banks is backed by Sovereign Guarantee of the Government of Iran.

Subsequently, DFS conveyed its approval to enhancement of the facility covered under the Framework Agreement from ₹ 9 billion to ₹ 30 billion. Accordingly, the EDF, on

May 04, 2016, entered into an Amendatory Agreement to the Framework Agreement with the aforesaid seven Iranian banks for the enhanced facility of ₹ 30 billion. The facility amount of ₹ 30 billion is envisaged for financing import of steel rails from India, and development of the Chabahar port. The modalities of utilisation of the credit will be decided in accordance with the Framework Agreement.

Under the Framework Agreement, the first contract for an aggregate value of ₹ 8.19 billion, for supply of 150,000 tonnes of steel rails from India to the Railway of the Islamic Republic of Iran through the Bank of Industry and Mine, Iran, has since been approved under the Buyer's Credit Facility. As of March 31, 2018, disbursements aggregating ₹ 8.11 billion have been made under the contract by the EDF. Pending receipt of approval for a

GOI guarantee for raising funds in the EDF, the disbursements are being funded by the EDF out of an interim loan provided by the Bank's General Fund. Financing for the balance steel rails contract, and the contract for the Chabahar Port project are at various stages of negotiation/finalisation.

At the instance of the Iranian side, a proposal for purchase of six (6) Pneumatic Ship-Unloaders valued at EUR 12.88 million for Chabahar Port Development Project has been approved. Implementation is underway.

Profit before tax of the Export Development Fund during FY 2017-18 was ₹ 114.54 million as against ₹ 101.67 million during FY 2016-17. After providing for tax of ₹ 39.64 million, the post-tax profit amounted to ₹ 74.90 million, as against ₹ 66.49 million during FY 2016-17. The profit ₹ 74.90 million is carried forward to next year.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The President of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of the Export Development Fund of the Export-Import Bank of India ('the Bank'), which comprises of the Balance Sheet as at 31st March, 2018 and the Profit and Loss Account for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. The Management of the Bank is responsible for the preparation of the financial statements in accordance with the Export-Import Bank of India Act, 1981 ('the Act') and the Regulations framed thereunder. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility:

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
4. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
5. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements, in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Bank's management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
6. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

7. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements give the information in accordance with the requirements of the Act and the Regulations framed thereunder and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Export Development Fund of the Bank as at 31st March, 2018;
- (ii) In the case of the Profit and Loss Account, of the profit for the year ended 31st March 2018.

Report on Other Legal and Regulatory Matters:

- 8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of the Act and the Regulations framed thereunder.
- 9. We report that:
 - i) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

- ii) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

10. In our opinion, the Balance Sheet and Profit and Loss Account comply with the mandatory Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

11. We further report that:

- i) The Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report, are in agreement with the books of account and the returns.
- ii) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books.

For **SORAB S. ENGINEER & CO.**
Chartered Accountants
 Firm Registration No. 110417W

CA N. D. ANKLESARIA
PARTNER
 MEMBERSHIP NO. 10250

Mumbai, 18th May, 2018.

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2018**EXPORT DEVELOPMENT FUND**

	This year (As at 31.03.2018) ₹	Previous year (As at 31.03.2017) ₹
LIABILITIES		
1. Loans:		
a) From Government	-	-
b) From Other Sources	6,932,011,546	5,374,610,504
2. Grants:		
a) From Government	128,307,787	128,307,787
b) From Other Sources	-	-
3. Gifts, Donations, Benefactions:		
a) From Government	-	-
b) From Other Sources	-	-
4. Other Liabilities	951,143,165	309,162,861
5. Profit and Loss Account	585,967,085	511,063,467
Total	8,597,429,583	6,323,144,619
ASSETS		
1. Bank Balances:		
a) In current accounts	116,549	163,809
b) In other deposit accounts	-	204,000,000
2. Investments	-	-
3. Loans and Advances:		
a) In India	-	-
b) Outside India	8,116,580,978	5,809,030,094
4. Bills of Exchange and Promissory Notes Discounted, Rediscounted:		
a) In India	-	-
b) Outside India	-	-
5. Other Assets:		
a) Accrued interest on:		
i) Loans and Advances	238,400,353	98,617,251
ii) Investments/bank balances	-	10,301,762
b) Advance Income Tax paid	242,331,703	201,031,703
c) Others	-	-
Total	8,597,429,583	6,323,144,619

EXPORT DEVELOPMENT FUND

	This year (As at 31.03.2018) ₹	Previous year (As at 31.03.2017) ₹
CONTINGENT LIABILITIES		
i) Acceptances, Guarantees, Endorsements and other obligations	-	-
ii) On outstanding forward exchange contracts	-	-
iii) On underwriting commitments	-	-
iv) Uncalled Liability on partly paid investments	-	-
v) Claims on the Bank not acknowledged as debts	-	-
vi) Bills for collection	-	-
vii) On participation certificates	-	-
viii) Bills Discounted/Rediscounted	-	-
ix) Other monies for which the Bank is contingently liable	-	-

Note:

The Bank has established Export Development Fund in terms of Section 15 of Export-Import Bank of India Act, 1981 (The Act). In terms of Section 17 of the Act, before granting any loan or advance or entering into any such arrangement, Exim Bank has to obtain the prior approval of the Central Government.

For and on behalf of the Board

Shri Debasish Mallick
Deputy Managing Director

Shri T. S. Tirumurti

Shri Rajeev Rishi

Shri David Rasquinha
Managing Director

Shri Pankaj Jain

Smt. Geetha Muralidhar

Shri Rajnish Kumar

As per our attached report of even date
For **Sorab S. Engineer & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 110417W

(CA N. D. Anklesaria)
Partner
M. No. 010250

Mumbai, May 18, 2018

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018**EXPORT DEVELOPMENT FUND**

	This year ₹	Previous year ₹
EXPENDITURE		
1. Interest	555,196,969	90,924,855
2. Other Expenses	3,143,189	794,779
3. Profit carried down	114,545,618	101,673,294
Total	672,885,776	193,392,928
Provision for Income Tax	39,642,000	35,187,000
Balance of profit transferred to Balance Sheet	74,903,618	66,486,294
	114,545,618	101,673,294
INCOME		
1. Interest and Discount:		
a) loans and advances	663,567,960	98,617,251
b) investments/bank balances	4,697,714	43,277,262
2. Exchange, Commission, Brokerage and Fees	4,620,102	51,498,415
3. Other Income	-	-
4. Loss carried to Balance Sheet	-	-
Total	672,885,776	193,392,928
Profit brought down	114,545,618	101,673,294
Excess Income/Interest tax provision of earlier years written back	-	-
	114,545,618	101,673,294

For and on behalf of the Board

Shri Debasish Mallick
Deputy Managing Director**Shri T. S. Tirumurti****Shri Rajeev Rishi****Shri David Rasquinha**
Managing Director**Shri Pankaj Jain****Smt. Geetha Muralidhar****Shri Rajnish Kumar**As per our attached report of even date
For **Sorab S. Engineer & Co.**
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 110417W**(CA N. D. Anklesaria)**
Partner
M. No. 010250

Mumbai, May 18, 2018

NOTES

भारतीय निर्यात-आयात बैंक के कार्यालय

प्रधान कार्यालय

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई - 400 005.

फोन: +91 22 22172600 | फैक्स: +91 22 22182572

ई-मेल: ccg@eximbankindia.in | वेबसाइट: www.eximbankindia.in, www.eximmitra.in

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद

साकार II, पहली मंजिल, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के पास,
एलिसब्रिज पी. ओ., अहमदाबाद - 380 006.

फोन: +91 79 26576852/26576843 | फैक्स: +91 79 26577696

ई-मेल: eximahro@eximbankindia.in

बैंगलोर

रमणश्री आर्केड, चौथी मंजिल, 18, एम. जी. रोड, बैंगलोर - 560 001.

फोन: +91 80 25585755/25589101/04

फैक्स: +91 80 25589107

ई-मेल: eximbro@eximbankindia.in

चंडीगढ़

सी-213, दूसरी मंजिल, एलान्ते कार्यालय,
औद्योगिक क्षेत्र फेज-1, चंडीगढ़.

फोन: +91 172 4629171/73 | फैक्स: +91 172 4629175

ई-मेल: eximcro@eximbankindia.in

चेन्नै

ओवरसीज टॉवर्स, चौथी एवं पांचवी मंजिल, 756-एल,
अन्ना सलाई, चेन्नै - 600 002.

फोन: +91 44 28522830/31 | फैक्स: +91 44 28522832

ई-मेल: eximchro@eximbankindia.in

गुवाहाटी

नेडफी हाउस, चौथी मंजिल, जी. एस. रोड, दिसपुर,

गुवाहाटी - 781 006.

फोन: +91 361 2237607/609 | फैक्स: +91 361 2237701

ई-मेल: eximgro@eximbankindia.in

हैदराबाद

गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंजिल, 6-3-639/640,

राज भवन रोड, खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद - 500 004.

फोन: +91 40 23307816/21 | फैक्स: +91 40 23317843

ई-मेल: eximhro@eximbankindia.in

कोलकाता

वाणिज्य भवन, चौथी मंजिल, (अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण केंद्र),
1/1 बुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016.

फोन: +91 33 22833419/20 | फैक्स: +91 33 22891727

ई-मेल: eximkro@eximbankindia.in

नई दिल्ली

स्टेट्समैन हाउस, तल मंजिल, 148, बाराखंबा रोड,

नई दिल्ली - 110 001.

फोन: +91 11 23474800 | फैक्स: +91 11 23322758/23321719

ई-मेल: eximndro@eximbankindia.in

पुणे

44, शंकरशेठ रोड, पुणे - 411 037.

फोन: +91 20 26403000 | फैक्स: +91 20 26458846

ई-मेल: eximpro@eximbankindia.in

लंदन शाखा

5वीं मंजिल, 35 किंग स्ट्रीट, लंदन ईसी 2वी 8 बीबी, यूनाइटेड किंगडम.

फोन: +44 20 77969040 | फैक्स: +44 20 76000936

ई-मेल: eximlondon@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

आबिदजान

5वीं मंजिल, अज्यूर बिल्डिंग, 18-दॉक्टर क्रोजे रोड,
प्लेत्यो-आबिदजान, कोत दि'वार.

फोन: +225 20 24 29 51 | मोबाइल: +225 79707149

फैक्स: +225 20 24 29 50

ई-मेल: eximabidjan@eximbankindia.in

अदिस अबाबा

हाउस नं. 46, जैक्रोस एस्टेट कंपाउंड, वारेडा,

बोले सब-सिटी, अदिस अबाबा, इथियोपिया.

फोन: +251 116 222296 | फैक्स: +251 116 610170

ई-मेल: aaro@eximbankindia.in

ढाका

मधुमिता प्लाज़ा कॉन्कोर्ड, 12वीं मंजिल, प्लॉट सं. 11, रोड नं. 11,
ब्लॉक जी, बानानी ढाका - 1213.

फोन: +88 01 708 520 444

ई-मेल: eximdhaka@eximbankindia.in

दुबई

लेवल 5, टेनेसी 1बी, गेट प्रीसिक्ट बिल्डिंग नं. 3,

दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र, पीओ बॉक्स नं. 506541, दुबई, यूएई.

फोन: +971 4 3637462 | फैक्स: +971 4 3637461

ई-मेल: eximdubai@eximbankindia.in

जोहांसबर्ग

दूसरी मंजिल, सैंडटन सिटी टिवन टॉवर्स ईस्ट, सैंडहर्स्ट एक्सटेंशन 3,
सैंटन 2196, जोहांसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका.

फोन: +27 11 3265103/13 | फैक्स: +27 11 7844511

ई-मेल: eximjro@eximbankindia.in

सिंगापुर

20, कोलियर व्हे, #10-02, सिंगापुर - 049319.

फोन: +65 65326464 | फैक्स: +65 65352131

ई-मेल: eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंगटन डी. सी.

1750 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू एन. डब्ल्यू. सूइट 1202,

वाशिंगटन डी. सी. 20006, संयुक्त राज्य अमेरिका.

फोन: +1202 223 3238 | फैक्स: +1202 785 8487

ई-मेल: eximwashington@eximbankindia.in

यांगून

हाउस नं. 54/ए, तल मंजिल, बोरायुत मार्ग, डैगन टाउनशिप,
यांगून, म्यांमार.

फोन: +95 1389520 | मोबाइल: +95 1389520

ई-मेल: eximyangon@eximbankindia.in

OUR GLOBAL FOOTPRINT

Head Office

Centre One Building, 21st Floor, World Trade Centre Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.
Ph.: +91 22 22172600 | Fax: +91 22 22182572
E-mail: ccg@eximbankindia.in | Website: www.eximbankindia.in | www.eximmitra.in

Offices in India

AHMEDABAD

Sakar II, 1st Floor, Next to Ellisbridge Shopping Centre,
Ellisbridge P. O., Ahmedabad - 380 006.
Ph.: +91 79 26576852/26576843 | Fax: +91 79 26577696
E-mail: eximahro@eximbankindia.in

BENGALURU

Ramanashree Arcade, 4th Floor, 18, M. G. Road,
Bengaluru - 560 001.
Ph.: +91 80 25585755/25589101-04 | Fax: +91 80 25589107
E-mail: eximbro@eximbankindia.in

CHANDIGARH

C- 213, 2nd Floor, Elante Offices,
Industrial Area Phase -1, Chandigarh - 160 002.
Ph.: +91 172 4629171/73 | Fax: +91 172 4629175
E-mail: eximcro@eximbankindia.in

CHENNAI

Overseas Towers, 4th and 5th Floor, 756-L,
Anna Salai, Chennai - 600 002.
Ph.: +91 44 28522830/31 | Fax: +91 44 28522832
E-mail: eximchro@eximbankindia.in

GUWAHATI

NEDFI House, 4th Floor, GS Road, Dispur, Guwahati - 781 006.
Ph.: +91 361 2237607/609 | Fax: +91 361 2237701
E-mail: eximgro@eximbankindia.in

HYDERABAD

Golden Edifice, 2nd Floor, 6-3-639/640, Raj Bhavan Road,
Khairatabad Circle, Hyderabad - 500 004.
Ph.: +91 40 23307816-21 | Fax: +91 40 23317843
E-mail: eximhro@eximbankindia.in

KOLKATA

Vanijya Bhawan, 4th Floor, (International Trade Facilitation Centre),
1/1 Wood Street, Kolkata - 700 016.
Ph.: +91 33 22833419/20 | Fax: +91 33 22891727
E-mail: eximkro@eximbankindia.in

NEW DELHI

Statesman House, Ground Floor,
148, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.
Ph.: +91 11 23474800 | Fax: +91 11 23322758/23321719
E-mail: eximndro@eximbankindia.in

PUNE

44, Shankarsheth Road, Pune - 411 037.
Ph.: +91 20 26403000 | Fax: +91 20 26458846
E-mail: eximpro@eximbankindia.in

London Branch

5th Floor, 35 King Street,
London EC2V 8BB, United Kingdom.
Ph.: +44 20 77969040 | Fax: +44 20 76000936
E-mail: eximlondon@eximbankindia.in

Offices Overseas

ABIDJAN

5th Floor, Azur Building, 18-Docteur Crozet Road,
Plateau, Abidjan, Côte d'Ivoire.
Ph.: +225 20 24 29 51 | Fax: +225 20 24 29 50
E-mail: eximabidjan@eximbankindia.in

ADDIS ABABA

House No. 46, Jakrose Estate Compound,
Woreda 07, Bole Sub-City,
Addis Ababa, Ethiopia.
Ph.: +251 118 222296 | Fax: +251 116 610170
E-mail: aaro@eximbankindia.in

DHAKA

Modhumita Plaza Concord, Floor 12, Plot No. 11,
Road No. 11, Block G, Banani, Dhaka - 1213. Bangladesh.
Ph.: +88 01 708 520 444
E-mail: eximdhaka@eximbankindia.in

DUBAI

Level 5, Tenancy 1B, Gate Precinct Building No. 3, Dubai
International Financial Centre, PO Box No. 506541, Dubai, UAE.
Ph.: +971 4 3637462 | Fax: +971 4 3637461
E-mail: eximdubai@eximbankindia.in

JOHANNESBURG

2nd Floor, Sandton City Twin Towers East, Sandhurst Ext. 3,
Sandton 2196, Johannesburg, South Africa.
Ph.: +27 11 3265103/13 | Fax: +27 11 7844511
E-mail: eximjro@eximbankindia.in

SINGAPORE

20, Collyer Quay, #10-02, Singapore - 049319.
Ph.: +65 65326464 | Fax: +65 65352131
E-mail: eximsingapore@eximbankindia.in

WASHINGTON D.C.

1750 Pennsylvania Avenue NW, Suite 1202,
Washington D.C. 20006, United States of America.
Ph.: +1 202 223 3238 | Fax: +1 202 785 8487
E-mail: eximwashington@eximbankindia.in

YANGON

House No. 54/A, Ground Floor, Boyarynyunt Street,
Dagon Township, Yangon, Myanmar.
Ph.: +95 1389520
E-mail: eximyangon@eximbankindia.in



केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ परेड, मुंबई - 400 005.

Centre One Building, Floor 21,
World Trade Centre Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.

+91 22 22172600

+91 22 22182572

ccg@eximbankindia.in

www.eximbankindia.in, www.eximmitra.in

हमे फॉलो करें:

Follow us on:    

